





2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा स्वीकृत पाठ्य-पुस्तक

# भारतीय

## अर्थशास्त्र की रूप-रेखा

(ग्यारहवीं कक्षा के लिए)

लेखक

एस. सी. तैला

एम. ए., एल-एल. बी, आर. ई. एम.,

प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, श्री गंगानगर

तथा

ए. के. जैन

एम. ए. बी. कॉम., आर. ई. एम.,

प्रबंधात्मक विभाग, सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय, गंगानगर



“भारतीय अर्थशास्त्र की रूपरेखा” पुस्तक विशेषकर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नव-निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार ग्यारहवीं कक्षा के लिए लिखी गई है। अल्प समय में ही पुस्तक के द्वितीय संस्करण का प्रकाशित हो जाना इसकी उपादेयता का प्रतीक है।

विषय को सफ़िकर बनाने के लिए सरल भाषा और आकर्षक शैली का सहारा लेकर भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल बातों को प्रस्तुत किया गया है। विशिष्ट शब्द हिन्दी तथा अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में दिए गए हैं। यथा स्थान तालिकाएँ, चित्र व मानचित्र भी दिए गए हैं। प्रत्येक अध्याय के प्रारम्भ में किसी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का उद्धरण तथा अन्त में अध्याय का सार और चुने हुए महत्वपूर्ण परीक्षा-प्रश्न दिए गये हैं जिससे विद्यार्थियों को विषय दोहराने में सुविधा हो।

इस पुस्तक में भारत सरकार द्वारा मान्य शब्दावली का प्रयोग किया गया है।

हम उन सभी लेखकों, विचारकों और विद्वानों के आभारी हैं जिनके विचारों व पाठ्य-सामग्री का समावेश इस पुस्तक में किया गया है। आशा है पाठकगण समय-समय पर अपने बहुमूल्य सुझाव देकर हमें अनुश्रुत करें।

1 जून 1970

एन. सी. तेल

ए. के. जैन

# विषय-सूची

अध्याय	पृष्ठ संख्या
1. ब्रिटिश शासन काल में भारतीय अर्थ व्यवस्था	1- 2
2. भारतीय कृषि	22- 3
3. भारत में कृषि की जोड़ें	37- 5
4. कृषि के साधन I (बीज, खाद, उपकरण व पशु)	51- 6
5. कृषि के साधन II (सिंचाई)	62- 8
6. कृषि के साधन III (ग्रामीण वित्त)	85- 5
7. भारतीय कृषि की पद्धति	100-11
8. सामुदायिक विकास	112-17
9. भारतवर्ष में सहकारिता आन्दोलन	126-14
10. कृषि विपणन	149-11
11. ग्रामीण ढोचों में सहायक व्यवसाय	161-17
12. भारतवर्ष में भूमि सुधार	172-1
13. कृषि-अर्थिक	183-1
14. भारतीय औद्योगिक विकास का सामान्य सर्वेक्षण	194-2
15. आधुनिक भारतीय उद्योग	211-2
16. भारतीय विदेशी व्यापार	243-2
17. भारत में बेरोजगारी की समस्या	263-2
18. भारत में आर्थिक नियोजन I	277-5
19. भारत में आर्थिक नियोजन II	296-4

## ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय अर्थ व्यवस्था

जिस समय साधुनिक औद्योगिक प्रणाली की जन्मभूमि पश्चिम यूरोप में भ्रमर्य जातिवा निवास करती थी, उन दिनों भारत अपने पासकों के घन धर्मव तथा अपने शिल्पकारों के कौशल के लिए विख्यात था । इसके बहुत समय पश्चात् भी, जबकि पश्चिम से साहसी व्यापारी भारत में पहले पहल आये थे, इस देश का औद्योगिक विकास उन्नत यूरोपीय राष्ट्रों से किसी प्रकार घटिया न था ।

औद्योगिक आयोग, 1918

ब्रिटिश शासन से पूर्व भारतीय अर्थ व्यवस्था अपनी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध थी । यहाँ के उद्योग धन्ये, कलाशिल्प व सम्पत्ता संस्कृति अत्यन्त प्राचीन समय से ही उन्नत थे । जब यूरोप के वे देश जो आज विश्व के सबसे अधिक विकसित देश कहे जाते हैं अत्यन्त पिछड़ी हुई अवस्था में थे तब भारत आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से बहुत समृद्ध था । भारतीय अर्थ व्यवस्था के गौरवशाली अतीत के सम्बन्ध में कोई प्रमाणिक अंक शास्त्रीय इतिहास तो उपलब्ध नहीं है किन्तु समय समय पर यहाँ आये विदेशी यात्रियों के संस्मरणों, लेखों आदि से भारत की उन्नत अर्थ व्यवस्था की जानकारी मिलती है ।

भारतीय कारीगरों की उत्कृष्ट कला के प्रतीक अत्यन्त कलात्मक वस्त्रों का निर्माण, हीरे जवाहरात का काम, आदि विश्व भर में सुप्रसिद्ध थे । भारत टाका की मलमल विदेशों को निर्यात करता था । ऐसा मसौह के 2000 वर्षों से पूर्व मिस्र की मर्मियाँ (Mummies) भारतीय मलमल में लिपटी हुई पायी गई । ऐसा विवरण मिलता है कि 17 वीं शताब्दी के अन्त में भारतीय मलमल कम कोमत पर ही इंग्लैण्ड भेजी जाती थी । इससे वहाँ के उन्नी व रेशम के वस्त्र निर्माताओं को खतरा



उत्पन्न होने लगा । इसीलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में अनेक कानून हुए जिनके अनुसार भारतीय वस्तुओं के आयात का निषेध किया गया । इन सब निषेधों एवं कानूनों के बावजूद भी भारतवर्ष से प्रतिवर्ष भारी मात्रा में वस्त्र इंग्लैण्ड भेजा करता था ।

इसके अतिरिक्त भारत के अग्य प्राचीन गौरवशाली उद्योग व इस्पात, पोत निर्माण, बरतनों पर कलात्मक काम, आदि हैं । भारत की कृषि एवं सिंचाई के साधनों की उन्नत अवस्था अनेक उल्लेख मिलते हैं । संक्षेप में हम यह बतल सकते हैं कि भारत अत्यन्त गौरवशाली था ।

किन्तु धीरे धीरे गौरव की यह परम्परा समाप्त हो गई । भारतीय अर्थ व्यवस्था अर्द्ध विकसित अर्थ व्यवस्था के स्तर पर आती है । इस आर्थिक विघटन के लिए अनेक कारण बताये जा सकते हैं । कुछ पाश्चात्य विद्वान भारतीय धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं की स्थिति के लिए उत्तरदायी मानते हैं । श्रीमती बेरा एन्स्टेड भारतीय जनसंस्था को तथा श्री बेडनपावेल भारतीयों की निर्धनता आर्थिक विघटन के लिए उत्तरदायी मानते हैं । श्री नावेल्स (1911) के अनुसार इसका मुख्य कारण भारत का धार्मिक व सामाजिक पतन है । किन्तु हमारे विचार में इस आर्थिक विघटन का मूल कारण शासन की घातक नीति ही थी ।

ब्रिटिश राज्य का भारतीय उद्योगों एवं अर्थ व्यवस्था पर प्रभाव हुआ, इसे समझने के लिए यह आवश्यक है कि पहले हम भारतीय अर्थ व्यवस्था की उन विशेषताओं का अध्ययन करें जो भारत के आगमन से पूर्व विद्यमान थीं ।

ब्रिटिश पूर्ण अवधि में भारतीय अर्थ व्यवस्था की विशेषताएँ—

1. ग्राम व्यवस्था—अंग्रेजों के पूर्व भारत की अर्थ व्यवस्था का मूल आधार स्वावलम्बी ग्रामीण इकाईयाँ थीं । 19 वीं

आरम्भ तक प्रत्येक ग्राम सामा-  
जिक एवं आर्थिक दृष्टि से आत्म  
निर्भर था। ग्रामवासियों को तीन  
वर्गों में बाँटा जा सकता है—  
(अ) कृषक, (ब) कारीगर या  
दस्तकार एवं श्रमिक तथा (स)  
ग्राम अधिकारी Village Officer  
ग्राम में शान्ति व्यवस्था के लिए  
ग्राम मुखिया या पटेल उत्तरदायी  
होता था। पटवारी एवं चौकीदार  
सुरक्षा सम्बन्धी कार्य करते  
थे। गाँव की पंचायत न्याय  
व्यवस्था के लिए कार्य  
करती थी। दस्तकारों को  
गाँव की उपज में से प्रत्येक  
कमल पर अनाज मिलता  
था और बड़ले में वे गाँव  
वालों का काम करते थे।

प्राचीन ग्राम व्यवस्था  
की मुख्य विशेषता आत्म  
निर्भरता (Self sufficient)  
थी। यातायात एवं संचार  
वाहन के साधनों के अभाव  
में ग्राम एवं पूँजी की गति-

ब्रिटिश पूर्व भारतीय अर्थ-  
व्यवस्था की विशेषताएँ

1. स्वावलम्बी ग्राम इकाईयाँ
2. कृषि
3. उद्योग व हस्तशिल्प
4. नगर
5. व्यापार एवं यातायात व  
संचार वाहन
6. सामाजिक व्यवस्था

क्रमशः ग्राम के लगान बसूली तथा



भारतीय ग्राम

शीलता (Mobility) का अभाव था। चूँकि ग्राम की आवश्यकताओं  
को ग्राम में ही पूरा कर लिया जाता था इसलिए वस्तु विनिमय प्रण

(Barter System) का प्रचलन था और प्रायः मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। परम्पराओं एवं रीति रिवाजों का प्रभाव, लगन, मजदूरी एवं कीमतों के निर्धारण पर पर्याप्त रूप से पड़ता था। व्यवसायों चुनने की स्वतन्त्रता नहीं थी और पैतृकता के आधार पर ही काम किए जाते थे।

संक्षेप में, हम यह कह सकते हैं कि ग्रामों में जीवन व्यवस्था अत्यन्त सरल थी और प्रतियोगिता का प्रभाव था। परम्पराओं का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता था।

(2) कृषि (Agriculture)—अन्य देशों के अतीत की ही भाँति भारत में भी कृषि व्यवसाय की प्रधानता थी। कृषि वस्तुओं का साम



भारत में कृषि

अतन्त्र सीमित था। यातायात के साधनों के अभाव में कृषि व्यापारीकरण नहीं हो पाया था। कृषकों की स्थिति देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न थी कृषि की पद्धति बहुत पिछड़ी हुई थी।

3. उद्योग व हस्तशिल्प (Industries and Handicrafts)—यद्यपि कृषि भारतीय जनता का मुख्य व्यवसाय था फिर भी यहाँ के उद्योग विषय विस्फोट थे। सूती वस्त्र उत्पादन में ठाके की मलमल तथा बनारस की साड़ियाँ, कश्मीर व पंजाब के ऊनी वस्त्र, लोह इस्पात, पत्थर की मूर्तियाँ, बर्तन बनाने का व्यवसाय, लकड़ी व धातु पर कारीगरी आदि भारत के कतिपय उल्लेखनीय उद्योग रहे हैं। गाँवों के उद्योगों की तुलना में कस्बों एवं शहरों के उद्योग अधिक समृद्ध व्यवस्था

में थे । प्रत्येक नगर किसी न किसी व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध था । इस प्रकार भारत का औद्योगिक अतीत अत्यन्त गौरवशाली रहा है । कहा भी जाता है—“The Glory that was India”

4. नगर (Town)—प्राचीन काल में भारतीय आर्थिक जीवन में नगरों का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है । यद्यपि आँकड़ों के आधार पर यह कहना अत्यन्त कठिन है कि जनसंख्या का कितना भाग नगरों में रहता था किन्तु अनुमान लगाया जाता है कि नगरों में जनसंख्या का 10 प्रतिशत से अधिक भाग नहीं रहता था । नगरों का जीवन प्राचीन जीवन से भिन्न था । यहाँ के निवासी साक्षरों के लिए पढ़ोसी गाँवों पर निर्भर रहते थे । नगरों में उद्योग सुव्यवस्थित रूप से संगठित थे । बाजार विस्तृत थे और मुद्रा का पर्याप्त उपयोग होता था । सास पत्नों के रूप में हुण्डियों का प्रयोग किया जाता था । प्रो. गाडगिल (Prof. Gadgil) के अनुसार “ये (नगर) भारत के सामान्य जीवन से भिन्नता रखने वाले थे ।” नगरों की उत्पत्ति एवं समृद्धि मुख्य रूप से तीन कारणों पर आधारित मानी जाती थी—

- (अ) वे नगर धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, जैसे—बनारस, गया, पुरी, नासिक आदि ।
- (ब) नगरों के विकास का दूसरा कारण राजधानी या न्यायालय के केन्द्र के रूप में स्थापित होना था जैसे—दिल्ली लखनऊ, लाहौर, पूना, तंजौर, मुसिदाबाद, हाका आदि ।
- (स) तीसरे, वे नगर जिनका विकास औद्योगिक या व्यापारिक नगरों के रूपों में हुआ, जैसे—मिर्जापुर, बंगलौर, आदि ।

इस प्रकार एक या दूसरे कारण से नगरों का विकास हुआ ।

5. व्यापार (Trade) यातायात एवं संदेशवाहन के साधनों की स्थिति—अंग्रेजों के पूर्व भारत में ग्रामों की स्वावलम्बी इकाई के रूप में उपस्थिति एवं यातायात व संदेश वाहन के साधनों में व्यापार की

निम्न धरणी नहीं थी। सामाजिक व्यापार की जमी के कारण देश के निम्न विभिन्न भागों में जीमों में बहुत छार था।

वातावरण व भरेस बाह्य के वायुन अत्यन्त गिरी वसा में थे। यद्यपि समय समय पर जासकों में मङ्गुकी के निर्माण में बधि रिवाज किन्तु भारत जैसे विगत देश के लिए ये प्रमाण नग्न थे।

6. सामाजिक व्यवस्था—अंदेजों के पूर्व भारत की सामाजिक व्यवस्था में परम्परा एवं रिवाज का वातावरण व्याप्त था। सर्व एक रीति रिवाजों से समित समान में परिवर्तनों की पुकारन बहुत कम थी। इनका प्रभाव इति एवं उद्योगों की पद्धति पर पड़ना था और परम्परागत पद्धतियाँ ही प्रचलित रहती थी।

संयुक्त परिवार प्रथा एवं जाति प्रथा का प्रचलन था। इनका इतिहास भी रहा हो, इसमें कोई संदेह नहीं कि इस व्यवस्था ने बाकी हृद तक आर्थिक व सामाजिक जीवन को प्रभावित किया है। जन्म ही समाज में उसका स्थान, ऊँचा या नीचा, निर्धारित करता था। स्त्रियों की दशा भी अधिक अच्छी नहीं थी। कुल मिलकर अंदेजों के पूर्व भारत का सामाजिक जीवन परम्पराओं से बन्त था एवं आर्थिक विकास के लिए उचित वातावरण सँवार करने में असमर्थ था।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी का भारत में आगमन

एवं ब्रिटिश शासन की स्थापना

पुर्तगालियों द्वारा पूर्वी देशों के किये जाने वाले व्यापार की वस्तुओं को देखकर अंदेज भी आकर्षित हुए। सन् 1600 ई० में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना की स्वीकृति दी। इस कम्पनी का मूलधन 70,000 पौण्ड था। जैसे यूरोप में भारत के साथ व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने की दृष्टि से अनेक ईस्ट इण्डिया कम्पनियों की स्थापना हुई। पर इंग्लैण्ड, फ्रांस तथा

हालेण्ड की ईस्ट इण्डिया कम्पनियों को छोड़कर शेष सभी असफल हो गईं । यहाँ हमारा तात्पर्य इंग्लैण्ड की ईस्ट इण्डिया कम्पनी से ही है ।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने सन् 1606 में मुगल-सम्राट जहाँगीर से भारत में एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की । इस कारखाने की स्थापना सन् 1612 में सूरत में हुई । सन् 1639 में कम्पनी ने मद्रास में फोर्ट सेंट जार्ज का निर्माण किया । बम्बई का द्वीप किंग चार्ल्स द्वितीय से खरीदकर सन् 1687 में कम्पनी ने अपने कारखाने वहाँ लगाए । कम्पनी ने सन् 1700 में बंगाल में अपना मुख्य स्थान कलकत्ता में स्थापित किया । फाँसिरी पांडीचेरी एवं कलकत्ता के उत्तर में बन्दर नगर पर अपना अधिकार किये हुए थे ।

सन् 1744 से 1763 तक फ्रांस व इंग्लैण्ड के मध्य यूरोप, एशिया एवं अमेरिका का युद्ध होता रहा । भारत वर्ष में भी अंग्रेज एवं फ्रांसिसी कम्पनियों के बीच कर्नाटक युद्ध चलते रहे । कर्नाटक युद्ध के अन्तिम दौर में फ्रांसिसियों की सत्ता पूर्ण रूप से नष्ट हो गई । इस प्रकार सन् 1763 के पश्चात् भारत में अंग्रेजों के कोई भी यूरोपियन प्रति-द्वन्दी नहीं रहे ।

इसपर बंगाल में महत्वपूर्ण घटनाएँ हुईं । सन् 1756 में नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से कलकत्ता ले लिया । यूरोप से लौटने पर लार्ड क्लाइव (Lord Clive) ने सन् 1757 में प्रकट रूप में नवाब से संधि की और शुभ रूप से उनके (नवाब के) विरुद्ध घटपट में रत हो गये । नवाब सन् 1757 में प्लासी के युद्ध में पराजित हुए और सन् 1760 में यूरोप जाने से पूर्व लार्ड क्लाइव ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी को भारत के विशाल क्षेत्रीय शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया । इसके पश्चात् भी कम्पनी व नवाबों के बीच संघर्ष चलता रहा । लार्ड क्लाइव भारत में फिर तीसरी और अन्तिम बार सन् 1765 में भागे और उन्होंने एक नवीन एवं अविस्मरणीय नीति का प्रतिपादन किया ।

सन् 1765 में भारत के बादशाह की स्थिति बड़ी आवाहोल हो रही थी फिर भी उन्हें देश का शासक माना जाता था । क्लाइव

जिन्होंने सन् 1757 में बंगाल को शक्ति से प्राप्त किया था, 1765 में भारत के सम्राट से बंगाल प्रान्त के दीवानी अधिकार सम्बन्धी अनुज्ञापत्र प्राप्त कर लिया । इस प्रकार ईस्ट इन्डिया कम्पनी को बंगाल पर शासन करने का कानूनी अधिकार प्राप्त हो गया ।

सन् 1769 में ब्रिटिश अधिकारियों ने मद्रास में अधिकार स्थापित किया । सन् 1773 में ब्रिटिश संसद ने भारत में स्थिति सुधारने की दृष्टि से एक रेग्युलेटिंग एक्ट पारित किया । इस एक्ट के अनुसार कम्पनी के सभी अधिकृत क्षेत्रों की देश रेस का प्रशासनिक अधिकार मिल गया और उनकी समुचित व्यवस्था हेतु गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई । लार्ड वारेन हेस्टिंग्स जो उस समय बंगाल के गवर्नर थे, सन् 1774 में प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किये गये । लार्ड हेस्टिंग्स सुधार चाहते हुए भी अनेक कठिनाइयों के कारण ऐसा नहीं कर सके । कम्पनी के प्रशासन को इंग्लैण्ड की राज सत्ता के अन्तर्गत लाने के लिए पिट का इण्डिया एक्ट सन् 1784 में पास हुआ । सन् 1785 में वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैण्ड के लिए रवाना हो गए । उनके जाने के समय तक कम्पनी बंगाल, मद्रास, बनारस आदि क्षेत्रों पर सत्ता स्थापित कर चुकी थी ।

सन् 1784 के पिट्स एक्ट के अन्तर्गत कम्पनी के सभी नागरिक, सैनिक एवं राजस्व कार्यों की देश रेस ब्रिटिश शासन द्वारा नियुक्त कमिश्नरों के खरिये होने लगी । सन् 1793 में लार्ड कार्नवालिस ने बंगाल में स्थायी जमींदारी बन्दोबस्त का प्रबन्ध किया । 1793 में कम्पनी का अनुज्ञापत्र फिर से जारी किया गया । किन्तु इसमें व्यापार पर से कम्पनी के एकाधिकार की समाप्ति हो गई । 1805 तक बंगाल के अनिच्छित बनारस आदि क्षेत्रों पर भी यह कानून लागू कर दिये गये । मैसूर एवं मराठा राज्यों को हरा कर ये क्षेत्र भी कम्पनी ने अपने अधिकार में कर लिए ।

कम्पनी के आर्थिक व प्रशासनिक अधिकारों पर धीरे-धीरे ब्रिटिश सरकार ने नियंत्रण स्थापित करना प्रारम्भ कर दिया । सन् 1857 में

गदर (स्वतन्त्रता संग्राम) (Mutiny or war of Independence) के कारण कम्पनी का पतन हुआ । कम्पनी के विगत कार्यों से भारतीय राजा अपने भविष्य के प्रति सन्निकट हो गए । उनके विद्रोह को समाप्त करते समय ब्रिटिश सरकार ने कम्पनी को समाप्त करना भी उचित समझा ।

गदर के तुरन्त बाद इंग्लैंड के तरकाशील प्रधान मंत्री लार्ड पामस्टन ने कम्पनी के अध्यक्ष को ब्रिटिश सरकार के इस निर्णय की सूचना दी कि भारत सरकार के कार्यों की देखरेख सीधे ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत होगी । अगस्त 1858 में भारत में उत्तम शासन हेतु अधिनियम पारित किया गया । इस प्रकार सन् 1858 में कम्पनी के स्थान पर सीधा शासन ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया ।

सन् 1600 में ईस्ट इन्डिया कम्पनी भारत में विस्तृत व्यापारिक दृष्टिकोण लेकर धार्मिक धीरे-धीरे देश की प्रजासैनिक व्यवस्था को भी अपने हाथों में लेती गई । कम्पनी की इन गतिविधियों पर ब्रिटिश सरकार धीरे-धीरे नियंत्रण स्थापित करती गई । सन् 1857 के गदर के बाद ही ब्रिटिश सरकार ने अधिनियम पारित करके कम्पनी का कार्य समाप्त कर शासन अपने देखरेख में ले लिया । इन अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनी के अधिकार एवं कर्तव्य भारत सचिव को सौंप दिये गये । इस अधिनियम में 75 धाराएं थी जिनमें से अधिकांश ब्रिटिश शासन की समाप्ति तक चली रहीं ।

इस अधिनियम के अन्तर्गत 15 सदस्यों की एक परिषद् की सहायता से भारत सचिव द्वारा ईस्ट इन्डिया के प्रदत्त सभी क्षेत्रों का शासन चलाने की व्यवस्था थी । परिषद् के सदस्यों एवं भारत सचिव से संबंधित सभी व्यवसाय भारत के राजस्व में से जुड़ाए जाते थे । भारत के गवर्नर जनरल तथा महाराज और बार्बडो के गवर्नर की नियुक्ति का अधिकार इंग्लैंड की रानी को था । इन अधिनियम में भारत के हिंदू विरोधी अनेक बातें थी जिनकी जानकारी सामान्य जनता को नहीं थी ।



भारत में ब्रिटिश शासन (British Rule in India) — भारत में लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों का शासन रहा । भारत जैसे विशाल देश पर अंग्रेजों का अधिकार ब्रिटिश धार्मिक धर्म्युद्ध के लिए अत्यन्त लाभकारी सिद्ध हुआ । ब्रिटेन के अधिकार में सबसे बड़ा उपनिवेश या जिसका क्षेत्रफल इंग्लैंड से बीस गुना व यूरोप के सभी बड़े देश भारत की ओर भाँटा लगाए रहे और जिस द्वारा भारत विश्व ही यूरोप में पूँजीवाद के विकास में महत्वपूर्ण ब गिना हुई । भारत उपनिवेश ने ही ब्रिटेन को विश्व की सर्वोच्च स बलने में मदद की । स्वयं माट्टे बर्जन् ने 1898 में यह स्वीकार कि यदि हम भारत को छोड़ दें तो हमारे शासन का धूर्य अस्त हो जाएगा इस प्रकार भारत पर ब्रिटिश शासन घेठ ब्रिटेन के हितों के प्रब एवं प्रवर्द्धन में सहायक हुआ ।

भारतीय अर्थ व्यवस्था पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव — दो शताब्दियों तक तकनीकी एवं औद्योगिक दृष्टि से उन्नत ग्रेट ब्रिटेन शासन भारत बर्षों पर कायम रहा उनका अधिक प्रभाव क्या रहा इसका एक मात्र उत्तर है — भारत की धार्मिक स्थिति में गिरा भाई । अमेज बिद्वान बेरा एन्स्टे ने यह स्पष्ट रूप से कहा है : जन-जीवन की समृद्धि पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव निस्तदेह अत्य निराशाजनक रहा । इसी प्रकार से अमेरिकन विद्वान् प्रोफेसर । एवं. कुपनान ने कहा भारतीय औद्योगीकरण पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव अत्यन्त निराशाजनक रहा ।

इस प्रकार यह एक सर्व विदित तथ्य है कि भारतीय अर्थ व्यवस्था पर ब्रिटिश शासन का अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । भारत पर परम्परागत गौरव ब्रिटिश शासन काल में कम होता गया । यहाँ ही विभिन्न धार्मिक क्षेत्रों पर पड़े प्रभावों का ब्योरेवार अध्ययन करेंगे-

(1) सम्पन्नता के मध्य गरीबी का प्राबुध्वि — भारत एक गरीब देश है किन्तु अब उसमें निर्धन लोग निवास कर

है। यह विरोधामास ब्रिटिश शासन की ही देन है। कम्पनी के

आगमन से पहले भारत के औद्योगिक विकास का स्तर बहुत ऊँचा था। यहाँ प्राकृतिक साधनों की भी कमी नहीं थी किन्तु ब्रिटिश शासन के कारण भारतीय जनता का जीवन स्तर नीचा हो गया।

17 वीं सदी में जहाँ भारतीय गाँवों में चावल, घाटा, मक्खन, दूध, फल, चीनी, मिठाईयाँ आदि प्रचुर मात्रा में प्रयोग किये जाते थे वहाँ ब्रिटिश शासन की सवधि में द्वितीय महा-युद्ध के समय भारत की 60 प्रतिशत जनसंख्या की आय रुक आना

ब्रिटिश शासन का प्रभाव  
सम्पन्नता के मध्य गरीबी  
का प्रादुर्भाव

2. भारत से धन का प्रवाह
3. भारत पर श्रृंखला
4. निमित्त पदार्थों के निर्यात में कमी
5. आयात में वृद्धि
6. भारतीय उद्योगों का विनाश
7. जमींदारी प्रथा का उदय
8. आर्थिक शोषण व मत्वाचार
9. कृषि पर जनमार में वृद्धि
10. अन्य प्रभाव

प्रति व्यक्ति प्रतिदिन थी। इससे स्पष्ट है कि आर्थिक विकास के सभी साधनों के विद्यमान होते हुए भी अंग्रेजों की स्वार्थपरता के कारण भारतवासी निर्धन हो गए।

2. भारत से धन का प्रवाह—ईस्ट इण्डिया कम्पनी भारत में व्यापार की दृष्टि से आविर्भूत हुई। बदलती हुई परिस्थितियों के कारण कुटिल अंग्रेजों ने देश के अनेक भागों का शासन टेबलनियर के याता संस्मरणों पर आधारित प्रबन्ध भी अपने हाथों में ले लिया। शासन हथियाने के बाद कम्पनी नाम मात्र की बीमर पर अस्तुर्त शरीर कर भारत से बाहर भेजती थी। इस प्रकार अंग्रेजों ने भारतीय पदार्थों की बहुत कम कीमत देकर भारतीय किसानों और व्यापारियों को सूटा और उस धन को भारत के बाहर ले गए।

त पर श्रृण

इण्डिया कम्पनी के भारत में स्थापित होने से पूर्व भारत पर कोई श्रृण नहीं था किन्तु सामन व्यवस्था एवं कम्पनी के भारत पर श्रृण होता गया और भारत को लगभग 7 करोड़ राशि केवल कम्पनी के कारण चुकानी पड़ी। इस प्रकार इण्डिया कम्पनी ने भारत का आर्थिक शोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

निर्मित पदार्थों के निर्यात में कमी—

1760 के पश्चात् इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति का सूत्रपात हुआ। इस क्रान्ति के परिणामस्वरूप इंग्लैण्ड को ऐसे बाजारों की आवश्यकता पड़ी जो वहाँ के बने हुए माल को खपा सके। अंग्रेजों ने भारत को इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त पाया। जहाँ भारतवर्ष निर्मित माल का भारी मात्रा में निर्यात करता था। वहाँ ब्रिटिश शासन में निर्मित पदार्थों का आयातकर्ता देश बन गया। ब्रिटेन के नए उद्योग-पेशेवरों ने भारत के शोषण की अधिक व्यवस्थित योजना बनाकर भारत के निर्मित पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा दिया। जहाँ भारत कमी के मूल्य वस्त्र, हाथीदाँत व लकड़ी की उत्कृष्ट वस्तुएँ, आदि निर्यात करता था ब्रिटिश शासन काल में कच्चा माल, जैसे खालें, छूट, बपास आदि वस्तुओं को निर्यात करने वाला देश बन गया। भारत से कच्चा माल मंगाकर अपने देश में औद्योगीकरण को बढ़ा देने की ब्रिटिश बुद्धिमत् नीति ने हमारे उद्योगों को गहरा बाधा पहुँचाया।

उद्योग में वृद्धि—

औद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप इंग्लैण्ड ने भारत को अपने बाजार के रूप में प्रतिष्ठित करने की दृष्टि से भारतीय उद्योगों के निर्माण वस्तुओं पर अनेक प्रतिवन्ध लगाए। इससे अंग्रेजों ने अपने देश की भारत में वेश्मने के लिए अनेक बहाने उठाए। इस प्रकार भारत को एक प्रमुख निर्यातकर्ता देश या ब्रिटिश नीति के कारण एक उद्योग देश बन गया।

## (6) उद्योगों का विनाश—

धोद्योगिक क्रान्ति के सूत्रपात के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। ब्रिटिश उद्योगपतियों ने भारत के आर्थिक शोषण की एक सुव्यवस्थित योजना बना कर भारत को अपना बाजार बना दिया। 19 वीं सदी के पूर्वार्द्ध में भारतीय उद्योगों के साथ भेदभाव का व्यवहार किया गया। इस नीति के अनुसार इंग्लैण्ड के पदार्थ तो भारत में बिना किसी रोक टोक के आ सकते थे किन्तु भारतीय वस्तुएं इंग्लैण्ड नहीं जा सकती थीं। इस प्रकार भारत एवं अन्य देशों के बीच भी नौ-वहन कानून के अंतर्गत व्यापार का निषेध कर दिया गया। इस प्रकार ब्रिटिश टैरिफ नीति भारतीय उद्योगों के लिए घातक एवं ब्रिटिश उद्योगों के लिए हितकारी सिद्ध हुई। उद्योगों के पतन के कारण ढाका, मुग़िदाबाद आदि धोद्योगिक नगरों का भी पतन हुआ और कारीगरों की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। ब्रिटिश नीति के कारण भारतीय उद्योगों के पतन का अध्ययन इसी अध्याय में आये किया जाएगा।

## (7) जमींदारी प्रथा का उदय—

ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगान वसूली की एक नवीन पद्धति को जन्म दिया। सन् 1793 में लार्ड कार्नवालेस ने बंगाल में प्रयोग के तौर पर स्थायी भूमि बन्दोबस्त की प्रथा लागू की। कार्नवालेस ने इस व्यवस्था के अन्तर्गत जमींदारों को कानूनी तौर पर भूमि का स्थायी मान लिया। किसानों पर यह जमींदार वर्ग शासन करने लगा और अनुवस्थित भूस्वामी (Absentee landlord) के रूप में प्रकट हुआ। जैसा हम आगे चलकर पढ़ेंगे। यह वर्ग (जमींदार) किसानों का शोषण करने लगा और भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का विरोध करने वाला बना। अंग्रेजों की यह पद्धति भी भारत के लिए लगभग पीने की सी थोड़ी तक सिर दर्द बनी रही।

8. आर्थिक शोषण (Economic exploitation) व सत्ताचार—  
जब सन् 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व प्रशासन का अधिकार

शोषण का नवीन द्वार खुल गया। इस मृष्वी पर ईस्ट इंडिया  
शासन (सन् 1765 से 1784 तक) के समान कोई भी घटु  
अथ तक नहीं देखी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के  
अन्तरत्न लगान वृद्धि, निचाई के साधनों तथा सार्वजनिक निर्माण  
उपेक्षा, आदि कारणों से जनता परेशान हो गई। सन् 1770  
के भयंकर भूकाल में लाखों मौत के गिराव हुए। ऐसे समय  
कंपनी ने लगान समूची में हृदयहीनता दिखाई। बीस वर्ष के  
शासन में अन्न, धन और धर्म का भण्डार भारत में प्रायः  
कर रह गया। ब्रिटिश शासन काल की सभी नीतियाँ भारत  
के शोषण की रहीं। अंग्रेजों ने भारतीय हितों की सदैव उपेक्षा  
ब्रिटिश सरकार ने अनेक अवसरों पर भारतीय जनता का दमन  
और अत्याचार किये। हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास इन  
से भरा पड़ा है।

9. कृषि पर जन भार में वृद्धि—ब्रिटिश सरकार की नीति के  
भारतीय उद्योग धन्धों का हास हुआ। परिणामस्वरूप इनमें  
नरींगर व अमिक बेकार हो गये। करोड़ों कलाकार, दस्तकार,  
कुम्हार, लोहार आदि शहरी एवं गाँवों में रोजगार के साधनों  
में बड़ी दयनीय स्थिति में थे। इन सबका भार कृषि पर पड़ा  
पहले से ही अधिक जन भार वाली कृषि पर इनका और बोझ आ  
भारतीय ग्रामीण अर्थ व्यवस्था पर एक और दूरगामी प्रभाव  
भारत में जो पहले कृषि व उद्योग धन्धों वाली अर्थ व्यवस्था थी  
ब्रिटिश औद्योगिक पूँजीवाद का एक कृषि उपनिवेश मात्र बनकर  
गयी।

10. अन्य प्रभाव—ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणाम भारत के  
प्रतिकूल ही रहे। यद्यपि महायुद्धों की अवधि में भारत में उद्योग  
की स्थापना के कुछ सरकारी प्रयत्न हुये किन्तु भारत की  
स्वतंत्रता प्राप्ति तक कोई महत्वपूर्ण परिणाम नहीं निकला। अंग्रेजों के  
काल में भारत के नील, चाय, कच्चा व रबर के बागानों पर

विदेशियों का अधिकार स्थापित हो गया। इन उद्योगों में भी भारतीय श्रमिकों का बहुत शोषण किया गया। ब्रिटिश शासन का एक मुख्य परिणाम कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक क्रांति (Social Revolution) के रूप में हुआ। अंग्रेजों के शासन काल में देश का एकीकरण होकर एक मूल में शासन व्यवस्था स्थापित हो गई। ब्रिटिश शासन के अन्तिम 50 वर्षों में रेलें, सड़कें और सिंचाई के साधनों का विस्तार हुआ जिससे भारत में आर्थिक संक्रांति (Economic transition) का मूलपाठ हुआ।

संक्षेप में हम यह सकते हैं कि अंग्रेजों का शासन भारतीय अर्थ-व्यवस्था को प्रायः नष्ट करने में सफल हुआ। ब्रिटिश सरकार ने भारत के आर्थिक विकास के लिए कोई रचनात्मक कदम नहीं उठाया। यही कारण है भारतीय अर्थ व्यवस्था अब भी भंडे विकसित अवस्था में है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना आर्थिक विकास संभव नहीं है।

भारत में आर्थिक संक्रांति (Economic transition in India) —

भारत में ब्रिटिश शासन काल में 18 वीं तथा 19 वीं शताब्दी में जो आर्थिक परिवर्तन हुए उन्हें हम आर्थिक संक्रांति के नाम से पुकारते हैं। इस अवधि में गाँवों एवं नगरों के आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इंग्लैण्ड की औद्योगिक क्रांति, शासन की नीतियों एवं अन्य बातों का आर्थिक जीवन पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए।

आर्थिक संक्रान्ति की पृष्ठभूमि तथा कारण (Back ground & causes)

इसी अध्याय के प्रारम्भ में हम अर्थ व्यवस्था की उन विशेषताओं का अध्ययन कर चुके हैं जो आर्थिक संक्रान्ति से पूर्व (ब्रिटिश शासन से पूर्व) भारत में विद्यमान थी। इन विशेषताओं से संक्रान्ति की पूर्ण चोटिका की जानकारी मिल जाती है।

आर्थिक संक्रान्ति के मुख्य कारण निम्नांकित थे—

(1) ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन तथा ब्रिटिश शासन की स्थापना—

आर्थिक संक्रान्ति के मुख्य कारण —

1. ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन व ब्रिटिश शासन की स्थापना
2. इंग्लैण्ड की औद्योगिक क्रांति
3. उद्योगों व व्यापार में वृद्धि
4. परिवहन के साधनों का विकास
5. पश्चिमी विचारधारा का आगमन

औरंगजेब के समय से मुगल शासन का पतन प्रारम्भ हो गया। अंग्रेजों ने भारत में अपने हितों की रक्षा की। परिणामस्वरूप भारतीय आर्थिक व्यवस्था में गिरावट आती गई। इस प्रकार ब्रिटिश शासन का प्रभाव भारत की आर्थिक संक्रान्ति पर पर्याप्त मात्रा में हुआ।

(2) इंग्लैण्ड की औद्योगिक क्रांति (Industrial Revolution) — अठारहवीं शताब्दी में इंग्लैण्ड में महत्वपूर्ण औद्योगिक परिवर्तन हुए। ब्रिटिश उद्योगों में मशीनों एवं आविष्कारों का प्रयोग किया गया। इस औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप इंग्लैण्ड में बनने वाले पदार्थों की बिक्री के लिए विस्तृत वाजारों की आवश्यकता हुई। भारत भी औद्योगिक क्रांति के प्रभावों से अछूता नहीं रह गया और आर्थिक संक्रान्ति हुई।



3. उद्योगों व व्यापार की दिशाओं में परिवर्तन—भारत में चाय, रबर, नील व कच्चा बागान, जूट आदि नये उद्योगों का विकास तथा इंग्लैंड से बढ़ते हुए व्यापारिक सम्बन्धों ने भारतीय अर्थ व्यवस्था का नई दिशा दी। इनका प्रभाव आर्थिक संक्रान्ति पर हुआ।

4. परिवहन का विकास—ब्रिटिश शासकों ने राजनीतिक दृष्टि से यातायात के साधनों का विकास किया। ब्रिटिश जहाजी बेड़ों ने भारतीय समुद्री व्यापार में महत्वपूर्ण योग दिया। इन साधनों ने भारतीय अर्थ व्यवस्था में परिवर्तनों को बढ़ावा दिया।

5. पश्चात्य (Western) विचारधारा—भारत में आर्थिक शान्ति लाने का मुख्य श्रेय ब्रिटिश शासकों को है जिन्होंने पश्चिमी देशों की सम्यता, रहन-सहन एवं सामाजिक व्यवस्था से भारत का परिचय करवाया। आज भी भारतीय जीवन पर पश्चात्य विचारधारा का व्यापक प्रभाव दिखाई देता है।

संक्षेप में, ब्रिटिश शासन व्यवस्था और उनकी आर्थिक नीतियों ने ही भारत में आर्थिक संक्रान्ति का सूत्रपात किया।

#### आर्थिक संक्रान्ति के परिणाम

आर्थिक संक्रान्ति से भारत के आर्थिक जीवन पर अनेक प्रभाव पड़े। यहाँ हम उन प्रभावों (Effects) का अध्ययन करेंगे।

1. आर्थिक संक्रान्ति द्वारा गाँवों तथा कृषि के क्षेत्रों में परिवर्तन—प्राचीन भारतीय संगठन की भूल इकाई ग्राम व्यवस्था में परिवर्तन होने लगी। गाँवों के पृथक्कीकरण एवं स्वावलम्बन की स्थिति समाप्त होने लगी। प्राचीन जीवन में नवीन वस्तुओं की आवश्यकताओं का समावेश होने लगा।

#### आर्थिक संक्रान्ति के प्रभाव

1. गाँवों व कृषि पर
2. उद्योगों पर
3. दुमिक्षों पर
4. बैंकिंग पर
5. शहरीकरण
6. नये वर्ग सम्बन्ध
7. अन्य



गाँवों में बाहर से बस्तुएँ आने लगी और गाँव दूगरे स्थानों को पदार्थ भेजने लगे ।

आर्थिक संक्रान्ति के परिणाम स्वरूप कृषि की उन्नति के निमित्त और विस्तृत बाजार खुल गये । बाजारों के विस्तार के साथ धानुओं के मूल्य में समानता आने लगी । गाँवों में धीरे-धीरे विविधता के स्थान पर मुद्रा का प्रचलन होना लगा । गाँवों में समुक्त परिवार प्रथा के स्थान पर व्यक्तिवादी भावना का विस्तार हुआ ।

कृषि के क्षेत्र में आर्थिक संक्रान्ति के परिणाम स्वरूप बहुतायत में वृद्धि हुई । परम्परागत कृषि के स्थान पर कृषि का व्यापारी (Commercialisation) हुआ । परिवहन व संचार के माध्यमों द्वारा, स्वयं नहर के खुल जाने से तथा विदेशों में हमारे कृषि पदार्थों की माँग ने कृषि को व्यापारिक ढंग से प्रतिष्ठित करने में सहायता दी ।

हमारे उद्योग धर्मों के नष्ट हो जाने के कारण कृषि पर जनता का भार बढ़ गया । कृषि पदार्थों के मूल्य कम होने और उद्योगों समाप्ति के कारण उत्पन्न बेरोजगारी ने कृषकों पर अल्प भार में कर दी ।

1. इस प्रकार आर्थिक संक्रान्ति के गाँवों में स्वावलम्बी इलाक़ों की समाप्ति कर कृषि पर जन-भार में वृद्धि कर दी ।

2. आर्थिक संक्रान्ति द्वारा उद्योगों पर प्रभाव—इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति, भारत में ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीति भारत के विदेशी व्यापार एवं नी-बहुल पर घातक प्रतिबन्ध लगाते भारतीय उद्योग धर्मों का पतन हुआ । भारतीय औद्योगिक धर्मों को इंग्लैण्ड में बने पदार्थों की भारी स्पर्धा का सामना करना पड़ा । विदेशी सरकार की नीति के परिणाम स्वरूप हमारे देश में विदेशी पूँजी ( Foreign Capital ) तथा साहस का आगमन हुआ । चाय, नील, कपास व रबर के बागानों आदि व्यवसायों में इन्होंने अंग्रेज व अन्य देशों के उद्योगपतियों ने अपना अधिकार समाप्त

निम्न। इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति के स्वरूप भारी मशीनों का आविष्कार हुआ। भारत में भी भारी मशीनों एवं नवीन तकनीक के आगार पर कुछ नये उद्योगों की स्थापना हुई। समुद्र के पास स्थित होने से मद्रास, कलकत्ता एवं बम्बई बड़े व्यापारिक एवं औद्योगिक केन्द्र बन गये। बड़े नगरों में औद्योगीकरण के कारण अनेक समस्याएँ भी उत्पन्न हो गईं।

इस प्रकार औद्योगिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और हमारे शरीरों को मजबूर होकर कृषि पर आश्रित होना पड़ा।

3. आर्थिक संक्रांति का दुर्भिक्षों (Famines) पर प्रभाव— गाँवों के पृथक्कीकरण के कारण जहाँ पहले अनालों को दूर करने में प्रयत्न नहीं किये जा सकते थे वहाँ यातायात के साधनों के विकास एवं कृषि के व्यापारीकरण के पश्चात् अनालों की प्रधानता भी दूर कर पाना सम्भव हो गया। आर्थिक संक्रान्ति के बाद लोगों के पास रहने से अधिक क्रय शक्ति (Purchasing power) भी और विस्तृत बाजार से जहाँ से यातायात के शीघ्र साधनों द्वारा इस्तेमाल से वे साठान्न पहुँचाये जा सकते थे।

4. बैंकिंग पर प्रभाव—विदेशी व्यापार एवं पूंजी के कारण देश में बैंकों व अन्य साख्त संस्थाओं का विकास हुआ। बड़े पैमाने पर उद्योगों का विकास होने के कारण अधिकाधिक बैंकिंग व्यवस्था का विकास हुआ।

5. जब शहरों में बड़े उद्योगों की स्थापना हो गई तो गाँवों से वे बेकार शरीरों शहरों की ओर आने लगे। इस प्रकार शहरों और गाँवों में रहने वालों के मध्य एक नये प्रकार के सम्बन्धों का उदय हुआ।

6. नये वर्ग सम्बन्धों का उदय—आर्थिक संक्रांति के परिणाम-स्वरूप परम्परागत सम्बन्धों के स्थान पर नये वर्गों का उदय हुआ। कृषक, उद्योगपति, श्रमिक व प्रशासकों के नये वर्गों का उदय हुआ और इनके सम्बन्धों में नया मोड़ आया।

7. अन्य प्रभाव—इन सबके अलावा आर्थिक संक्रान्ति ने हमारे सदियों से चली आ रही परिवर्तनशील सामाजिक व्यवस्था को भी प्रभावित किया। प्रतिष्ठा और रीति-रिवाज के स्थान पर सामेदारी एवं प्रतिस्पर्धा के सिद्धान्तों के आधार पर समाज व अर्थ व्यवस्था की रचना प्रारम्भ हुई।

उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि आर्थिक संक्रान्ति से कुछ अच्छे एवं अधिकतर बुरे प्रभाव हमारी अर्थ व्यवस्था पर पड़े। भारत जहाँ कृषि एवं उद्योग वाला देश था वह ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत आर्थिक संक्रान्ति के कारण केवल कृषि प्रधान देश बन कर रह गया।

### सारांश

प्राचीन भारत अत्यन्त गौरवशाली था, किन्तु धीरे-धीरे उसकी यह गौरव की परम्परा समाप्त हो गई। इस विघटन का मूल कारण ब्रिटिश शासन की घातक नीति थी।

ब्रिटिश पूर्ण अर्थ में भारतीय अर्थ व्यवस्था की विरोधताएँ

(1) स्वावलम्बी ग्राम इकाइयाँ (2) कृषि (3) उद्योग व हस्त-शिल्प (4) नगर (5) व्यापार, यातायात एवं सदेश वाहन तथा (6) सामाजिक व्यवस्था।

ब्रिटिश शासन की स्थापना

1600 ई० ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना की स्वीकृति दी। सन् 1700 में बंगाल में अपना मुख्य स्थान उभरने बलकत्ता में स्थापित किया। 1773 में ब्रिटिश संसद ने रेग्युलेशन एक्ट पास किया। सन् 1784 में पिट का इण्डिया ऐक्ट पास किया।

सन् 1857 के गदर के कारण इस कम्पनी का अन्त हुआ तथा ब्रिटिश सरकार ने शासन अपने हाथ में ले लिया। भारत में लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों का शासन रहा।

### ब्रिटिश शासन का प्रभाव—

(1) सम्पन्नता के मध्य परीबी का प्रादुर्भाव (2) भारत से धन का प्रवाह (3) भारत पर ऋण (4) निमित्त पदार्थों के निर्यात में कमी (5) आयात में वृद्धि (6) भारतीय उद्योगों का विनाश (7) अमीदारी प्रथा का उदय (8) धार्मिक शोषण व अत्याचार (9) कृषि पर जनभार में वृद्धि तथा (10) अन्य प्रभाव

### आर्थिक संक्रान्ति के कारण

(1) ईस्ट इण्डिया कम्पनी का आगमन व ब्रिटिश शासन की स्थापना (2) इंग्लैण्ड की औद्योगिक क्रान्ति (3) उद्योगों व व्यापार में वृद्धि (4) परिवहन के साधनों का विकास तथा (5) पारचात्य विचारधारा ।

### आर्थिक संक्रान्ति के प्रभाव—

(1) गाँवों व कृषि पर (2) उद्योगों पर (3) दुर्मित्तों पर (4) बेकिंग पर (5) शहरीकरण (6) नये वर्ग सम्बन्ध व (7) अन्य ।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आर्थिक विकास के लिए राजनीतिक स्वतन्त्रता आवश्यक है ।

### प्रश्न

1. ब्रिटिश पूर्व भारतीय अर्थ व्यवस्था की कोन-कोन सी विशेषताएँ थीं?
2. ईस्ट इण्डिया कम्पनी के बारे में आप क्या जानते हैं ? भारतीय अर्थ व्यवस्था पर ब्रिटिश शासन का क्या प्रभाव पड़ा ?
3. आर्थिक संक्रान्ति किसे कहते हैं ? इसके क्या कारण थे ? इसका क्या प्रभाव हुआ ?
4. आर्थिक संक्रान्ति पर एक निबन्ध लिखिये ।

## अध्याय 2

### भारतीय कृषि

#### (INDIAN AGRICULTURE)

“जब खेती फलती-फूलती है, तब सब धन्ये पनपते हैं, परन्तु जब भूमि को बन्जर छोड़ दिया जाता है, तो धन्ये भी नष्ट हो जाते हैं।”

—गुरुराज

“भारत में दलित जातियाँ हैं और उन्हीं के समान हमारे दलित उद्योग भी हैं, दुर्भाग्य से कृषि भी उन्हीं में से एक है।”

—डॉ. बलाउसर्जन

भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के निवासियों का सदियों से कृषि ही मुख्य व्यवसाय रहा है। कहा गया है कि कृषि हमारी संस्कृति का आधार है (Agriculture is the basis of our culture)। यह विश्व का प्राचीनतम व्यवसाय है। औद्योगिक क्रान्ति के पश्चात् ब्रिटन, फ्रांस, अमरीका, जर्मनी आदि देश विज्ञान एवम् उद्योगों के क्षेत्र में बहुत विकसित हो गए जबकि कुछ देश कृषि प्रधान हो बने रहे। भारत में कृषि व्यवसाय का ही प्रभुत्व है। कृषि हमारी जीवन प्रणाली (way of life) है। कृषि विकास के लिए स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् अनेक कार्यक्रम अपनाये गए। यह सर्वमान्य तथ्य है कि कृषि की उन्नति के बिना भारतीय अर्थ व्यवस्था की उन्नति संभव है।

भारतीय अर्थ व्यवस्था में कृषि का महत्व

#### (Importance of Agriculture in Indian Economy)

भारतीय अर्थ व्यवस्था में कृषि का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। कहावत है कि “उत्तम भेरी, मध्यम बान, निम्नट चाकरी, भीत निदान।” इस कहावत से भारतीय जीवन में कृषि की उपयोगिता प्रतिभक्षित



होती है। भारतीय अर्थ-व्यवस्था में कृषि का महत्व निम्नांकित तथ्यों से स्पष्ट हो जायेगा।

1. जीविकोपार्जन (Livelihood) का मुख्य साधन—सन् 1961 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की 69.8 प्रतिशत जनसंख्या मुख्यतः कृषि पर आश्रित है। कृषि भारतवासियों का मुख्य व्यवसाय है और इसीलिए भारत को "कृषि प्रधान देश" कहा जाता है।

2. राष्ट्रीय आय (National Income) में महत्वपूर्ण योग—देश की वार्षिक कुल आय का लगभग आधा भाग कृषि से प्राप्त होता है। सन् 1967-68 में कृषि से 14,973 करोड़ रुपये प्राप्त हुए जो कुल राष्ट्रीय आय का 53.1 प्रतिशत है। \* राष्ट्रीय आय में कृषि का योग सन् 1950-51 में 51.3 प्रतिशत, सन् 1955-56 में 45.3 प्रतिशत, सन् 1960-61 में 48.7 तथा सन् 1966-67 में 49.2 प्रतिशत रहा। विश्व में ऐसा कोई अन्य राष्ट्र नहीं है, जिसमें कृषि से इतने बड़े प्रतिशत तक देश की आय को प्रभावित किया हो।

3. सरकार की आय—राज्य सरकारों की भूमि के लगान (Land Revenue), कृषि आयकर (Agricultural Income Tax) स्टाम्प तथा पंजीयन (Stamp and Registration) शुल्क के रूप में बहुत-सी आमदनी कृषि से प्राप्त होती है। रेलों को भी कृषि पदार्थों के ढोने से आय प्राप्त होती है। इस प्रकार हमारे देश की सरकारों का बजट कृषि पर निर्भर है।

4. बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्य—कृषि के द्वारा ही भारत के करोड़ों लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध होती है। पिछले कुछ वर्षों में कृषि हमें आवश्यक भोजन सामग्री प्रदान करने में असमर्थ रही है। यदि हम चाहते हैं कि विदेशों से खाद्यान्न न मंगाने पड़े तो हमें कृषि की उन्नति करनी होगी। सन् 1967-68 में 14.14 करोड़

हेक्टर भूमि पर सादाग्न कोए नये दिन पर 955 मान टन माद्यान  
बैदा हुए ।\*

5. असंतुलित अर्थ-व्यवस्था (Unbalanced Economy) में  
कृषि का महत्व—हमारे देश की अर्थ व्यवस्था बहुत असंतुलित है ।  
हमारी जनसंख्या का लगभग 69.8 प्रतिशत भाग कृषि पर निर्भर है ।

भारतवर्ष में कृषि का महत्व

1. जीविकोपार्जन का मुख्य साधन
2. राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योग
3. सरकार की आय
4. जनसंख्या के लिये भोजन
5. असंतुलित व्यवस्था में कृषि का महत्व
6. उद्योगों के लिए कच्चा माल
7. अन्तर्राष्ट्रीय महत्व
8. निर्यात में महत्व
9. सामाजिक व राजनैतिक महत्व

देशी पर आर्थिक निर्भरता हमारे देश की बहुत बड़ी कमजोरी है । यदि कृषि में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो जाए तो देश पर आर्थिक संकट आ सकता है । अतः कृषि का हमारी अर्थ-व्यवस्था के लिए बहुत महत्व है ।

6. उद्योगों के लिए कच्चा माल (Raw materials)—कृषि हमें केवल भोज्य पदार्थ ही नहीं प्रदान करती बरन् हमारे उद्योगों के लिए कच्चा माल भी जुटाती है । कपास सूती वस्त्रोद्योग के लिए, पटसन लूट उद्योग के लिए, गन्ना चीनी उद्योग के लिए, तिलहन तेल उद्योग के लिये, तथा रबर आदि

कृषि जन्य वस्तुएं अन्य उद्योगों के आधार का काम करती हैं । भारत में औद्योगिक आवश्यकता की वस्तुओं के उत्पादन में कृषि की जा रही है ।

7. अन्तर्राष्ट्रीय महत्व (International Importance)—बड़े कृषि पदार्थों के उत्पादन में भारत का विश्व में बहुत महत्वपूर्ण स्थान

है। भारत चाय, मूंगफली और गन्ने के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है और लाख के उत्पादन में लगभग एकाधिकार (monopoly) है। चावल, जूट आदि के उत्पादन में भारत सप्ताह का दूसरे नम्बर का देश है। कपास, तिलहन, तम्बाकू व एण्डोली के उत्पादन में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है।

8. निर्यात (exports) में महत्व—भारत से निर्यात होने वाले पदार्थों में कृषि पदार्थों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे यहाँ से जूट, तिलहन, चाय, तम्बाकू, कढ़वा आदि पदार्थ बाहरी देशों को भेजे जाते हैं जिनसे हमें विदेशी मुद्रा मिलती है। यह हमारी पंचवर्षीय योजनाओं की सफल बनाने में सहायक है। सन् 1967-68 में चाय, कॉफी, कपास तम्बाकू, फल आदि कृषि-जन्य पदार्थों का निर्यात लगभग 293 करोड़ रुपये के मूल्य का हुआ।\*

9. कृषि का सामाजिक व राजनीतिक महत्व (Social and political importance)—कृषि व्यवसाय सुखी हुआ में किया जाता है इसलिए कृषक आत्मसंतोषी होते हैं। इससे हमें सैनिकों की प्राप्ति होती है जो देश की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक हैं। साथ ही कृषकों के विचार, उनका पक्ष आदि देश की सामाजिक व राजनीतिक स्थिरता पर विशेष प्रभाव डालते हैं।

इस प्रकार हम कहते हैं कि कृषि भारत का प्राण है, किन्तु वर्तमान समय में कृषि के पिछड़ेपन के कारण यह भलाभादायक व्यवसाय बन गया है।

### भारतीय कृषि का पिछड़ापन (Backwardness of Indian Agriculture)

कहा जाता है कि “भारतवर्ष में पिछड़े हुए वर्ग है और पिछड़े हुए उद्योग भी, दुर्भाग्यवश कृषि भी इनमें से एक है।” इससे यह स्पष्ट है कि अन्य देशों की तुलना में भारतीय कृषि पिछड़ी हुई है। “भारत एक सम्पन्न देश है जिसमें निर्धन जनता निवास करती है” (India is a



rich country inhabited by poor people) वाली कहावत भी यह स्पष्ट करती है कि भारत की भूमि उपजाऊ और जलवायु कृषि के अनुकूल है फिर भी कृषि उद्योग की स्थिति अच्छी नहीं है।

डॉ. वेस्ट्रो के अनुसार "विश्व की दो-तिहाई जनसंख्या स्वाधीन रूप से भूखी रहती है और उसकी एक-तिहाई जनसंख्या भारत में रहती है, जिसमें से 30 प्रतिशत जनसंख्या तो भूखे स्तर (Starvation level) पर ही रहती है।" इससे भी स्पष्ट होता है कि देश में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध नहीं है। हमारा देश कृषि प्रधान होते हुए भी हमे विदेशों से अनाज एवम् अन्य कृषि पदार्थ मंगाने पड़ते हैं।

कृषि के विद्येपन की जानकारी के लिए हमारे देश की प्रति एकड़ उपज की तुलना अन्य देशों से की जानी चाहिए। गेहूँ के क्षेत्र में भारत की तुलना में अमेरिका और कनाडा में दुगुना तथा मिथ में तिगुना उत्पादन होता है। भारतीय चावल की प्रति एकड़ पैदावार की तुलना में मिथ चीगुना, जापान और अमेरिका तिगुना तथा चीन दुगुना उत्पादन करता है। मिथ हमसे लगभग सात गुना केपास प्रति एकड़ पैदा करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में प्रति एकड़ उत्पादन विश्व के अनेक देशों की तुलना में बहुत कम है। यहाँ हम कृषि के विद्येपन के कारणों पर प्रकाश डालेंगे।

कृषि के विद्येपन के कारण—हमारे देश में कृषि की विद्यही दशा के मुख्य कारण ये हैं—

1. जनसंख्या का भूमि पर अत्यधिक भार (Excessive pressure of population on land) - देश की 69.8 प्रतिशत जनसंख्या कृषि में लगी हुई है, जिसमें क्षेत्र छोटे-छोटे हो गये हैं और आप कम प्राप्त होती है। लोगों की कई प्रकार की उपज हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाती। जैसा कि हम ऊपर बताया चुके हैं, हमारे देश में प्रति एकड़ उपज भी कम है। भारतीय कृषि की विद्यही दशा के मुख्य कारण प्राकृतिक तथा मानवीय हैं।

2. कृषि का वर्षा पर निर्भर होना (Dependence on Monsoon)—हमारी कृषि वर्षा पर निर्भर है। वर्षा अनिश्चित, कम

तथा असमान होती है। अतः अनावृष्टि और अतिवृष्टि दोनों से प्रकाल पड़ जाते हैं और कृषि को हानि पहुँचती है। प्रकाल तो भारतीय ग्राम्य प्रबंध व्यवस्था के एक घंटा घन गये हैं। हमारे देश में अभी तक सिंचाई के साधनों की प्रगति आवश्यकता को देखते हुए बहुत ही कम है और कृषि योग्य क्षेत्र में से केवल पाँचवें भाग में ही कृत्रिम साधनों द्वारा सिंचाई होती है। भारतीय कृषि वर्षा में एक जुआ है (Indian agriculture is a gamble in rains)। वर्षा अनिश्चित है। कभी अतिवृष्टि हो जाती है तो कभी अनावृष्टि। टिड्डियों का भी प्रकोप रहता है तथा जानवरों द्वारा फसलों को काफी हानि पहुँचती है। पेड़ों को रोग लग जाते हैं। बहुधा कीड़ों और बीमारी से फसलें खराब हो जाती हैं। इन प्राकृतिक प्रकोपों से कृषि उत्पाति कम हो जाती है। सरकार सिंचाई के साधनों का प्रबन्ध कर प्राकृतिक कारकों पर अधिकार पाने में सफल है।

3. क्षेत्रों का अत्यधिक बिखरा (fragmented) और छोटा होना - क्षेत्रों का अत्यधिक छोटे छोटे बिखरे होने के कारण क्षेत्रों की उपज की हानि होती है। क्षेत्रों के अत्यधिक छोटे होने से बुँदा खुदवाने, बाड़ (fence) लगाने और आधुनिक यन्त्रों के प्रयोग पर धन खर्च करना अनाधिक (uneconomical) हो जाता है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की सीमाएँ और सामान से जाने से भी ध्वंस से बहुत सा क्षय, समय और शक्ति नष्ट होती है।

कृषि की विछड़ो दशा के कारण

1. भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक भार
2. कृषि का वर्षा पर निर्भर होना
3. क्षेत्रों का बिखरा व छोटा होना
4. भूमि पर स्थायी सुधार का अभाव
5. कृषकों का निर्धन, अशिक्षित, निर्बल और मायबदा होना
6. पूँजी का अभाव
7. बिजली के असुविधाजनक साधन
8. वैज्ञानिक ढंग से कृषि न करना
9. सहायक साम-धान्यों का अभाव
10. परिवार साहूकार
11. उत्तम बीज और साद की कमी

4. भूमि पर ख़राई मुषारों का अभाव—भूमि पर ख़राई मुषारों के अभाव के कारण भी हमारी खेती की दशा हीन है। बिचाई के साधनों जैसे कुएं, तालाब और नहरों की कमी, बाड़ों (fences) का अभाव, दोषपूर्ण पट्टे की प्रचाली आदि खेती के लिये हानिकारक हैं।

5. धमिकों का निर्धन, अज्ञानी, निर्बल और भाग्यवादी (fatalist) होना—हमारे देश के खेती पर काम करने वाले धमिक निर्धन, अज्ञानी, निर्बल और भाग्यवादी होते हैं। उनका जीवन स्तर बहुत नीचा है। शिक्षा के अभाव के कारण अधिकांश कृषक भ्रम्य विश्वासी हैं तथा उनमें उन्नति की भावनाओं का अभाव है। उनकी कृषिविद्या मुर्खों पुरानी है और वे बहुधा परिवर्तनों का विरोध करते हैं। हमारे किसानों की कार्य-कुशलता विदेशी किसानों से बहुत कम है।

6. पूँजी (Capital) का अभाव—खेती की हीनता का एक और कारण पूँजी का अभाव है। दरिद्र होने के कारण किसानों के पास कृषि में पूँजी लगाने की नहीं है। गाय, बैल, पशु आदि ही किसानों की महत्वपूर्ण पूँजी है, जो संख्या में अधिक है परन्तु अकुशल है। पूँजी नहीं होने से कृषक उत्तम खाद, उत्तम बीज और उत्तम औजार काम में नहीं ला सकता। आधुनिक खेती के यन्त्रों और मशीनों के उपयोग के बारे में तो वह विचार भी नहीं कर सकता।

7. बिस्फी के असन्तोषजनक साधन—बिस्फी के साधन संतोषप्रद नहीं हैं और अधिकतर किसानों का माल कम कीमत पर गाँव में ही बिक जाता है। ऋणी होने के कारण तथा अन्य कठिनाइयों के कारण उन्हें अपना उत्पादन विवश होकर कम मूल्य पर ही बेच देना पड़ता है जिससे उनकी आय कम होती है, किन्तु पंचवर्षीय योजनाओं के सूत्रपाठ में स्थिति में परिवर्तन हुआ है।

8. वैज्ञानिक (Scientific) ढंग से कृषि न करना—कृषि प्रणाली इतनी अविकसित तथा हानिप्रद है, कि जब तक उसे आधुनिक आधार पर संगठित करके इसके तरीकों को बदला नहीं जायगा, हम ख़राई उत्पादन वृद्धि की कोई कल्पना कर ही नहीं सकते। भारतीय किसान

दरिद्रता तथा अज्ञानता के कारण आधुनिक वैज्ञानिक साधनों का उपयोग करने में हिचकिचाते हैं। अतः कृषि एक पिछड़ा उद्योग बन गया है।

9 सहायक काम-धंधों (Subsidiary occupations) का अभाव—भारतीय कृषि मौसमी (seasonal) होने के कारण कृषक को खेतों में केवल 6-8 महीने तक ही काम रहता है और बाकी समय में कोई सहायक धंधा न होने के कारण कृषक बेकार रहता है जिससे उसकी आय कम हो जाती है।

10. गाँव का साहूकार—हमारे देश में खेती की उन्नति में गाँव का साहूकार भी बाधक है। वह ऊँची ब्याज की दर पर, जो 12% से 40% तक पाई जाती है, ऋण देकर किसानों में गड़बड़ी कर किसानों को चपुल में जकड़े रखता है। किसानों की फसल सस्ती दर पर खरीद लेता है और बहुत सी रहन रसी हुई जमीन किसानों से महाजनों के हाथों में चली जाती है। ऋणग्रस्त होने के कारण किसानों के पास खेती की उन्नति के लिए धन नहीं रहता तथा उन्हें अपनी फसल भी साहूकार की सस्ती दर पर बेचनी पड़ती है।

11. उत्तम बीज और खाद की कमी—विज्ञान निम्न धेनी के बीज काम में लेते हैं जिससे अच्छी फसल नहीं होती। विज्ञान खाद की ओर भी विशेष ध्यान नहीं देते। प्रतिवर्ष बहुत सा गोबर जले बनाकर जला दिया जाता है। हरी खाद, रासायनिक, हड्डी और मछली की खाद का देश में बहुत कम उपयोग होता है। भूमि की उर्वरा शक्ति कम होने से उत्पादन गिरता है।

कृषि उत्पाति में सुधार के उपाय (Remedial measures)—

यदि हम कृषि उत्पादन में वृद्धि चाहते हैं, तो खेती में सुधार करने होंगे, जिससे कि प्रति एकड़ उत्पादन दर बढ़े और देश खाद तथा उद्योगों के लिए कच्चे माल में आत्म निर्भर बन सके।

1. सिंचाई की योजना का विकास—कृषि की उत्पाति में सुधार के लिए यह आवश्यक है कि कृषि की मानसून से स्वतन्त्र किया जाय।

असः सिचाई के साधनों—नहरों, कुँवों, तालाबों, आदि का तीव्र विकास नितान्त आवश्यक है।

2. चकबन्दी ( Consolidation of holdings ) व सहकारी खेती—चकबन्दी और सहकारी खेती (Co-operative farming) द्वारा हम खेती को अन्तर्विभाजन और भागबंटन (Sub division and fragmentation) के दोषों से बचा सकते हैं और बड़े पैमाने की खेती के लाभ उठा सकते हैं। मिनी की उपज में वृद्धि करने के लिये अच्छी खाद, उत्तम बीज, उत्तम औजारों का प्रयोग होना चाहिये। ट्रैक्टरों द्वारा बेकार जमीन को खेती के योग्य बनाना चाहिए। रूस की भाँति जगह-जगह ट्रैक्टर स्टेशनों की स्थापना करनी चाहिये जो आधुनिक औजार और उनके फुटकर भागों का सग्रह करें। बैलों की नस्ल (breed) सुधार कर उसकी कार्यशक्ति में वृद्धि करनी चाहिये।

3. कीटाणुनाशक दवाइयों का प्रयोग—नरह-तगह के कीटाणु भी हमारी खेती को बहुत हानि पहुँचाते हैं। टिट्टियों के दल प्रनिरप हरी-

कृषि उत्पाति में सुधार के उपाय

1. सिचाई की योजनाओं का विकास

2. चकबन्दी व सहकारी खेती

3. कीटाणु-नाशक दवाइयों का प्रयोग

4. सहकारी समितियों का गठन

5. फुटीर उद्योगों की उन्नति

6. फुपकों के विचारों में सुधार

7. पशुओं की दशा में सुधार

8. कृषि का वैज्ञानिकरण

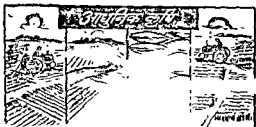
मरी फसल को नष्ट करके बहुत हानि पहुँचाते हैं। इस हानि को रोकने के लिये कीटाणु-नाशक दवाइयों के प्रयोग का प्रचार किया जाय, जिससे कृषक अपनी फसल की रक्षा कर सके।

4. सहकारी समितियों द्वारा पुँजी व बिजली के अन्य साधनों की सुविधा—सहकारी समितियों द्वारा उचित ब्याज पर किसानों को पुँजी उधार देने तथा खेती की उत्पाति की बिक्री का उचित प्रबन्ध करने

की सुविधायें होनी चाहिये। देश में बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों—साख, विक्रय, बहुपक्षी आदि—का गठन अत्यावश्यक है।

5. गांव में कुटीर उद्योगों की उन्नति के द्वारा कृषि पर जन-भार में कमी—गांवों में कुटीर उद्योग चालू करने चाहिये, जिससे लोग भूमि पर ही आश्रित न रहें और भूमि पर जन-भार कम हो जाय। इससे बेकारों को काम मिलेगा, किसान अपने बेकार समय का उपयोग कर सकेंगे तथा उनकी भाव में वृद्धि होगी। हमको केवल कृषि परिस्थितियों में नहीं परन्तु कृषक स्वयं में भी सुधार करना चाहिये। हमें किसानों का जीवन-स्तर ऊँचा करना है, और उनको शिक्षित बनाना है, जिससे प्रगतिशील हों और उनकी कार्य-कुशलता में वृद्धि हो। किसानों को यह विश्वास दिलाया जाय कि खेती के सुधारों से होने वाला लाभ उन्हीं का होगा, जिससे कि वे मन लगाकर अपना कार्य करें, और खेती में सुधार करने के लिए प्रयत्न करें। कृषि विकास में भूमि-व्यवस्था के सुधार का महत्वपूर्ण स्थान है।

6. कृषकों के विचारों में सुधार—अज्ञान के कारण कृषकों में भाग्यवाद तथा पुराने और बुरे रीति-रिवाजों में विश्वास उत्पन्न हो गये हैं। अतः यह आवश्यक है कि उनमें शिक्षा का प्रचार किया जाय जिससे उनके विचारों में सुधार हो और वे नये-नये तरीके अपनाकर अपनी उत्पादकता को बढ़ाने का भरसक प्रयत्न करें।



7. पशुओं की दशा में सुधार—हमारे देश में किसानों के पशु बहुत दुर्बल हैं और कम कार्यकुशल हैं तथा बीमारी से घिरे रहते हैं। इन समस्याओं में सुधार, चारे का उचित प्रबंध तथा पशु-वैद्यशास्त्रों की सुविधाओं का प्रबन्ध करना चाहिये।

8. कृषि का वैज्ञानिकीकरण (Scientific agriculture)—कृषि विकास के लिए विज्ञान का महत्व बहुत बड़ा गया है। विज्ञान के द्वारा प्रकृति पर निर्भरता को दूर किया जा सकता है। रासायनिक तथा अन्य प्रकार की खादों के उपयोग, उन्नत और सुधरे हुए कृषि औजारों के प्रयोग तथा वैज्ञानिक दृष्टि से खेती करने के लिए प्रचार एवं प्रसार करना आवश्यक है।

### भारत में कृषि विकास के लिए कृषि नियोजन ( Agricultural Planning )

“हमारे देश की संस्कृति का आधार कृषि ही है।” स्वतन्त्रता के पश्चात् देश के सम्मुख कृषि सुधार की समस्या सम्मोह रूप से उपस्थित हुई। नियोजन के बिना आर्थिक एवं सामाजिक विकास सम्भव नहीं होता। अतः देश में कृषि नियोजन की आवश्यकता ही नहीं अपितु अनिवार्य है। भारत में कृषि-नियोजन के विस्तृत उद्देश्य हैं। कृषि-नियोजन से तात्पर्य केवल मौलिक पदार्थों की पैदावार को बढ़ाना ही नहीं है अपितु देश के प्राकृतिक साधनों का अधिकतम विकास करना, कृषकों का आर्थिक एवं सामाजिक विकास करना, शोषण को अन्त करना तथा रोजगार का प्रसार और आर्थिक असमानता को दूर करके देश को शक्तिशाली एवं समृद्धिशाली बनाना है। द्वितीय महायुद्ध से उत्पन्न समस्याओं को हल करने के लिए अनेक योजनाएँ प्रस्तुत की गईं, जिनमें कृषि को महत्व दिया गया।

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56)—इस योजना में कृषि विकास को प्राथमिकता (Priority) दी गई। इसके कुल 2,356

करोड़ रुपये के आयोजित व्यय में से कृषि, सिंचाई, विजली आदि के लिए 1,018 करोड़ रुपये रहे गये थे जो कुल व्यय का 43.2 प्रतिशत था । (1) इस योजना में कृषि, सिंचाई एवं शक्ति के विकास पर 884 करोड़ रुपये व्यय किए गए । (2) खाद्यान्नों में 30%, कपास में 45% तथा तिलहन के उत्पादन में 80% की वृद्धि हुई । (3) सिंचाई की योजनाओं के लिए 518 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई । (4) 64.5 लाख हेक्टर भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था की गई । रासायनिक खाद के लिए सिन्दरी में खाद का कारखाना खोला गया । (5) उत्तम बीज की व्यवस्था, कृषि में नवीन वैज्ञानिक अनुसंधान, चकबन्दी, सहकारी साधन एवं वितरण समितियों का विरास किया गया । (6) पशुओं की नस्ल में सुधार, सहकारिता, प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा सहकारी कृषि के प्रयोग किए गए और 1,40,000 ग्रामों में सामुदायिक विकास (community development) कार्य आरम्भ किया गया ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61)—इसमें कृषि के उत्पादन लक्ष्यों (production targets) की प्राप्ति हेतु 666.65 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी । इस योजनाकाल के अन्त में कृषि पदार्थों का उत्पादन सूचकांक (index number) (1949—50=100) के आधार पर 135 हो गया । इस योजनाकाल में उन्नत किस्म के बीज, खाद तथा सिंचाई के साधनों के विकास के निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकी । उत्पादन लक्ष्यों को भी सन् 1957-58 व 1959-60 वर्षों की फसलों के उत्पादन में कमी के कारण प्राप्त नहीं किया जा सका । प्रथम योजना में कृषि का उत्पादन 17% बढ़ा जबकि द्वितीय योजना में यह वृद्धि 16% ही थी ।

द्वितीय योजना-काल में लगभग 64 लाख हेक्टर भूमि में सिंचाई (Irrigation) का प्रबन्ध किया गया तथा विभिन्न प्रकार की खासों मो. दन खादों (manures and fertilizers) का अतिरिक्त प्रयोग किया गया ।



चतुर्थ योजना (1961-66)—इस योजना के अन्तर्गत—(1) सिंचाई साधनों का विस्तार, (2) रासायनिक खाद की पूर्ति का विस्तार, (3) उन्नत बीज, (4) पौधों का रक्षण, (5) सुघरे हुए हल और जोरारों का विस्तार आदि कार्यक्रम सम्मिलित हैं। इस योजना में कृषि उत्पादन की वृद्धि की दर पहले से दृगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के पाँच उद्देश्यों में से 'खाद्यान्नों में आत्म निर्भरता प्राप्त करना एवं उद्योगों और निर्यात की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कृषि का उत्पादन बढ़ाना' भी एक उद्देश्य है। इस अवधि में खाद्यान्नों का उत्पादन 30 प्रतिशत तथा अन्य फसलों का उत्पादन 31 प्रतिशत बढ़ाये जाने की व्यवस्था थी। सिंचित क्षेत्र 2.82 करोड़ हेक्टर से बढ़कर 3.62 करोड़ हेक्टर हो जाने का अनुमान था। इस योजना में कृषि विज्ञान पर 1089 करोड़ रुपये खर्च हुए।\*

चतुर्थ योजना—सन् 1966 से 1971 तक की प्रस्तावित चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कृषि कार्यक्रमों के लिए 1,944 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। संशोधित योजना-प्राकल्प में कृषि विकास हेतु 2217 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।† इस योजना में कृषि को परम्परागत जीवन-यापन की पद्धति के स्थान पर औद्योगिक आधार पर प्रतिष्ठित करने का लक्ष्य रखा गया था। सिंचाई, भू-संरक्षण, भूमि सुधारों आदि कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने की व्यवस्था की गई थी।

स्रोत में हम यह कह सकते हैं कि सरकार ने अर्थ व्यवस्था में कृषि के महत्व का मुद्दिर कर पंचवर्षीय योजनाओं में इसके विकास पर वर्तमान ध्यान दिया है। फिर भी कृषि के क्षेत्र में अधिक प्रयत्नों की आवश्यकता है।

• Aspects of the Fourth Plan, p. 4

† चतुर्थ योजना तीन वर्षों के लिए स्वर्णिम कर दी गई थी। अब यह योजना 1 अप्रैल 1969 से प्रारम्भ हो गई है।

‡ Yojna, April 20, 1969—p. 16

## सारांश

भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि हमारी जीवन प्रणाली एवम् प्रति का आधार है।

कृषि का अर्थ व्यवस्था में महत्व—जीविकोपार्जन का मुख्य साधन, रोज घाय में योग, सरकार की आय, जनसंख्या के लिए भोजन, मुलित अर्थ-व्यवस्था में कृषि का महत्व, उद्योगों के लिए कच्चा माल, राष्ट्रीय महत्व, निर्यात में महत्व, सामाजिक व राजनीतिक महत्व।

कृषि अर्थ व्यवस्था का प्राण है।

कृषि का विखड़ापन—अन्य देशों की तुलना में भारतीय प्रति एकड़ त पैदावार कम है। कारण—भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक, कृषि का बर्षा पर निर्भर होना, खेतों का बिलरा व छोटा होना, पर स्थायी सुधारों का अभाव, कृषकों का निर्धन होना, असिद्धित, ल व माल्य-बादी होना, पूँजी का अभाव, बिजली की असन्तोषजनक सेवा, वैज्ञानिक कृषि का अभाव, सहायक धर्मों का अभाव, माहूँकार शेषपूर्ण कार्यप्रणाली, उत्तम बीज व खाद की कमी।

कृषि में सुधार के उपाय—निर्चार्ड, ऋणबन्दी व सहकारी कृषि, अनुनामक दवाओं का प्रयोग, सहकारी समितियों का गठन कुटीर ग की उपनि, कृषकों के बिचारों में सुधार, पशुधो की दसाओं में र, कृषि का वैज्ञानीकरण।

विकास और नियोजन—

प्रथम योजना में कृषि विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई। योजना में कृषि विकास पर कुल योजना व्यय का 43.2 प्रतिशत खर्च हुआ।

द्वितीय योजना में 667 करोड़ रुपये खर्चे करके कृषि उत्पादन में 49-50 की तुलना में) 35 प्रतिशत वृद्धि हुई।

तृतीय योजना में कृषि उत्पादन की दर को दुगुना करने का लक्ष्य गया। इस योजना में कृषि विकास कार्यों पर 1089 करोड़ खर्चे हुए।

समुच्च योजना में कृषि की औद्योगिक आधार पर प्रतिष्ठित करने का उद्देश्य रखा गया है ।

सरकार पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत कृषि विकास कार्यक्रमों पर ध्यान दे रही है ।

### प्रश्न

1. भारतीय कृषि के प्रमुख दोषों की व्याख्या कीजिये तथा कृषि-सुधार के उपाय बताइये ।
2. भारतीय अर्थ व्यवस्था में कृषि का महत्व बताइये । भारतीय कृषि के पिछड़े होने के क्या कारण हैं ? इसके सुधार के उचित उपाय सुझाइये ।  
(राज. बो., हा. से., 1965)
3. भारतीय कृषि की उन्नति के सुझाव दीजिये ।  
(राज. बो., हा. से. 1967)
4. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—  
(अ) भारत में कृषि उपज कम होने के प्रमुख कारण ।  
(राज. बो., हा. से. 1969)

## अध्याय 3

### भारत में कृषि की जोतें

#### (AGRICULTURAL HOLDINGS IN INDIA)

“भारत में भूमि को ‘आर्थिक भूकम्पों’ के कारण बार-बार उप-विभाजित होना पड़ता है।”

—नाथेल्ल

“भूमि के उपविभाजन और अपखण्डन से साहस नष्ट होता है, धन की बड़े पैमाने पर सर्वादी होती है, सीमा बनाने में भूमि का बहुत सा भाग बेकार हो जाता है और गहरी खेती असम्भव होती है।”

—डॉ० मैन

भारतीय कृषि को विकसित करने के उपायों में आर्थिक जोत (Economic holding) का निर्माण करना उल्लेखनीय है। दुर्भाग्य से भारतवर्ष में कृषि जोतों का आकार सतोषप्रद नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से इस दिशा में सुधार के कतिपय प्रयास किए गए हैं। यहाँ हम कृषि जोतों के विभिन्न स्वरूपों की चर्चा करेंगे।

कृषि जोत का अर्थ एवं महत्व—कृषि जोत या इकाई का तात्पर्य उस भूमि के क्षेत्र से है जिस पर कृषक द्वारा कृषि की जाती है। कृषि जोत का प्रभाव कृषक एवं कृषि दोनों पर ही पड़ता है। बिना उचित कृषि जोत के अच्छे बीज, खाद, यंत्र आदि का प्रयोग सम्भव नहीं हो सकता। कृषि में स्थायी सुधारों का लागू करना भी कृषि जोत के आकार पर निर्भर करता है। इस प्रकार कृषि जोत का आकार कृषि सम्बन्धी समस्याओं से अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

## कृषि जोतों के प्रकार (Types of Agricultural holdings)

कृषि जोतों को मुख्यतः निम्नोक्तिन भागों में बांटा जा सकता है—

1. आर्थिक जोत (Economic holding)—इस शब्द के अनुसार "आर्थिक जोत वह जोत है जो इस पर निर्भर रहने वाले परिवार को एक सामान्य प्रकार के जीवन स्तर की सुविधाएँ प्रदान कर सके।" यह वह इकाई है जो किसान की साधारण जीवन स्तर

कृषि जोतों के प्रकार

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. आर्थिक जोत   | मान्य करने हेतु बांटा जा सकता है। सरकार अनाधिक |
| 2. बुनियादी जोत | जोतों के स्थान पर इन इकाइयों                   |
| 3. आदर्श जोत    | की स्थापना करने के लिए प्रयत्न-                |
| 4. अनाधिक जोत   | जोन है।  |

2. बुनियादी जोत (Basic Holding)—यह वह जोत है जो आर्थिक जोत से आकार में छोटी है तथा जिससे कम आकार की इकाई आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं होती है। यह कृषक को न्यूनतम जीवन स्तर हेतु आवश्यक भाग प्रदान करती है। देश के अनेक भागों में यह इकाई भी उपलब्ध नहीं है।

3. आदर्श या अनुकूलतम जोत (Optimum holding)—आदर्श जोत कृषि का वह आकार होता है जिस पर कृषक को उसके द्वारा भूमि पर लगाये गये साधनों की सुलना में अतिरिक्त लाभ मिलना है। राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति के पास रखी जाने वाले इस जोत का अधिकतम आकार निर्धारित कर दिया जाता है। सामान्यतः इस जोत का आकार आर्थिक जोत से तीन गुना होता है। आर्थिक विषमताओं को दूर करने की दिशा में आदर्श जोत का निर्धारण सामाजिक दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है।

4. अनाधिक जोत (Uneconomic holdings)—ऐसी छोटी इकाईयाँ जिसमें कृषि व्यवसाय का संचालन अलाभदायक हो अनाधिक जोतों के नाम से पुकारी जाती हैं। भारतवर्ष में इस प्रकार की जोतों

का बाहुल्य है। देश में कुछ स्थानों पर जोतों का आकार इतना छोटा है कि उन्हें 'खिलौना जोत' (Toy holding) के नाम से पुकारा जाता है। इन जोतों के बारे में हम खेतों के उपविभाजन एवं अपखण्डन की समस्या के अन्तर्गत विस्तार से पढ़ेंगे।

खेतों का उपविभाजन एवं अपखण्डन

(Sub-division and Fragmentation of holdings)

अर्थ—'उपविभाजन' (Sub-division) का अर्थ उत्तराधिकारियों में खेत का बार-बार छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देने से है। किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उसकी भूमि का वितरण उसके उत्तराधिकारियों में किया जाता है और फिर इसका पुनर्विभाजन किया जाता है। इस क्रिया से भूमि का बार-बार विभाजन होता है और खेतों का आकार छोटा होता चला जाता है।

'अपखण्डन' (Fragmentation) का तात्पर्य भूमि के उन टुकड़ों से होता है जो एक-एक से न होकर दूर-दूर स्थित होते हैं। संक्षेप में, भूमि का छोटे-छोटे खेतों में बाँटा जाना उपविभाजन और खेतों का दूर-दूर बिखरा होना अपखण्डन कहलाता है।

भारतवर्ष में खेतों का आकार छोटा होने के साथ-साथ दूर-दूर बिखरे होने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। कुछ सर्वेक्षणों के अनुसार भारत में जोत (holding) का औसत आकार 3.2 हेक्टर (7.5 एकड़) है। किन्तु नेशनल सेम्पल सर्वे (N. S. S.) के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में जोतों (holdings) का औसत आकार 5.43 एकड़ है। यदि हम दूसरे देशों\* की जोतों के औसत आकार से इसकी तुलना करें तो स्पष्ट हो जायगा कि भारत में खेतों का आकार बहुत छोटा है। इतना ही नहीं जोत का औसत आकार भारत के विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न है। जहाँ राजस्थान में जोत का औसत आकार

---

\* कुछ प्रमुख देशों की जोतों का औसत आकार इस प्रकार है—  
संयुक्त राज्य अमेरिका 215 एकड़, ब्रिटेन 66 एकड़, फ्रांस 26 एकड़, युगोस्लाविया 11 एकड़ आदि।

७४४ हेक्टर (१७ एकर) है वही बिहार में ४ और केरल में १०५ हेक्टर (२५ एकर) की औसत जोन है। अपसङ्गन के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार के अध्ययन किये गये हैं जिनसे पता लगता है कि क्षेत्र छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटे हुए नहीं हैं, वरन् जोन एक स्थान पर न होकर दूर-दूर स्थित है। डॉ० मैन (Mann) ने दक्षिण के एक गाँव का सर्वेक्षण करके पता लगाया कि गाँव के १५६ कृषकों के पास ४१८ क्षेत्र के टुकड़े थे जिनमें से लगभग ५३५ नेत्रों का घातार ४०३ हेक्टर (एक एकर) से भी कम था। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में क्षेत्रों का उपविभाजन के साथ-साथ अपसङ्गन की समस्या भी पाई जाती है।

उप-विभाजन एवं अपसङ्गन के कारण—अब हम कृषि के विकास को कुठित करने वाली इस समस्या के कारणों का अध्ययन करेंगे।

१. हमारे देश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है किन्तु औद्योगीकरण का विकास तेजी से न हो सकने के कारण भूमि पर जनसंख्या का भार (Pressure of population) बढ़ता जा रहा है। परिणाम-स्वरूप क्षेत्रों का घातार छोटा होता जा रहा है।

क्षेत्रों में उप-विभाजन एवं अपसङ्गन के कारण

१. जन-संख्या की वृद्धि
२. उत्तराधिकार के नियम
३. संयुक्त परिवार प्रथा का अन्त
४. कुटीर-उद्योगों का ह्रास
५. भूमि को साझे पर देने की प्रथा.

२. उत्तराधिकार के नियम (Laws of Inheritance and Succession)—हमारे देश में उत्तराधिकार के नियमों के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद भूमि उसके पुत्रों में समान रूप से बाँटी जाती है। यहाँ इंग्लैंड की तरह ज्येष्ठाधिकार (Primogeniture) पद्धति का प्रचलन नहीं है। इस प्रकार

भूमि का विभाजन छोटे-छोटे अनाधिक टुकड़ों में हो जाता है।

३. संयुक्त परिवार (Joint family) प्रथा का अन्त—भारतवर्ष में बहुत प्राचीन काल से यह प्रथा प्रचलित थी जिसके अन्तर्गत

परिवार के सदस्य साथ-साथ रहते थे और भूमि का बंटवारा नहीं होता था। किन्तु वास्तव्य शिक्षा-दीक्षा ने व्यक्तिवादी मान्यता को प्रोत्साहन दिया है। परिणामस्वरूप अब परिवार के सदस्य भूमि एवं अन्य सम्पत्ति का विभाजन करके अपना हिस्सा पलग रखना चाहते हैं।

4. कुटीर उद्योगों का ह्रास—अनेक कारणों से कुटीर उद्योगों का ह्रास हो गया और जो कारीगर इन उद्योगों में लगे हुए थे वे भी कृषि पर आधारित हो गए। फलस्वरूप क्षेत्रों के टुकड़े छोटे-छोटे हो गये।

5. भूमि के प्रति मोह—भूमि सामाजिक प्रतिष्ठा का मापदण्ड तो है ही, साथ ही स्वतन्त्रतापूर्वक काम करने के लिए मनुष्य क्षेत्री का ही सहारा लेता है। हमारे देश में किसानों का भूमि के प्रति बहुत मोह है और वे भूमि के छोटे से छोटे टुकड़े को भी अपने ही पास रखना चाहते हैं। प्रत्येक उत्तराधिकारी अपने पिता के सभी क्षेत्रों में हिस्सा लेना चाहता है जिससे क्षेत्रों के दूर-दूर स्थित होने की समस्या को बढ़ावा मिलता है।

6. भूमि को सामे पर देने की प्रथा—बड़े बड़े भूमिपति बहुधा अपनी भूमि पर स्वयं क्षेत्री नहीं करते। वे अपनी भूमि को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटकर अलग-अलग किसानों को सामे पर दे देते हैं। इससे भूमि के जोत का मानिक एक होते हुए भी जोत के छोटे-छोटे टुकड़े हो जाते हैं।

उप-विभाजन एवं अपक्षजन की हानियाँ (Disadvantages)—  
क्षेत्रों के छोटे-छोटे एवं बिखरे होने से क्षेत्री में कई हानियाँ होती हैं और कृषि भाषिक दृष्टि से अलामप्रद हो जाती है। इसके मुख्य दोष इस प्रकार हैं—

1. कृषि उत्पादन लागत (Cost of production) में वृद्धि—  
क्षेत्रों का छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजन होने पर किसान अपने साधनों का पूरा-पूरा लाभ नहीं उठा सकता। कई क्षेत्र तो ऐसे होते हैं जिनमें



सुझाई भी नहीं की जा सकती और यदि उनमें खेती की भी जाय तो उत्पादन से सागत अधिक हो जाती है ।

2. कृषि सुधारों (Agricultural Improvements) का संभव न होना—खेतों का क्षेत्रफल छोटा होने पर भूमि पर कृषि सुधार नहीं किए जा सकते । छोटे-छोटे खेतों पर कुआँ खोदना, पक्की नालियाँ बनाना आदि लाभदायक नहीं होता । इन सुधारों के प्रभाव में कृषि की प्रति एकड़ पैदावार में कमी आती है ।

3. बाड़, मेड़ आदि लगाने में कठिनाई—जानवरों आदि से फसलों की रक्षा करने के लिए आवश्यक खेतों की बाड़ (fence) बगैरह लगाई जाएँ । जहाँ खेतों के टुकड़े बहुत छोटे-छोटे और दूर-दूर स्थित हों वहाँ बाड़ लगाने में बहुत सर्वा होता है और बहुत बाड़ें लगाने और मेड़ें छोड़ने से उतनी भूमि खेती के काम में नहीं ली जा सकती ।

4. यांत्रिक खेती (Mechanised farming) अव्यवहार्य हो जाती है—छोटे खेतों पर यांत्रिक खेती लाभदायक नहीं होती । ट्रैक्टर, कुन्डोजर, प्रेसर, आदि समय और धन बचाने वाले मयंत्र (time and labour saving devices) का प्रयोग छोटे-छोटे भूमि के टुकड़ों पर नहीं किया जा सकता ।

5. निगरानी (Supervision) में कठिनाई—छोटे-छोटे बिचरे हुए खेतों की देखभाल या निगरानी करना न केवल कठिन ही होगा है, बरन् खर्चीला भी होता है ।

6. समय, धन व धन का अव्यय (wastage) —जब खेत दूर-दूर स्थित हों तो कृषि के योजार, पशु आदि माधनों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने से जाने में समय, धन व धन का व्यय होता है जिससे कृषि लाभदायक व्यवहार बन जाता है ।

7. भगड़े और मुकदमेबाजी (litigation)—खेतों के दूर-दूर स्थित होने की दशा में मार्ग, सीमा, पानी, बाढ़ सम्बन्धी अनेक भगड़े पैदा हो जाते हैं। फलस्वरूप किसान आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं और मुकदमेबाजी चलती है जिनमें धन, समय व शक्ति की बर्बादी होती है।

8. पूंजी मिलने में कठिनाई—जब खेतों का आकार छोटा होता है तो इनको रहन (mortgage) रख कर रुपया उधार नहीं मिलता, और यदि मिलता भी है तो बहुत कम। बिना रहन रखे ऊँची ब्याज दर देनी पड़ती है।

9. गहरी खेती (intensive cultivation) सम्भव नहीं—भूमि का छोटे-छोटे टुकड़ों में दूर-दूर स्थित होना गहरी खेती को कठिन बनाता है, क्योंकि कृषि सुधार के विभिन्न साधनों को इन टुकड़ों पर नहीं लगाया जा सकता।

10. खेती का अनुविभाजनक तथा कृषि योग्य भूमि का बेकार होना—खेतों के दूर-दूर होने तथा उनका आकार छोटा होने से उन पर धम और पूंजी की व्यवस्था करने में कठिनाई होती है और कई खेतों को बिना काफ़ी किए ही छोड़ना पड़ता है।

उप-विभाजन एवं अपसंजन के लाभ (Advantages)—खेतों के उप-विभाजन एवं अपसंजन के पक्ष में कुछ बलीतें दी जाती हैं जो इस प्रकार हैं—

उप-विभाजन एवं अपसंजन से हानियाँ

1. कृषि उत्पादन लागत में वृद्धि
2. कृषि सुधारों का सम्भव न होना
3. बाढ़-मेड़ लगाने में कठिनाई
4. यांत्रिक खेती असम्भव
5. निगरानी में कठिनाई
6. समय, धन व धन का अपव्यय
7. भगड़े और मुकदमेबाजी
8. पूंजी मिलने में कठिनाई
9. गहरी खेती सम्भव नहीं
10. खेती का अनुविभाजनक और भूमि का बेकार होना

1. "सभी अण्डे एक टोकरी में मत रमो" (Do not keep all the eggs in one basket) एक पुरानी कहावत है। टोकरी इसी प्रकार भूमि के भिन्न-भिन्न टुकड़ों पर खेती करने से किसान आर्थिक संकट से बच सकता है। यदि एक क्षेत्र पर फसल सराब हो जाए तब भी किसान दूसरे क्षेत्रों की उत्पत्ति से गुजारा कर सकता है। अतः बिगड़े क्षेत्रों पर कृषि करने से जोखिम (risk) घट कर कम हो जाता है।

2. डा० रामाकृष्ण मुकुर्जी का मत है कि भूमि के अलग-अलग टुकड़ों पर खेती करने से भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी और जलवायु में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं। विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने से किसान को अधिक दिनों तक काम मिलता है। पर यह दलील अधिक महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि अपसृजन का अर्थ प्रायः एक ही प्रकार की मिट्टी और जलवायु वाले क्षेत्रों से है।

3. कुछ लोग यह दलील भी देने हैं कि उप-विभाजन से किसान का आर्थिक स्तर समान होता है और पूँजीवादी कृषि (capitalist farming) नहीं बन पाती। परन्तु भारत में भूमि का विभाजन इतने छोटे-छोटे टुकड़ों में हो गया है कि अब इनसे लाभ होने के बजाय हानि ही अधिक होती है।

### समस्या का उपचार और प्रगति

इस समस्या का शीघ्र निवारण बहुत ही आवश्यक है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से सरकार कई उपाय काम में ला रही है जिनसे समस्या का समाधान करके भविष्य में होने वाले भूमि के उप-विभाजन एवं अपसृजन को रोका जा सकेगा। यहाँ हम इन उपायों और उनकी प्रगति के बारे में भी विचार करेंगे।

1. भूमि पर जनसंख्या के भार में कमी की जानी चाहिये—देश में औद्योगीकरण का विकास करके भूमि पर जनसंख्या के बढ़े हुए भार को कम करने से क्षेत्रों के भावी विभाजन की समस्या को दूर किया जा सकता है। यह एक दीर्घकालीन उपाय (long term measure) है।

2. उत्तराधिकार के नियमों में परिवर्तन—कुछ लोगों का मत है  
 खेतों में इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए अपने उत्तराधिकार के नियमों

परिवर्तन किया जाना चाहिए  
 इंग्लैण्ड की भाँति ही ज्येष्ठा-  
 धार नियम बना लेना चाहिये ।  
 करने से भूमि के स्वामी की  
 के बाद सबसे बड़े लड़के को  
 भूमि का स्वामित्व प्राप्त हो  
 गा । किन्तु इस प्रकार का नियम  
 नाया जाना भारत में अव्यव-  
 रक प्रतीत होता है । फिर भी  
 नियम तो बनाया ही जा सकता  
 जिसमें सभी उत्तराधिकारियों  
 भूमि पर बराबर अधिकार तो  
 केन्तु खेती के लिए भूमि को टुकड़ों में न बाँटा जाय ।

उप विभाजन तथा अपसन्देह  
 की समस्या का उपचार

1. भूमि पर जनसंख्या का  
 भार कम करना चाहिये
2. उत्तराधिकार के नियमों  
 में परिवर्तन
3. चकबन्दी
4. कानून द्वारा भाषिक जोतों  
 का निर्माण
5. जोतों की सीमा निर्धारण
6. सहकारी कृषि

3. चकबन्दी ( Consolidation of holdings )—इस समस्या  
 सुलझाने का सबसे प्रभावशाली उपाय चकबन्दी है । चकबन्दी के  
 विधान को उसके विभिन्न भूमि के टुकड़ों के बन्दे एक ही स्थान  
 समान बीमर को भूमि दी जाती है । चकबन्दी के सम्बन्ध में ब्रिटेन,  
 इ. फ्रांस, डेनमार्क व अन्य में परीक्षण किये गए हैं जिनसे यह स्पष्ट  
 है कि प्रायः किसान स्वेच्छा से (voluntarily) चकबन्दी करने  
 पार नहीं होते ।

भारतवर्ष में सबसे पहले  
 पंजाब और उत्तर-प्रदेश प्रांति  
 में । परन्तु इनके

का कार्य बड़ी-  
 में प्रारम्भ किया  
 १९१६, पंजाब

विमानों के विरोध करने पर उन्हें चकबन्दी के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था। धीरे-धीरे ऐसे कानून बनाए गए जिनके अन्तर्गत चकबन्दी में अनिवार्यता का तत्व (element of compulsion) सम्मिलित कर लिया गया। कानूनों के अन्तर्गत यदि सातेदारों का एक निश्चित भाग चकबन्दी करना चाहे तो दूसरे न चाहने वाले कारखानारों को भी चकबन्दी करने के लिए बाध्य (force) किया जा सकता है। इस प्रकार के कानून बन जाने पर भी चकबन्दी का कार्य अधिक प्रगति न कर सका। इसलिए ऐसे कानूनों की आवश्यकता हुई जिनके द्वारा चकबन्दी का अधिकार सरकार को मिल सके। सबसे पहले सन् 1947 में बम्बई में इस प्रकार का कानून बना। इसी प्रकार के कानून पंजाब, दिल्ली, उत्तर-प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य-प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मैसूर आदि राज्यों में बन गए हैं। हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत चकबन्दी कार्यक्रम का महत्वपूर्ण विकास हुआ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 11.05 हेक्टर (3 करोड़ एकड़) भूमि पर चकबन्दी हो चुकी थी। तृतीय योजना काल में 11.245 हेक्टर (3.10 करोड़ एकड़) भूमि पर चकबन्दी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभी तक चकबन्दी का सबसे अधिक कार्य पंजाब में हुआ है जहाँ 7.01 लाख हेक्टर (175 लाख एकड़) भूमि पर चकबन्दी हो गई है। राजस्थान में लगभग 10.42 लाख हेक्टर (26 लाख एकड़) भूमि पर चकबन्दी का कार्य सम्पन्न हो चुका है।

4. आर्थिक ओलों (Economic holdings) का निर्माण—आर्थिक ओल वह ओल है जो एक औसत परिवार (average family) को सम्पत्ति के ओल के रूप में प्रदान कर सके। इस प्रकार की ओलों का कानून निर्माण करने से ओलों की उप-विभाजन और सातहन में रोक का संवेदा। आर्थिक ओल का निर्धारण करने समय अन्य कई बातों पर ध्यान रखा जाता है जैसे—भूमि की उपजाऊ शक्ति, सिंचाई की सुविधाएँ, बाँधी से दूरी, सेतु के स्तम्भ और बट्टियाँ आदि। इस प्रकार आर्थिक ओल का अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न होगा।

### 5. जोतों का सीमा निर्धारण (Ceiling on land holding):—

यह भी सुझाव दिया जाता है कि छोटे-छोटे खेतों की समस्या को दूर करने के लिए जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए। जिन लोगों के पास इस सीमा से अधिक भूमि हो, सरकार उन्हें मुआवजा देकर प्राप्त करले और उसे अधिक जोत से कम क्षेत्र वाले खेतों में विभाजित कर दे। प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में अधिकतम सीमा निर्धारण के कार्य पर जोर दिया गया। सीमा निर्धारण के भी दो पहलू हैं— (1) वर्तमान भूमिपतिवों के पास जो जमीन है उसकी अधिकतम सीमा का निर्धारण और (2) भविष्य में जो जमीन ली जाये उसकी सीमा का निर्धारण। अधिकतम सीमा निर्धारण में भी भूमि की उर्वरा शक्ति, सिंचाई के साधन आदि बातों का प्रभाव पड़ता है। देश के लगभग सभी राज्यों में सीमा निर्धारण के कानून लागू कर दिये गये हैं। राजस्थान में यह सीमा (माबो तथा वर्तमान दोनों ही जोतों पर) 25 से 336 स्टैण्डर्ड एकड़\* निर्धारित की गई।

सहकारी कृषि (Co-operative farming)—भूमि के उप-विभाजन एवं अपखण्डन की समस्या से बचने के लिए सहकारी कृषि भी अपनाई जा सकती है। छोटी जोतों की वर्तमान समस्या का निराकरण तो शकबन्दी से हो जाएगा, किन्तु भविष्य में विभाजन को रोकने का प्रभावशाली तरीका केवल सहकारी कृषि ही है। इन पद्धति के अंतर्गत छोटे-छोटे किसान मिलकर सहकारिता के सिद्धान्तों पर कृषि सहकारी समितियाँ (Better Farming Societies) बनाकर ऋणों की पध्दती खाद, बीज आदि भेवाए दी जाती हैं। द्वितीय योजना में सहकारी कृषि के विकास पर अधिक बल दिया गया। भारत में पाइलट योजनाओं (Pilot projects) के अन्तर्गत तृतीय योजना के अन्त तक 2,749 सहकारी कृषि समितियों का गठन किया जा चुका था। इनके अतिरिक्त 2,752 सहकारी कृषि समितियाँ पाइलट योजनाओं के क्षेत्र के बाहर

बनाई गई। तृतीय योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा साठ की गई भूमि का वितरण करने में सहकारी कृषि समितियों को प्राथमिकता दी गई। जून 1967 में सहकारी कृषि समितियों की संख्या 7,866 थी।\*

इस प्रकार हम देखते हैं कि उप-विभाजन एवम् अपखण्डन कृषि के लिए बहुत हानिकारक है। इसे दूर करने के प्रयत्नों से आर्थिक जोत के निर्माण को बल मिलेगा। प्रसन्नता की बात है सरकार सहकारी कृषि, चकबन्दी एवं अधिनियमों के आधार पर समस्या के हल के लिए आगरुक है।

### सारांश

कृषि के उत्थान के लिए आर्थिक जोतों का निर्माण आवश्यक है।

आर्थिक जोत—वह जोत है जिस पर एक परिवार सामान्य जीवन स्तर के लिए साधन जुटा सके।

बुनियादी जोत—वह जोत है जिसके बिना कोई भी कृषक न्यूनतम जीवन स्तर के लिए आय प्राप्त नहीं कर सकता।

आदर्श जोत—वह अधिकतम जोत है जिस पर लगाये गए साधनों की तुलना में अतिरिक्त लाभ मिलता है।

अनार्थिक जोत—वह है जिसके कारण कृषि अलाम्ब्यक व्यवसाय बनी हुई है। भूमि का उप-विभाजन व अपखण्डन ही इसके लिए उत्तरदायी हैं।

उपविभाजन व अपखण्डन के कारण—

(1) जनसंख्या की वृद्धि, (2) उत्तराधिकार के नियम, (3) संकुल परिवार प्रथा का अन्त, (4) कुटीर उद्योगों का ह्रास, (5) भूमि के प्रति मोह तथा (6) भूमि को साभे पर देने की प्रथा।

हानियाँ—उत्पादन लागत में वृद्धि, कृषि सुधारों का सम्भव न होना, बाढ़-पेड़ की कठिनाई, यान्त्रिक खेती असम्भव, निगरानी की कठिनाई, समय, खम और धन का अपव्यय, ऋणों और मुकदमेदाजी, पूंजी मिलने में कठिनाई, गहरी खेती में कठिनाई, खेती का असुविधाजनक तथा भूमि का बेकार होना ।

लाभ—किसान की आर्थिक संकट से रक्षा, भूमि की विभिन्नता का लाभ, पूंजीवादी कृषि का न पनप सकना ।

समस्या का उपचार—भूमि पर जनसंख्या के भार में कमी, उत्तराधिकार के नियमों में परिवर्तन, चक्रवन्दी, बानून द्वारा आर्थिक जोतों का निर्माण, जोतों का सीमा निर्धारण तथा सहकारी कृषि ।

सरकार आर्थिक जोतों के निर्माण के प्रति जागरूक है ।

## प्रश्न

1. भारतीय अर्थ व्यवस्था में कृषि जोतों के उपविभाजन व अपखण्डन के कारणों का उल्लेख कीजिये । इसके दोषों का वर्णन करते हुए उपायों पर प्रकाश डालिए ।
2. भूमि के उपविभाजन एवं अपखण्डन के कारण बताते हुए समस्या को सुलझाने के उपायों का विवेचन कीजिये ।
3. उप-विभाजन एवं अपखण्डन के दोषों को दूर करने के लिए भारत में किए गये प्रयत्नों का उल्लेख कीजिये ।
4. टिप्पणियाँ लिखिए—(अ) चक्रवन्दी (Consolidation) (राज. बोर्ड, हा. से. 1964) (ब) आर्थिक जोत (Economic holdings), (ग) सीमा (Ceiling) निर्धारण ।
5. "छोटी सतार्थिक जोतें ही कृषि विकास में माने वाली अनेक कठिनाइयों की जड़ हैं ।" इस उक्ति की व्याख्या कीजिए ।

(राज. बोर्ड, हा. से., 1961 तथा 1964)



6. भूमि के उप-विभाजन व विनष्टन का क्या अर्थ है ? इसके परि-  
णामों को समझाइये । (रात्र. बोर्ड, हा. से., 1966)

7. संश्लिष्ट टिप्पणियाँ लिखिए—

(अ) कृषि जोतों की खादबन्दी (रात्र. बोर्ड, हा. से., 1968)

(आ) सहकारी कृषि ।

8. भारत में भूमि के उपविभाजन तथा धरापतन के कारणों का  
विवेचन कीजिये ।

(रात्र. बोर्ड, हा. से., 1969)

## अध्याय 4 कृषि के साधन ]

### AGRICULTURAL INPUTS—I

“मेरे अनुमान से पुगना हल पिछले 2000 या 3000 वर्षों से काम चला रहा है। मुझे मालूम नहीं कि कितने समय से यह प्रयुक्त हुआ है।” यदि आप बहुत अच्छा हल खाते हैं तो बेल इतने बलवान नहीं कि वे उसे खींच सकें। लेकिन ये सब ऐसी समस्याएँ हैं जिनका हल निकासी जा सकता है।”

—श्री अयाहूर साल नेहक

भारत की कुल जनसंख्या का 69.8 प्रतिशत भाग कृषि पर निर्भर है। यह हमारी जनसंख्या के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन है, और कृषि से राष्ट्रीय आय में बहुत योगदान मिलता है। सन् 1967-68 में कृषि से राष्ट्रीय आय का 53.1 प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ। किन्तु कृषि सामंदायक व्यवसाय नहीं है। इन्हीं बड़ी जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी होने पर भी हमें विदेशों से अनाज मंगाना पड़ता है। विश्व के अन्य देशों की अपने व्यवसायों के अध्ययन से पता चलेगा कि अमेरिका में केवल 13 प्रतिशत, कान्ट्रेलिया में 12 प्रतिशत, कनाडा में 15 प्रतिशत और फ्रांस में 25 प्रतिशत, जनसंख्या ही कृषि पर अवलम्बित है और भी वे अपने व्यवसायों स्वावलम्बी हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद भी वही से लाखों टन अनाज दूसरे देशों को भेज दिया जाता है। इसके अतिरिक्त भारत की तुलना में विश्व के अनेक देशों का प्रति एकड़ औसत उत्पादन कहीं अधिक है। इन सब तथ्यों से स्पष्ट है कि भारतीय कृषि उन्नत अवस्था में नहीं है। तीसरे अध्याय में हमने कृषि के पिछड़ेपन के कारणों का विस्तार से अध्ययन किया था। इन

कारणों में से अधिकांश ऐसे हैं जो कृषि के साधनों (Agricultural Inputs) से सम्बन्ध रखते हैं। इस अध्याय में हम उन साधनों का विस्तृत अध्ययन करना चाहेंगे जो कृषि की उन्नति को प्रभावित करते हैं।

**कृषि के साधनों का महत्व**—परांप्रणीत कृषि के लिए कृषि-साधनों का महत्व अधिक है। जिसे अर्थ व्यवस्था में कृषि साधन उन्नत व्यवस्था में है उस अर्थ व्यवस्था की विकास की दर (Rate of growth) संतोषजनक होती है। यहाँ प्रति एकड़ घनित उत्पत्ति घटिक होती है और उत्पादन की लागत (Cost of production) काफी कम होती है। कृषि साधनों से सम्पन्न देशों में कृषि लाभदायक (Profitable) व्यवसाय होता है और वह राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योग देती है। इसके विपरीत जहाँ ये साधन पिछड़ी हुई अवस्था में होते हैं वहाँ कृषि लाभदायक व्यवसाय बन जाता है।

भारतवर्ष में कृषि विकास की अत्यन्त आवश्यकता है। कृषि विकास के बिना औद्योगिक विकास की गति को तीव्र नहीं बनाया जा सकता। इन सब दृष्टियों से कृषि साधनों का पर्याप्त मात्रा में होना बहुत आवश्यक है।

**कृषि के साधन**—भारतीय कृषि साधनों के अन्तर्गत उन्नत बीज, उर्वरक, कृषि उपकरण, पशु, सिंचाई की सुविधाएँ तथा साख सुविधाएँ सम्मिलित की जाती हैं। इनका कृषि विकास से बहुत गहरा सम्बन्ध है। इस अध्याय में हम उन्नत बीज (Improved Seed), उर्वरक (Fertilizers), कृषि उपकरण (Agricultural implements) तथा पशुओं (Animals) के सम्बन्ध में विचार करेंगे। सिंचाई एवं कृषि साख का अध्ययन आगामी दो अध्यायों में किया जाएगा।

**उन्नत बीज (Improved Seed)**—उत्तम बीजों का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना कृषि विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है। यह कृषि सुधार की विधियों में सबसे सरल एवं कम खर्च वाली है। उन्नत

बीजों को अपनाने से कृषि पैदावार में 10 से 15 प्रतिशत वृद्धि की जा सकती है। उत्तम बीजों के चुनाव, शकर बीजों (Hybrid Seeds) के प्रयोग एवं उन बीजों के प्रयोग करने से सम्बन्धित जानकारी का प्रसार कृषि विकास में महत्वपूर्ण योग देता है।

भारतीय कृषक उन्नत बीजों का महत्व जानता है। किन्तु अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण वह अपने ही संग्रहित बीजों का प्रयोग कर लेता है जो प्रायः घटिया किस्म के होते हैं। अब तक अधिकांश किसान स्थानीय (Local) किस्म के बीजों का ही प्रयोग करता रहा है। ये बीज न अच्छी प्रकार से साफ हो किये जाते हैं और न इनका उचित संग्रह ही किया जाता है जिससे इनकी किस्म धीरे-धीरे घटिया हो जाती है। बीज बोने के समय कृषक के पास अच्छा बीज सरोदने के लिए पैसा नहीं होता और वह साहूकार से घटिया बीज ही उधार पर सरोदने को बाध्य हो जाता है।

पिछले कुछ वर्षों से सुधरे हुए बीजों के विनिरण एवं गुणन (Multiplication) के कार्य में कृषि विभाग एवं अन्य राजकीय संगठन कार्य कर रहे हैं। किन्तु बीज देने की प्रक्रिया अत्यन्त जटिल होने के कारण अधिकांश कृषक इसमें साथ नहीं उठा सके हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बीज गुणन एवं वितरण का व्यवस्थित कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। इस अवधि में 3,600 बीज-गुणन केन्द्र (Seed Multiplication Centres) खोले गये। तृतीय योजना के अन्त तक साठान्तों के उन्नत बीजों का प्रयोग 4.86 करोड़ हेक्टर क्षेत्रफल में होने लगा था। चतुर्थ योजना में यह क्षेत्रफल बढ़कर 9.75 करोड़ हेक्टर हो जाने का लक्ष्य है। इस योजना में चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा तथा मक्का के उन्नत बीजों का प्रयोग बढ़ाया जाएगा।

उन्नत बीजों का प्रयोग बढ़ाने के लिए निम्नांकित उपाय काम में लाये जाने चाहिये—

1. बीज-गुणन केन्द्रों की संख्या में वृद्धि की जाए ।

2. उत्तम बीजों के प्रयोग सम्बन्धी जानकारी कृषकों को दी जानी चाहिए ।

3. अच्छे बीज रिपायरी दर पर कृषकों को दिये जाने चाहिए ।

4. उत्तम बीजों के प्रदर्शन फार्म (Demonstration Farms) स्थापित किये जाने चाहिए ।

5. अच्छे बीजों को सग्रह करने के लिए गोदामों (Godowns) की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

6. प्रत्येक विकास मण्ड एवं जिला स्तर पर बीज भण्डार स्थापित किये जाने चाहिए जो फसल पैदा होने तक कृषकों को ये बीज उपहार दे सकें ।

7. बीजों के घुणोकरण (Gradation), प्रमाणीकरण (Standardisation), आदि की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए ।

8. केन्द्रीय स्तर पर गठित "राष्ट्रीय बीज निगम" की भांति राज्य एवम् जिला स्तर पर ऐसे संगठन स्थापित किये जाने चाहिए ।

9. विभिन्न राज्यों में भारतीय कॉटन मिल फेडरेशन द्वारा संचालित कपास विकास योजना (Cotton Development Project) की ही भांति अन्य निजी संगठनों द्वारा उत्तम बीजों के प्रसार की योजनाएँ चलायी जानी चाहिए ।

**खाद एवं उर्वरक (Manures and Fertilizers)—**

भारतवर्ष की मिट्टियों में अनेक उर्वरा तत्वों का अभाव हो गया जिसकी पूर्ति खाद व उर्वरकों से की जा सकती है । गोबर की खाद, कम्पोस्ट की खाद, आदि कुछ परम्परागत खादें हैं जिनका विस्तृत

प्रयोग अनेक कारणों से सम्भव नहीं हैं। इसलिए रासायनिक उर्वरकों (Chemical Fertilizers) का उपयोग करना अत्यन्त आवश्यक है। यहाँ हम खाद एवं उर्वरकों की कुछ मुख्य विशेषों एवं उनकी वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में विचार करेंगे—

(अ) गोबर की खाद (Cow dung manure or Farm Yard manure)—गाय-बैलों से प्राप्त होने वाली गोबर की खाद अन्य प्रकार के खादों की तुलना में अत्यधिक नाइट्रोजन रखती है। कमल की पैदावार में वृद्धि के लिए आवश्यक सभी तरह इसके मोहूद होते हैं। लगभग पिछले 100 वर्षों में विभिन्न विद्वानों, आयोगों व समितियों ने इसके दुरुपयोग की खर्षा की है। अधिकांश गोबर का प्रयोग घरों में ईंधन के रूप में जलाने के लिए कर लिया जाता है क्योंकि गाँवों में जलाने की लकड़ी की कमी है। योजना आयोग के प्रतिबन्ध जलाये जाने वाले गोबर की मात्रा 400 मिलियन टन मानी है। इसके अतिरिक्त जो गोबर खाद बनाने के लिए काम में लाया जाता है उसका संप्रसारण का तरीका भी दोषपूर्ण है। इसलिए कुल गोबर का लगभग 20 प्रतिशत भाग नष्ट हो जाता है।

गोबर की खाद का पूर्ण सदुपयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि (1) गाँवों के नजदीक भीम उगने वाले वृक्ष, ईंधन प्राप्त करने लिए लगाए जाने चाहिये। (2) किसानों को खाद संग्रहित रखने के लिए गड्ढे (Manure pits) बनाने और पशुओं के दूध देने जाने वाले मूत्र व गोबर को संप्रसारण करने के तरीकों की जानकारी दी जानी चाहिये।

(ब) कम्पोस्ट द्वारा खाद—घास एवं जड़ों के कूड़े-कचरा, बाग, बगीचा व मड़ा कर यह खाद संसार की जाती है। मड़ा की गतिधियों के पानी से भी खाद संसार की जाती है। भारत में इस प्रकार की खाद

का उत्पादन बढ़ रहा है। सन् 1965-66 में सामुदायिक विभाग गंधों में 54,13,400 कम्पोस्ट के गड्ढे (Compost pits) भोड़े गये। सन् 1968-69 में ग्रामीण कम्पोस्ट खाद का उत्पादन 14.8 करोड़ टन होने का अनुमान है।\*

भारत में इन प्रकार के खाद के उत्पादन में अधिक प्रगति नहीं हो पायी क्योंकि उचित प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव है। इसके अतिरिक्त जनता के सहयोग की कमी, किसानों द्वारा इसके प्रति प्रयास की भावना, माता-पिता की कठिनाई आदि कारणों से भी कम्पोस्ट की खाद बनाने के कार्य में अधिक प्रगति नहीं हुई। इन सब बातों को दूर करने के प्रयत्न कर इस खाद के निर्माण को बढ़ाया जाना चाहिये।

(स) दधिर चूर्ण खाद (Manure from Animal waste)—कसाई स्थानों में व्यर्थ जाने वाला पशुओं का दधिर, पशुओं की हड्डियाँ, बाल, आदि का प्रयोग भी खाद के रूप में किया जा सकता है। हड्डियों में फॉस्फेट होती है जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करती है। मछली के बचे हुए पदार्थों का उपयोग भी खाद बनाने के लिए किया जा सकता है। किन्तु भारतवर्ष में ऐसे खादों को बनाने एवं प्रयोग करने की प्रवृत्ति कम पाई जाती है। इसके मूल में परम्परागत धार्मिक विचार हैं जिनके कारण ये उर्वरता के इन उपयोगी साधनों का प्रयोग नहीं करते।

(द) हरी खाद (Green manure)—भारत में हरी खाद का प्रयोग अत्यन्त प्राचीन काल से ही होता आया है। यह मिट्टी में नमी बनाए रखने हेतु सर्वोत्तम है। इसमें सन्, चना, ज्वार, आदि खेत में बोए जाते हैं और जब पौधे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उन्हें हार्व किया जाता है। ऐसा करने से मिट्टी में नाइट्रोजन व अन्य तत्व प्राप्त हो जाते हैं जो कृषि पैदावार में भारी वृद्धि कर देते हैं। भारत में इसका अधिक प्रयोग नहीं हो पाता। सन् 1968-69 में हरी खाद का क्षेत्र 1.03 करोड़ हेक्टर हो जाने का अनुमान है।

\*India 1969, p. 235

(घ) रासायनिक उर्वरक (Chemical Fertilizers)—ऊपर बनावे गये विभिन्न खाद भारत की कृषि आवश्यकताओं की प्रांशिक पूर्ति ही कर पाते हैं। अतः पिछले 15 वर्षों से हमारे यहाँ रासायनिक खाद का प्रयोग बढ़ना जा रहा है। अब इन उर्वरकों की महत्ता से किसान सुपरिचित हैं। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उपयोग सन् 1968-69 में 14 लाख टन था जो सन् 1969-70 में बढ़कर 20 लाख टन हो आया। फास्फोरस युक्त उर्वरक का उपयोग सन् 1968-69 में 24 लाख टन हुआ।\* किन्तु इससे भी इस मात्रा से कहीं अधिक है। चौबी योजना में पोटाश का उर्वरक के रूप में प्रयोग भी बढ़ाया जायेगा।

उर्वरकों का उत्पादन मुख्य रूप से सिन्दरी फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, नागपुर, मेवेल्ली, टांघे तथा राऊरकेला के कारखानों में होता है। हमारे देश में आवश्यकता से कम उत्पादन होने के कारण उर्वरकों का आयात करना पड़ता है। इनको कीमत भी अधिक है। इन कृषि उर्वरकों के प्रयोगों के सम्बन्ध में कुछ अज्ञानता अब भी फैली हुई है। यतः इनके प्रयोग की सही विधि का ज्ञान कृषकों को कराया जाना चाहिये। उर्वरकों का मौतरिक उत्पादन बढ़ाने के हर संभव प्रयत्न किये जाने चाहिये ताकि इनकी कीमतें भी कम हो सकें सरकारी संस्था 'भारतीय खाद निगम' (Fertilizer Corporation of India) के कारखाने में नये कारखाने बनाये जायेंगे। उर्वरक विनरल ऑयल समिति ने उर्वरकों की विनरल व्यवस्था में सुधार लाने के निश्चय में काम करने व उत्तमता पर ध्यान देने की सिफारिश की है। किसानों को उर्वरक खरीदने के लिये ऋण भी दिये जाने चाहिये।

उत्प्रेत सारों के अलावा गिलहन एवम् खली की खाद मानवीय एवं पशुओं में निविन खाद, आदि भी प्रयोग की जाती है किन्तु इनका सेव प्रारम्भ सीमित है।



भारत में खाद के अधिकाधिक प्रयोग की आवश्यकता है जिससे कृषि की प्रति एकड़ पैदावार में वृद्धि लाई जा सके। कहा जाता है—  
‘खाद पड़े तो खेत, नहीं तो कूड़ा खेत।’

### कृषि उपकरण (Agricultural Implements)

भारत में अब तक भी प्राचीन काल से चले आ रहे यंत्रों एवं उपकरणों का प्रयोग होता है। कृषि के विद्युद्धारण के लिये ये उपकरण भी उत्तमदायी हैं। भारतीय कृषि औजारों की चर्चा करते हुए श्री डार्लिंग (Darling) ने कहा है—“हल भूमि को केवल कुदे देता है; हाथ की दराती जो कृषक की अपेक्षा बालक के लिए अधिक उपयुक्त प्रतीत होती है; पुराने ढंग की टोकरी से हवा द्वारा मूछे को चलान किया जाता है और गन्नासा जिसके प्रयोग से बहुत सा चांग नष्ट हो जाता है, आज भी अपने प्राचीन किन्तु अविस्मरणीय कार्यों पर जमे हुए हैं।”

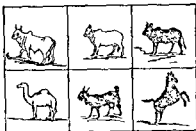
इन सब बातों से कृषि औजारों का विद्युद्धारण प्रसट होता है पर-  
म्परागत औजारों के स्थान पर सुधरे हुए औजारों की प्रतिष्ठित करने की अत्यन्त आवश्यकता है। भारतीय कृषि में कृषि की वैज्ञानिक एवं सामुदायिक बनाने की दृष्टि से औजारों में सुधार लाने की आवश्यकता है। कृषक इनका साधनहीन है कि वह स्वयं सभी औजार नहीं खरीद सकता। इसलिए गृहकारी समितियों द्वारा सामूहिक रूप से खर्च प्राप्त कर उन्हें बारी-बारी से काम में लाने की व्यवस्था की जानी चाहिये। नये औजारों के माध्यम-माध्य कृषि की पद्धति में परिवर्तन लाने आवश्यक है। चौकी योजना से विभाजन पर कृषि औजार केन्द्र (Agricultural Implements Centre) स्थापित किये जाने की आवश्यकता है। सुधरे हुए औजारों से सम्बन्धित प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जायेगी।

### पशु (Animals)—

हमारे देश की अर्थ व्यवस्था के बारे में कहा जाता है कि “भारत बैलचारी दुग्ध में रह रहा है।” यह कथन हमारी कृषि के विद्युद्धारण के

भारे में हो जाता है। यह भी स्पष्ट होता है कि हमारी धर्म-  
व्यवस्था में बैल का बहुत अधिक महत्व है। बैल के अतिरिक्त घोड़ा,  
ऊँट, बकरी, भेड़, गाय आदि कृषक के लिए बहुत उपयोगी हैं। पशु-  
पालन व्यवसाय, यातायात, सिंचाई, जुताई, बुवाई आदि में पशु शक्ति  
का बहुत महत्व है।

भारत में पशुओं की संख्या अत्यधिक है। यहाँ प्रति 40.3 हेक्टर (100 एकड़) जोती-  
बोई भूमि के पीछे 97 पशु हैं। सन् 1961 की पशु गणना के अनुसार देश में कुल पशुओं की



भारत के पशु

संख्या 33.6 करोड़\* थी। हमारी ग्रामीण धर्म-व्यवस्था में पशुओं का महत्व थी एम. एल. ब्राह्मण के शब्दों से स्पष्ट प्रकट होता है—“पशुओं के बिना किसान के खेत नहीं जोते जा सकते, उनके खलिहान खाली पड़े रहते हैं, घोर खाने पीने में स्वाद अशुभ रह जाता है, क्योंकि शाकाहारी देश में भी, दूध और भक्षण त मिलने से अधिक दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है ?”

भारतीय पशु दुर्बल एवं अकुशल हैं। इसके मुख्य कारण हैं—“भारे की बर्मी, हल्की नस्ल, पशु रखने के दोषपूर्ण ढंग, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, बीमारियाँ तथा पशुओं के स्वास्थ्य की अवहेलना। जयार घोर बेरी के शब्दों में, “भारत में पशुओं से केवल अधिक काम ही नहीं लिया जाता, इसके साथ-साथ उन्हें मर पेट भोजन भी नहीं दिया जाता। यहाँ तो बर्दाश्त ही कोई किसान अपने पशु को स्वस्थ

रखने का प्रयास करता दिखाई देता है।" किन्तु सब पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा पशु-धन उन्नत करने के कई प्रयत्न हो रहे हैं। चतुर्थ योजना में पशु-पालन के लिए 91० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

पशुओं की हीन दशा में सुधार लाने के उपायों में घारे को कमो से दूर करना, नम्ल सुधार के कार्यक्रमों को अपनाना, पशुओं के रोगों को रोकथाम करना आदि उल्लेखनीय हैं।

उक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि भारत के कृषि-साधनों को उन्नत रिये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है। कृषि साधनों की उन्नति के बिना कृषि विकास सम्भव नहीं है।

### सारांश

भारत की कुल जनसंख्या का 69.8 प्रतिशत भाग कृषि पर निर्भर है। कृषि हमारी जनसंख्या के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन है। तथा तसे राष्ट्रीय आय में भी बहुत योगदान मिलता है। किन्तु हमारी कृषि अत्यन्त पिछड़ी अवस्था में है।

वि के साधनों का महत्व—

विकास की दर संतोषजनक, औसत उत्पत्ति अधिक, उत्पादन लागत कम, लाभदायक व्यवसाय, राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योग।

वि के साधन

(1) उन्नत बीज, (2) खाद एवं उर्वरक—(अ) गोबर की खाद, (ब) कम्पोस्ट द्वारा खाद, (ग) श्वित् चूर्ण खाद, (द) हरी खाद, (3) रासायनिक उर्वरक। (3) कृषि उपकरण, (4) अन्य पशु।

संक्षेप में, कृषि विकास के लिए उन्नत कृषि-साधनों की आवश्यकता है।

## प्रश्न

कृषि साधनों का महत्व स्पष्ट कीजिये ।

भारतीय कृषि को उन्नत बनाने के लिए किन-किन साधनों को उपयोग में लाना चाहिये ?

भारतीय कृषि की उन्नति के सुझाव दीजिये ।

(राज. बोर्डे, हा. से., 1967)

टिप्पणी लिखिये—

(अ) खाद एवं उर्वरक

(ब) उन्नत बीज ।

## अध्याय 5

# कृषि के साधन II

## AGRICULTURAL INPUTS—II

भारतवर्ष में सिंचाई

(IRRIGATION IN INDIA)

“भारत की मिट्टी के लिए पानी जादू का काम करता है।”

डॉ० बाँसकर

“सिंचाई सम्बन्धी कार्यों ने जीवन को सुरक्षित बनाया है। इनसे उत्पादन, भूमि के मूल्य एवम् राजस्व की वृद्धि हुई है। इसने दुर्भिक्ष सम्बन्धी व्यय को कम कर दिया है।”

—धीमती नविलता

भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है कृषि के लिए यह आवश्यक है कि कृषक उत्तम बीज (seeds), खाद (manure) तथा भूमि का अच्छी तरह प्रयोग करें, किन्तु उचित और नियमित रूप से पानी मिले बिना खेती की अच्छी पैदावार नहीं हो सकती। उत्तम पैदावार के लिए पर्याप्त मात्रा में समयानुसार पानी की आवश्यकता होती है। भारतवर्ष में पानी दो प्रकार से प्राप्त होता है—(1) मानसूनी हवाओं द्वारा, जो इस देश में कुछ महीनों में ही चलती हैं, और (2) सिंचाई के साधनों द्वारा। देश की खेती के लिए पानी की कुल आवश्यकता का लगभग 90 प्रतिशत भाग इन्हीं मानसूनी हवाओं द्वारा प्राप्त किया जाता है। इन्हीं हवाओं द्वारा देश के अधिकांश भागों में वर्षा होती है। पश्चिमी समुद्री तट व बंगाल के पश्चिमी भागों में वर्षा की अधिकता के कारण सिंचाई के साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती, परन्तु देश के

अन्य भागों में वर्षा की मात्रा, समय तथा स्थान अनिश्चित है। यदि इन स्थानों में वर्षा समय पर हो जाती है तो पैदावार भी अच्छी होती है, अन्यथा नहीं।

### सिंचाई की आवश्यकता (Need of Irrigation)

सन् 1815 में लार्ड हेस्टिंग्स ने भारत के लिए सिंचाई की योजनाओं की बड़ी आवश्यकता प्रकट की थी। सन् 1850 में लार्ड क्लाइवी ने लिखा था, "मैं सर्वत्र देखता हूँ कि इस देश की जमीन में उपजाऊपन विरल है, निम्न बहुत बर्बाद पड़ी है। इन मैदानों को बहुमुख्य क्षेत्रों में परिवर्तित करने के लिए केवल जल की आवश्यकता है।" ब्रिटिश सरकार ने सिंचाई के साधनों की उन्नति पर बहुत कम ध्यान दिया।

कृषि-उत्पादन बढ़ाने के लिये जल की प्राप्ति की अत्यन्त आवश्यकता है। भारत ने अपने प्राकृतिक साधनों का अब तक पूरा सदुपयोग नहीं किया है। परिणाम यह है कि करोड़ों व्यक्ति अनेक घातनाओं से ग्रस्त रहते हैं। प्रति वर्ष देश की अनाज (famine) और बाढ़ों (floods) का सामना करना पड़ता है। जो देश आधे दिन प्रकृति के प्रकोपों का सामना बने, वह कैसे बन सकेगा? प्रकृति की इस स्याई धमकी (Permanant threat) का एक ही उपाय है और वह है नदियों के जल का उपयोग। जल समुद्र में बहकर जाता है या जमीन में नष्ट हो जाता है उसका विनाश बांधों द्वारा सदुपयोग करना चाहिये। साथ ही जो नदियाँ मार्ग बदलकर दूसरे प्रांतों को छूती हैं उनके मार्गों पर नियंत्रण करना चाहिये।

हमारे देश के लिए सिंचाई की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से स्पष्ट है—

1. वर्षा की अनिश्चितता (uncertainty) — हमारे देश में वर्षा असावधिक (untimely) तथा अनिश्चित होती है। कभी अनिवृष्टि तो कभी अनावृष्टि (draught) और प्रायः इनके कारण देश के कई

स्थानों में दुमिस्त पड़ जाते हैं। अतिवृष्टि और अनावृष्टि दोनों ही हानिकारक हैं। किसान की आय का एक मात्र साधन-कृषि-उत्पाद हो जाता है।

### निचाई की आवश्यकता के कारण

1. वर्षा की अनिश्चितता
2. वर्षा का असमान वितरण
3. सर्दियों में वर्षा का अभाव
4. कुछ फसलों को अधिक पानी की आवश्यकता
5. घसालों से रक्षा
6. बढ़ती हुई जनसंख्या

मात्रा में होती है। इसके विपरीत ऐसे स्थान भी हैं जैसे, औद्योगिक मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा तथा दक्षिणी भारत के पठार, जहाँ पर वर्षा अनिश्चित है और कम मात्रा में होती है।

3. सर्दियों में वर्षा का अभाव—मद्रास में कुछ दिनों को छोड़कर जाड़े के दिनों में प्रायः वर्षा का अभाव रहता है। जल: जाड़े की फसल के लिये कृषि साधनों द्वारा निचाई करना निरान्न आवश्यक है। निचाई के साधन मिलने पर कृत्रिम मिश्र-मिश्र प्रकार की फसलें पैदा कर सकेगा। सेहू, चना, आदि फसलें जो जाड़े की फसलें हैं, निचाई के साधनों के बिना नहीं उगाई जा सकती।

4. कुछ फसलों को अधिक पानी की आवश्यकता होती है—गन्ना, चावल, पटसन (Jute), आदि फसलों को अत्यधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। दक्षिण-पश्चिम मानसून का पानी हमेशा अनिश्चित ही रहता है। जल के कमजोर दिनों अधिक पानी की आवश्यकता होती है, कृषि निचाई साधनों के बिना नहीं उगाई जा सकती।

5. अकालों से रक्षा—सिंचाई के साधन देश में अकाल पड़ने को रोक कर हमारी रक्षा करते हैं ।

6. बढ़ती हुई जनसंख्या—देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को पाने और अन्य प्रकार की वस्तुओं की बढ़ती माँग की पूर्ति करने के लिए भी सिंचाई के साधन आवश्यक हैं ।

अतः भारत जैसे विशाल देश की उपजाऊ भूमि का सिंचाई के बिना उपयोग उठाना असम्भव है । वर्षा पर निर्भरता बहुत हानिकारक है । देश में पानी हो सब कुछ है ।

भारत में सिंचाई की सुविधाएँ (Irrigation facilities in India)

1. भारत कृषि-प्रधान देश है और यहाँ की 69.8 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आश्रित है । कृषि की उत्तम पैदावार के लिये सुव्यवस्थित सिंचाई के साधनों का होना अत्यन्त आवश्यक है और इन साधनों की सुविधाएँ देश को प्राप्त हैं ।

2. सिंचाई के साधनों के लिये हमारे देश में प्रकृति ने बड़ी सहायता प्रदान की है । देश की भूमि का अधिकांश भाग ऐसा है जिसमें वर्षा का जल सन्दरभ बना जाता है । आवश्यकता पड़ने पर यह जल पौधों द्वारा निष्कासित जा सकता है । हमारे देश की मिट्टी नरम होने के कारण बृष्ट जल सोखने के लिए उपयुक्त है ।

3. भारतवर्ष के उत्तरी मैदान में नदियों का जाल सा बिछा हुआ है और साथ ही यह मैदान समतल और बालू होने के कारण नहरें खोदने के योग्य भी है । भूमि के नरम होने के कारण खोदने में असुविधा नहीं होती ।

4. उत्तरी भारत की प्रायः सभी नदियाँ हिमालय की हिमश्रृङ्खला की चोटियों से निकलती हैं, अतः सदैव जल से पूर्ण रहती हैं । वर्षा के दिनों में जब वर्षा विचलती है तो इनमें पानी निरन्तर बढ़ता है और वे भूमि में नहीं पाती । नदियों के जलपूर्ण रहने के कारण इनमें



निकाली जाने वाली नहरों को भी पानी मिलता रहता है और इन नहरों का पानी आवश्यकतानुसार सिंचाई के लिये उपयोग किया जाता है।

5. देश के विभिन्न भागों में, विशेषकर दक्षिणी भाग में, वर्षा का पानी तात्कालिक बनाकर रोका जा सकता है।

6. देश के कई भागों में कृषि बनाने की बहुत सम्भावनाएँ हैं।

### सिंचाई से लाभ (Advantages of Irrigation)

भारतवर्ष जैसे कृषि प्रधान देश में, जहाँ 69.8 प्रतिशत जनता खेती

#### सिंचाई से लाभ

1. अकाल से बचाव
2. निरन्तर खेती
3. प्रति हेक्टर उपज में वृद्धि
4. विस्तृत खेती सम्भव
5. जनसंख्या का ठीक बंटवारा
6. विशेष फसलों का उत्पादन
7. किसानों की आय में वृद्धि
8. आवागमन के साधनों में वृद्धि
9. सरकार की भाय में वृद्धि
10. आंतरिक व विदेशी व्यापार में वृद्धि
11. देश के उद्योग धर्मों को प्रोत्साहन
12. नहरी खेती-कृषि भाय में वृद्धि

उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है।

3. उपज में वृद्धि—सिंचाई साधनों द्वारा आवश्यकतानुसार पानी मिलने से भी भूमि की प्रति हेक्टर उपज में वृद्धि होती है, और साथ ही गुण उपज बढ़ती है।

पर निर्भर है। और जहाँ खेती की सफलता का प्रभाव व्यापार, उद्योग वाणिज्य तथा सारे देश के आर्थिक जीवन पर पड़ता है, सिंचाई के साधनों का बड़ा भारी महत्व है। सिंचाई के मुख्य लाभ निम्न हैं—

1. अकाल से बचाव—सिंचाई अकाल से बचने का अनुपम साधन है। सिंचाई के साधन होने से भारतीय कृषि वर्षा का जुमा नहीं रहेगी।

2. निरन्तर खेती (Continuous cultivation)—सिंचाई से वर्ष भर निरन्तर खेती का व्यवसाय चलता रहता है और कई प्रकार की फसलें उत्पन्न कर साथ के

4. विस्तृत, खेती सम्भव (Extensive cultivation)—खेती की भूमि के लिये क्षेत्र में वृद्धि होती है। शुष्क परती और बंजर (barren) भूमि पानी से खेती के योग्य बन जाती है। इस प्रकार लाखों एकड़ अतिरिक्त भूमि खेती के प्रयोग में आ गई है और खेती का प्रसार हुआ है।

5. जनसंख्या का बंटवारा—पानी आवादी वाले भागों से सिंचाई की सुविधाओं वाले नये भागों में मनुष्य जाकर बस जाते हैं, जैसे नहरों के किनारे बस्तियाँ (Canal Colonies) बस गई हैं।

6. विशेष फसलों की उपज सम्भव—सिंचाई से चावल, गन्ना, कपास, आदि कीमती फसलें जिनकी अधिक व बार-बार पानी की आवश्यकता होती है, पैदा हो सकती हैं। ये फसलें देश के लिये बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनसे किसानों की आय बढ़ती है।

7. कृषकों की आय—किसानों की आय, सुसहली, कयशक्ति और रहन-सहन के स्तर में वृद्धि होती है।

8. आवागमन के साधनों में वृद्धि—कुछ नहरें सिंचाई के अतिरिक्त आवागमन के लिये भी उपयुक्त साधन होती हैं, जिनसे माल एवं यात्री सस्ते किराये पर इधर-उधर पहुँचाये जा सकते हैं।

9. सरकार की आय में वृद्धि—सिंचाई सुविधाओं के फलस्वरूप परती जमीन बिकने से, पानी से, लमान से, रेलों के मुताफे बढ़ने से, प्रजा की साय और कर देने की शक्ति बढ़ने आदि से सरकार की आय बढ़ती है। साथ ही अकाल पर किये जाने वाले खर्च की बचत होती है क्योंकि अकाल नहीं पड़ते हैं।

10. व्यापार में वृद्धि—उत्पादन बढ़ने से देश के आन्तरिक तथा विदेशी व्यापार में वृद्धि होती है।

11. उद्योग धन्यों को प्रोत्साहन—कच्चा मूल्य अधिक और सस्ता मिलने से तथा वस्तुओं का उपयोग व माँग बढ़ने से उद्योग धन्य पनपते हैं और देश की उन्नति होती है ।

12. गहरी खेती—सिचाई से गहरी (Intensive) खेती संभव होती है जिससे कृषि उत्पादन और आय बढ़ती है ।

### हानियाँ (Disadvantages)

1. जल प्लावन (Water logging)—नहरों के बनने से कभी-कभी भूमि में पानी की अधिकता हो जाती है जिससे कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाएँ होने लगती हैं । इनके कारण उपज की मात्रा और किस्म को हानि होती है ।

#### सिचाई से हानियाँ

1. पानी की अधिकता
2. भूमि क्षार
3. कीचड़, दल-दल, रोग
4. पानी वितरण समस्या
5. जन-धन की हानि

#### 2. भूमि बेकार होना—

पानी की अधिकता से कालान्तर में भूमि बेकार हो जाती है । भूमि पर क्षार (salt effervescence) फैल जाता है और पौधे नहीं पनप सकते । पंजाब में इस कारण से

हजारों हेक्टर उपजाऊ भूमि खेती के अयोग्य हो गई है ।

3. बीमारियाँ—नहरों के आस-पास कीचड़ और दल-दल रहने से मलेरिया व अन्य संक्रामक बीमारियों के कीड़े उत्पन्न होकर बीमारियाँ फैलना बहुधा पाया जाता है ।

4. नहरों के पानी की किसानों में वितरण करने की समस्या—बहुत सा पानी बेकार नष्ट होता है और पानी के बँटवारे के लिये किसानों में ईर्ष्या-द्वेष और झगड़े होते हैं ।

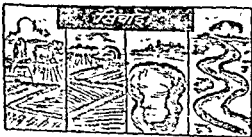
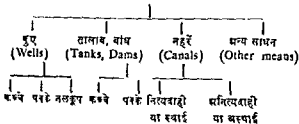
5. प्राकृतिक हानि—कभी कभी नहरें या तालाब टूटने से जन धन की क्षति हो जाती है ।

सिंचाई के अनगिनत साधन हैं। सिंचाई की व्यवस्था और साधनों में भारतीय कृषि को निश्चित, अच्छा और सफल बनाने में बहुत सहायता दी है। भूमि की उपज को बढ़ाकर और उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि की उन्नति को प्रोत्साहन देकर देश में सम्पन्नता बढ़ाने में सहायता दी है। सिंचाई की हानियों का आसानी से निवारण हो सकता है। सारे देश में सिंचाई के विविध साधनों को खूब बढ़ाना चाहिये, ये देश के हित में हैं।

### सिंचाई के साधन (Means of Irrigation)

देश के विभिन्न भागों में प्राकृतिक भिन्नता के कारण अलग-अलग प्रकार के साधन पाये जाते हैं। मुख्य साधन निम्न हैं—

### कृत्रिम सिंचाई के साधन (Means of Irrigation)



कुएँ (wells) — भारतवर्ष के बहुत से भागों में कुओं द्वारा सिंचाई

सिंचाई के साधन

1. कुएँ (Wells)
2. तालाब (Tanks)
3. नहरें (Canals)
4. अन्य (Others)

होती है। पूर्वी पंजाब, उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग, बंगाल और बिहार का उत्तरी भाग कुओं द्वारा सिंचाई के लिए प्रसिद्ध है। इन कुओं की भूमि में पानी की सतह (water level) ऊँची है और सोने से

## भारत सिंचाई के साधन



जहाँ पर पानी मिल जाता है। अतः इस प्रकार की भूमि  
एँ खोदने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहीं-कहीं पर 2-44  
मीटर (8 या 10 फीट) खोदने पर ही पानी निकल आता  
है। इन जगहों को अधिक ध्यान नहीं करना पड़ता।

वर्ष में कुल लगभग 25 लाख कुएँ हैं जिन पर लगभग 100  
लाखों की लागत लगी है। भारत में कुल सिंचित भूमि के  
लिए पानी पर कुओं से निर्भर होती है। कुएँ प्रायः व्यक्तिगत होते  
हैं। सरकार भी तकावी (Taccavi) ऋण देकर कुओं के बनाने  
में सहायता देती है। 'अधिक घन उपजाऊँ सामंदाहन' (Grow More  
Foods Campaign) के अन्तर्गत हजारों कुएँ बनवाये गये। मोमबत्ती  
2-08 (5 एकड़) भूमि को सींच सकता है और प्रति  
एकड़ अतिरिक्त (additional) उत्पादन होता है।  
कुओं के बनवाने के लिए सरकार सहायताएँ ऋण देती है। सन्  
1947 में सरकार ने साधन बढ़ाने के लिए अमेरिका के विशेषज्ञों  
को राय के अनुसार ट्यूब-वells (tube wells) का निर्माण  
करवाया। पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा बिहार प्रदेश ट्यूब-वells के  
लिए उपयुक्त बताये गये हैं। इन कुओं को खनाने के लिये  
विशेष विज्ञान की है, जिसको प्राप्त करने के लिये भारत में  
विशेषज्ञ भेजे गये हैं। सस्ती विजली से ट्यूब वेल्स निर्माण में  
सिंचाई।

तालाब (Tanks)—तालाब प्रायः राज्य सरकार के होते हैं।  
लगभग 35,000 तालाब हैं और के सभी जातों के हैं।  
हई तालाब अत्यन्त प्राचीन काल के बने हुए हैं तथा कुछ पट  
वत्तः इनको साफ करते रहने (desilting) की आवश्यकता पड़ती  
है। मैसूर, मद्रास और राजस्थान के उदयपुर विभाग में तालाब  
के लिये बनाये गये हैं। इनका मुख्य कारण यह है कि इन  
की भूमि पचरीली तथा खेतों की बनी हुई है और वहाँ तालाब  
से बनाये जा सकते हैं। पिछले कुछ सालों से मद्रास सरकार

ने नये तालाबों के निर्माण और पुरानों की मरम्मत की ओर विशेष ध्यान दिया है। भारत में सिंचित भूमि के लगभग 20% भाग पर तालाब से सिंचाई होती है।

**नहरें (Canals)**—नहरों का निर्माण सर्व-प्रथम मुगलों के शासन काल में हुआ। इन नहरों के द्वारा पानी की कमी किसी हद तक दूर हो गई, किन्तु भारत में नहरों, कुओं तथा तालाबों से सिंचाई के लिये वर्षा काल में ही पानी मिल सकता था और गर्मियों के दिनों में प्रायः सूखा पड़ जाता था। अंग्रेजों ने भारतवर्ष में इस प्रकार नहरें बनवाईं जिनमें वर्ष भर पानी बहा रहता है और किसानों को आवश्यकतानुसार पानी मिल जाता है। सन् 1854 ई० में सबसे पहली नहर गंगा नदी पर बनवाई गई। वर्तमान काल में नहरों द्वारा सिंचाई सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है, किन्तु नहरें सब स्थानों पर नहीं लोरी या मक्खनी और न उनको सब जगह बनाने से लाभ हो हो सकता है। नहरों की गोदों के लिये निम्नलिखित बातों की आवश्यकता है।

(1) भूमि समतल तथा बालू होनी चाहिये। पथरीली तथा उबड़ खाबड़ भूमि में नहरों की सोदना कठिन है और खर्च भी अधिक लगता है।

(2) नहरें उन नदियों से निकाली जायें जो सदैव पानी से भरी रहती हों ताकि नहरों को सदा पानी मिलता रहे। बरसाती नहरें गर्मियों के दिनों में शुष्क हो जाती हैं और सिंचाई के काम की नहीं रहती।

(3) जिस भूमि में होकर नहर निकाली जाय वह मज्झी होनी चाहिये, वरना नहर सोदने का कोई लाभ न होगा।

भारतवर्ष में तीन प्रकार की नहरें मिलती हैं

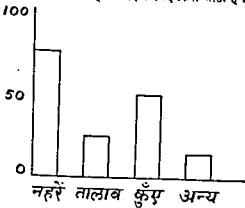
1. स्पर्श नहरें (Perennial canals)—ये सदैव जल से भरी रहती हैं। नदियों में बांध बांधकर पानी एकत्रित किया जाता है और वह पानी फिर नहरों में बहता है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ हिमालय काश में बहते विषमता के कारण जलपूर्ण रहती हैं और इन नदियों से निकलने वाली नहरों में भी जल भर पानी रहता है।

2. बाढ़ाई नहरें (Inundation canals)—इन नहरों में केवल वर्षा में पानी रहता है और वर्ष के शेष महीनों में ये शुष्क रहती हैं। इसलिए इन्हें बाढ़ाई नहरें भी कहते हैं। इनका वर्षा में ही उपयोग किया जा सकता है।

3. तालाबी नहरें—(Storage Works Canals)—किसी घाटी या तराई में बांध बना कर एक बड़ा तालाब बना दिया जाता है। जमा किया हुआ पानी नहरों द्वारा क्षेत्रों तक पहुँचाया जाता है। इन्हें गोदामी नहरें या तालाबी नहरें कहलाती हैं। इस प्रकार की नहरें दक्षिण भारत तथा मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं।

जल क्षेत्र (Irrigated Area)—

हमारे देश में लगभग 15.49 करोड़ हेक्टर भूमि कृषि योग्य है—जिसमें से लगभग 19 प्रतिशत अर्थात् 2.64 करोड़ हेक्टर भूमि पर सिंचाई होती है। † अनुमान लगाया जाता है कि भारत के जल संसाधन लगभग 168 खरब घन मीटर हैं जिनमें से लगभग 5.55 खरब मीटर का प्रयोग ही सिंचाई के लिए किया जाता है। ‡



India 1969, p. 225

India 1969, p. 275



भारत में सन् 1965-66 में सिंचाई के विभिन्न साधनों के अनुसार सींची गई भूमि का क्षेत्रफल इस प्रकार था—

सिंचाई के साधन	कुल सिंचित भूमि का क्षेत्रफल	
	(करोड़ हेक्टर में)	प्रतिशत
नहरें	1.10	41.7
तालाब	0.44	16.6
बुएँ	0.84	31.8
अन्य साधन	0.26	9.9
—योग	2.64	100.0

यह कुल सिंचित क्षेत्रफल 2.64 करोड़ हेक्टर है जो सन् 1950-51 की तुलना में 55 लाख हेक्टर अधिक है। ‡ सन् 1950-51 में सिंचित क्षेत्र 2.08 करोड़ हेक्टर तथा सन् 1955-56 में 2.26 करोड़ हेक्टर था।

बहुमहसोस नदी घाटी योजनाएँ—

भारत निचाली की दृष्टि से संसार के समस्त देशों में आगे है और यही वहाँ निचाली के साधनों में वृद्धि की अत्यन्त आवश्यकता है। भारत की नदियों तथा भूमि में बहुत जल निहित है और ऐसा कहा जा सकता है कि सभी तरह से प्राकृतिक जल संचार के 7 प्रतिशत जल का ही

† *India 1969*, p. 226

‡ *India 1969*, p. 226

हो सका है और शेष या  
 द में व्यर्थ चला जाता है  
 बाढ़ इत्यादि से जनसंख्या  
 की सम्पत्ति को हानि  
 है। इस जलराशि को  
 और विद्युत उत्पादन में  
 जा सकता है। अतः  
 क युग में भारत सरकार  
 में ऐसी योजनाएँ चालू  
 जिनमें (1) सिंचाई की

बहुउद्देशीय योजनाओं के उद्देश्य

1. सिंचाई
2. विद्युत शक्ति का उत्पादन
3. बाढ़ पर नियन्त्रण
4. भूमि का कटाव रोकना
5. मछली उद्योग को पनपाना
6. यातायात के साधनों में वृद्धि
7. स्वास्थ्यवर्द्धक व रमणीक स्थानों का निर्माण

होगी, (2) विद्युत शक्ति का उत्पादन होगा जिससे देश के  
 धन्ये चलेंगे, (3) बाढ़ पर नियन्त्रण होगा, (4) भूमि के कटाव  
 रोका जायगा, जिससे देश की होने वाली धन-जन की क्षति को  
 ग सकेगा, (5) एकत्रित जल में मछलियों का पालन किया  
 (6) यातायात के साधन बढ़ेंगे और (7) स्वास्थ्यवर्द्धक व  
 स्थानों का निर्माण किया जाएगा। उद्देश्यों की इस बहुलता के  
 उन्हें बहुपन्थी अथवा बहुउद्देशीय योजनाएँ कहते हैं। अतः  
 योजनाओं से अनिप्राय ऐसी योजनाओं से है जिनके द्वारा अनेक  
 की पूर्ति हो सकती है।

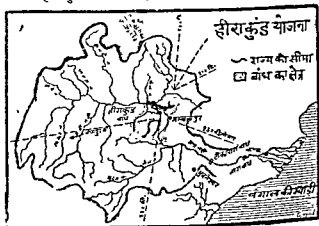
भारत की कुछ प्रमुख नदी-घाटी योजनाएँ

(River Valley Projects)

1) रामोदर घाटी योजना—इस घाटी योजना में बिहार व  
 बंगाल के क्षेत्र सम्मिलित हैं। योजना के अन्तर्गत तिरुंगा,  
 मादुरान और पंचेत नामक चार बाँध बनाये गये हैं। योजना  
 अल्प लगभग 1.9 लाख हेक्टर (4.7 लाख एकड़) भूमि की  
 तथा 1.39 लाख सहस्र किलोवाट बिजली का उत्पादन  
 होगा।

2. भाजरा-नांगल योजना—यह भारत की सबसे विशाल बहुउद्देशीय योजना है। इस योजना के अन्तर्गत सतलज नदी पर 222.3 मीटर ऊँचा बाँध, नांगल बाँध, दो बिजली घर, हारडल चेनल और उस पर दो बिजली घर, नहरों द्वारा सिंचाई की योजना आदि पर कुल 175.6 करोड़ रुपया खर्च होगा जिससे पंजाब तथा राजस्थान की प्रतिस्थापित क्षमता की 6,04,000 किलोवाट विद्युत प्राप्त होगी। केवल दाहिने विद्युतगृह के प्रतिरिक्त योजना का लगभग सभी कार्य पूरा हो चुका है।

3. हीराकुण्ड योजना—उड़ीसा में महानदी पर बनाए गए इस



बांध की अनुमानित लागत 70-78 करोड़ रुपये है। यह विश्व का सबसे लम्बा मुख्य बांध है और इसके विद्युत-गृह ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। 1,23,000 किलोवाट की प्रतिस्थापित क्षमता वाले विद्युत गृह ने रुरकेला इस्पात कारखाना, अल्मूनियम फैक्ट्री हीराकुण्ड, सीमेंट फैक्ट्री राजगंगापुर, पेपर मिल बृजराजनगर तथा अन्य अनेक उद्योगों को विद्युत देना प्रारम्भ कर दिया है। बिजली की बढ़ती हुई मांग को

पूरा करने के लिए योजना का दूसरा चरण प्रारम्भ किया गया है जिससे चिपलिमा स्थान पर विद्युत निर्माण कार्य किया जाएगा। इस योजना के दूसरे चरण की लागत 14.32 करोड़ रुपये होगी।

(4) तुंगभद्रा योजना—मध्य और मैसूर राज्यों की इस संयुक्त योजना की लागत 60 करोड़ रुपये आंकी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनाया गया है और 99,000 किलोवाट विद्युत शक्ति पैदा करने वाले तीन विद्युत-गृह बनकर तैयार हो चुके हैं।

(5) रिहन्द बांध योजना—उत्तर प्रदेश की रिहन्द नदी पर एक बांध बनाया गया है जो उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त बिहार को भी सिंचाई की सुविधा प्रदान करता है। 3 लाख किलोवाट प्रतिस्थापित क्षमता वाले विद्युत-गृह का निर्माण किया गया है यह योजना अल्पमूल्यम व अन्य छोटे-बड़े उद्योगों को बिजली प्रदान करती है। जल-विद्युत का प्रयोग कृषि और सिंचाई के विकास के लिए भी उत्तर प्रदेश के पूर्वी एवं दक्षिणी भागों में किया जायगा। इस योजना की अनुमानित लागत 46.5 करोड़ रुपये हैं।

(6) कोयना योजना—महाराष्ट्र में देशमुख बाड़ी नामक स्थान पर 42.7 करोड़ की लागत का एक बांध बनाया जा रहा है जो विद्युत इकाइयों के द्वारा 2.4 लाख किलोवाट विद्युत का निर्माण करेगा। इसमें से 2.3 लाख किलोवाट बिजली बम्बई व पुना को दी जाएगी। शेष निरन्तरता मार्गों में पहुँचाई जाएगी।

पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई—

(Irrigation under the Five Year Plans)

कृत्रिम साधनों से सिंचाई करना भारत की एक प्राचीन विशेषता है। प्राचीन समय में कई नहरें और तालाब बनाए गए थे। समय समय पर विभिन्न आयोग, कमेटियाँ भी सिंचाई के विकास की योजनाएं प्रस्तुत करती रहीं। सन् 1919 के मुखर्जी के अन्तर्गत सिंचाई एक

प्रामाण्य विषय बन गया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय सरकार ने सिंचाई व्यवस्था को विकसित करने के कार्यक्रम तैयार किए।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में केवल 203.5 लाख हेक्टर (515 लाख एकड़) भूमि पर सिंचाई होती थी। इस योजना के अन्त तक सिंचित भूमि का क्षेत्रफल बढ़कर 226 लाख हेक्टर हो गया। इस योजना काल में सिंचाई के विकास पर 380 करोड़\* रुपये खर्च हुआ। इस योजना काल में सिंचाई की छोटी-बड़ी 170 योजनाएँ (projects) प्रारम्भ की गईं।

द्वितीय योजना काल में सिंचाई की बड़ी व मध्यम योजनाओं† पर 370 करोड़ रुपये खर्च किए गए। छोटी सिंचाई योजनाएँ (Minor irrigation schemes) इन छेप से बाहर हैं। ये छोटी योजनाएँ सामुदायिक विकास (Community Development) कार्यक्रम का ही एक अंग हैं। इस अवधि में सिंचाई की छोटी बड़ी 195 योजनाएँ प्रारम्भ की गईं। इस योजनाकाल में 55.5 लाख हेक्टर भूमि की अधिक सिंचाई होने लगी। कई नदी घाटी योजनाओं एवं सिंचाई की अन्य योजनाओं पर कार्य पूरा हो गया।‡

तृतीय योजना काल में सिंचाई, बाढ़-नियंत्रण, खादि कार्यक्रमों पर 661 करोड़ रुपये खर्च किये जाने का लक्ष्य रखा गया था। योजना काल में 95 नई मध्यम योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया। इस योजना काल में सिंचाई क्षति (Irrigation potential) का लगभग

\* Third Five Year Plan—Final Draft, p. 382

† बिन सिंचाई योजनाओं की जागण 5 करोड़ रुपये या अधिक होती है। ये बड़ी योजना (Major), तथा दस लाख रुपये और नीचे करोड़ रुपये के बीच की योजनाएँ मध्यम योजनाएँ (Medium Schemes) कहलाती हैं।

‡ भारत की मुख्य नदी घाटी योजनाओं के सम्बन्ध में विस्तार के संस्करणों की पुस्तक में यह सूचे हैं।

उपयोग किए जाने की व्यवस्था थी। इस प्रकार कुल सिंचित क्षेत्र बढ़ कर 362 लाख हेक्टर हो जाने का लक्ष्य था।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रमों पर 963.8 करोड़ रुपये खर्च करने की व्यवस्था रखी गई है।\*

### राजस्थान में सिंचाई (Irrigation in Rajasthan)

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय निम्नवाही केवल एक नहर—मगनहर (बीकानेर में) थी जिसके द्वारा प्रतिवर्ष 6 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होती थी। राजस्थान के उत्तरी तथा उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा का औसत 10 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर है। इसलिए यहाँ सिंचाई का बहुत महत्व है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में राज्य में सिंचाई के विकास हेतु 754 लाख रुपये खर्च किये गये। इस योजना में 96 मध्यम परियोजनाओं पर कार्य पूरा कर लिया गया।

द्वितीय योजना में सिंचाई विकास पर 1972 लाख रुपये खर्च किये गये और राज्य में सिंचित भूमि का क्षेत्र 413.8 हजार एकड़ भूमि\*\* हो गया जबकि 1955-56 में केवल 56 हजार एकड़ भूमि पर सिंचाई होती थी।

तृतीय योजना की समाप्ति तक छोटी सिंचाई योजनाओं से 170 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई हुई। चतुर्थ योजना काल में सिंचाई विभाग ने राज्य में 3 करोड़ रुपये की लागत के कार्य करने का प्रस्ताव किया है।

\* Aspect of the Fourth Five Year Plan, Plan in outline, p. 5

\*\* प्रगतिशील राजस्थान : सिंचाई, फरवरी 1966, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान; पृ० 8

## राजस्थान की मुख्य योजनाएं

**चम्बल घाटी योजना**—इस योजना के अनुसार विद्युत उत्पादन केन्द्रों सहित तीन बांधों और एक पाले ( सिंचाई बांध ) का निर्माण किया जा रहा है। साथ में आवश्यक नहरों का निर्माण हो रहा है। राजस्थान-मध्य प्रदेश सीमा पर चम्बल नदी पर गांधी सागर बांध बनाया गया है जो कोटा से दक्षिण में 64.25 कि० मी० (40 मील) दूर है। दूसरा बांध "राणा प्रताप सागर बांध" प्रथम बांध से 32.2 कि० मी० (20 मील) नीचे राजस्थान के एक ग्राम रावत मट्टा के समीप बनाया जा रहा है। तीसरा बांध "कोटा बांध" कोटा से लगभग 16.1 कि० मी० (10 मील) दूर है। इनके अतिरिक्त कोटा नगर से 9.65 कि० मी० (6 मील) की दूरी पर "कोटा बैरेज" बनाया गया है, जिससे दो नहरें निकाली गई हैं। योजना के फलस्वरूप 4 43 लाख हेक्टर ( 11 लाख एकड़) भूमि की सिंचाई होगी और 2 लाख सहस्र किलोवाट बिजली का उत्पादन सम्भव होगा जिससे कोटा, साखेरी, जयपुर, अजमेर आदि क्षेत्रों को लाभ पहुँचेगा। योजना पूर्ण होने पर लगभग 4.825 लाख मी० टन अतिरिक्त अन्न उत्पन्न होगा और कृषि का रूप ही बदल जायगा। योजना के प्रथम चरण पर लगभग 63.59 करोड़ तथा द्वितीय चरण पर 17.21 करोड़ रुपये व्यय होने हैं।



**जवाई योजना**—राजस्थान में एरिनपुरा रेलवे स्टेशन के पास जवाई नदी पर यह बांध बनाया गया है। यह सन् 1956 में तैयार हो गया था। इससे लगभग 24180 हेक्टर (60 सहस्र एकड़) भूमि की सिंचाई

होगी और (20 हजार टन) अतिरिक्त साद्यान्न उत्पन्न होगा।

**राजस्थान नहर परियोजना—हरीके (Harike Barrage)** से जो सतलज नदी पर बनाया गया है, एक नहर, जिस पर लगभग 66.47 करोड़ रुपये व्यय होंगे, निकालने की परियोजना जुलाई, 1957 में स्वी-

कृत की गई थी। इस परि-  
योजना को दो भागों में  
विभक्त किया गया है—

(1) मुख्य नहर 215 कि.  
मी. (134 मील) लम्बी  
होगी जिसमें से 178 कि.  
मी. (110.8 मील) पंजाब  
क्षेत्र में होगी (Rajasthan  
Feeder) और (2) निचली  
नहर जो 467 कि. मी.  
(291 मील) लम्बी होगी  
और राजस्थान के क्षेत्र में  
होगी इसे राजस्थान नहर  
कहते हैं। इसे मुख्य नहर से  
पानी मिलेगा। सन् 1968-  
69 तक सम्पूर्ण राजस्थान



फीडर और राजस्थान नहर का 196 कि. मी. (122 मील) लम्बा भाग  
तैयार हो जाने की आशा है। परियोजना का शेष भाग सन् 1971-78  
तक पूरा होगा। सूरतगढ़ शाखा और रावतसर डिस्ट्रीब्यूटरी बन कर  
तैयार हो गई है।

प्रारम्भ में इस नहर को रावी और व्यास नदियों से पानी दिया  
जायेगा। बाद में इन दोनों नदियों पर बनाये जाने वाले बाँधों से पानी  
की कमी को पूरा करने के लिए पानी दिया जायेगा। प्रारम्भ में इससे



बीकानेर, जैमलमेर तथा श्री गंगानगर के जिनकी 10.5 लाख हेक्टर (26.20 लाख एकड़) भूमि में सिंचाई होगी जिनमें 5.8 मो० टन (5.7 लाख टन) सादाभूत उष्णमान होगा जिनका मूल्य करीब 156 करोड़ रुपये होगा। राजस्थान नहर बोर्ड की देग-रेख में यह कार्य चल रहा है। राजस्थान नहर प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई योजना है। सन् 1966 तक इस योजना के कुल व्यय 86500 हेक्टर (2.15 लाख एकड़) भूमि की सिंचाई प्रारम्भ हो गई। राजस्थान नहर पूरी कुवाई की होगी तथा इसकी कुल संस्था: 693 दि० मो० (425 मील) के लगभग होगी। आगामी 20 वर्षों में योजना के पूरे होने के अनुरूप लगभग 3 हजार मए गांव बच जायेंगे तथा 27.4 लाख मो० टन (27 लाख टन) पनिरिक्त अन्न पैदा होगा। प्रत्यक्ष रूप में लगभग 25899 वर्ग दि० मो० (10 हजार वर्ग मील) का क्षेत्र इस योजना से प्रभावित होगा।

### सारांश

सिंचाई का महत्व—भारतीय कृषि वर्षा का जुमा मानी जाती है। अनिश्चितता से बचने के लिए सिंचाई को विशेष महत्व देना आवश्यक है। भारत में सिंचाई की आवश्यकता के मुख्य कारणों में—वर्षा की अनिश्चितता, वर्षा का असमान वितरण, सर्दी में वर्षा का अभाव आदि उल्लेखनीय है।

सिंचाई से लाभ (1) अकाल से बचाव (2) निरन्तर खेती (3) प्रति हेक्टर उपज में वृद्धि, (4) विस्तृत खेती सम्भव, (5) जन-संख्या का ठीक बंटवारा, (6) विशेष फसलों का उत्पादन, (7) किसानों की आय में वृद्धि, (8) आवागमन के साधनों में वृद्धि, (9) सरकार की आय में वृद्धि (10) व्यापार में वृद्धि, (11) उद्योग घरों को प्रोत्साहन तथा (12) गहरी खेती।

सिंचाई से हानियाँ—(1) पानी की अधिकता (water logging),

(2) भूमि का बेकार हो जाना, (3) रोगों की प्रचलता, (4) जल वितरण समस्या तथा (5) जन-घन की हानि ।

सिंचाई के साधन—(1) कुएं—पूर्वी पंजाब, उ० प्र० के पूर्वी भाग, बिहार के उत्तरी भाग तथा अन्य राज्यों में कुओं से सिंचाई की जाती है । (2) तालाब—मुख्यतः मद्रास, मैसूर, आंध्र प्रदेश और राजस्थान (उदयपुर द्वीयोजन) में पाये जाते हैं । (3) नहरें—उत्तर प्रदेश, पंजाब व मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं ।

पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई—प्रथम योजना काल में सिंचाई के विकास पर 380 करोड़ रुपये खर्च हुआ । योजना काल में सिंचाई का क्षेत्र 209 लाख हैक्टर (1950-51) से बढ़कर सन् 1964-65 में 263 लाख हैक्टर हो गया ।

द्वितीय योजना काल में सिंचाई व मध्यम योजनाओं पर 370 करोड़ रुपये खर्च किए गए । तृतीय योजना में सिंचाई के विकास के लिए 661 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी । चतुर्थ योजना में सिंचाई व बाई निम्नवर्ण कार्यक्रमों के लिए 963.8 करोड़ रुपये रखे गये हैं ।

### प्रश्न

1. भारतीय कृषि में सिंचाई का क्या महत्व है ? भारत के 'मिन्न-मिन्न भागों' में सिंचाई के कौन-कौन से साधन प्रयोग किये जाते हैं ?

इनका तुलनात्मक महत्व भी बताइए ।

(राज. बोर्ड, इन्टर, 1952 तथा म. प्र. बोर्ड, हा. से., 1961)

2. भारत की मिन्न-मिन्न सिंचाई व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए और नहरों की सिंचाई से होने वाले लाभ-हानियों का विवेचन कीजिए ।

(मजमेर बोर्ड, इन्टर, 1962 तथा सागर वि. वि., 1952)

3. "बहुउद्देशीय योजनाओं" से क्या समझते हैं ? किन्हीं दो योजनाओं के बारे में विस्तार से लिखिए ।  
(राज. बोर्ड, इन्टर, 1960 तथा हा. से., 1960 व 1962)

4. निम्न पर टिप्पणियाँ लिखिए—  
(अ) राजस्थान नहर (राज. बोर्ड, हा. से., 1967), (आ) मादा नौगल, (इ) चम्बल योजना, (ई) दामोदर घाटी योजना तथा (उ) पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई, (ऊ) नल-कूप (राज. बोर्ड, हा. से., 1969)

5. भारतीय कृषि के लिए सिंचाई का महत्व समझाइये । भारत में सिंचाई के विभिन्न साधनों का वर्णन कीजिए ।  
(राज. बोर्ड, हा. से., 1966)

## अध्याय 6

### कृषि के साधन III

#### AGRICULTURAL INPUTS-III

भारत में ग्रामीण वित्त

#### (RURAL FINANCE IN INDIA)

“भारतीय कृषक ऋण में जन्म लेता है, ऋण में रहता है और ऋण ही मरता है।”\*

—साही कृषि आयोग

“ऋण सस्मृता ही कृषि की असफलता का कारण है।”

—बुल्क

प्रत्येक व्यवसाय को चलाने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। कृषि व्यवसाय के लिए भी साख (Credit) के सस्ते एवम् सुलभ साधनों का बहुत महत्व है। दुर्भाग्य से भारतवर्ष में कृषि साख की कमी सततपत्रक नहीं है। गाँवों में रहने वाले कारीगरों को भी अपनी संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भारतीय ग्रामीणों का वित्त का अधिकांश भाग कृषि से संबंधित है।

#### साख की आवश्यकता (Need of Agricultural Credit)

कृषक को खेती के लिए साख की जो आवश्यकता होती है उसे तीन प्रकार में बाँटा जाता है--

\*“Indian Farmer is born in debt, lives in debt and dies in debt”—Royal Commission on Agriculture.

### 1. अल्पकालीन साख (Short term credit)—

इसकी आवश्यकता कृषक के दिनप्रति दिन के कार्यों के लिए होती है। खाद, बीज, आदि साधनों की प्राप्ति के लिए आवश्यक इस साख की अवधि लगभग 9 मास से 15 मास तक होती है।

### 2. मध्यकालीन साख (Medium-term Credit) —

इस साख की आवश्यकता सामान्यतः कृषि के लिए पशु बंधन खरीदने, कुआ, बाड़ (Fence) तथा मकान बनाने एवं भूमि पर मुघार करने के लिए होती है। कृषक द्वारा सामाजिक कार्यों के लिए भी जो ऋण लिए जाते हैं वे इसी श्रेणी में आते हैं। इस साख की अवधि सामान्यतः षेड से पाँच वर्ष तक की होती है।

### 3. दीर्घकालीन साख (Long-term credit)—

सम्बन्धी अवधि के साख की आवश्यकता भूमि खरीदने, पुराने ऋण का मुगतान करने, भूमि में स्थायी मुघार करने आदि के लिए होती है। किसान धीरे-धीरे इन ऋणों का मुगतान करता है। यह ऋण प्रायः पाँच वर्ष से बीस वर्ष तक की अवधि का होता है।

कृषि कार्यों के अतिरिक्त भी कृषक को ऋण की आवश्यकता होती है। विवाह, धार्मिक उत्सव, आदि कार्यों के लिए जो ऋण लिए जाते हैं वे अनुत्पादक (unproductive) होते हैं। किसान ऐसे ऋणों पर अधिक ब्याज देता है।

### ग्रामीण साख के साधन (Agencies of Rural credit)

ग्रामीण साख प्रदान करने के साधनों में साहूकार (Money lender) का स्थान मुख्य है। अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने (All India Rural Credit survey committee) सन् 1951-52 में अपने प्रतिवेदन (Report) में बताया कि भारतीय ग्रामीण साख के विभिन्न स्रोत एवं उनके द्वारा प्रबंधित राशि का प्रतिशत निम्न प्रकार है—

# स्रोत

# साल पूति का प्रतिशत

1. पेशेवर साहूकार	44.8
2. किसान साहूकार	24.9
3. रिश्तेदार तथा मित्र	14.2
4. सरकार	3.3
5. सहकारी संस्थाएं	3.1
6. व्यापारिक बैंक	0.9
7. अन्य साधन	8.8

योग 100.0

उपयुक्त तालिका से पता लगता है कि सर्वोत्तम के समय ग्रामीण साल की पूति का मुख्य स्रोत साहूकार था। साहूकारों की कार्य-वृद्धि में दोष होते हुए भी किसान उन्हें से अपनी अधिकांश आवश्यकताओं की पूति करते हैं। किन्तु अब स्थिति में परिवर्तन आ रहा है। साहूकारों का स्थान धीरे-धीरे सहकारी संस्थाएं ले रही हैं। सन् 1968-69 में सहकारी संस्थाओं के द्वारा कृषकों को 559 करोड़ रुपये का ऋण दिया



गाँव का साहूकार

मया । इस राशि में 450 करोड़ रुपये मध्य एवं प्रत्यक्षकारीय तथा 100 करोड़ रुपये का दीर्घकालीन ऋण सम्मिलित है । अब हम साल के विभिन्न साधनों का अलग अलग अध्ययन करेंगे—

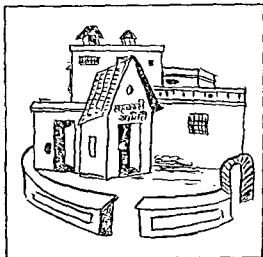
✓ (1) साहूकार (Money Lender)—ग्रामीण साख का लगभग 70 प्रतिशत भाग साहूकारों (पेशेवर और किसान) से प्राप्त होता है । महाजन ग्रामीण अर्थ व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग हैं । महाजन उत्पादक और अनुत्पादक सभी कार्यों के लिए ऋण देता है । उसकी कार्य पद्धति सरल होती है, और किसान को किसी भी समय जमानत (security) न होने पर भी ऋण मिल जाता है । साहूकार ऋण से सीधा सम्बन्ध रखता है और स्थानीय परिस्थितियों से परिचित होने के कारण वह प्रत्येक ऋणी की आर्थिक स्थिति को जानता है । इन कारणों के कारण ही साहूकार ग्रामीण साख का सर्वोपरि साधन है । साहूकारों की कार्य पद्धति में कई दोष पाए जाते हैं, जैसे (क) ब्याज की दर बहुत ऊँची होती है । (ख) ब्याज की अग्रिम (advance) बसूली करता है । (ग) हिसाब किताब में गड़बड़ी करके किसानों को ठगता है । (घ) ऋणी पर अपने प्रभाव का दुरुपयोग करके उसकी फसल कम दामों पर खरोद लेता है । (ङ) किसानों से तरह-तरह की मेंट लेता है और उन्हें अपने दावों की भांति समझता है ।

सरकार द्वारा साहूकारों की दूषित कार्य पद्धति पर रोक लगाई जा रही है । लगभग सभी राज्यों में साहूकारों के लाइसेंस लेने, हिसाब-किताब रखने, ब्याज की दर निर्धारण करने और गैर कानूनी कार्यों पर रोक लगाने के लिए अधिनियम पास किए जा चुके हैं । गाँव में साहूकार का एकाधिकार होने के कारण किसान अब भी अपनी साख सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए उन्हीं के पास जाता है ।

(2) रिश्तेदार एवं मित्र (Relatives and friends)—ग्रामीण साख की दूसरी महत्वपूर्ण एजेंसी रिश्तेदार और मित्र है । इनकी कार्य प्रणाली का कोई कानूनी रूप नहीं है । इनमें साधारणतया कोई लिखा-पढ़ी नहीं होती और ब्याज भी नहीं लिया जाता । भारत सरकार द्वारा

किए गए सर्वेक्षणों से पता लगता है कि पहले की तुलना में अब इस साधन का महत्व कम होता जा रहा है ।

(3) सरकार (Government) —सरकार भूमि सुधार अधिनियम तथा कृषक ऋण अधिनियम के अन्तर्गत किसानों को तकावी (Taccavi) ऋण देती है । सरकारी ऋणों की मात्रा बहुत कम तो हानी ही है, साथ ही इन्हें मिलने में बहुत समय लग जाता है इन ऋणों की कानूनी पद्धति (procedure) भी जटिल होती है इसलिये ये ऋण ग्रामीण साक्ष में बहुत अधिक महत्व नहीं रखते ।



### सहकारी समिति

(4) सहकारी संस्थाएं (Co-operative Institutions) —यद्यपि सहकारी संस्थाओं का प्रारम्भ भारत में सन् 1904 में हो चुका था फिर भी इन समितियों द्वारा ग्रामीण साक्ष का बोझ सा-भाग हो प्रदान



किया जाता है। इतना ही नहीं अधिकांश सहकारी संस्थाएँ किसानों को अल्पकालीन ऋण ही देती हैं इसलिए वांछ्य होकर किसान को मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण के लिए साहूकार के पास जाना पड़ता है। चिन्नु धीरे धीरे स्थिति में परिवर्तन हो रहा है और ग्रामीण साक्ष के क्षेत्र में सहकारी संस्थाओं का महत्व बढ़ता जा रहा है। सहकारी समितियों का विस्तृत अध्ययन अगले अध्याय में किया जाएगा।

✓(5) व्यापारिक बैंक (Commercial Banks)—हमारे देश में व्यापारिक बैंक ग्रामीण साक्ष प्रदान करने का कार्य नहीं के बराबर करते हैं, क्योंकि इनकी शाखाएँ शहरों और कस्बों में स्थित हैं। वैसे ये बैंक साहूकारों, व्यापारियों, आदि को ऋण देकर परोक्ष में ग्रामीण साक्ष में योग देते हैं तथापि किसानों को साक्ष प्रदान करने में ये नगण्य हैं। व्यापारिक बैंकों पर सामाजिक नियन्त्रण (Social control) स्थापित होने के पश्चात् उनके लिए यह आवश्यक हो गया है कि वे अपनी जमाओं का एक निश्चित भाग कृषकों को अग्रिम देने हेतु निर्धारित कर दें।

(6) अन्य साधन—जमींदार, व्यापारी एवं अन्य साधनों द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋणों को इस समूह में सम्मिलित किया गया है। अब जमींदार का महत्व कम होता जा रहा है। व्यापारी फसल खरीदने के लिए ही रुपया अग्रिम (advance) देता है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारत में ग्रामीण वित्त की एक उचित और सुव्यवस्थित साक्ष प्रणाली का अभाव है। ग्रामीण साक्ष सुविधाओं के विस्तार के लिए सहभागिता का विकास करना होगा। व्यापारिक बैंकों को ग्रामीण साक्ष में योग देना चाहिए। महाजनो का प्रभुत्व कम करने के लिए कृषि के सभी कार्यों में सहकारिता की उन्नति की जानी चाहिए।

### ग्रामीण ऋण प्रस्तुता (RURAL INDEBTEDNESS)

“भारतीय किसान ऋण में जन्म लेते हैं, ऋण में जीवन व्यतीत करते हैं और ऋण में ही मर जाते हैं।” भारत में यह बहावत सदा-सर्वदा के

ले गए सत्य सी बन गई है। किसान स्वयं ऋण में डूबा हुआ रहता ही है किन्तु उनकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी भी ऋण में डूबे रहते हैं। ऋण-प्रस्तता किसान को धनमंथ्य व उदासीन बनाती है और नैतिक दृष्टि से गिराती है। ऋषी को अपने जीवन में कोई आनन्द नजर नहीं आता।

### ✓ ऋण प्रस्तता के कारण (Causes of Indebtedness)

✓ अब प्रश्न यह है कि भारत में ग्रामीण ऋण इतना क्यों है? इसके निम्न कारण हैं:—

1. किसान की निर्धनता— भारतीय किसान बहुत गरीब है और उसकी आय भी कम है। इसलिए फसल खराब हो जाने की स्थिति में दूसरे साधनों से ऋण लेना होता है क्योंकि उसकी वचन-शक्ति नहीं के बराबर है।

2. अनाधिक, सामाजिक व आर्थिक कार्य—किसान अनशिक्षित होता है और वह सामाजिक व आर्थिक कृत्यों पर अपना पानी की तरह बहाता है। किसान की स्वयं की आय बहुत कम होनी है इसलिए उसे इन कार्यों के लिए ऋण लेना पड़ता है।

### ऋण-प्रस्तता के कारण

1. किसान की निर्धनता
2. किसान का अज्ञान व फिज़ल खर्चों
3. पुस्तैनी ऋण ✓
4. माहूकार की दूषित पद्धति
5. शेती की पैदावर में कमी
6. भूमि का छोटे छोटे टुकड़ों में बँटा होना
7. भूमि पर जनसंख्या का भार बढ़ना
8. प्राकृतिक परिस्थितियाँ
9. दुर्बल पशुधन
10. अधिक लगान
11. कृषक की अस्वस्थता
12. व्याज की ऊँची दर

3. पंचक ऋण—(Ancestral debt)—एक पिता की मृत्यु के बाद साधारण उत्तराधिकारियों को ऋण ही वसीयत (inheritance) मिलता है। किसान अपने पूर्वजों का ऋण चुकाने के लिए ऋण लेते हैं। इस प्रकार वे अत्यधिक ऋण-प्रस्तता के मगर में फँस जाते हैं।

4. साहूकार की दूधित पद्धति—प्रमोण साहू के क्षेत्र में साहू-कार के एकाधिकार होने के कारण किसान को ऋण के लिये उसी पर निर्भर रहना पड़ता है। साहूकार अपनी इस शक्ति का दुरुपयोग कर किसानों को मन माने ढंग से ठगता है, सूद की दर बहुत अधिक वसूल करने के अतिरिक्त ऋणी किसान की फसल कम दामों पर खरीदने का पहला अधिकार उसी का होता है, जिससे किसान अपने उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त नहीं कर सकता। परिणाम स्वरूप उसके ऋण भार में और भी वृद्धि हो जाती है।

5. खेती की पैदावार में कमी—भारतीय कृषि बहुत विखड़ी हुई अवस्था में है, और प्रति एकड़ पैदावार बहुत कम है। ऐसी स्थिति में किसान कृषि भाय से अपना मरण-पोषण नहीं कर सकता है और बाध्य होकर उसे ऋण लेना पड़ता है।

6. भूमि का छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटा होना—खेती का उप-विभाजन व अपसंजन कृषि को अलाम्बदायक बनाता है और किसान को अपने प्रतिदिन के कार्यों के लिए भी ऋण लेना पड़ता है।

7. भूमि पर जनसंख्या का भार बढ़ना—भारत में जनसंख्या बहुत तीव्र-गति से बढ़ रही है और दूसरे घन्टों के प्रभाव में उनका अधिकांश भाग भूमि पर ही निर्भर रहता है। आवश्यकता से अधिक अनुषंगों के भूमि पर आश्रित होने से कृषि से प्राप्त होने वाली आय कम हो जाती है और परिवार का मरण-पोषण करने के लिए कृषकों को ऋण लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है।

8. प्राकृतिक परिस्थितियाँ—भारतीय कृषि प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। यह ठीक ही कहा जाता है कि भारतीय कृषि मानसून का गुलाम है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, टिड्डी, हिमपात, आंधी, आदि कई प्राकृतिक कारणों से फसल नष्ट हो जाती है और किसानों को अन्न भी उधार लेकर खाना पड़ता है।

9. पूर्ण वसु—भारत में वसुधन कमजोर है और अधिकांश

किसानों पर भार स्वरूप है। पशुओं में बीमारी फैलने पर बहुत अधिक संख्या में पशु मर जाते हैं और नए पशु खरीदने के लिए किसान को ऋण लेना पड़ता है।

10. अधिक लगान—भूमि के लगान की दर ऊँची है। जिस वर्ष कमल नष्ट हो जाती है उस वर्ष तो किसान के लिए लगान चुकाना और भी कठिन हो जाता है और मजबूर होकर उसे साहूकार की शरण लेनी पड़ती है।

11. कृषक की अस्वस्थता—किसानों का जीवन-स्तर बहुत नीचा होने के कारण वे दुर्बल होते हैं और अनेक बीमारियों के शिकार होने रहते हैं, जिससे उनकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। ऐसी दशा में उनकी धाँय और कम हो जाती है और विवश होकर उन्हें ऋण लेना पड़ता है।

12. व्याज की ऊँची दर—ग्रामीण साख के साधनों में साहूकार का स्थान प्रमुख है। वह किसानों की साखारी का अनुचित लाभ उठा कर व्याज की बहुत ऊँची दर वसूल करता है जो ऋण-शक्तता में कृत्रिम करती है। इसका ही नहीं सरकारी सहायकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों की व्याज दर भी अधिक होती है।

**ऋण-शक्तता के प्रभाव—**

ग्रामीण ऋण-शक्तता के कारण देश में अनेक बुराईयाँ उत्पन्न हो गई हैं। सदियों से ऋण मात्र में रहे रहने के कारण किसान का दृष्टिकोण निराशावादी (pessimistic) बन गया है। ऋण-शक्तता के निम्न प्रमुख दोष हैं—

1. कृषक की कार्यक्षमता में कमी—ऋण-ग्रस्त किसान सर्वत्र निराशाओं से घिरा रहता है। ऋण में डूबे रहने के कारण उसका उत्पाद कम हो जाता है। परिणामस्वरूप उसकी कार्य-क्षमता कम हो जाती है और वह अपने परिवार का भरण-पोषण भी नहीं कर सकता।

2. कृषक को अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता साहूकारों से खपवा उधार लेने की महत्वपूर्ण शक्ति यह भी होती है। यणों अपनी फसल उन्हीं के हाथ बेचेगा। परिणाम यह होता है साहूकार किसान की पैदावार को बाजार माव से कम कीमत पर खरीद लेते हैं और किसान को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता।

3. किसान का भूमि पर अधिकार से वंचित होना—बहुधा किसान अपनी भूमि की जमानत पर ऋण लेता है और जब वह ऋण को सफलतापूर्वक चुका नहीं कर पाता तो विवश होकर उसे अपनी भूमि बेच

- ऋण-प्रस्तुता के परिणाम
1. कृषक की कार्यक्षमता में कमी
  2. कृषक को फसल का उचित मूल्य नहीं मिलना
  3. किसान का भूमि पर अधिकार नहीं रहता
  4. किसान का नैतिक पतन
  5. किसान का शोषण

पड़ती है। अतः कृषक भूमि-हीन अधिक हो जाता है।

4. किसान का नैतिक पतन—ऋण-प्रस्तुत रहने के कारण किसान को साहूकार या दास बनकर रहना पड़ता है और उसका नैतिक पतन हो जाता है।

5. किसान का शोषण—(exploitation)—ऋण-प्रस्तुता

के कारण किसान का विभिन्न प्रकार से शोषण होता है। जिससे गरीब किसान और अधिक गरीब हो जाता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि ऋण-प्रस्तुता ने किसान को निराशा-वादी, निर्धन, भूमि-हीन और दुर्बल बना दिया है। अतः इस समस्या को सौधताशील दूर करना अति आवश्यक है।

समस्या का हल एवं प्रगति—

ऋण-प्रस्तुता की समस्या के हल पर विद्युती गानास्त्री ने विचार प्रारम्भ हुआ, किन्तु समस्या का व्यवहारिक हल प्राप्त करने के अश्वस्थित

प्रयत्न स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद ही किये गए । यहाँ हम ऋण-व्यस्तता को दूर करने के उपायों और उनकी प्रगति के बारे में विचार करेंगे ।

1. ऋणों को कम करना—ऋण-व्यस्तता को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि पुराने ऋणों में कुछ कटौती की जाय । इन कटौतियों के लिए समझौता कमेटियाँ (Conciliation Boards) बना दी जाएँ। अनेक राज्यों में पुराने ऋणों में अनिवार्य रूप से कटौती करने में कुछ कानून बन चुके हैं और कई जगह समझौता परिपक्व कायम हो चुकी है ।

2. साहूकारों की दूषित कार्य पद्धति पर रोक—कृषि साक्ष के क्षेत्र में साहूकार ही मुख्य स्रोत है । इनके एकाधिकार से अनेक बुरा-इयाँ पनप गई हैं । इसलिये सरकार को साहूकार पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिये । हिसाब-किताब की जाँच पड़ताल, लाइसेंस पद्धति आदि को प्रभावशाली बनाकर किसानों की रक्षा की जानी चाहिये । सन् 1930 के पश्चात् महाजनों की दूषित कार्य पद्धति को रोकने के लिए विभिन्न राज्यों में कानून पारित कर दिए गए हैं । इन कानूनों के अन्तर्गत महाजनों के लिए लाइसेंस लेना हिसाब-किताब रखना और पाँच करवाना, ऋणों को समय-समय पर भुनघन व व्याज की सूचना देना अनिवार्य कर दिया गया है । कई राज्यों में इनके द्वारा दिए जाने वाले ऋण की व्याज दर भी निर्धारित कर दी गई है । इन कानूनों का सख्ती से पालन करवाना चाहिये ।

3. भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबन्ध—कई राज्यों में ऐसे कानून बन गये हैं जिनके अनुसार साहूकार किसान की भूमि पर कब्जा नहीं कर सकता । परन्तु उनका प्रभावशाली उपयोग नहीं किया है । सन् 1910 का पंजाब भूमि हस्तांतरण नियम इस दिशा में पहला प्रयास था ।

4. कृषि-साक्ष व्यवस्था का विकास—वर्तमान कृषि साक्ष में आमूलभूत परिवर्तन करके साक्ष के नवीन ढाँचे का विकास आवश्यक है । पुराने ऋणों का भुगतान करने के लिए अधिकाधिक भूमि विकास

बैंक (Land Development Banks) खोलने चाहिये। इस देश में भूमि विकास बैंकों की संख्या 726 (केन्द्रीय और प्राथमिक मिता कर) है। अल्पकालीन व मध्यकालीन माध्य के लिए सुदृढ़कारी समितियों का तीव्र गति से विस्तार आवश्यक है। ग्रामीण सहकारी समितियों का कार्य संचालन कुशल नहीं है। किसानों को माध्य, बिना उत्पादन घाटि कार्यों में महंगारी समस्याओं की सेवाएं उपलब्ध कराना चाहिये जिससे वे साहूकारों के चपुल से निवृत्त सकें। किसानों को भू सुधार एवं अधिक उद्देगदन के लिए सरकारी 'तकावी' ऋण भी-सुगम से और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने चाहिये। देश के बैंकों को ग्रामीण साक्ष में भाग लेना चाहिये। प्रसन्नता की बात है कि रिजर्व बैंक तथा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया इस ओर महत्त्वपूर्ण प्रयास कर रहे हैं। व्यापारिक बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण स्थापित होने के पश्चात् इन बैंकों ने कृषि साक्ष के क्षेत्र में बहुत सहयोग दिया है।

**ऋण प्रस्तुता को दूर करने के उपाय**

1. ऋणों को कम करना
2. साहूकारों की दूषित पद्धति पर रोक
3. भूमि के हस्तान्तरण पर रोक
4. कृषि साक्ष व्यवस्था का विकास
5. कृषकों को आय में वृद्धि
6. फिजल सखों पर रोक

5. कृषकों की आय में वृद्धि ऋण-प्रस्तुता की समस्या को दूर करने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारी जाय। इस सम्बन्ध में यह जानना महत्त्वपूर्ण होगा कि सरकार पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत कृषि की उन्नति के निश्चित कार्यक्रम चला रही है जिससे कृषि की हालत ध्वस्त सुधरेगी।

6. फिजल सखों पर रोक—उन सभी सुधारों के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि गाँव बागों में नियन्त्रयता की भावना का संभार किया जाये। विमान अनेक धार्मिक और सामाजिक घबतरों पर दबा

दृष्टि देने तीन वर्षों से भूमि विकास बैंक का नाम बदल कर भूमि विकास बैंक कर दिया गया है।

सुधार लेकर पानी की तरह बहाना है। अनावधिक व्यय को रोकना बहुत आवश्यक है। ग्राम पंचायतों, जीवन सुधार-सहकारी समितियाँ, शिक्षा का प्रसार और किछल खर्ची के विरुद्ध प्रचार, हम उद्देश्य को प्राप्त कर बनने में समर्थ होंगे।

कुछ समय से सरकार ने उपर्युक्त क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण कदम उठाये हैं। इषि उपज वृद्धि, साख-व्यवस्था सुधार तथा सहकारिता आन्दोलन की तीव्र गति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

रिजर्व बैंक, जो देश का केन्द्रीय बैंक है, ग्रामीण वित्त के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण हिस्सा ले रहा है। रिजर्व बैंक का कृषि साख विभाग (Agricultural Credit Department) कृषि वित्त समस्याओं का

शराब

विवाह

मोसर

ब्याज

मुकदमें

लगान

रवाद

बीज

बैल





अध्ययन करने, राज्य सरकारों एवं बैंकिंग संस्थाओं को ग्रामीण साख प्रदान करने के क्षेत्र में सहायता करने एवं अपने एजेंट 'स्टेट बैंक' के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में साख प्रदान करने का काम करता है।

ग्रामीण वित्त की सुविधाओं के लिए सहकारी संस्थाओं का विस्तार, साहूकारों की कार्य प्रणाली में सुधार, अगति का निवारण, राज्य सरकारों, बैंकिंग संस्थाओं एवं अन्य एजेंसियों द्वारा सहयोग किया जाना चाहिये।

### सारांश

कृषि के लिए तीन प्रकार की साख की आवश्यकता होती है—

(1) मत्स्यकालीन, (2) मध्यकालीन, तथा (3) दीर्घकालीन।

ग्रामीण साख के साधन

साहूकार 69.7% रिस्तेशर आदि 14.2%, सरकार 3.3%, सहकारी समितियाँ 3.1%, व्यापारिक बैंक 0.9 तथा अन्य 8.8%। इन साधनों में साहूकार ग्रामीण साख व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। किन्तु उसकी कार्य पद्धति में कई दोष हैं। इन दोषों को दूर किया जाना जरूरी है। अब सहकारी संस्थाओं का महत्व बढ़ता जा रहा है।

ग्रामीण ऋण-प्रश्न—भारतीय किसान ऋण में जन्म लेता है, ऋण में ही रहता है और ऋण में ही मरता है—ऋण-प्रश्न का अनुमान ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति के अनुसार 283 रु० प्रति परिवार है।

कारण—(1) किसान की निर्धनता, (2) अज्ञानता और फिजूल खर्ची, (3) पुश्तैनी ऋण, (4) साहूकार की दूषित पद्धति, (5) खेती की पैदावार में कमी, (6) भूमि का छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटा होना, (7) जनसंख्या का भार बढ़ना, (8) प्राकृतिक परिस्थितियाँ, (9) दुर्बल पशु, (10) अधिक मगान, (11) कृषक की अस्वस्थता, (12) व्याज की ऊँची दर।

ऋण-प्रस्तुता के परिणाम—(1) कृषक की कार्यक्षमता में कमी, (2) कृषक को अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलना, (3) किसान का भूमि पर अधिकार नहीं रहता (4) किसान का शोषण ।

समस्या का उपचार—(1) ऋणों को कम करना, (2) साहूकारों की दूषित कार्य पद्धति पर रोक (3) भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध, (4) कृषि साहस व्यवस्था का विकास, (5) कृषकों की आय में वृद्धि, तथा (6) फिदूल सूची पर रोक

सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत इस समस्या को हल करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

### प्रश्न

1. ग्रामीण साक्षर किसे कहते हैं इसके कौन-कौन से साधन हैं ।
2. ऋण-प्रस्तुता से घाप क्या समझते हैं ? कारण सहित स्पष्ट कीजिये तथा परिणाम भी बताइये ?
3. ऋण प्रस्तुता को दूर करने के उपाय बताइये । भारत सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है ?
4. भारत में ग्रामीण ऋण-प्रस्तुता के कारणों का वर्णन कीजिये ।

(राज. बोर्ड, हा. से., 1966 तथा 67)

## अध्याय 7

### भारतीय कृषि की पद्धति

“भारतीय कृषक अनेक बातों में उतना ही अच्छा है जितना कि ब्रिटिश किसान और कुछ बातों में तो यह उससे भी श्रेष्ठ है। यदि उसकी कुछ बुराइयाँ हैं तो वे कृषि पद्धति में सुधार की सुविधाओं के अभाव के कारण हैं।”  
—डॉ. बायलर

कृषि हमारी अर्थ व्यवस्था का आधार है। यह हमारे जीने का तरीका (way of life) भी माना जाता है। किन्तु जैसा पहले स्पष्ट किया जा चुका है कृषि अभी एक अलाभदायक व्यवसाय के रूप में चलाया जा रहा है। विदेशों से भारी मात्रा में अन्न का आयात, कृषि पर आश्रित जनसंख्या की तुलना में कृषि से प्राप्त राष्ट्रीय आय का योग कम होना तथा अन्य देशों की तुलना में यहाँ की प्रति एकड़ घासत पैदावार का कम होना इसके पिछड़ेपन के प्रमाण हैं। कृषि के पिछड़ेपन के कारणों को पाँच भागों में बाँटा जा सकता है—

1. कृषि के ढाँचे से सम्बन्धित—इसमें भूमि अधिकार की प्रणाली प्राचीन है।

2. संगठन सम्बन्धी—इसमें कृषि भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े, उचित संगठन का अभाव, प्रादि बातें प्राचीन हैं।

3. कृषक से सम्बन्धित कारण—इसमें कृषक की अशिक्षा, अज्ञानता, रूढ़िवादिता, भाव्यवादिता प्रादि कारण सम्मिलित किये जाते हैं।

4. कृषि के साधनों से सम्बन्धित—इसमें कृषि उपज के लिए आवश्यक साधनों का पिछड़ापन आ जाता है। ये साधन हैं—बीज, खाद, पशु, सिंचाई, वित्त, औजार प्रादि।

5. कृषि की पद्धति से सम्बन्धित कारण—इस वर्ग में कृषि की परम्परागत शैली एवं पद्धति से सम्बन्धित दोषों का समावेश होता है।

उक्त दोषों के प्रथम चार वर्गों के बारे में हम पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम कृषि पद्धति से सम्बन्धित बातों का अध्ययन करेंगे।

**उन्नत कृषि पद्धति का महत्व—**

किसी भी देश की कृषि-अवस्था में सुधार लाने के लिए उसकी पद्धति में आमूल चूल परिवर्तन करने पड़ते हैं। अविकसित कृषि पद्धति कृषि विकास का मार्ग अवरोध कर देती है। उन्नत कृषि पद्धति से प्राप्त होने वाले लाभ निम्नांकित हैं—

1. कृषि उत्पादन की वृद्धि में उन्नत कृषि पद्धति बहुत सहायक होती है।

2. किस्म सुधार की दृष्टि से भी उन्नतशैली कृषि पद्धति का बहुत महत्व है। कृषि पैदावार बढ़ने के साथ वस्तु की उत्तमता में सुधार की दृष्टि से यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

3. उन्नतशैली कृषि पद्धति के द्वारा उत्पत्ति लागत (Cost of production) में कमी लाकर कृषक व उपभोक्ता दोनों को पहुँचाया जा सकता है।

4. उन्नत कृषि पद्धति सदैव कृषक का समय व धन बचाती है जिसका उपयोग अन्य आर्थिक व सामाजिक कार्यों में किया जा सकता है।

5. उन्नत कृषि पद्धति के अन्तर्गत देश में उपलब्ध सभी प्राकृतिक साधनों—मिट्टियों, जलवायु तथा सिंचाई के साधनों का सदुपयोग समभव होता है।

6. कृषि पद्धति में उपयोग आने वाली दोहरी फसल प्रणाली, फसल चक्र आदि प्रणालियों के द्वारा भूमि की उर्वरा शक्ति में होने वाली क्षति को पूरा किया जा सकता है।

उन्नति कृषि पद्धति के साम

1. उत्पादन की मात्रा में वृद्धि
2. उत्पादन की उन्नत किस्म
3. उत्पादन खर्च में कमी
4. समय व धन की बचत
5. प्राकृतिक साधनों का सदुपयोग
6. भूमि की उर्वरा शक्ति का कम ह्रास
7. रोजगार में वृद्धि
8. कृषकों की आय में वृद्धि
9. उद्योग पेशों को उत्तम व पर्याप्त सामग्री
10. विदेशों पर से कृषि सामग्री की निर्भरता में कमी

7. रोजगार में वृद्धि प्रदान करने का बहुत बड़ा काम भी उन्नत कृषि की प्रणाली कर देती है। सघन खेती योजना एम्बु अन्य कार्यों में अधिकाधिक लोगों को रोजगार दिया जा सकता है।

8. उन्नत कृषि प्रणाली के प्रयोग से कृषक कम साधन में ही अधिक कृषि पदार्थों का उत्पादन करने लग जाता है। परिणाम-स्वरूप कृषकों की आय में वृद्धि होती है जिसका उपयोग आर्थिक विकास के लिए किया जा सकता है।

9. उन्नत कृषि पद्धति अपना-

कर देश में उद्योग-पेशों के लिए आवश्यक उत्तम किस्म का कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में तैयार दिया जा सकता है।

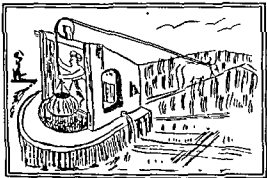
10. उन्नत कृषि पद्धति से ही देश में आवाश्यकता के अनुसार कृषि पदार्थ तैयार किये जा सकते हैं। इससे विदेशों पर आश्रित एवं अन्य कृषि सामग्री के सम्बन्ध में निर्भरता कम हो जाती है।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि उन्नत कृषि पद्धति अपनाकर देश के बहुमुखी विकास में योग दिया जा सकता है।

भारतीय कृषि पद्धति—

प्राचीनकाल में भारतीय जीवन व्यवस्था गरम होने के कारण कृषि की आवश्यकता अनुभव नहीं की गई। गाँवों में कृषि कार्य स्थानीय

आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही किया जाता था। यदि एक स्वावलम्बी इकाई के रूप में था और जो कुछ उत्पादन होता था उसका उपयोग वहीं कर लिया जाता था। इस सबके लिए परम्परागत कृषि पद्धति ही ठीक थी। किन्तु सम्यता के विकास के साथ मानव की आवश्यकताएं बढ़ती गईं। भारत में भी गाँवों का पृथक्करण (Isolation) समाप्त हुआ और कृषि में व्यापारीकरण (Commercialisation) की प्रवृत्ति का उदय हुआ। विनिष्ठीकरण (Specialisation) के इस युग में उत्पादन पद्धतियों में आमूल-मूल परिवर्तन लाये बिना उत्पादन क्षेत्र में अपना प्रभुत्व कायम रखना कठिन हो गया। भारत में इस सताब्दी के मध्य तक कृषि की प्राचीन पद्धति का ही धोल-बाला था



## कुँपे से सिंचाई

और यही का कृषि व्यवसाय अत्यन्त घाटे (Loss) का घण्टा बन कर रह गया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत कृषि पद्धतियों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाये गए। कृषि के विकास की दृष्टि से ये परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण हैं।

भारतीय कृषि पद्धति की नवीन प्रवृत्तियाँ—

भारत की कृषि पद्धति की कतिपय उल्लेखनीय प्रवृत्तियाँ निम्नांकित हैं—

1. विस्तृत खेती (Extensive Cultivation)—भूमि एक ऐसा प्राकृतिक साधन है जिसमें मानव प्रयत्नों से वृद्धि नहीं की जा सकती। किन्तु कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि की जा सकती है। ऐसा करना तभी सम्भव है जब देश की बेकार पड़ी हुई भूमि को वैज्ञानिक साधनों की सहायता से कृषि योग्य बनाया जा सके। इस प्रकार से कृषि भूमि के क्षेत्र में वृद्धि करने के प्रयत्नों को हम विस्तृत खेती कहते हैं। इससे भूमि पर आश्रित जनसंख्या को अधिक रोजगार व बड़ी हुई आमदनी प्राप्त होती है।

भारतवर्ष में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् विस्तृत खेती के अनेक प्रयास किये गये। बौद्ध जंगलों को साफ करके, रेगिस्तान में सिंचाई की व्यवस्था करके तथा नये कृषि भूखण्डों का पता लगाकर खेती करने के प्रयत्न उल्लेखनीय हैं। उड़ीसा की दण्डकारण्य योजना, तराई की सादर योजना व राजस्थान में उत्तरी नहरों द्वारा सिंचाई की योजनाएँ विस्तृत खेती की कतिपय महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं। भारत में 1950-51 में जहाँ 13.15 करोड़ हेक्टर भूमि पर खेती की जाती थी वहाँ 1965-66 में यह क्षेत्रफल 15.49 हेक्टर हो गया।\*

अब भारतवर्ष में विस्तृत खेती को अधिक व्यापक क्षेत्र में लागू करना सम्भव नहीं है क्योंकि एक ओर तो जंगलों को साफ करना अन्य व्यापक दृष्टियों से लाभदायक नहीं है और दूसरी ओर अब अधिक भूमि उपलब्ध ही नहीं है। इसलिए कृषि विकास की दृष्टि से विस्तृत खेती पद्धति का सहारा लेना अब अधिक लाभदायक नहीं होगा।

2. यंत्रिक खेती (Mechanised Farming)—भारतीय कृषि के साधनों के विद्युत्पन का अध्ययन करते समय हमने यहाँ के परम्परागत

कृषि उपकरणों की उपयोगिता के सम्बन्ध में विचार किया था। कृषि विकास में उन्नत यंत्रों एवं उनके द्वारा की जाने वाली यांत्रिक खेती का महत्वपूर्ण स्थान है।



यांत्रिक कृषि का तात्पर्य यह है कि पशुओं एवं मनुष्यों द्वारा किये जाने वाले कुछ कार्य यंत्रों की सहायता से किए जाएं। यह यांत्रिक कृषि पूर्ण अथवा आंशिक हो सकती है। पश्चिमी देशों में मानवीय श्रम के अभाव में पूर्ण यांत्रिक खेती की दिशा में प्रयास हो रहे हैं। यांत्रिक कृषि में ऐसे यंत्रों का प्रयोग किया जाता है जो छोटे छोटे कार्य कर सकें और कृषि के लिए सुविधायें प्रदान कर सकें। कुछ यंत्र हैं—ट्रेक्टर जिनका प्रयोग परम्परागत हलों के स्थान पर किया जाता है; कम्बाइन्ड ड्रिल (Combined Drill) जिसकी मदद से खाद व बीज एक साथ बोले जा सकें, हार्वेस्टर जो फसल की कटाई में सहायक है, कपास चुनने का यन्त्र, धालू निकालने का यन्त्र, गन्ना पेरने का आधुनिक यन्त्र, बिजली की मोटर, डीजल व तेल से चलने वाले पम्पिंग सेट आदि।

भारतवर्ष में यांत्रिक कृषि के पक्ष एवं विपक्ष में अनेक तर्क दिए जाते हैं। यांत्रिक खेती के पक्ष में दलीलों की जाती है कि इससे (1) कृषि



उत्पादन में वृद्धि (2) श्रमिकों की कुशलता में वृद्धि (3) लागत व्यय में कमी (4) निचार्ज की व्यवस्था में सुधार (5) व्यापारिक कृषि को प्रोत्साहन (6) सामाजिक व्यवस्था में सुधार (7) दीर्घकाल में अधिक रोजगार, आदि लाभ प्राप्त होये। इसके विपरीत यह कहा जाता है कि यांत्रिक खेती से भारतीय अर्थ व्यवस्था में अनेक दोष उत्पन्न हो जाने का भय है। ये संभावित कठिनाइयाँ हैं—(1) कृषकों में बेरोजगारी, (2) भारत में कृषि जोत का छोटा होना, (3) कृषकों का निर्धन होना, (4) यंत्रों को चलाने के लिए प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की कमी, (5) शक्ति के साधनों का अभाव (6) जनसंख्या के बढ़ते हुए आकार को काम देना सम्भव नहीं (7) भारत में यंत्रों का अभाव आदि।

उपरोक्त दलीलों को देखने के पश्चात् यह कहा जा सकता है कि सिद्धान्त रूप में कृषि का यांत्रीकरण सामंदायक है किन्तु हमारी अर्थ-व्यवस्था की कुछ कठिनाइयों को देखते हुए इसे अभी कुछ सीमित क्षेत्रों में ही लागू किया जाना चाहिये। यंत्रों का उद्देश्य मानव की प्रश्रयपना करना नहीं बल्कि कृषक की सहायता करना है। सरकारी कृषि एवं सांख्यिक क्षेत्र में कृषि फार्म यांत्रिक कृषि के उपयुक्त क्षेत्र हैं।

भारतवर्ष में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान यांत्रिक कृषि के अनेक प्रयत्न किये गये। देश में चार बड़े यांत्रीकृत फार्म जम्मू-कश्मीर, मीनाज (मध्य प्रदेश), मुरतगढ़ व जेतसरे (दोनों राजस्थान) में हैं। देश में विश्व बैंक की सहायता से एक 'केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन' की स्थापना की गई है। भारतीय कृषकों ने अनेक यंत्रों का प्रयोग प्रारम्भ कर दिया है। सन् 1961 की गणना के अनुसार भारत में उन्नत इस्पात के हलों (Ploughs) की संख्या 5,83,72 हजार थी। शक्ति से चलने वाले गन्ना पेरने के यंत्र 33,000 तेन तथा बिजली से चलने वाले निचार्ज के पम्प जमना: 2-30 लाख तथा 1-60 लाख एवं कृषि के कार्यों के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले ट्रैक्टरों की संख्या 31 हजार थी।

सामान्य कृषक की विदग्धता एवम् कृषि जोनी का उचित आकार न होने के कारण यांत्रिककरण के मार्ग में कठिनाइयाँ हैं। इसलिए अभी सहकारी एवम् सरकारी स्तर के बड़े फार्मों को छोड़कर कृषि के क्षेत्र में आंशिक यांत्रिक कृषि को लागू करना ही उचित होगा।

### 3. फसलों का हेर फेर (Crop Rotation) —

कृषि भूमि पर निरन्तर फसलें उगाते रहने में मिट्टी में पकावट की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मिट्टी की उर्वराशक्ति में इस कमी के परिणामस्वरूप कृषि पैदावार में ह्रास होने लगता है। इस कमी को दूर करने की एक परम्परागत पद्धति है—फसलों का हेरफेर या फसल चक्र (Rotation of crops)। हमारे किसान सदियों से इस पद्धति को जानते हैं और आवश्यकतानुसार इसका प्रयोग भी करते हैं। इस पद्धति के अंतर्गत एक ही भूमि पर अनेक फसलें बारी-बारी से बाई जाती हैं। ऐसा करने से एक फसल में होने वाले उर्वराशक्ति के ह्रास की दूमरी फसल से क्षतिपूर्ति करली जाती है। उदाहरण के लिए सायाधानों के निरन्तर बाँते रहने की अपेक्षा यदि बीच में दालें बोई जाती हैं तो सायाधानों की प्रति एकड़ पैदावार में वृद्धि हो जाती है।

फसल चक्र से मिट्टी की उर्वरता बढ़ने के साथ-साथ मिट्टी का कटाव रुकता है। इस हेर फेर से फसलों की कीटाणुओं व रोगों से भी बचत होती है। भारत में यह पद्धति बहुत अनुकूल है।

### (4) मिश्रित फसलें (Mixed Cropping) —

भूमि की उर्वराशक्ति में होने वाली कमी की क्षति पूर्ति के लिए मिश्रित फसलों की पद्धति का भी अनुसरण किया जाता है। इस फसल मिश्रित पद्धति में एक ही साथ दो या अधिक फसलें बोई जाती हैं। खरीफ में बाजरा, मूँग, मोठ, ज्वार, अरहर, उरद, मक्का आदि तथा रबी में गेहूँ, चना, जौ, ज्वार आदि फसलों का एक साथ बोया जाना फसल मिश्रण के ही उदाहरण हैं। इस प्रकार दोहरी या अनेक फसल



पौध संरक्षण कार्यक्रमों में विदेशी मुद्रा की कठिनाई को दूर करने, प्रशिक्षण की व्यवस्था करने व स्थानीय संगठनों का सहयोग लेने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

#### (6) सघन कृषि कार्यक्रम (Intensive Agricultural Programme) —

मागत में विस्तृत क्षेत्रों की सम्भावनाएं बहुत कम हैं। अतएव कृषि पैदावार में वृद्धि के सघन कृषि कार्यक्रमों की अनिवार्यता अनुभव की जाने लगी है। सघन कृषि में सिंचाई के उन्नत साधन, उन्नत बीज व खाद उन्नत कृषि उपकरण, साख की मुविषा आदि साधनों का आदर्शनम प्रयोग करके कृषि पैदावार में वृद्धि करने का प्रयत्न किया जाता है।

भारतवर्ष में सघन कृषि के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों से प्रयत्न किये जा रहे हैं। सन् 1961-62 में जिला सघन कृषि कार्यक्रम (Intensive Agricultural District Programme तथा (IADP) का आरम्भ किया गया। सन् 1964-65 में सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम (Intensive Agricultural Area Programme) की शुरुआत की गई। इस समय देश के 15 जिलों में यह कार्यक्रम चल रहा है।\*

कृषि पद्धति की वर्तमान प्रवृत्तियों में कृषि अनुसंधान, भू-संग्रहण, आदि की भी सम्मिलित किया जा सकता है जिनसे कृषि विकास में बहुत सहायता मिलती है। भारतीय कृषि पद्धति में अब भी काफी प्रयत्न करने की सम्भावना है।

#### सारांश

कृषि हमारे जीने का तरीका (Way of life) भी माना जाता है।

कृषि के निक्षेप के कारण —

(1) कृषि हाथ से सम्पन्न। (2) मजदूर से सम्पन्न (अ) भूमि के छोटे छोटे टुकड़े, (ब) उचित मजदूर का समाय (3) कृषक से

संबंधित (अ) कृषक की अनिष्टा, (ब) अज्ञानता, (स) दक्षिणदिता, (द) माय्यवादिता (4) कृषि के साधनों से संबंधित—(अ) बीज, (ब) खाद, (स) पशु, (द) सिंचाई, (य) विस्त, (र) बीजार । (छ) कृषि पद्धति से संबंधित ।

उन्नत कृषि पद्धति के साम—

(1) उत्पादन मात्रा में वृद्धि, (2) उत्पादन की उन्नत विस्म, (3) उत्पादन व्यय में कमी, (4) समय व थम की बचत, (5) प्राकृतिक साधनों का सदुपयोग, (6) भूमि की उर्वराशक्ति का कम ह्रास, (7) रोजगार में वृद्धि, (8) कृषकों की आय में वृद्धि, (9) उद्योग धंधों को उत्तम व पर्वति सामग्री, तथा (10) विदेशों पर से कृषि सामग्री की निर्भरता में कमी ।

भारतीय कृषि पद्धति की नवीन प्रवृत्तियाँ—

(1) विस्तृत होती—भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इसके अनेक प्रयास किये गये किन्तु अब कृषि विकास की दृष्टि से यह पद्धति अधिक लाभदायक नहीं है ।

(2) यांत्रिक होती—इसमें ऐसे यंत्रों का प्रयोग किया जाता है जो छोटे 2 कार्य कर सकें व कृषि के विकास के लिये सुविधायें प्रदान कर सकें । भारत में चार बड़े यंत्रीकृत फार्म हैं ।

(3) फसलों का हेरफेर—भारत में यह पद्धति बहुत अनुकूल है ।

(4) मिश्रित फसलें—इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है । यह पद्धति कृषि की उन्नति के लिये लाभदायक है ।

(5) पौध संरक्षण—भारत में फसलों की रोगों, कीड़ों आदि से लगभग 600 करोड़ रु० की हानि होती है । इस दिशा में "पौध संरक्षण, संगरोध, तथा मंडार निर्देशालय" के निदेशन में पौध संरक्षण कार्य किए जा रहे हैं ।

(6) सघन कृषि कार्यक्रम—सन् 1961-62 में "जिला सघन कृषि कार्यक्रम" (IADP) को प्रावजन किया गया। सन् 1964-65 में 'सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम' (IADP) की शुरुआत की गई। देश के 15 जिलों में यह कार्यक्रम चल रहा है।

### प्रश्न

1. भारत में कृषि के विछोड़ने के क्या-क्या कारण हैं ?
2. "उन्नत कृषि पद्धति का महत्व स्पष्ट कीजिये।
3. भारतीय कृषि पद्धति को समझाते हुये उसकी सबसे पद्धतियों का वर्णन कीजिये।

## अध्याय 8

### सामुदायिक विकास

#### COMMUNITY DEVELOPMENT

“समस्त भारत में मानव क्रियाओं के ये (सामुदायिक विकास) केन्द्र ऐसे ज्योति स्तम्भ (Lamp Posts) हैं जो घने अंधकार प्रकाश फैला रहे हैं। यह प्रकाश उस समय तक फैलना रहेगा जब तक कि भारत भूमि आलोकित न हो उठे।” — श्री जवाहरलाल नेहरू

भारत में सामुदायिक विकास एवं राष्ट्रीय सेवाओं का प्रारम्भ अमेरिका की प्रेरणा से हुआ। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् राष्ट्रीय प्रगति के लिए ‘अधिक अन्न उपजाओ और मजदूरी’ (Grow More Food Enquiry Committee) की निवारकों पर, सामुदायिक विकास योजनाओं का आरम्भ हुआ।

अर्थ—

‘सामुदायिक’ शब्द अंग्रेजी भाषा के ‘कम्युनिटी (Community)’ शब्द का हिन्दी रूपान्तर है, जिसका अर्थ किसी विशेष ‘बसती अथवा समूह’ से है। सामुदायिक विकास से हमारा आशय किसी गाँव या मण्डल के विकास की सामूहिक योजना से है। ‘इण्डिया’ 1967 के अनुसार “सामुदायिक विकास आरम्भ-महायत्ना का यह कार्यक्रम है जिसे ग्रामबासी स्वयं नियोजित करें और स्वयं ही क्रियान्वित करें तथा जिसमें राज्य की ओर से वित्तीय तथा तकनीकी सहायता मिले।”\*

*“It is a programme of aided self to be planned and implemented by the villagers themselves, the Government offering only technical guidance financial assistance.”*

योजना आयोग (Planning Commission) के अनुसार "सामुदायिक विकास वह पद्धति है जिसे ग्रामीण विस्तार एजेंसी द्वारा ग्रामवासियों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन को पूर्ण रूप से सुधारने की प्रक्रिया संवर्धनीय योजनाएँ प्रारम्भ करना चाहती हैं।

इस प्रकार सामुदायिक विकास योजनाएँ वे कार्यक्रम हैं जिनके द्वारा जन सहयोग (Public Co-operation) के आधार पर ग्रामीण परिदृष्टि व अज्ञानता को दूर करना है।

**सामुदायिक विकास एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं में भेद—**

सामान्यतः इन दोनों का अर्थ ग्राम या कृषि विकास के सदर्भ में ही प्रयुक्त किया जाता है। फिर भी इन दोनों में कुछ भिन्नता है—

1. सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का क्षेत्र राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रमों की अपेक्षा बड़ा होता है।

2. सामुदायिक विकास योजना एक पद्धति है किन्तु राष्ट्रीय विस्तार सेवाएँ एक साधन हैं।

3. सामुदायिक विकास योजना सम्पूर्ण ग्रामीण जीवन के व्यापक विकास पर आर देती है जबकि राष्ट्रीय विस्तार योजना केवल कृषि विकास कार्यक्रमों से ही सम्बन्धित होती है।

4. सामुदायिक विकास कार्यक्रमों पर राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं की अपेक्षा अधिक व्यय होता है।

सन् 1953 में बलरामराव देवड़ा समिति की सिफारिशों पर इनका अन्तर्गत समाप्त कर दिया गया।

**इन योजनाओं का महत्व (Importance)**

ग्रामीण विकास के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक साधकान् साधन है। इसके अन्तर्गत सामाजिक भाव के साथ-साथ उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्न किए जाते हैं जिससे एक इन्टिग्रेटेड ग्रामीण समाज तथा विकासोन्मुख भाव व्यक्तता का विकास हो सके। इस अन्धोत्तन



से गरीबी व अमीरी के भेद को दूर करने के प्रयत्न किए जायें जिससे हमारे गांवों में रहने वाले वास्तविक स्वतन्त्रता के प्रभु अनुभव कर सकें। ग्रामों के बहुमुखी विकास के महान् उद्देश्यों के ये योजनाएँ चलायी जा रही हैं। श्री एस. के. डे के अनुसार सामूहिक विकास योजना एक ऐसा उद्योग है जिसका परिणाम चतुर भाली अत्यन्त सावधानी से करता है। यह योजना जंगल के समान नहीं है जिसमें मुक्त व्यापार की तरह वृक्ष वनस्पतियाँ भी हैं।"

इन कार्यक्रमों से ग्रामीण क्षेत्र की जनता को विकास के लिए मिलती है, कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है, यातायात, पशु सहकारिता, सिंचाई योजनाएँ आदि का विस्तार होना है तथा महत्वपूर्ण उपलब्धि जनता के दृष्टिकोण में परिवर्तन आने की है।

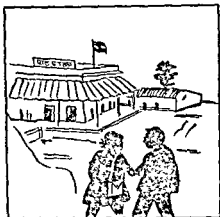
योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले कार्यक्रम—

ये योजनाएँ अपनी सहायता आप करो (Help your self) कार्यक्रम हैं जिनको क्रियान्वित करने का भार स्वयं ग्रामवासियों पर सरकार तो केवल मार्ग दर्शन, प्राविधिक तथा वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इन परियोजनाओं का संचालन पंचायत राज संस्था ऐच्छिक संगठनों एवं राज्य स्वी देखरेख में चलता है। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत निम्नोक्त कार्यक्रम चलाये जाते हैं—

1. कृषि विकास—नवीन यंत्र व पद्धतियों की सहायता उत्पादन वृद्धि, सिंचाई के साधनों की व्यवस्था, भूक्षरण (Soil erosion) की रोकथाम, सहकारी विपणन, पशु-पालन आदि का विस्तार करके कृषि की सहायता की जाती है।

2. शिक्षा का प्रसार—देश के दूरस्थ भागों में बच्चों को शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा एवं सर्वांगीण विकास की शिक्षा का प्रबन्ध किया जाता है।

3. यातायात सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में ग्रामीण सड़क एवं यातायात के साधनों का विकास उद्देश्यनीय है।



## शिक्षा प्रसार

4. ग्रामीणों का विकास—भारतीय अर्थ व्यवस्था में इन उद्योगों को पुनर्जागृत कर अधिक रोजगार देने का प्रबन्ध किया जाता है।

5. स्वास्थ्य सेवाएँ—इन योजनाओं के जरिये ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबन्ध किया जाता है।

6. आवास व्यवस्था—ग्रामीण क्षेत्रों में गृह निर्माण कार्यक्रमों को चलाया जाता है।

7. प्राबिधिक प्रशिक्षण—ग्रामीण विकास के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के शिक्षण की व्यवस्था की जाती है।

8. समाज एवं महिला कल्याण कार्य—इन योजनाओं के द्वारा समाज के विपक्षी बर्गों, स्त्रियों एवं बालकों के कल्याण के कार्यक्रम चलाये जाते हैं।

संक्षेप में, हम यह कह सकते हैं कि ग्रामीण विकास के सभी कार्यक्रम इन योजनाओं में सम्मिलित किये जाते हैं।



## स्वास्थ्य सेवाएँ

**सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की प्रगति०**

भारत सरकार ने अमेरिका की फोर्ड फाउन्डेशन से आर्थिक सहायता लेकर सर्व प्रथम इन योजना का प्रारम्भ उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में सितम्बर सन् 1948 में पाइलट प्रोजेक्ट (Pilot Project) के रूप में किया। सेवाग्राम, बम्बई तथा मद्रास में भी इसी प्रकार के कृत्रिम प्रयोग किये गए। इन सब की सफलता से प्रभावित होकर भारत सरकार ने 2 अक्टूबर सन् 1952 को भारत के विभिन्न भागों में 55 क्षेत्रों पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया। ग्राम-सभाओं में स्वास्थ्यम्बुज एवं स्वशिक्षण के आधार पर स्वयं योजना द्वारा कलाएँ

जाने वाले इस कार्यक्रम को पंचायतों, सहकारी समितियों एवं विकास मण्डलों द्वारा प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था की गई ।

ये कार्यक्रम खण्ड की इकाइयों (Units of block) में चलाये जाते हैं । इस खण्ड इकाई में लगभग 100 गाँव आते हैं जिनका क्षेत्रफल 190 से 520 वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या लगभग 60 से 70 हजार होती है ।

प्रथम योजना के अन्तर्गत 1200 खण्ड स्थापित करने का लक्ष्य था । योजना में इन पर 46.02 करोड़ रुपये खर्च किया गया । प्रथम योजना के अन्त में देश में 1,069 खण्ड थे जिनके अन्तर्गत 1,06,00 गाँव तथा 6.9 करोड़ जनसंख्या आ चुकी थी ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन कार्यक्रमों को देश भर में फैलाने का प्रस्ताव किया गया । योजना के अन्त में 3,100 खण्ड थे जिनके अन्तर्गत 20.9 करोड़ जनसंख्या आ चुकी थी ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में इन पर लगभग 288 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है । योजना के अन्त तक लगभग 40 करोड़ जनसंख्या इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत आ चुकी थी । इस योजना में अतिरिक्त रोजगार देने के सस्तेखर्चीय प्रयत्न किये गए । तृतीय योजना की अवधि में 12 जनवरी सन् 1958 को राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council) ने 'सामुदायिक विकास अध्ययन दल' द्वारा प्रस्तावित 'पंचायत राज' (लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण) की स्थापना सम्बन्धी सिफारिश स्वीकार कर ली । तदनुरूप जम्मू-कश्मीर, केरल तथा मध्यप्रदेश के अतिरिक्त सभी राज्यों में 'पंचायती राज' की व्यवस्था की लागू कर दिया गया है । इसके अन्तर्गत ग्राम, खण्ड एवं जिला-स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को विकास एवं प्रशासन सम्बन्धी विशिष्ट अधिकार एवं क्षतिपूर्ति प्रदान की गई है । ग्राम स्तर पंचायत राज का मुख्य आधार तीन संस्थाएँ पंचायत, सहकारी समिति तथा पाठशाला है । विकास ... निर्वाचन प्रणाली से चुनी हुई



पंचायत राज्य

पंचायत उत्तरदायी होती है। आर्थिक कार्यों के क्षेत्र में सहकारी समिति तथा मौसमिक, सांस्कृतिक एवं अन्य प्रवृत्तियों के लिए पाठशाला सामुदायिक केन्द्र के रूप में कार्य करती है।

वर्तमान स्थिति—31 जनवरी सन् 1969 को देश में 5,265 सामुदायिक विकास समूहों के जिनके अन्तर्गत 5,66,900 गांवों में बसने वाली 40-46 करोड़ जनसंख्या लाभ उठा रही थी।\*

वित्तीय व्यवस्था—सामुदायिक विकास योजनाओं के संचालन के लिए वित्तीय साधनों की व्यवस्था जनता एवं सरकार दोनों ही मिलकर करते हैं। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामवासी किसी एक कार्य को प्रारम्भ करते हैं और उसमें अपना स्वयं, धन या सामान देते हैं। इन योजनाओं के लिये केन्द्रीय व राज्य सरकारें आवर्त्तक खर्च (Recurring expenses) का आधा-आधा तथा अनावर्त्तक व्यय (non recurring expenses) का 3:1 के अनुपात में बाँटती हैं। 31 मार्च सन् 1966 तक जन-सहयोग की राशि 151-30 करोड़ रुपये आँकी गई है जो सामुदायिक विकास पर किए गए कुल सरकारी खर्च का 32 प्रतिशत है। प्रारम्भ से लगाकर तृतीय योजना के अन्त तक इन कार्यक्रमों पर 502-22 करोड़ रुपये सरकार द्वारा व्यय किये गये हैं।

संयोजन (Organisation)—

सामुदायिक विकास योजनाओं का संयोजन विभिन्न स्तरों पर इस प्रकार किया जाता है—

केन्द्र स्तर पर (At the Centre level)—भारत सरकार का कृषि, सामुदायिक विकास एवं सहकारिता मंत्रालय इस कार्यक्रम के लिए पूर्ण उत्तरदायी है। मूल नीति के प्रश्नों का निर्धारण उच्च-स्तरीय समिति द्वारा होता है। अन्य मंत्रालयों से सहयोग स्थापित करने के लिए विभिन्न समितियाँ हैं।

राज्य स्तर पर ( At the State level )—राज्य स्तर पर इन कार्यक्रमों का उत्तरदायित्व राज्य विकास समिति पर होता है जिसका अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होता है । कतिपय मंत्रीगण इस समिति के सदस्य एवं विभाग प्रायुक्त ( Development Commissioner ) इस समिति का सचिव होता है । विस्तृत प्रायुक्त सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को नियामित करता है तथा विभिन्न विभागों के विकास कार्यों में समन्वय स्थापित करता है ।

जिलास्तर पर (At the District level) —जिलाधीन (Collector) की अध्यक्षता में गठित जिला विकास समिति एवं जिला परिषद् जिला विकास कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं । जिने की सभी पंचायत समितियों के अध्यक्ष, जिले के विधान सभा के सदस्य व समस्त राज्य जिला परिषद् के सदस्य होते हैं । जिला परिषद् एवं जिला विकास समिति विकास कार्यों का संचालन करते हैं ।

ब्लॉक स्तर पर (At the Block level) —ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति इन कार्यक्रमों के निर्माण संचालन के लिए उत्तरदायी है । पंचायत समिति के सदस्य उम्र छेक की श्राम पंचायतों के सरपंच (अध्यक्ष) तथा कुछ सहचरण (Co-opted) किये गये महिला एवं निम्नो जातियों के प्रतिनिधि होते हैं । ब्लॉक का प्रशासन चलाने के लिये एक विकास अधिकारी ( B. D. O ) तथा कुछ प्रसार अधिकारी होते हैं ।

ग्राम स्तर पर (At the Village level) — ग्राम स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यों के लिए ग्राम पंचायत एवं ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता (V. L. W ) उत्तरदायी होते हैं । ग्राम में एक विकास कार्यों के निष्पन्नियों का जानकारी होगा है और यह दृष्टि के धारणा कार्य क्षेत्रों में भी कार्यवाही को सहायता करता है ।

इस प्रकार हमारे देश में सामुदायिक विकास योजनाओं का संरक्षण पूर्णतः उन्नत (Democratic) है ।

## कमियाँ (Shortcomings)—

सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की भारत में शान्तिकारी आन्दोलन की संज्ञा दी जाती है। किन्तु अभी इन योजनाओं की सफलता के मार्ग में अनेक बाधाएँ हैं—

1. प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी—देश में इन योजनाओं के लिये प्रशिक्षित कार्यकर्त्ताओं की कमी है। राष्ट्रीय सामुदायिक विकास अध्ययन एवं अनुसन्धान परिषद् अब देश भर में चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की देख-रेख करती है। आशा है यह कमी शीघ्र ही दूर हो जायेगी।

2. कर्मचारियों का दल—जन-साधारण के इस आंदोलन में कार्यकर्त्ताओं का उचित व्यवहार आवश्यक है। किन्तु इस आंदोलन में सगे कुछ कर्मचारियों के व्यवहार से जनसाधारण इस ओर आकर्षित नहीं हो पाता। अतः इन कर्मचारियों के उचित व्यवहार के लिए प्रयत्न किये जाने चाहिये।

3. कार्यक्रमों की दृश्यता—इन योजनाओं के कार्यक्रम व विशेष अनि विस्तृत एवं दृश्य है। परिणाम स्वरूप किसी भी क्षेत्र में सगठित प्रयत्न करके निश्चित फलों की प्राप्ति नहीं की जा सकती।

### कमियाँ—

1. प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव
2. कर्मचारियों का दल
3. कार्यक्रमों की दृश्यता
4. दीर्घपूर्ण प्रायमिकताएँ
5. वित्तीय साधनों पर अधिक जोर
6. जन सहयोग का अभाव
7. पंचायत राज संस्थाओं के दीप

4. दीर्घपूर्ण प्रायमिकताएँ—यह आन्दोलन मूलतः दृष्टि विकास के समकक्ष चलने वाला है किन्तु उचित मोड़-मोड़ के अभाव में सदस्यों



एवं अन्य निर्माण कार्य ही अधिक हुए हैं और कृषि विकास के कार्यक्रम गौण हो गये हैं ।

5. वित्तीय साधनों पर अधिक जोर—इन योजनाओं में अधिक-तर वित्त प्राप्ति के उपायों एवं वित्तीय साधनों के उपयोग पर ही अधिक जोर दिया गया है । इन योजनाओं का लक्ष्य जन-साधारण में जागृति करना होना चाहिये ।

6. जन सहयोग का अभाव—जन-साधारण में चेतना का अभाव है इसलिये ये कार्यक्रम जनता में लोकप्रिय नहीं हो पाये । मूल रूप में जहाँ इन कार्यक्रमों का लक्ष्य स्वावलम्बन एवं आत्मनिर्भरता है वहाँ ये योजनाएं अधिकांश क्षेत्रों में सरकारी योजनाएं बनकर रह गई हैं और वांछित जन-सहयोग का अभाव रहा है ।

7. पंचायत राज संस्थाओं के दोष—ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव और अनुचित दलबन्धियों के कारण जनता का पूरा विश्वास नहीं जम पाया है । परिणाम स्वरूप पंचायत राज संस्थाएँ इस क्षेत्र में वांछित कार्य नहीं कर पाई हैं ।

सफलता के लिए सुझाव—

जैसा पहले स्पष्ट किया जा चुका है ये कार्यक्रम सभी वांछित सफलता प्राप्त नहीं कर सके हैं । यह हमारे युग का एक बहुत बड़ा प्रयोग है और इसकी सफलता की घोर विषय की बात है । इसलिये हमें कुछ रचनात्मक प्रयत्न करके आंदोलन को सफल बनाना चाहिये । यहाँ हम कुछ सुझाव दे रहे हैं—

1. इन आंदोलन में सम्मिलित विद्ये जाने वाले सभी कार्यक्रम सुनिश्चित होने चाहिये । अत्यधिक महंगाराशी (over ambitious) योजनाओं का निर्माण बन्द कर देना चाहिये ।

2. कार्यचारियों को उचित प्रशिक्षण देने के साथ-साथ उनके लिए आचार संहिता (Code of conduct) आदि बना दिये जाने चाहिये ताकि जनता उनके व्यवहार से संतुष्ट रह सके ।

3. जन सहयोग प्राप्त करने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि इन योजनाओं का महत्व एवम् उद्देश्य जनता में अधिक से अधिक प्रचारित किया जाना चाहिये ।

4. विभिन्न सरकारी विभागों में समन्वय ( Co-ordination ) स्थापित किये बिना सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों को तेजी से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता । इसके लिए केन्द्र, राज्य, जिला एवं खण्ड स्तर पर समन्वय समितियाँ स्थापित की जानी चाहिए ।

5. शिक्षा का प्रसार किये बिना प्रजातन्त्र में किसी भी आन्दोलन को सफलतापूर्वक नहीं चलाया जा सकता । पंचायत राज संस्थाओं की सफलता का रहस्य शिक्षा के प्रसार में ही निहित है । कुछ समय तक प्रौढ़ शिक्षा व समाज शिक्षा के कार्यक्रमों को युद्ध-स्तर ( War level ) पर चलाया जाना चाहिये ।

6. सामुदायिक विकास के नाम पर किये जाने वाले अनावश्यक व्यय रोकना, परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को इसमें सम्मिलित करना एवं विस्तृत जन-सहयोग प्राप्त करने के उपाय भी इस दिशा में सहायक होंगे ।

उक्त अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम अधिक सफल नहीं हुए हैं किन्तु यह समझना भूल होंगे कि ये कार्यक्रम सर्वथा असफल रहे हैं । इनसे भारतीय ग्रामों में एक नया वातावरण तैयार हुआ है । यदि इस देश में प्रजातन्त्र एवं आर्थिक नियोजन को सफल बनाना है तो इन कार्यक्रमों को मुहड़ आधार पर प्रतिस्थापित करना होगा क्योंकि "विस्तार सेवाएँ एवं सामुदायिक संस्थाएँ लोकतन्त्र के प्राण हैं ।"

### सुझाव—

1. सुनिश्चित योजनाएं
2. कर्मचारियों का प्रशिक्षण
3. जनता में प्रसार
4. विभिन्न विभागों में समन्वय
5. शिक्षा का प्रसार
6. अन्य सुझाव

## अध्याय 9

### भारतवर्ष में सहकारिता आन्दोलन

---

#### CO OPERATIVE MOVEMENT IN INDIA

“यदि सहकारिता अस्तित्व में आए तो भारतीय भारत की सबसे बड़ी आशा समाप्त हो जायेगी।”

साहू कृषि आयोग

“सहकारिता लोकतंत्र की सम्पदा एवं संरक्षित है।”

भारत का युग सहयोग का युग है। विश्व की समूची समस्याओं का हम आन्तिमपूर्ण सहयोग के आधार पर सम्भव है। भारतवर्ष में भी सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में सहकारिता का उदय हुआ है। यहाँ हम सहकारिता का अर्थ एवं उसके महत्व का अध्ययन करेंगे।

#### सहकारिता का अर्थ (Meaning of Co-operation) —

जब अधिक अथवा सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कुछ व्यक्ति स्वेच्छा से (Voluntarily) मिलकर प्रयत्न करें तो उसे हम सहकारिता अथवा सहयोग (Co-operation) कहते हैं। यह पद्धति पूँजीवाद (Capitalism) तथा समाजवाद (Socialism) दोनों ही पद्धतियों से उत्तम मानी गई है। इसमें व्यक्ति मिलकर उत्पादन के सब उपादान (factors) जुटाते हैं। शक्तिहीन तथा अकेले व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के सहयोग से भी भौतिक सुविधाएँ प्राप्त करके जीवन स्तर (standard of living) को ऊँचा बना सकते हैं। सहकारिता के द्वारा समाज में फैली हुई रुढ़ियों को भी हटाया जा सकता है। इस प्रणाली में व्यक्तिगत लाभ का स्थान सामाजिक सेवा (Social good) के सेती है। प्रतिस्पर्धा (Competition) को जगह सहयोग का-

उद्योग हो जाता है। सहकारिता एक विस्तृत और व्यापक विचार-धारा है। आजकल की सम्पत्ता में यह हमारे जीवन का ढंग (way of life) बन गया है।

सहकारिता के सम्बन्ध में दो गई कुछ प्रमुख परिभाषाएँ निम्न हैं—

1. प्रो. सेलिगमेन के अनुसार—“सहकारिता का पारिभाषिक अर्थ उत्पादन और वितरण में प्रतियोगिता का परित्याग तथा सभी प्रकार के मध्यस्थों (Middlemen) की आवश्यकता समाप्त कर देना है।”

2. संबंधी गौडन तथा ब्रोयन के शब्दों में—“सहकारिता आर्थिक संगठन का एक विशिष्ट रूप है, जिसमें लोग सुनिश्चित व्यावसायिक नियमों के अनुसार निश्चित व्यावसायिक उद्देश्य (Business purposes) के लिये मिलकर काम करते हैं।”

3. सर हारिस प्लन्केट के अनुसार—“सहकारिता वह भाव्य सहायता है जो संगठन द्वारा अधिक प्रभावपूर्ण (effective) हो जाती है।”

4. सहकारी आयोजन समिति (Co-operative planning Committee) ने सहकारिता को इन शब्दों में परिभाषित किया है—“सहकारी समिति एक ऐसी संस्था है जिसमें व्यक्ति समानता (equality) के आधार पर आर्थिक हितों की उन्नति के लिए स्वेच्छा से (voluntarily) सम्मिलित होते हैं।”

5. श्री सी. आर. फे. (C. R. Fay) के मतानुसार—“सहकारी समिति हीन व्यक्तियों की संस्था है जो व्यापारिक कार्यों के लिये प्रारंभ की जाती है और जिसमें हीन व्यक्ति सम्मिलित रूप में अपनी तथा अन्य व्यक्तियों की दुर्बलता त्याग करके नयी शक्ति प्रदान कराते हैं।” एक अन्य स्थान पर श्री फे (Fay) ने कहा है कि, “सहकारी समिति एक ऐसी संस्था है जो हीन (poor) व्यक्तियों के द्वारा व्यापारिक

उद्देश्यों के लिए स्थापित की जाती है। उसका संचालन सर्वोच्च स्तर पर होता है और जिसने भी व्यक्ति इनमें सम्मिलित होता है उसकी समिति के काम को उनी अनुपात (proportion) में विभाजित करने को प्रस्तुत रहते हैं जिस अनुपात में उन्होंने समिति की सेवा प्राप्त (in proportion to patronage) की हों।”

### सहकारिता की विशेषताएं (Characteristics of Co-operation)

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सहकारिता की निम्नांकित विशेषताएं हैं:—

1. सदस्यता की एच्छिकता (Voluntary character)—सहकारी संस्थाओं का मूल आधार सदस्यता की एच्छिकता है। समिति की सदस्यता ग्रहण करने के लिये किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता।

2. सदस्यता की स्वतन्त्रता (Freedom of membership)—प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी जाति, वर्ग अथवा लिंग भेद के समिति का सदस्य बन सकता है। इसकी सदस्यता सब लोगों के लिए खुली होती है क्योंकि इनमें रोक रहित नीति की अपनाया जाता है।



3. समानता (Equality)—सहकारी समिति के सभी सदस्यों का स्तर बराबर होता है और वे सभी संचालन में समान रूप से भाग ले सकते हैं।

4. एक सबके लिये व सब एक के लिये (Each for all and all for each) — यह सिद्धान्त सहकारिता की मुख्य विशेषता है। इसी आदर्श पर सहकारी समितियाँ कार्य करती हैं।

5. प्रजातन्त्रात्मक संगठन (Democratic set up) — सहकारी समितियों का संगठन व प्रबन्ध प्रजातान्त्रिक ढंग पर होना है और बैठकों में एक व्यक्ति को एक ही वोट देने का अधिकार होता है (One member one vote principle)।

6. आर्थिक आवश्यकताओं (Economic necessities) को पूरा करने का उद्देश्य — सहकारी समिति एक विशेष आर्थिक उद्देश्य को लेकर चलाई जाती है। इससे समाज के पिछड़े हुए और दुर्बल व्यक्तियों को संरक्षण मिलता है और वे अपनी आर्थिक उन्नति करते हैं।

7. नैतिक गुणों (Moral qualities) पर जोर — यह आन्दोलन सदस्यों में मित्रभाव, सहृदयता, पारस्परिक मेलजोल और नैतिक गुणों के उत्थान पर ध्यान देता है।

सहकारिता की विशेषताएँ

1. एकीयता
2. स्वतन्त्रता
3. समानता
4. एक सबके लिए व सब एक के लिये
5. प्रजातन्त्रात्मक संगठन
6. आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने का उद्देश्य
7. नैतिक गुण
8. प्रतिद्वन्द्विता का अन्त
9. मध्यमों का नाश
10. सेवा भावना

8. प्रतिद्वन्द्विता (Competition) का अन्त — सहकारी समितियों के निर्माण से पलायन प्रतिद्वन्द्विता (Cut throat Competition) का अन्त हो जाता है।

9. मध्यमों का नाश (Elimination of Middlemen) — सहकारी समितियों द्वारा व केवल प्रतिद्वन्द्विता का अन्त होकर उत्पादन

वृद्धि होती है वरन् उत्पादक एवं उपभोक्ताओं के बीच मध्यस्थों का भी घन्ट हो जाता है ।

10. सेवा भावना (Spirit of Service)—ये समितियाँ भौतिक लाभ की अपेक्षा समाज तथा सदस्यों की सेवा पर अधिक जोर देती हैं । समाज सदस्यों या उपभोक्ताओं पर दबाव या थोका डालकर लाभ कमाना सहकारिता आन्दोलन का उद्देश्य नहीं होता ।

सहकारिता का महत्व (Importance of Co-operation)—

"सहकारिता" पूंजीवाद एवं समाजवाद दोनों ही प्रणालियों में उत्तम मानी गई । इस पद्धति में व्यक्तिगत लाभ का स्थान सामूहिक हित में लेता है । इसके द्वारा शक्तिहीन तथा अकेले व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर सभी भौतिक सुविधाएं प्राप्त करके अपना जीवन स्तर ऊँचा उठा सकते हैं । सहकारिता एक व्यापक और विस्तृत विचारधारा है जिसे आचरण की सम्पत्ता में जीने का तरीका (way of life) माना जाता है । सहकारिता उत्पत्ति तथा वितरण के क्षेत्र में होने वाली अनावश्यक प्रतिযোগिता (Competition) को समाप्त कर देती है । विदेशों में सहकारिता अनेक क्षेत्रों में सक्रिय रही है सहकारी समितियाँ समाज में छिड़े हुए दोषों को दूर कर नए जीवन की मांगों को प्रतिष्ठित करने में सहायता करती हैं । सहकारिता से समाज के दुर्बल व्यक्तियों में आत्म विश्वास की भावना बढ़ती है और उनका हाथ बन्द हो जाता है । ये समितियाँ सदस्यों को नैतिक, सैक्युलर, प्रशासनिक एवं सामाजिक लाभ भी प्रदान करती हैं ।

सर मैल्कम डार्लिंग (Sir Malcom Darling) के शब्दों में—

"एक अच्छी सहकारी समिति में मुद्रमेषात्री, चिट्ठू लबी, शराबखोरी और जुआबाजी सभी कम हो जाते हैं और उनके स्थान पर परित्याग, आत्म शिक्षण, ईमानदारी, "मिठाई, विद्युत्, स्वच्छता और वास्तविक अज्ञानता पाया जाता है ।"

भारत में सहकारी आन्दोलन का इतिहास (History of Co-operative movement in India)—

सन् 1882 में लार्ड रिपन को सर विलियम वेडरबर्न और म्याया-घोश रानाड़े ने ग्रामीण ऋण की समस्या को हल करने के लिये सहकारी कृषि बैंकों की स्थापना का सुझाव दिया था। सन् 1897 में सर फ्रेडरिक निकलसन ने तथा 1901 में दुमिश जांच समिति ने ग्रामीण साख के लिए ग्रामीण सहकारी बैंकों की स्थापना का सुझाव दिया।

भारत में सहकारी आन्दोलन का वास्तविक सूत्रपात सन् 1904 में ही हुआ जबकि सरकार ने सहकारी साख समिति अधिनियम (Co-operative Credit Societies Act 1904) बनाया। इस कानून के अन्तर्गत केवल सहकारी साख समितियाँ बनाई जा सकती थीं जिनका उद्देश्य ऋण देना और जमा प्राप्त करना ही था। सहकारी साख समितियों को दो भागों में बांटा गया—(1) ग्रामीण, और शहरी कुछ समय बाद ही इस कानून में कमियाँ नज़र आने लगीं जिनके कारण आन्दोलन की व्यवस्था, साम वितरण की व्यवस्था व केन्द्रीय संस्थाओं की स्थापना की व्यवस्था इस कानून के अन्तर्गत नहीं थी।

अतः इस कानून में सुधार करने के लिए सन् 1912 में दूसरा सहकारी अधिनियम पास किया गया जिसके अन्तर्गत गैर-साख समितियाँ (Non credit Societies) भी स्थापित की जा सकती थीं। केन्द्रीय साख संस्थाओं का गठन तथा समितियों का नए सिरे से वर्गीकरण इस नियम की दो और उल्लेखनीय बातें हैं। इन सुधारों के परिणाम-स्वरूप सहकारी आन्दोलन तेजी से फैलने लगा। सन् 1914 में सर एडवर्ड मेकलेन के नेतृत्व में एक समिति सहकारी आन्दोलन की जांच के लिए बनाई गई जिमने अनेक सुझाव दिए। सन् 1919 में मोन्टेगू के अन्तर्गत सहकारिता प्रांतीय विधय बना दिया

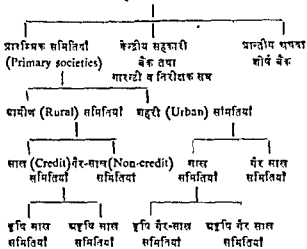


गया। अमग-पलग प्राप्ति में इससे सम्बन्धित कानून बनाए गए। सन् 1926 के शाही कृषि आयोग (Royal Commission on Agriculture) तथा सन् 1931 की भारतीय बैंकिंग जांच समिति (Indian Banking Enquiry Committee) के प्रतिवेदनों से भी आन्दोलन को बल मिला। सन् 1929-33 की विवशतापी मंदी ने आन्दोलन को बहुत घबरा पहुँचाया। कृषि पदार्थों का मूल्य बहुत कम होने से समितियों का क्षण हूबने लगा। परिणामस्वरूप कई समितियों को अपना कार्य बन्द करना पड़ा। सन् 1935 में रिजर्व बैंक के कृषि साख विभाग (Agricultural Credit Department) की स्थापना की गई जिसने आन्दोलन की विस्तार से जांच की।

द्वितीय महायुद्ध काल में सहकारी आन्दोलन का विकास हुआ। इस अवधि में अनेक सहकारी संस्थाएँ खोली गईं जो लोगों की उचित मूल्य पर वस्तुएं बेच सकें। वस्तुओं की कीमत बढ़ने से किसानों की हालत सुधरी और सहकारी संस्थाओं का विकास हुआ। सन् 1945 की सहकारी नियोजन समिति ने आन्दोलन की कमियों का पता लगाया और सुझाव दिया कि प्रारम्भिक सहकारी समितियों को बहुबन्धी सहकारी समितियाँ (Multipurpose Co-operative societies) में बदल देना चाहिए।

सन् 1945 के बाद सहकारी आन्दोलन का तेजी से विस्तार हो रहा है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद योजना आयोग (Planning Commission) का गठन किया गया जिसने सहकारिता के विकास पर बहुत जोर दिया। सन् 1957 में सर मेल्कम डालिंग ने सहकारिता के प्रगति एवं भावी विकास के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत की। सन् 1960 में श्री बंकिमलाल मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसने ग्रामीण साख पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। भारत में सहकारी संस्थाओं का वर्तमान आँका इस प्रकार है—

## सहकारी समितियाँ



उपयुक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि हमारे देश की सहकारी संस्थाओं को छोटे और बड़े तीन भागों में बाँटा जाता है—

1. प्रारम्भिक सहकारी समितियाँ—इन समितियों में सदस्यों का सीधा सम्बन्ध रहता है। केन्द्रीय संस्थाएं इन समितियों की मदद करती हैं। ये समितियाँ साख व नैर-साख सभी कार्यों के लिए बनाई जा सकती हैं। ये समितियाँ फिर दो भागों में बाँटी जा सकती हैं—(क) ग्रामीण और (ख) शहरी। द्वितीय योजना के अन्त में इन समितियों की संख्या 2 लाख 10 हजार को थक देश में 3,32,400 समितियाँ हैं।\*

2. केन्द्रीय संगठन—ये संगठन प्राथमिक समितियों को संघटित करने और उनकी मदद करने के लिए बनाए जाते हैं। सन् 1966-67 में केन्द्रीय सहकारी बैंकों की संख्या 346 † थी।

\* India 1969 p. 268

† India 1969—p. 269

3. राज्य अथवा शीर्ष बैंक—केन्द्रीय सहकारी संस्थाओं की सहायता करने के लिए राज्य स्तर पर एक शीर्ष बैंक होता है। भारत में ऐसे बैंकों की संख्या 25 है।

भारतवर्ष में साख सहकारिता (Co operative Credit Movement)

भारतवर्ष में ग्रामीण साख का महत्व सर्व विदित है। परन्तु ग्रामीण साख के साधनों की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। जिनको गुप्तार एवं अन्य कार्यों के लिए साख की आवश्यकता होती है जिनको पूरा करने में सहकारी साख (Co-operative credit) संस्थाएँ भी किमान की सहायता करती हैं। हमारे देश में पाई जाने वाली कुल सहकारी समितियों का लगभग 79 प्रतिशत भाग सहकारी साख समितियों के रूप में है। ऐसा होना स्वाभाविक भी है क्योंकि हमारे यहाँ सहकारी आन्दोलन मुख्यतः किसानों को सस्ते ब्याज दर पर ऋण दिलाने के लिए ही प्रारम्भ हुआ था। सन् 1904 का सहकारी कानून वेदम साख समितियों के गठन पर ही प्रकाश डालता था। इस प्रकार हमारे देश के सहकारी ढाँचे में साख सहकारी समितियों का विशेष स्थान है, इसलिए यहाँ हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे।

कृषि सहकारी समितियों का संगठन एवं कार्य-प्रणाली

भारत में सहकारी संस्थाओं को तीन भागों में बाँटा जा सकता है—ग्राम्य या राज्य के स्तर पर राष्ट्रीय बैंक या शीर्ष बैंक (Apex Banks) जिला, तहसील या ताल्लुका स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक, तथा गाँव अथवा सहरी में समुदाय के स्तर पर प्राथमिक सहकारी साख समितियाँ यहाँ हम प्राथमिक कृषि (ग्राम्य ग्रामीण) सहकारी साख समिति के संगठन एवं कार्य पद्धति पर विचार करेंगे जिनसे कृषि क्षेत्र की अन्य समितियों की कार्य प्रणाली की सामान्य जानकारी प्राप्त आयेगी।

गाँवों में पाई जाने वाली ये समितियाँ रेडिक्ल (Raiffeisen) विद्याओं पर आधारित हैं। इनकी कार्य प्रणाली एवं संगठन के बारे में निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं—

(1) सम्पत्ति (Membership)—एक ही गाँव ग्राम्य गाँव के 10 वर्ग (15 वर्ग की जगह के ऊपर) इयक निवासर समिति ग्राम्य

कर सकते हैं। सदस्यों की संख्या 100 से अधिक नहीं होती है, किन्तु दूसरी पंचवर्षीय योजना के अनुसार बड़ी समितियों की सदस्य संख्या 500 तक कर दी गई है। सदस्य संख्या सीमित होने से सदस्यों में पारस्परिक सहयोग स्थापित हो जाता है।

2. कार्य क्षेत्र (Area of operation)—प्रायः एक गाँव में एक ही सहकारी साक्ष समिति की स्थापना हो सकती है। किन्तु व्यवहारिकता में कुछ राज्यों में कई गाँव एक समिति के अन्तर्गत आ जाते हैं। श्री संजुष्टाल मेहता कमेटी 1960 का मत था कि एक समिति के अन्तर्गत आने वाले गाँवों की दूरी समिति के प्रधान कार्यालय से 3-4 मील से अधिक नहीं होनी चाहिये। व्यवहार के दृष्टिकोण से इसका क्षेत्र "पंचायत का कार्य क्षेत्र" होना अधिक उत्तम रहेगा।

3. रजिस्ट्रेशन (Registration)—समिति का गठन करने हेतु 10 या अधिक वयस्क (major) व्यक्ति राज्य के सहकारी विभाग के रजिस्ट्रार के पास आवेदन पत्र देकर समिति का पंजीयन (registration) करा सकते हैं।

4. उद्देश्य (Aims)—इनका उद्देश्य सदस्यों के भौतिक तथा नैतिक स्तर (material and moral standards) दोनों को ऊँचा उठाना है। सदस्यों की सहायता करने के साथ-साथ उनके नैतिक गुणों, जैसे—मितव्ययता (thrift), समय की पावन्दी (punctuality) मिलनसारी, स्वावलम्बन (self-help) आदि की भावनाओं को जागृत करती है।

5. दायित्व (Liability)—प्रारम्भिक कृषि साक्ष समितियों के सदस्यों का दायित्व असीमित होता है। अपरिमित दायित्व (unlimited liability) के सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक सदस्य समिति के ऋण को व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से चुकाने के लिये बाध्य होता है। सदस्य प्रायः एक गाँव के होते हैं इसलिये आपसी विश्वास बना रहता है। इस कारण से वे असीमित दायित्व स्वीकार कर लेते हैं। अब ग्रामीण क्षेत्र में भी सीमित दायित्व समितियाँ बड़ी संख्या में स्थापित हो गई हैं।

6. प्रबन्ध (Management)—इन समितियों का प्रबन्ध प्रजा-सन्धारमक (democratic) तथा अवैतनिक (honorary) होता है। इनके प्रबन्ध का उत्तरदायित्व दो समितियों पर होता है—(घ) साधारण सभा (General Meeting) तथा (आ) कार्यकारिणी समिति या प्रबन्ध समिति (Managing or Executive Committee)। साधारण सभा में समिति के सभी सदस्य सम्मिलित हैं। साधारण सभा की बैठक साधारणतया वर्ष में एक बार होती है। साधारण सभा पदाधिकारियों का चुनाव करना, वैतनिक सेक्रेटरी की नियुक्ति करना, बजट पास करना, रजिस्ट्रार और आय-व्यय निरीक्षकों की रिपोर्टें पर विचार करना आदि कार्य करती है। यह समिति वार्षिक लाभ के वितरण और रक्षित कोष (Reserve fund) के उपयोग निर्धारित करने के प्रतिरिक्त सदस्यों को दिये जाने वाले आदि प्रश्नों पर भी विचार करती है।

कार्यकारिणी सभा के कार्यों में प्रमुख हैं—साधारण सभा के आदेशों का पालन करना, ऋण देना, ऋण वसूली तथा धन की व्यवस्था करना, वार्षिक हिसाब-किताब साधारण सभा में प्रस्तुत करना आदि।

7. पूंजी (Capital)—समिति प्रवेश शुरू, अथ पूंजी (Share capital), जमाएं (Deposits) तथा ऋण के द्वारा कार्यशील पूंजी (Working capital) का प्रबन्ध करती है। कहीं-कहीं समितियों के अंश (Shares) नहीं होते। बाह्य साधनों से प्राप्त पूंजी में केन्द्रीय सहकारी बैंक, राजकीय बैंक तथा अन्य समितियों का योगदान उल्लेखनीय है।

8. निरीक्षण एवं जांच (Audit and supervision)—इन समितियों के काम का निरीक्षण एवं हिसाब किताब की जांच का उत्तरदायित्व राज्य के सहकारी विभाग के रजिस्ट्रार पर होता है। वह निरीक्षक तथा अवेक्षकों की नियुक्ति करता है जो इस कार्य को करते हैं।

9. ऋण का उद्देश्य (Object of loans)—साधारणतया ऋण उत्पादन कार्यों (Productive purposes) के लिए दिये जाते हैं,

जैसे—बीज, खाद औजार आदि खरीदना । किन्तु कभी-कभी किसानों को साहूकार के चुंगल से बचाने के लिये धनुस्पादक बायीं तथा पुराने ऋण को चुकाने के लिए भी ऋण दिए जाते हैं ।

10. ऋण की वसूली (Recovery)—ये समितियाँ अपने सदस्यों से ऋण वसूली के लिये कित्तें (Installments) कर लेती हैं और भुगतान ऐसे समय पर माँगा जाता है जबकि सदस्यों के लिये चुकाना सुविधाजनक हो । ऋण वसूली ठीक समय पर होनी चाहिए । केवल वास्तविक कठिनाई होने पर ही वसूली स्थगित (postpone) की जाती है ।

11. जमानत (Security)—सैद्धान्तिक रूप से इन सहकारी समितियों में ऋण के लिए वास्तविक जमानत सदस्यों की ईमानदारी और चरित्र (honesty and character) है । परन्तु व्यवहार में ऋण देते समय समिति अन्य दो सदस्यों की जमानत लेती है जिससे ऋणों के हूबने का डर कम हो जाता है ।

12. व्याज की दर—इन समितियों की व्याज दरें महाजन एवं बाजार की प्रचलित दरों से काफी कम होती हैं । परन्तु ये दरें अत्यन्त नीची हों तो गाँव वाले अनावश्यक ऋण लेने को प्रेरित होंगे ।

13. लाभ का वितरण—जहाँ अंश पूंजी नहीं होती, उस समिति का सारा लाभ रक्षित कोष में जमा कर दिया जाता है । जहाँ अंश पूंजी होती है वहाँ लाभ का कम से कम  $\frac{1}{2}$  भाग रक्षित कोष में जमा करने के बाद शेष लाभ 10% शिक्षा, परोपकार और अन्य सामाजिक कार्यों के लिए व्यय हो सकता है । बचे हुए लाभ को निश्चित सीमा तक सदस्यों में सांझा (dividend) के रूप में बाँटा जा सकता है ।

14. पचायत (Arbitration)—समिति और सदस्यों के बीच होने वाले झगड़े या मतभेद को निपटाने के लिये पचायत का गठन होता है । इससे व्याजालयों से नहीं जाना पड़ता है और समय, शक्ति तथा धन में बचत हो जाती है ।

15. समिति का भंग होना—(Dissolution)—रजिस्ट्रार को यह अधिकार है कि यदि वह किसी समिति के कार्य से संतुष्ट नहीं है तो उसे भंग कर दे।

**भारतवर्ष में कृषि सहकारी संस्थाओं की वर्तमान स्थिति—\***

भारतवर्ष के सहकारी क्षेत्र में कृषि सहकारी संस्थाओं का वाहुल्य है। यहाँ हम कुछ कृषि सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली एवं वर्तमान स्थिति का अध्ययन करेंगे।

1. सहकारी कृषि साख (Agricultural credit) समितियाँ—भारत में इन समितियों का महत्व बहुत है। ये समितियाँ कृषकों को सस्ते ब्याज दर पर ऋण प्रदान करती हैं। सन् 1966-67 में इन समितियों की संख्या 1-97 लाख थी। इन समितियों की सदस्य संख्या 2-70 करोड़ थी।

2. भूमि विकास बैंक (Land Development Banks)—ये बैंक कृषकों को दीर्घकालीन साख ऋण प्रदान करने का कार्य करते हैं। राज्य स्तर पर एक केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक होता है जो उस राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित प्राथमिक बैंकों को ऋण देता है। देश में 18 केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक (Central Land Mortgage Banks) हैं। प्राथमिक भूमि बन्धक बैंकों की संख्या 707 है। इन बैंकों की सदस्य संख्या 12-55 लाख तथा कार्यशील पूंजी 173-59 करोड़ रुपये है। 1966-67 में इन बैंकों ने 40-84 करोड़ रुपये का ऋण दिया।

3. सेवा सहकारी समितियाँ (Service co-operative Societies)—यह प्राणीय व्यक्तियों का वह संगठन है जो अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिये

पारस्परिक सहायता एवं सहकारिता के सिद्धान्त के आधार पर संगठित हुए हैं। द्वितीय योजना के अन्तर्गत बहुउद्देशीय सहकारी समितियों को अधिक व्यापक रूप में संगठित कर सेवा सहकारी समितियों में परिणत कर दिया गया। ये समितियाँ कृषकों के लिए साख, विपणन, सिंचाई, कृषि-उपकरण, आदि की व्यवस्था करती हैं। ये समितियाँ कुटीर उद्योगों के कारीगरों की मदद भी करती हैं। ये समितियाँ सहकारी कृषि (Co-operative Farming) का मार्ग प्रशस्त करती हैं। इन समितियों का ग्रामीण ऋण व्यवस्था में बहुत महत्व है।

4. विपणन समितियाँ (Marketing Societies)—कृषि में सहकारी विपणन समितियों का महत्व बहुत है। इनके द्वारा कृषकों को पर्याप्त मात्रा में अन्न, अपनी उपज का उचित मूल्य एवम् पदार्थों की सुरक्षित रखने की सुविधाएँ प्राप्त हो जाती हैं। देश में 3,295 प्राथमिक विपणन समितियाँ हैं जिनकी सदस्य संख्या 20 92 लाख एवम् कार्यशील पूँजी 76.49 लाख रुपये हैं।

5. गन्ना विक्रय (Sugarcane Supply) समितियाँ—किसान जब गन्ना मोता है तो उसका उचित मूल्य प्राप्त करने के लिये इन समितियों की सहायता ली जाती है। ये समितियाँ मुख्यतः बिहार एवं उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय हैं। प्रारम्भिक समितियों की संख्या 6,488 है जिनकी सदस्य संख्या 26.61 लाख है।

6. सहकारी खेती (Co-operative farming) समितियाँ—अब कृषि विकास के लिए सहकारी खेती का महत्व स्वीकार कर लिया गया है। उपविभाजन व अपसंयोजन को रोकने, कृषि श्रमिकों के पुनर्वास एवं पारिवारिक खेती के लिए ये समितियाँ बहुत उपयोगी हैं। मार्च सन् 1968 में इन समितियों की संख्या 8,582 थी।\*

7. ग्राम्य समितियाँ—इन समितियों में ग्राम्य विपणन समितियाँ, सिंचाई समितियाँ, भवन निर्माण समितियाँ, मछियारों की समितियाँ,



चरबन्दी समितियों, आदि उत्प्रेक्षनीय है जिन्होंने कृषि के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया है।

**कृषि के विकास में सहकारी समितियों का योग—**

*(Role of Co-operative Societies in Agricultural Development of India)*

भारतवर्ष में सहकारिता आंदोलन मुख्यतः कृषि साधन की सुविधाओं के विस्तार हेतु ही प्रारम्भ किया गया। सत्यवान् कृषि सहकारिता के क्षेत्र में अन्य गैर साधन (Non-credit) समितियों की भी स्थापना की गई। कृषि क्षेत्र में सहकारी समितियों से निम्नांकित लाभ प्राप्त हुए हैं—

1. आर्थिक लाभ (Economic Advantages)—के रूप में इन समितियों द्वारा सबसे पहला लाभ व्याज दर में कमी के रूप में कृषकों को प्राप्त हुआ है। वही पहले साहूकार मनमानी व्याज दर वसूल करता था वही अब 6 से 8 प्रतिशत व्याज की दर पर ऋण प्राप्त हो जाता है।

2. ऋण शक्तता से मुक्ति—सहकारी समितियों एवं भूमि बचक (भूमि विभाग) बैंकों ने घासीय ऋण प्रणाली में बहुत कमी की है। इससे किसान की स्वतंत्र रूप से धाने बढ़ने के अवसर मिले हैं।

3. सुपन्न साधन—घामान दिनों में ऋण की आवश्यकता एवं अन्य सुलभ स्रोतों के अभाव पर सहकारी संस्थाओं ने साधन प्रदान कर किसानों की बहुत सेवा की है।

4. बचत—सहकारी समितियों के सदस्यों में अनुशासक सचय (savings) की प्रवृत्ति को रीढ़ कर कृषकों में बचत की भावना (habit) को प्रोत्साहन दिया है। यह बचत देश के आर्थिक विकास में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखती है।

5. कृषि विपन्न समितियों द्वारा किसान की अपनी छात्र का उचित सुख विमना प्रारम्भ हो गया है। इन विपन्न समितियों ने कृषकों की कठिनाई को दूर करने में सहायता करने, उचित सुखों के प्राप्त

होने तक स्वयं उपार देने एवं अन्य दृष्टियों से कृषि की महाद सेवा की है। आज देश में लगभग 3,196 कृषि विपणन समितियाँ हैं।

6. कृषि उत्पादन में वृद्धि—  
सहकारी कृषि, पशु पालन समि-  
तियाँ, सहकारी कुक्कुट पालाएँ  
एवं अन्य सहकारी संगठनों से  
कृषि एवं उत्संबंधी व्यवसायों के  
उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है।

7. उपभोग सहकारिता  
(Consumers Co-operation)  
के जरिए कृषक ने उपभोक्ता के  
रूप में बहुत लाभ उठाये हैं। सस्ती  
एवं पर्याप्त मात्रा में उपभोग की  
वस्तुओं के उपलब्ध होने से कृषक  
की अच्छा जीवन बिताने का  
मकसद मिला है।

### कृषि सहकारिता के लाभ—

1. व्याज दर में कमी
2. ऋण प्रस्तुता से मुक्ति
3. सुलभ साध
4. बचत की आदत
5. कृषि उपज का उचित मूल्य
6. कृषि उत्पादन में वृद्धि
7. उपभोग सहकारिता
8. समाजवाद की ओर
9. सामाजिक विकास
10. गिदा सम्बन्धी लाभ
11. प्रशासनिक लाभ
12. नैतिक लाभ

8. समाजवाद की स्थापना में इन सहकारी संस्थाओं का बहुत  
महत्व है। गोपण मुक्त समाज की स्थापना बिना सूनी जालि के  
इसी आन्दोलन के जरिये संभव है। सहकारी समितियों ने समानता के  
सिद्धान्त से आर्थिक विषमताओं को दूर करने में बहुत प्रयत्न किये हैं।

9. सहकारी समितियों ने सामाजिक बुरादों को दूर करने में  
कृषकों की बहुत सहायता की है। अनेक सहकारी समितियों ने अपने  
सदस्यों को सामाजिक व्यवहारों पर दिये जाने वाले ध्य में कमी करने  
के निर्देश दिये हैं। सहकारी समितियाँ कृषि क्षेत्रों में शिक्षा, चिकित्सा,  
रोकथनी, सफाई एवम् समाज बह्वाण के अन्य कार्य भी करती हैं।

10. शिक्षा संबंधी लाभ (Educative advantages)—सहकारी समितियों ने लोगों के ज्ञान वृद्धि में भी सहायता की है। समिति के नियमों व उपनियमों के सम्बन्ध में उचित जानकारी प्राप्त करने के लिए साक्षर (literate) होना आवश्यक है। यदि सदस्य को किसी महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में उसका पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। इस प्रकार समितियाँ अनुशिक्षण का विद्योत्तर करती हैं। ये समितियाँ जनता को बतलाती हैं कि 'समंजन ही शक्ति है' (Unity is strength)।

11. प्रशासन संबंधी लाभ (Administrative advantages)—ये समितियाँ प्रजातांत्रिक ढंग पर अपना कार्य करती हैं जहाँ सदस्यों के वोट की बहुत कीमत होती है। ऐसी स्थिति में वे अपने मतधिकार (franchise) का उचित उपयोग करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। इससे प्रशासन अधिक कुशल हो जाता है। सब सदस्यों के अधिकार समान होते हैं। इसके अतिरिक्त इन समितियों में काम करने वाले व्यक्ति ही मालिक होते हैं, इसलिये सबसे पारस्परिक मेलजोल होता है और हड़ताल या तालाबंदी (strikes & lock-outs) का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है।

12. नैतिक लाभ (Moral advantages)—मायिक लाभों के साथ-साथ समितियाँ सदस्यों का नैतिक स्तर (moral standard) भी ऊँचा करती हैं क्योंकि अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति ही इन समितियों के सदस्य हो सकते हैं। सर मेलकॉम डार्लिंग (Sir Malcolm Darling) के अनुसार "एक अच्छी सहकारी समिति में मुकदमेबाजी (litigation) फिजूल खर्चों, सराब खोरी और जुमावाजी (gambling) सभी कम हो जाते हैं और उनके स्थान पर परिश्रम, आत्मविश्वास, ईमानदारी शिक्षा, पंचायतें, मितव्ययता (thrift), स्वावलम्बन (self help) और पारस्परिक सहायता (mutual assistance) पायी जाती हैं।

इस प्रकार कृषि के उत्थान में सहकारिता ने बहुत योगदान दिया है।

सहकारी आन्दोलन में कमियाँ—

भारतवर्ष में कृषि सहकारिता का विकास तो हुआ है किन्तु भ्रष्ट भी अनेक कमियाँ हैं जिनका निराकरण किये बिना यह आन्दोलन पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता ।

1. सहकारी समितियों द्वारा कृषक की आवश्यकताओं की आंशिक पूर्ति हो हो पाती है ऐसी स्थिति में वह साहूकारों के चपुल से छुटकारा नहीं पा सकता ।

2. समितियों के पास पूँजी की कमी—सामान्यतया सहकारी समितियों के पास अंश पूँजी छोड़कर अपनी पूँजी नहीं होती । उसे ऋण के लिए अन्य संस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ता है और ऋण नहीं मिलने की स्थिति में समिति का कार्य ठप्प हो जाता है ।

3. सहकारिता का समान विस्तार नहीं है—वैसे ही सहकारी संस्थाओं की कमी है और इन संस्थाओं का क्षेत्रीय वितरण भी असमान है । जैसे बम्बई, मद्रास आदि राज्यों में तो इन समितियों की बहुतायत है परन्तु अन्य राज्यों में कमी है ।

4. सहकारिता के सिद्धान्तों की अनभिज्ञता—इन समितियों के कर्मचारी और प्रबन्धकों का सहकारिता के सिद्धान्तों से अनभिज्ञ होने के कारण आन्दोलन का अधिक विकास नहीं हो सका है ।

5. ब्याज की ऊँची दर—सहकारी समितियों द्वारा दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दर भी ऊँची होती है क्योंकि समिति को भी अन्य संस्थाओं से ऋण लेना पड़ता है ।

6. प्रबन्धकों की स्वार्थपरता—समिति का प्रबन्ध कुछ स्वार्थी लोगों के हाथ में आ जाने पर किसानों को ऋण लेने के लिए रिरवत देनी पड़ती है ।

7. ऋण की जटिलता—सदस्यों को ऋण प्राप्त करने के लिए बापजी कार्यवाही करनी पड़ती है और ऋण बहुत देर से मिलता है । परिणामस्वरूप सदस्यों को साहूकार से ऋण लेना पड़ता है ।

8. बीचकालीन साज का अभाव—सहकारी समितियाँ किसानों

की केवल धनदायीन या मध्यस्थीन ऋण ही देती हैं। भूमि बन्धक बैंकों द्वारा दीर्घकालीन ऋण भी दी जाती है किन्तु वह नगण्य है।

9. समितियों का राजनीतिक प्रयोग—कई सहकारी समितियों के प्रबन्ध राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए इन समितियों का उपयोग करते हैं जिससे सहकारिता का विकास रहता है।

10. कृषकों की अशिखा—किसी भी आन्दोलन की सफलता के लिए शिक्षा का प्रसार आवश्यक है। भारत में किसानों की अशिखा

सहकारी आन्दोलन की कमियाँ

1. किसान की आवश्यकताओं की अशिख पूर्ति
2. पूर्ण की कमी
3. साख सहकारिता का असमान विस्तार
4. सहकारिता के सिद्धान्तों की अनभिज्ञता
5. ब्याज की ऊँची दर
6. प्रबंधकों की स्थाय्यरता
7. ऋण पद्धति की जटिलता
8. दीर्घकालीन साख का अभाव
9. समितियों का राजनीतिक उपयोग
10. कृषकों की अशिखा
11. बनावटी हिमाच-किताब
12. कृषकों में आत्म-विश्वास की कमी
13. असाख समितियों का अभाव

उन्हें सहकारी कार्य प्रणाली को समझने से रोकती है।

11. बनावटी हिमाच-किताब अधिकांश सहकारी समितियों समय पर ऋण का भुगतान (क्रेडिट सहकारी बैंकों को) नहीं कर पाती। सदस्यों पर समय पर ऋण का भुगतान न प्राप्त कर सकने की स्थिति में समिति अवधि से अधिक बकाया (over due) करार दे दी जाती है और वह नया ऋण प्राप्त नहीं कर सकती। ऋण प्राप्त करने के लिए प्रबन्धक झूठे हिसाब-किताब तैयार करते हैं जिससे बेईमानी और जालसाजी बढ़ती है जो सहकारिता के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है।

12. कृषकों में आत्म-विश्वास की कमी—भारत में सहकारिता-

ग्रान्दोलन राज्य सरकारों द्वारा चलाया जाता है जिससे स्वयं कृषकों ने आर्थिक विवशता की भावना पनप नहीं सकती है।

13. कृषि क्षेत्रों में अब भी गैर साक्षर समितियों का प्रभाव है जिसके बिना कृषि का संपूर्ण विकास सम्भव नहीं है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अनेक कारण हमारे सहकारी साक्षर आन्दोलन के मार्ग में रुकावटें डालते हैं लेकिन इन कर्मियों को दूर करना ही होगा। अखिल भारतीय ग्रामीण साक्षर सर्वेक्षणी (1951) ने ठीक ही बताया है, "सहकारिता असफल रही है, परन्तु इसे सफल होना ही चाहिये।"

ग्रान्दोलन की कमियों को दूर करने के उपाय एवं प्रगति—

सहकारी आन्दोलन को सफल बनाने के लिए अखिल भारतीय ग्रामीण साक्षर सर्वेक्षण समिति ने निम्नांकित सुझाव दिए हैं—

1. सहकारिता को पनपाने के लिए सरकार केवल निर्देशन का कार्य ही न करे बल्कि सहकारिता आन्दोलन में साधेदारी भी करे।
2. सहकारी प्रशिक्षण का व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाय।
3. बड़े भाऊदारी की प्राथमिक साक्षर समितियाँ बनाई जाएं। पर अब इस विचार को ठीक नहीं समझा जाता।

4. सहकारी संस्थाओं को पूँजी प्रदान करने के लिए इम्प्रीव्ड बैंक को स्टेट बैंक में बदल दिया जाए। सन् 1955 से ऐसा कर दिया गया है।

इनके अलावा कुछ और भी सुझाव दिए जा सकते हैं—

1. जो समितियाँ निर्धारित आदर्श तक न पहुँची उन्हें समाप्त कर दिया जाए।
2. इन समितियों को अधिक पूँजी प्राप्त करवाने के लिए सरकार, बैंक व अन्य सरवाए कम व्याज दर पर अधिक उधार दें।
3. समितियों के प्रबन्धकों के गैर-वास्तविक कार्यों को रोकने के लिए विधायी ढाँचा सुस्थापित किया जाय।

4. इन समितियों का कार्य शीघ्र पंचायतों के सहयोग से प्रभावशाली बनाया जाय ।

ऊपर बताए गए उपायों में से कई मान लिए गए हैं और तेजी से काम हो रहा है । द्वितीय योजना काल में कई सरकारें शान केन्द्र खोले गए हैं । पूँजी की सुविधाएं बढ़ाने के लिए रिजर्व ने उदार ऋण नीति का निर्धारण किया है । इस प्रकार भारत सहकारिता का भविष्य उज्ज्वल है । ठीक ही कहा गया है कि "में सहकारिता असफल रही है" परन्तु सहकारिता भव्य सफल चाहिये ।"

### सारांश

सहकारिता का अर्थ एवं महत्व—आर्थिक व सामाजिक जीवन की प्राप्ति के लिए कुछ व्यक्ति स्वेच्छा से मिलकर प्रयत्न करें तो इस सहकारिता कहते हैं ।

सहकारिता आर्थिक जीवन की सम्पत्ति में हमारे जीवन का बंधन स्थापित व वितरण में प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर सहकारिता व्यक्तियों में प्रशाननारमक तथा सामाजिक लाभ प्रदान करती है ।

भारत में सहकारी आन्दोलन का इतिहास—

आन्दोलन का वास्तविक मूलपात 1904 में हुआ । 1912 में सहकारी समिति एक्ट बना, जिसके अन्तर्गत असीस सहकारी समिति की बनाई जा सकती थी । 1919 के मोंटफोर्ड सुधारों के अन्तर्गत सहकारिता प्रान्तीय विषय बना दी गई । 1929-1933 की विश्वमंदी के कारण बस्तुओं की कीमतें कम हुई जिससे सहकारी आंदोलन को बढ़ा पड़ा । द्वितीय महायुद्ध के समय किसानों की विपत्ति सुलझा और आंदोलन विकसित हुआ । 1945 की सहकारी नियोजन समिति बस्तुधन्य सहकारी समितियों के गठन की निवारित की । स्वतंत्रता के बाद सहकारी आन्दोलन का तेजी से विकास हुआ ।

वर्तमान ढाँचा—हमारे देश की सहकारी संस्थाएं तीन भाग में बाँटी जा सकती हैं—(1) प्रारम्भिक सहकारी समितियाँ, (2) केन्द्रीय संस्थाएं और (3) राष्ट्रीय या शीर्ष बैंक।

भारतवर्ष में साख सहकारिता—हमारे यहाँ कुल सहकारी समितियों का 70 प्रतिशत भाग साख सहकारी संस्थाओं के रूप में है।

प्रारंभिक कृषि सहकारी साख समिति का संगठन एवं कार्य पद्धति—ये समितियाँ रेकमन-पद्धति पर आधारित होती हैं। इनका कार्य क्षेत्र प्रायः एक गाँव होता है। इन समितियों के सदस्यों का दायित्व असीमित होता है। जब सीमित दायित्व वाली कृषि साख समितियाँ भी स्थापित हो गई हैं। प्रबन्ध सामान्यतया अवैतनिक होता है। इनको ऋण केन्द्रीय संस्थाओं द्वारा प्राप्त होता है। भारत में इन समितियों की संख्या 1.97 लाख है। इन समितियों ने गाँव में साहूकार का एकाधिकार समाप्त कर व्याज की दरें कम कर दी हैं।

सहकारी साख छावरोसन की कमियाँ—ये समितियाँ किसानों की आंशिक आवश्यकताओं की ही पूर्ति कर सकती हैं क्योंकि इनके पास पूँजी की कमी है। साख सिद्धान्तों की अनमिश्रता, व्याज की ऊँची दर कुप्रबन्ध, अगिरा, जालसाजी आदि कुछ और सस्तेसमीय कमियाँ हैं।

सुझाव—सहकारिता पनपाने के लिए राज्य की सक्रिय साझेदारी, सहकारी प्रशिक्षण व पूँजी की सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिये और जो समितियाँ आदर्श तक नहीं पहुँची हैं उन्हें मंजूर कर देना चाहिये।

### प्रश्न

- 1.—'सहकारिता' से आपका क्या तात्पर्य है? इसकी विशेषताएं बतलाइए।
2. सहकारी समितियों के मुख्य भेदों पर टिप्पणी लिखिए।
3. सहकारी समितियों का राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था में महत्व निर्धारण



- कीजिए । उनसे होने वाले मुख्य मामों का वर्णन कीजिए ।
4. किसी प्रारंभिक कृषि सहकारी साख समिति के कार्य एवं प्रणाली का वर्णन कीजिए ।
  5. सहकारी साख आन्दोलन की कमी का उत्प्रेषण करते हुए सुझाव बताइये ।
  6. टिप्पणियाँ लिखिए—  
 (अ) सेवा सहकारी समितियाँ  
 (आ) केन्द्रीय सहकारी बैंक  
 (इ) राज्याधीन या कोष बैंक
  7. "सहकार" का क्या अर्थ है ? सहकारी समितियों के लाभ समझाइये । (राज. बोर्ड, हा. से. I)
  8. भारत में सहकारी साख आन्दोलन की उपलब्धियों का कीजिए । (राज. बो., हा. से. I)
-

## अध्याय 10 कृषि विपणन

### AGRICULTURAL MARKETING

“जब तक कृषि पैदावार के विपणन की समस्या को हल नहीं किया जाता तब तक कृषि की अन्य समस्याओं का हल भी अधूरा रहेगा।”

शाही कृषि सम्योग

“एक अच्छा किसान अपना एक नेत्र हल पर रखता है और दूसरा बाजार पर।”

1. कृषि विपणन का उदय—

प्राचीन भारत में, जबकि प्रत्येक गाँव एक स्वावलम्बी इकाई (Self sufficient unit) था, कृषि उत्पादन के विपणन की कोई समस्या नहीं थी। स्वावलम्बी इकाइयों के विघटन के साथ-साथ कृषि अन्य पदार्थों के विपणन का उदय हुआ। कृषि के व्यापारीकरण (Commercialisation) के पश्चात् तो विपणन की प्रक्रिया अधिक जटिल हो गई। यातायात एवं सदेशवाहन के साधनों के विस्तार के साथ-साथ कृषि पदार्थों के विपणन का क्षेत्र विस्तृत होता गया। कृषि को व्यापारिक भाषा पर प्रतिष्ठित करने के बाद किसानों और उपभोक्ताओं के बीच मध्यस्थों (Middlemen) का एक नया समूह बन गया। आज के इस वैज्ञानिक एवं प्रगतिशील युग में भी भारतीय कृषक की अज्ञानता के कारण कृषि पदार्थों के विपणन से उसे पूरा लाभ नहीं मिलता। वर्तमान भारतीय कृषि पद्धति दोषपूर्ण है। इस बारे में हम विस्तार से इसी अध्याय में आगे विचार करेंगे।

कृषि विपणन का अर्थ—

कृषि अन्य पदार्थों को उचित मूल्य पर बेचने की पद्धति को कृषि विपणन कहा जाता है। किसान को अपने पदार्थों का उचित मूल्य मिल

सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि उचित समय, स्थान और साधन के द्वारा इन पदार्थों को बेचा जाये। संयुक्त राज्य अमेरिका के विपणन के अध्यापकों के राष्ट्रीय संगठन के अनुसार "विपणन के अन्तर्गत वे व्यावसायिक क्रियाएँ आती हैं जिनके द्वारा माल, सेवाएँ आदि उत्पादन से उपभोग तक पहुँचते हैं।"

इस प्रकार हम, संक्षेप में, कह सकते हैं कि कृषि उपज को किसान से उपभोक्ता तक पहुँचाने के लिए जिन प्रक्रियाओं (Processes) की आवश्यकता होती है वे सब कृषि विपणन के अन्तर्गत आती हैं। ये क्रियाएँ निम्नांकित हैं—

- (1) कृषि उपज का संग्रह करके गोदामों में सुरक्षित रखना;
- (2) परिवहन के साधनों की व्यवस्था;
- (3) वस्तुओं का श्रेणीकरण (Grading)
- (4) वस्तुओं का प्रविधिकरण (Processing)
- (5) माप-तोल की सुव्यवस्थित प्रणाली;
- (6) मूल्य-निर्धारण की सुव्यवस्थित पद्धति तथा;
- (7) विक्री का स्थान व पद्धति का निर्धारण।

कृषि विपणन की उक्त क्रियाओं के सम्बन्ध में जोखिम उठाने (Risk bearing) का काम भी कृषि विपणन में सम्मिलित किया जाता है।

**कृषि विपणन का महत्व—**

(Importance of agricultural marketing)—

भारत में कृषि अधिकांश व्यक्तियों के जीविकोपार्जन का साधन है। कृषि विपणन की मुख्यवस्था किसानों के लिए लाभदायक है जबकि कृषि विपणन की दोषपूर्ण पद्धति किसानों एवं उपभोक्ताओं, दोनों के लिए हानिकारक है। यदि विपणन की सुव्यवस्था हो तो किसान को उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा और कृषि विकास की सम्भावनाएँ बढ़ेंगी। दूसरी ओर उपभोक्ताओं को भी उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न

एवं अन्य कृषि पदार्थ मिल सकेंगे । विपणन की मिश्र-मिश्र क्रियाओं में अनेक लोगों को रोजगार मिलता है । कृषि विपणन की समुचित व्यवस्था से उत्पादकों को कच्चे माल की उपलब्धि में कोई कठिनाई नहीं होती है । इस प्रकार मुख्यवर्षित कृषि विपणन की प्रणाली देश के अधिकांश वर्गों के लिए लाभदायक है । कहा जाता है कि भारत में कृषि का महत्व तो है ही किन्तु उससे भी अधिक महत्व कृषि उपज के विपणन का है । भारतवर्ष में कृषि-पदार्थों के विपणन की प्रणाली—

भारतवर्ष में कृषि उत्पादन का बहुत बड़ा भाग गाँवों में ही बेच दिया जाता है । छोटे-छोटे किसानों के पास अपनी जरूरत के अलावा बहुत ही थोड़ी उपज बचती है जिसे बहुधा गाँव में ही महाजन के हाथ बेच दिया जाता है । कुछ किसान निकटवर्ती मण्डियों में भी जाकर अपनी उपज को बेचते हैं । मण्डियों में बिक्री के लिए वे दलाल, आदितिए, एजेन्ट आदि की मदद लेते हैं । ये मध्यस्थ गाँवों में जाकर किसान की उपज को प्रचलित मूल्यों से भी बहुत कम दर पर खरीद लेते हैं । इस प्रकार हम देखते हैं कि किसान अपनी उपज चाहे गाँव में बेचे या मण्डी में, उसे पूरी कीमत नहीं मिलती । कुछ सहकारी बिक्री समितियाँ भी कृषि बिक्री का उचित प्रबन्ध कर रही हैं किन्तु इनकी संस्था आवश्यकता को देखते हुए बहुत कम है ।

**भारत की वर्तमान कृषि-विपणन व्यवस्था के दोष (Defects)**

कृषि पदार्थों की विपणन प्रणाली में कई दोष हैं । इन्हीं दोषों के कारण भारतीय कृषक अपनी उपज का पूरा मूल्य प्राप्त नहीं कर सकता । कुछ प्रमुख दोष इस प्रकार हैं—

1. वस्तुओं के श्रेणीकरण का अभाव—हमारे देश में कृषि पदार्थों के श्रेणीकरण (Grading) पर ध्यान नहीं दिया जाता । अतः बढ़िया किस्म का माल भी धाँटिया माल की दर पर ही बिकता है जिससे कृषक को हानि होती है ।

2. बिक्री की अहदी—किसान निर्धन है और वह पदार्थों की

बिक्री के लिए उचित अवसर की प्रतिष्ठा किए बिना ही बिक्री होकर उन्हें बेच देता है। इस कारण से वह अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं पा सकता।

3. कृषक की प्रतिष्ठा—जीवन के सभी पहलुओं में शिक्षा का बड़ा महत्व है। कृषि पदार्थों के विपणन में भारतीय कृषक की निरक्षरता का व्यापारी और मध्यस्थ अनुचित लाभ उठाते हैं और किसान का शोषण होता है।

विपणन व्यवस्था के शोष

1. वस्तुओं के श्रेणीकरण का अभाव

2. बिक्री की जल्दी

3. कृषक की प्रतिष्ठा

4. साहूकार का अनुचित दबाव -

5. संघर्ष की सुविधाओं का अभाव

6. मान्य सुविधाओं का अभाव

7. बाजार मूल्यों से संबंधित जानकारी का अभाव

8. मध्यस्थों की अधिकता

9. भार लोभ की विप्रेरणा —

10. बाजार की सुगन्धी

11. कीमत निर्धारण की सुविधा का अभाव

12. मानायात की सुविधाओं की कमी...

4. साहूकार का अनुचित दबाव—प्रायः किसान साहूकार के देनदार (debtors) होते हैं इस लिए महाजन किसान की उपज को कम कीमत पर ही आसानी से हथिया लेता है।

5. संघर्ष की सुविधाओं का अभाव—कृषि की पैदावार को सुरक्षित रखने के लिये गोदामों (Godowns) की सुविधाएँ नहीं हैं इसलिए किसान पैदावार को बेचने की जल्दी करता है।

6. मान्य-सुविधाओं का (Credit Facilities) अभाव—हम पहले देख चुके हैं कि भारत में प्राचीन मान्य सम्पत्तियों की एक मध्यस्थित प्रणाली का अभाव है जिससे निर्वन है उसे ऐसी संस्था

की आवश्यकता है जो उसकी उपज की जमानन पर कुछ रकम उधार दे सके और कीमती में वृद्धि होने तक उसकी पैदावार को सुरक्षित रख सके। भारतवर्ष में ऐसी संस्थाओं की कमी है, इसलिए किसान को कम कीमत पर ही पैदावार बेचना पड़ती है।

—7. बाजार-मूल्यों से सम्बन्धित जानकारी का अभाव—मण्डी में प्रचलित भावों की जानकारी किसानों तक पहुँचाने के साधनों के अभाव में महाजन किसानों की उपज को बहुत कम मूल्यों में खरीद लेते हैं।

8. मध्यस्थों की अघिक्ता—किसान और उपभोक्ता के बीच में कई मध्यस्थ होते हैं। ये मध्यस्थ खरीददार और विक्रेता दोनों से ही बर्मीशन लेते हैं। ये मध्यस्थ कई प्रकार के होते हैं, जैसे कच्चा आइ-रिया, पक्का आइरिया, दलाल, एजेंट आदि। ये मध्यस्थ अनेक प्रकार का कमीशन लेते हैं जिससे किसान को उपज का बहुत कम मूल्य मिल पाता है।

9. माप-तौल की भिन्नता—हमारे यहाँ अनेक प्रकार के तौल प्रचलित रहे हैं। कई व्यापारी और मध्यस्थ बाँट और तौल की भिन्नता के कारण किसानों को ठगते हैं। अब सरकार ने सारे देश में दण्डमत्त प्रणाली के समान माप-तौल प्रचलित कर दी है।

—10. बाजार में प्रचलित कुराइयाँ—किसान को मण्डी की पर-स्पर्धियों के अनुसार अनेक प्रकार की लागत-वर्मात, काटा, तुपाई, पत्तेदारी, गीजाला, प्याऊ-पच, चुंगो आदि देने पड़ते हैं। वहीं-वहीं तो किसान को अपनी उपज का बाधा मूल्य भी नहीं मिल पाता।

11. कीमत निर्धारण की गुप्त प्रथा—मण्डी में दलालों और आइरियों द्वारा कीमत निर्धारण के लिए घसमर 'हावा' प्रथा का प्रयोग किया जाता है। इसमें खरीददार और आइरिया करने वाले हाव बपड़े के पीछे रख कर दूसरों से कीमत का निर्धारण करते हैं। इस पद्धति में बेईमानी की जा सकती है जिससे किसान को ही हानि होने की सम्भावना रहती है।

12. यातायात की सुविधाओं की कमी—ग्रामीण क्षेत्रों में अभी यातायात के समुचित साधनों का विकास हो नहीं हो पाया है। इसलिये किसान अपनी उपज को मण्डो तक ले जाने में कठिनाई अनुभव करता है और पैदावार को गाँवों में ही महाजन के हाथ बेचने को बाध्य हो जाता है।

समस्या को हल करने के उपाय एवं प्रगति—

किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले इसके लिए यह आवश्यक है कि मध्यम्यों की संस्था कम हो, बाजार की कृत्रिमता हटाई जाए, यातायात के साधनों का विकास हो और मण्डियों की कार्य प्रणति पर नियंत्रण रखा जाए। यहाँ हम उन उपायों का वर्णन करेंगे जो कृषि पदार्थों के विपणन के दोषों को दूर करने में सफल हो सकेंगे।

1. सहकारी विपणन (Co-operative Marketing)—सहकारी विपणन संस्थाओं के विस्तार से बिन्ही के वर्तमान दोषों को दूर किया जा सकता है। इन समितियों के द्वारा किसानों को अपनी पैदावार का उचित मूल्य मिल सकेगा। किसानों को व्यक्तिगत रूप से बिन्ही में जो कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं वे सभी इन संस्थाओं द्वारा आसानी से दूर की जा सकती हैं। ये समितियाँ अपने सदस्यों के माल को, उचित कीमत आने तक, अपने पास सुरक्षित रखने का प्रबन्ध करती हैं और जरूरतमंद सदस्यों को कुछ रुपया उधार भी देती हैं। ये समितियाँ वस्तु का श्रेणीकरण (grading) भी कर सकती हैं जिससे उत्तम किस्म की वस्तु का अधिक मूल्य प्राप्त होता है। इन समितियों को भी तीन भागों में बाँटा जाता है—(क) प्रारम्भिक सहकारी विपणन समितियाँ, (ख) केन्द्रीय-बिन्ही-संगठन तथा (ग) राज्यीय (state) बिन्ही संगठन। इन तीनों का आपसी मेल-जोल व समन्वय होना आवश्यक है। प्रारम्भिक समितियों की आर्थिक स्थिति प्रायः बहुत सुदृढ़ नहीं होती इसलिये इनका केन्द्रीय-बिन्ही संगठन से सम्बन्ध होना वांछनीय है।

इन समितियों से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं—

- (अ) विपणन के क्षेत्र में सहकारिता के आ जाने से किसानों और खरीददारों के बीच मध्यस्थों की लम्बी शृंखला समाप्त हो जाती है, जिससे उत्पादक को अपनी पैदावार का उचित मूल्य मिल जाता है।
- (आ) ये संस्थाएँ किसानों को अपनी पैदावार का उचित मूल्य दिलाती हैं और जब तक माल न बिक जाए तब तक के लिए साख सुविधाएँ भी प्रदान करती हैं।
- (इ) सहकारी बिक्री संस्थाएँ अपने सदस्यों की पैदावार गोदामों में तब तक सुरक्षित रखती हैं जब तक कि पदार्थों का उचित मूल्य न मिल जाए।
- (ई) ये समितियाँ अपने सदस्यों की उपज का उचित श्रेणीकरण कर खरीददारों को भी लाभ पहुँचाती हैं।
- (उ) ये समितियाँ उत्पादकों को भी निश्चित समय पर कच्चा माल प्राप्त कराती हैं जैसे उत्तर प्रदेश एवं बिहार की गन्ना बेचने वाली सहकारी समितियाँ वहाँ की शक्कर मिलों की गन्ने की पूर्ति (Supply) करती हैं।
- (ऊ) ये समितियाँ अपने सदस्यों को अन्य लाभ भी पहुँचाती हैं जैसे अच्छे बीज, खाद, औजार, कीटाणुनाशक औषधियाँ देना आदि। इन समितियों के लाभ (Profits) का उपयोग भी सदस्यों के हित के लिए ही किया जाता है।

इस प्रकार सहकारी विपणन समितियाँ किसानों के बिक्री सम्बन्धी दोषों के निवारण का अचूक इलाज है। परन्तु भारत में अब भी इन समितियों के निर्माण के मार्ग में बाधाएँ हैं। प्रथम समितियों के पास पूँजी की कमी होती है तथा गोदाम की अधिक आवश्यकता है। यह है कि



समितियों की अगारियों की स्पर्धा (Competition) का मा-  
 करना पड़ता है। अगारों मालों की प्रभावित करने की शक्ति को  
 का प्रभाव करते हैं जिससे माल्य अपनी समिति के प्रति सचेत नहीं  
 और फिर अगारियों के अनुमति में लग जाते हैं।

इन अडिनादों की दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि स-  
 मितियों की पूर्ण बर्दाश्त जाए। माल्यों के लिए भी यह अनिवार्य  
 दिया जाय कि वे अपनी वैसाधार केवल सहकारी समिति के इ-  
 ही रहें।

**भारत में सहकारी विपणन समितियों की प्रगति—**

सहकारी विपणन के सम्बन्ध में व्यवस्थित प्रयत्नों का भार  
 सन् 1951 में हुआ। उत्तर प्रदेश व बिहार तथा की सहकारी विप-  
 समितियों, महागाह और पुत्रराज की बयाम विपणन समितियों का  
 अन्य राज्यों में कुछ समितियों स्थापित की गई। द्वितीय योजनाकाल  
 1,869 प्रारम्भिक सहकारी विपणन समितियों को 'राष्ट्रीय सहका-  
 विकास तथा मोदाम प्रमण्डल' में महापता दी गई। इन सन् 1967  
 भारत में देश में विपणन समितियों की संख्या 3,476 थी।\* इनमें  
 राष्ट्रीय विपणन समितियों की संख्या 24, केन्द्रीय मंडलों की संख्या  
 156 तथा प्रारम्भिक समितियों की संख्या 3,295 थी। इन समितियों  
 की सम्पूर्ण संख्या 21,86,197 तथा कार्यशील पूंजी (working  
 capital) 15,350 लाख रुपए थी।

सूचीय पञ्चवर्षीय योजनाकाल में 600 प्रारम्भिक विपणन समिति-  
 का गठन किया जाने का लक्ष्य था। सभी सहकारी विपणन की कु-  
 मात्रा 200 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष समझी जाती है जो तीसरी योजना

\*India 1969—p. 272 इसमें गुजरात व दूध विक्रय समितियों  
 की संख्या को सम्मिलित नहीं किया गया है।

के अन्त में बढ़कर 400 करोड़ हो जाने का अनुमान था । योजनाबद्ध ढंग में इन समितियों को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एवं अन्य संस्थाओं द्वारा साख्त भी प्रदान की जाएगी ।

2. नियन्त्रित बाजार—कृषि विपणन के दोषों को दूर करने का हमारा उपाय नियन्त्रित बाजारों (Regulated markets) की स्थापना है । इन बाजारों की स्थापना का उद्देश्य बाजार में प्रचलित अनुचित प्रथाओं को दूर कर विपणन को अधिक कुशल बनाना है । इन बाजारों का प्रबन्ध व्यापारियों, उपभोक्ताओं तथा सरकार के प्रतिनिधियों की एक समिति के हाथों में होता है । देश में अब नियन्त्रित बाजारों की संख्या\* 1,880 है ।

3. पदार्थों का श्रेणीकरण (Grading) तथा मानकीकरण (standardisation)—कृषि विपणन को लाभदायक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि पदार्थों के विभिन्न प्रमाण एवं श्रेणियाँ कायम की जाएँ जिससे उत्तम किस्म की वस्तु का उचित मूल्य मिल सके । हमारे देश में श्रेणीकरण का कार्य 'कृषि उत्पादन' (श्रेणीकरण) अधिनियम, 1937 के अन्तर्गत किया जाता है । विदेशी व्यापार के महत्वपूर्ण कृषि पदार्थों का श्रेणीकरण करना अनिवार्य है । घरेलू व्यापार की कुछ वस्तुएँ जैसे धी, चावल, मूँगे आदि के लिए 'एगमार्क' (Agmark) का चिह्न जो शुद्धता तथा अच्छी किस्म का प्रतीक है, निर्धारित किया जा चुका है । पर अभी यह काम बहुत धीमी गति से हो रहा है । अब तक श्रेणीकरण की 444 इकाइयाँ स्थापित हो चुकी हैं ।\*\*

4. गोदामों (Godowns) का निर्माण—कृषि पदार्थों के उचित मूल्य पाने तक उपज को संग्रह करने के लिए गोदाम होने चाहिये ।

\*India 1969—

सरकार ने सन् 1956 में 'कृषि उत्पन्न (विकास व गोदाम) अधिनियम' बनाया, जिसके अन्तर्गत एक केन्द्रीय गोदाम निगम (Central Warehousing Corporation) तथा प्रत्येक राज्य में एक गोदाम निगम स्थापित किए गए। इन निगमों ने मार्च सन् 1961 तक 40 तथा 266 गोदाम बनाए। द्वितीय योजना के अन्तर्गत मण्डियों में 16,70 गोदाम तथा गाँवों में 4,100 गोदाम बनाए गए। तृतीय योजना काल में गाँवों में 2,200 तथा मण्डियों में 9 गोदाम और बनाए गए।

5. मूल्य सम्बन्धी जानकारी का विस्तार—किसानों को बाजार उत्पन्न के बाजार भाव से परिचित करवाने के लिए मूल्य सम्बन्धी सूचनाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। अब रेडियो और समाचार पत्रों के माध्यम द्वारा भी मूल्य की सूचनाएँ देश के सभी भागों पहुँचाई जाती हैं। प्रतिदिन निश्चित समय पर आकाशवाणी के 'श्राद्ध कार्यक्रम' के अन्तर्गत विभिन्न मण्डियों में प्रचलित कृषि पदार्थों के भाव की सूचना रेडियो द्वारा दी जाती है।

6. यातायात के साधनों का विकास—किसान को अपने बाजार तक अपना माल पहुँचाने के लिए सस्ते और कुशल यातायात के साधनों की आवश्यकता होती है। प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत यातायात के विकास की बहुत महत्त्व दिया है। तीसरी योजना में यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि विकसित हुई क्षेत्र में कोई भी गाँव पक्की सड़क से 6.43 कि० मी० और ग्रामीण प्रकार की सड़क से 2.41 कि० मी० (1½ घण्टा) से अधिक दूर नहीं होगा।

7. मापतौल की इकायसय प्रणाली (Metric System)—किसानों को लागू करके तौल के बाटों व मात्रा के माप की विभिन्नता का ख़ात करा दिया गया। इससे विपश्चन में सुगमता हो गई है।

## सारांश

भारतीय कृषि विपणन व्यवस्था असंतोषजनक है।

विपणन का अर्थ—कृषि-जन्य पदार्थों को उचित मूल्य पर बेचने की पद्धति को विपणन कहा जाता है। विपणन के अन्तर्गत गोदामों की व्यवस्था, यातायात के साधन, वस्तुओं का श्रेणीकरण माप-तोल, मूल्य निर्धारण, बिक्री का स्थान, व पद्धति आदि क्रियाएँ आती हैं।

कृषि विपणन का महत्व—इससे किसानों, उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों को लाभ, अनेक व्यक्तियों को रोजगार मिलता है।

भारतीय विपणन व्यवस्था के दोष - (1) वस्तुओं के श्रेणीकरण का अभाव, (2) बिक्री की जल्दी, (3) कृषक की अशिक्षा, (4) सहकारी का अनुचित दबाव, (5) सग्रह की सुविधाओं का अभाव, (6) साल सुविधाओं का अभाव, (7) बाजार मूल्यों से संबंधित जानकारी का अभाव, (8) मध्यस्थों की अधिकता, (9) माप-तोल की मिश्रता, (10) बाजार की बराइरी, (11) कीमत निर्धारण की गुप्त प्रथा व (12) यातायात की सुविधाओं में कमी।

समस्या का हल एवं प्रगति—

(1) सहकारी विपणन—जून 1967 के अन्त में सहकारी विपणन समितियों की संख्या 3,476 थी। तृतीय योजना में 600 नई विपणन समितियाँ बनाई गयीं।

(2) नियन्त्रित बाजार-संख्या 1880

(3) पदार्थों का श्रेणीकरण तथा मानकीकरण।

(4) गोदामों की स्थापना—तीसरी योजना में गाँवों में 2,200 तथा महियों में 980 गोदाम खोल बनाए गए।

## प्रश्न

1. कृषि विपणन किसे कहते हैं, उसका क्या महत्व है? उसके दोषों को दूर करने के सुझाव दीजिये।

सरकार ने सन् 1956 में 'कृषि उपज (विशाल व गोदाम) अविनियम' बनाया, जिसके अन्तर्गत एक केन्द्रीय गोदाम निगम (Central Warehousing Corporation) तथा प्रत्येक राज्य में एक-एक गोदाम निगम स्थापित किए गए। इन निगमों ने मार्च सन् 1961 तक क्रमशः 40 तथा 266 गोदाम बनाए। द्वितीय योजना के अन्तर्गत मण्डियों में 16,70 गोदाम तथा गाँवों में 4,100 गोदाम बन चुके थे। तृतीय योजना काल में गाँवों में 2,200 तथा मण्डियों में 980 गोदाम और बनाए गए।

5. मूल्य जम्बान्धो जानकारी का विस्तार—किमानों को पत्नी उपज के बाजार भाव से परिचित करवाने के लिए मूल्य सम्बन्धी सूचनाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। अब रेडियो और समाचार पत्रों के माध्यम द्वारा भी मूल्य की सूचनाएँ देश के सभी भागों में पहुँचाई जाती हैं। प्रतिदिन निश्चित समय पर आकाशवाणी के 'ग्रामीण कार्यक्रम' के अन्तर्गत विभिन्न मण्डियों में प्रचलित कृषि पदार्थों के भावों की सूचना रेडियो द्वारा दी जाती है।

6. यातायात के साधनों का विकास—किसान को अच्छे बाजार तक अपना माल पहुँचाने के लिए सस्ते और कुशल यातायात के साधनों की आवश्यकता होती है। प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने पक्कियों योजनाओं के अन्तर्गत यातायात के विकास को बहुत महत्व दिया है। तीसरी योजना में यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि विकसित कृषि क्षेत्र में कोई भी गाँव पक्की सड़क से 6.43 कि० मी० और अन्य प्रकार की सड़क से 2.41 कि० मी० (1½ मील) से अधिक दूर नहीं होगा।

7. मापतोल की इशमलव प्रणाली (Metric System)—को लागू करके तोल के बाटों व मात्रा के माप की विभिन्नता का अन्त कर दिया गया। इससे विपणन में सुगमता हो गई है।

## ग्रामीण क्षेत्रों में सहायक व्यवसाय

### SUBSIDIARY OCCUPTIONS IN RURAL AREAS

“भारतीय ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में सहायक उद्योगों का स्थान गीढ़ की इड़ी के समान है।”

प्रस्तावना—

अत्यन्त प्राचीनकाल से ही हमारे आर्थिक जीवन में सहायक व्यवसायों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कृषि के अनिवार्य किये जाने वाले ये व्यवसाय ग्रामीण वर्ग व्यवस्था को समृद्धि प्रदान करने वाले हैं। यद्यपि ये व्यवसाय अनेक प्रकार के हो सकते हैं किन्तु भारतीय ग्रामीणों में उनकी विद्यमानता तीन बातों पर निर्भर करती है—(अ) व्यवसाय के अर्थ सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण, (आ) व्यवसाय के लिए आवश्यक कच्चे माल का गाँव में उपलब्ध होना तथा (इ) निम्न वस्तु के बेचपन (Marketing) की सुविधा।

गाँवों में ये परिस्थितियाँ मिश्र-मिश्र होने के कारण इन व्यवसायों की प्रकृति मिश्र-मिश्र होती है। कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जो सामान्यतः गाँवों में मिलते हैं, जैसे, दूध तथा घी का व्यवसाय, रस्सा-बुनने का काम, सूत कातने का काम आदि। अन्य व्यवसाय ऐसे हैं, जैसे रोजमर्रा के कोड़े पालने का व्यवसाय, ताड़-गुड़ उद्योग आदि। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विभिन्न क्षेत्रों में मिश्र-मिश्र प्रकार के व्यवसायों की विद्यमानता के पीछे वहाँ की वित्तीय परिस्थितियाँ होती हैं। वैसे ये घन्टे के सहायक हैं—प्रधान व्यवसाय नहीं।

सहायक उद्योगों का महत्व—

ये व्यवसाय हमारी ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को समृद्धिदायी बनाते हैं। भारतीय अर्थ व्यवस्था जैसी अर्द्ध-विविशिष्ट स्थिति वाले देशों के

2. जागत्रीय विमान की इन कठिनाइयों का उल्लेख कीजिए जिससे  
उने अपनी उड़ान की बिंदी के सम्बन्ध में सावधान करना पड़ा है।  
इन कठिनाइयों को दूर करने के उपायों पर प्रकाश डालिए ।
3. जागत्रीय बाजारों में प्रचलित मुख्य दोषों का वर्णन कीजिए।  
इन दोषों को दूर करने के उपाय बताइए ।
4. टिप्पणियाँ लिखिए—  
(अ) महङ्गारी विपणन, (आ) निर्दलित बाजार तथा (इ) खोले-  
कागज और मानकीकरण ।
5. भारत में कृषि पदार्थों की विक्रय-स्थितियों के दोषों का वर्णन  
कीजिये ।

(राय. बोटे, हा. से., 1968)

5. आर्थिक समानता—ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाले ये व्यवसाय बड़े उद्योगों की भांति धन के केन्द्रीयकरण को बढ़ावा न देकर विकेंद्रित अर्थ व्यवस्था को जन्म देते हैं। आय एवं धन के वितरण समानता पर आधारित ये व्यवसाय सच्चे समाजवाद के प्रवर्तक हैं।

6. कृषि के पूरक—जैसा पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है ये उद्योग के पूरक (Complimentary) हैं। ये कृषि पर ही आधारित होते हैं और कृषि को भी लाभ पहुँचाते हैं। इन उद्योगों से कृषि विकास में सहायता मिलने के साथ-साथ कृषक की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आता है।

7. अल्प लाभ—इन व्यवसायों में नैतिक व चारित्रिक उत्थान, कलात्मक गौरव की वस्तुओं के निर्माण, कारखाना प्रणाली के दोषों से मुक्ति आदि लाभ भी प्राप्त होते हैं।

इस प्रकार से व्यवसाय भारतीय अर्थ व्यवस्था में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

**कतिपय सहायक व्यवसाय—**

यहाँ हम भारतीय ग्रामों में पाये जाने वाले कतिपय महत्वपूर्ण सहायक व्यवसायों का अध्ययन करेंगे—

1. दूध तथा घी का व्यवसाय (Dairying)—बहते हैं कि प्राचीन भारत में घी और दूध की नदियाँ बहती थीं किन्तु अब इनकी बहुत कमी है। भारत सदा से ही प्रधानतः शाकाहारी (Vegetarian) देश रहा है इसलिए यहाँ दूध-घी का बहुत महत्व है। यद्यपि भारत का प्रति पशु औसत दूध का उत्पादन कम है फिर भी कुल मात्रा की दृष्टि से यहाँ ब्रिटेन का चार गुना, डेनमार्क का पाँच गुना, फ्रांस, स्वीडन का छः गुना तथा न्यूजीलैंड का सात गुना दूध तैयार किया जाता है। सन् 1961 में भारत में दूध का उत्पादन 220 लाख टन था जो तृतीय योजना के अन्त तक बढ़ कर 250 लाख टन हो जाने का अनुमान था।\*



लिए ये व्यवसाय बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारतीय संदर्भ में हम इन व्यवसायों से प्राप्त होने वाले लाभों का अध्ययन करेंगे।

1. अर्द्ध-बेकारी की समाप्ति—भारतीय कृषक को मात्र घर

सहायक उद्योगों का महत्व

1. अर्द्ध-बेकारी की समाप्ति
2. कृषकों की अतिरिक्त आय
3. स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति
4. कार्य प्रणाली की सरलता
5. आर्थिक समानता
6. कृषि के पुराने उद्योग
7. अन्य लाभ

काम करने की आवश्यकता नहीं होती। वर्ष में-सह चार बहने बिना काम के बिताता है। ऐसे सालों समय को परिवार की आर्थिक समृद्धि के लिए इन व्यवसायों में लगाया जा सकता है। इस प्रकार ये व्यवसाय हमारे लोगों में फैली अर्द्ध-बेकारी (partial unemployment) को समाप्त करने में सहायक हैं।

2. कृषकों की अतिरिक्त आय—ये व्यवसाय किसानों को इनके अतिरिक्त भी आय प्रदान कर कृषकों के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने में सहायता करते हैं।

3. स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति—कुछ वस्तुएँ जिनकी सीमित या स्थानीय होती हैं। इन व्यवसायों के द्वारा पूरी की जा सकती हैं। बड़े उद्योग या पूर्ण समय के उद्योग इन वस्तुओं के लिए उपयोगी नहीं होते क्योंकि इनकी माँग अत्यन्त सीमित होती है। इन व्यवसायों के द्वारा कृषक अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं।

4. कार्य प्रणाली की आवश्यकता—ये व्यवसाय बड़ी मात्रा में विमान के पर, खेत या बाड़ों में चलाये जा सकते हैं। इनके द्वारा परिवार के सदस्य भी अपना योग देते हैं। इनके लिए बड़े यंत्रों की एवं भारी मात्रा में पूँजी की आवश्यकता न होने के कारण किसानों द्वारा सरलता से अपना लिये जाते हैं।

2. ऊन व्यवसाय—भारतवर्ष में 4 करोड़ भेड़ें हैं जिनसे 720 लाख पौण्ड ऊन प्राप्त होती है। उत्तरी भारत की भेड़ों की ऊन सफेद तथा लम्बे रेशे वाली होती है। अब देश में 22 ऊनी कपड़े बनाने के कारखाने हैं जो गलीचे, कम्बल, शाल व ऊनी वस्त्र तैयार करते हैं। सन् 1967-68 में हमने 1,1×2 लाख रुपये\* के मूल्य की कच्ची ऊन (Raw wool) का आयात किया। हम पास्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड से कच्चा ऊन तथा इंग्लैण्ड और इटली से ऊनी वस्त्र मंगाते हैं। देश के कुल उत्पादन का लगभग आधा भाग हम कालीन-ऊन के रूप में निर्यात कर देते हैं जिससे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है।\*\*

भेड़ों से ऊन प्राप्त करने का व्यवसाय पंजाब, उत्तर-प्रदेश, मद्रास, राजस्थान, मंसूर, महाराष्ट्र व गुजरात राज्यों में होता है। समृतमर, बेंगलूर, श्रीनगर, आगरा, मिर्जापुर व कानपुर ऊनी-वस्त्राद्योग के केन्द्र हैं।

प्रसन्नता की बात है कि भारतवर्ष में भेड़ों से ऊन प्राप्त करने के तरीकों के विकास एवं नस्ल सुधारने के कार्यक्रमों पर अब अधिक ध्यान दिया जा रहा है। तृतीय योजना के अन्त में ऊन का उत्पादन 900 लाख पौण्ड हो जाने का अनुमान था। योजना काल में ऊन के खेपी करण एवं भेड़ों की नस्ल सुधार के कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई है।

3. घमड़े व लाल का व्यवसाय—भारतवर्ष में करोड़ों पशु मरते हैं और कुछ मांस प्राप्ति के लिए मारे जाते हैं जिनसे खालें प्राप्त होती हैं। हमें प्रतिवर्ष लगभग 250 लाख पशुओं की खालें प्राप्त होती हैं। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र एवं गुजरात से बढ़िया किस्म की खालें प्राप्त होती हैं। हम अधिकांश खालों को बाहर भेज देते हैं। रंगी हुई खालों का मुख्य माहूक इंग्लैण्ड एवं बिना रंगी खालों का मुख्य आयातक का देश संयुक्त राज्य अमेरिका है।

---

\* India 1969, p. 371

\*\* Third Five Year Plan—P. 350

दूध उपभोग की दृष्टि से भारत की स्थिति अर्धतोषजनक है। एक व्यक्ति के सन्तुलित आहार में कम से कम 10 लीटर दूध प्रतिदिन होना चाहिये पर दुर्भाग्यवश भारत में प्रति व्यक्ति दूध का उपभोग लगभग 5 घोंस प्रतिदिन है।\* पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश व उत्तरप्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में दूध का अधिक उपभोग किया जाता है।

भारतवर्ष में दूध उत्पादन क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, आंध्रप्रदेश, गुजरात और मध्यप्रदेश उल्लेखनीय हैं। घी उत्पादन करने वाले मुख्य राज्य पंजाब, बिहार, राजस्थान, मद्रास व मध्यप्रदेश हैं। अब कुछ व्यापारिक संस्थान बड़े पैमाने पर घी का उत्पादन भी करने लगे हैं। हमारे यहाँ अब बड़े पैमाने पर दुग्ध-मालाएँ सोती जा रही हैं। भारतीय दुग्ध व्यवसाय के पिछड़ेपन के कारणों में पशुओं की खरिद नसल, मिलावट की समस्या, पशुओं का दुर्बल एवं रोग-ग्रस्त होना, व्यवसाय का अव्यवस्थित होना आदि उल्लेखनीय हैं। कृषकों को सह-यक घन्टों में सबसे अधिक आय इसी व्यवसाय से मिलती है।

पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत देवरी व्यवसाय के विकास के लिए अनेक कार्यक्रम रखे गये हैं। प्रथम योजना में 781 साग करने लक्ष्य करके बड़े शहरों में दुग्ध-वितरण योजनाएँ चलाई गईं। द्वितीय योजना काल में देवरी-विकास कार्यक्रमों पर लगभग 12 करोड़ रु० खर्च किए गये। अब देवरी प्लांट्स की संख्या 29 है। दुग्ध वितरण की योजनाएँ भी चलाई जा रही हैं। पशु-वस्तियों तथा पशु-बोर्डन कारखानों के विस्तार से देवरी उद्योग का विकास होया। दुग्ध-शालाओं के सम्बन्ध में छः प्रशिक्षण केन्द्र चलाए जा रहे हैं। ये केन्द्र बरसाना, बेगलूर, ऐरे, पाननन्द, झाडाबाद तथा हरिनाटा में स्थित हैं। तृतीय योजना काल में देवरी कार्यक्रमों पर 36 करोड़ रुपये लक्ष्य करने की व्यवस्था थी।

2. ऊन व्यवसाय—भारतवर्ष में 4 करोड़ भेड़ें हैं जिनसे 720 लाख पौण्ड ऊन प्राप्त होती है। उत्तरी भारत की भेड़ों की ऊन सफेद तथा लम्बे रेशे वाली होती है। अब देश में 22 ऊनी कपड़े बनाने के कारखाने हैं जो गलीचे, कम्बल, शाल व ऊनी वस्त्र तैयार करते हैं। सन् 1967-68 में हमने 1,1×2 लाख कपड़े\* के मूल्य की कच्ची ऊन (Raw wool) का आयात किया। हम घास्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड से कच्चा ऊन तथा इंग्लैण्ड और इटली से ऊनी वस्त्र मंगाते हैं। देश के कुल उत्पादन का लगभग आधा भाग हम कालीन-ऊन के रूप में निर्यात कर देते हैं जिससे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है।\*\*

भेड़ों से ऊन प्राप्त करने का व्यवसाय पंजाब, उत्तर-प्रदेश, मद्रास, राजस्थान, मंसूर, महाराष्ट्र व गुजरात राज्यों में होता है। घमृतनर, बेगनौर, खोतनर, आगरा, मिर्जापुर व कानपुर ऊनी-वस्त्राद्योग के केन्द्र हैं।

प्रमत्तना की बात है कि भारतवर्ष में भेड़ों से ऊन प्राप्त करने के तरीकों के विकास एवं नस्ल सुधारने के कार्यक्रमों पर अब अधिक ध्यान दिया जा रहा है। तृतीय योजना के अन्त में ऊन का उत्पादन 900 लाख पौण्ड हो जाने का अनुमान था। योजना काल में ऊन के खेपीकरण एवं भेड़ों की नस्ल सुधार के कार्यक्रमों की प्राथमिकता दी गई है।

3. चमड़े व खाल का व्यवसाय—भारतवर्ष में करोड़ों पशु मरते हैं और कुछ माँस प्राप्ति के लिए मारे जाते हैं जिनमें खालें प्राप्त होती हैं। हमें प्रतिवर्ष लगभग 250 लाख पशुओं की खालें प्राप्त होती हैं। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र एवं गुजरात से बढ़िया बिस्म की खालें प्राप्त होती हैं। हम अधिकांश खालों को बाहर भेज देते हैं। रंगी हुई खालों का मुख्य ग्राहक इंग्लैण्ड एवं बिना रंगी खालों का मुख्य आयातक का देश संयुक्त राज्य अमेरिका है।

---

\* India 1969, p. 371

\*\* Third Five Year Plan—P. 350

भारत से सन् 1967-68 में लगभग 7.39 करोड़ रुपये के मूल्य का चमड़ा और सालें अन्य देशों को भेजा गया ।\*

भारतवर्ष में चमड़ा साफ करने और चमड़े की वस्तुएं बनाने का काम उत्तर प्रदेश के कानपुर व भागरा, महाराष्ट्र, बंगाल, केरल, राजस्थान तथा मध्यप्रदेश में बहुतायत से होता है । कमाये हुए चमड़े से सूटकेस, दस्ताने, घूट, जूते-जूतियाँ, चप्पल, घट्टे, बैग, घँसे, बटुए, मगर, चरस, मोटर की सीटें, तबले, डोल, नंगाड़े, पुस्तकों की जिल्दगात्री, कमर पेडियाँ, मिलारी कपड़े आदि वस्तुएं बनाई जाती हैं । दुर्भाग्यवश भारत में सालें प्राप्त करने व चमड़ा रंगने के तरीके बहुत पुराने हैं जिनसे उत्पात्ति की किस्म घटिया होनी है और विदेशों में इनका मूल्य कम मिलता है । तृतीय योजना में इस सम्बन्ध में उचित कार्यक्रम धपनाये गये ।

4. खादी उद्योग—गाँवों में किसानों के परिवारों द्वारा कपास की रुई बनाने, सूत कातने एवं हाथ से कपड़ा बुनने का काम बहुतायत से होता है ।

भारतवर्ष में खादी का बहुत महत्व है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए राष्ट्रपिता गाँधीजी ने जब राजनैतिक आन्दोलन का श्री गणेश किया तब उन्होंने इसके साथ ही देश की बेकारी को दूर करने के लिए खादी-प्रचार का आन्दोलन भी चलाया । पूज्य बापू के शब्दों में “हाम से कलाई भारतीय किसान के लिए आमदनी का एक स्थायी साधन है क्योंकि भोजन के पश्चात् मनुष्य को सबसे अधिक कपड़े की ही आवश्यकता होती है । यतः यह शाश्वत और सार्वभौम है । इसके लिए किसी विशेष पूँजी और मंहंगे औजारों की जरूरत नहीं पड़ती । इसमें भारीरक धन भी कम करना पड़ता है । अतः देश के ग़रीब और बृद्ध सभी समान रूप से इस काम को कर सकते हैं ।”

ऊन एवं सूत कातने के लिए अनेक प्रकार के चरसों का प्रयोग

किया जाता है। सूनी कपड़े के लिए गरवदा चक्र, देशी चरखा, विधान चक्र, अम्बर चरखा आदि अनेक प्रकार के चरखे काम में लाये जाते हैं।

5. हाथ से चावल साफ करने का उद्योग (Hand Pounding of Rice)—यह गाँवों में किया जाने वाला महत्वपूर्ण उद्योग है। ओखली या हाथ की चक्की द्वारा चावल से छिन्नका भलग किया जाता है। हाथ से साफ किया गया चावल अधिक शुद्ध और पोष्टिक माना जाता है। मिलों द्वारा इस क्षेत्र में कार्य करने पर नियंत्रण हेतु 1958 में चावल मिल कानून का निर्माण किया गया जिससे इस उद्योग को प्रतिकूल बह्का न पहुँच सके। ग्रामोद्योग कमिशन ने हाथ से कुटे चावल को लोकप्रिय बनाने की दिशा में अनेक कार्य किए हैं।

#### 6. गुड़ एवं खंडसारी (Gur & Kbandsari)

उद्योग—भारतवर्ष में चीनी मिलों के खुलने से पहले ही गाँवों में खाँड़ और गुड़ बनाने का व्यवसाय बहुत अधिक विकसित था। अब भी मुख्य गन्ना उत्पादक क्षेत्रों,



जैसे—उत्तर प्रदेश, बिहार आदि में यह व्यवसाय प्रचलित है। इसमें गन्ने को कोल्हू में पेल कर रस निकाला जाता है फिर बड़े-बड़े कड़ाहों में उबाला जाता है और खाँड़ बनाने के लिए इस गाढ़े पदार्थ को बोरी में भरकर भारी वस्तु से दबाया जाता है। गुड़ बनाने के लिए इसकी भेलियाँ बना ली जाती हैं। गाँव में अब भी गुड़ का प्रयोग बहुत होता है।

7. ताड़ गुड़ उद्योग (Palm Gur Industry)—ताड़ के पेड़ों से गुड़ बनाने का यह व्यवसाय देश के अनेक भागों में होता है। यह कहा जाता है कि इस व्यवसाय में रोजगार देने और उत्पादन बढ़ाने की

बहुत सम्भावनायें हैं। अनुमानतः हमारे देश में 5 करोड़ ताड़ के पेड़ हैं। मारी तथा घामीण उद्योग बोर्ड इस क्षेत्र में तकनीकी सहायता, मार्ग दर्शन, प्रदर्शन तथा वित्तीय सहायता दे रहा है। मराठ बन्दी आन्दोलन को सफल बनाने के लिए इस व्यवसाय का विकास करना आवश्यक है। इससे प्राप्त रंग—'नीरा' स्वास्थ्यवर्द्धक सस्ता पेय है।



ताड़-गुड़ उद्योग

8. मधु मक्खली पालन (Bee keeping)—अधिकतम राज्यों में किया जाने वाला यह व्यवसाय बहुत आमदायक है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश, पंजाब, कश्मीर, केरल, मद्रास आदि राज्यों में यह व्यवसाय किया जाता है। मधु मक्खली पालन व्यवसाय में जहर, बीज आदि बाजुयें प्राप्त की जाती हैं। इस व्यवसाय में लगे हुए लोगों की प्रशिक्षण, मार्ग दर्शन एवं वित्तीय सहायता देने हेतु मारी-घामीयों की कमीशन के कुछ योजनाएँ बनाई हैं।

9. घासी तेल उद्योग (Ghassal-Oil Industry)—घास तिलहन उपादक देशों में विश्व भर में दुबारा स्थान रखता है। इसके लो

नगरों में तेल प्राप्त करने के लिए बड़े-बड़े कारखाने चलाये जा रहे हैं फिर भी गाँवों में खेती के साथ-साथ घाघो (कोल्हू) से तेल निकालने का काम किया जाता है। कृषि कार्यों में लगे बैलों एवं देशी कोल्हू की सहायता से यह व्यवसाय चलाया जाता है।

10. रस्सा एवं टोकरियाँ बनाने के व्यवसाय—किसान अपने अवकाश के समय में पटसन के रस्से बनाने का व्यवसाय करते हैं। ये रस्से कुपों से पानी निकालने, पशुओं को बाँधने, चारपाइयाँ बुनने व अन्य कृषि कार्यों में प्रयुक्त किये जाते हैं।

घरों में कृषकों की स्त्रियाँ देश के अनेक भागों में बाँस या बेंत की टोकरियाँ एवं अन्य उपयोगी सामान बनाती हैं। यह व्यवसाय मुख्य रूप से उन भागों में किया जाता है जहाँ बाँस व बेंत आसानी से उपलब्ध होते हैं।

11. रेशमी कीड़े पालने का व्यवसाय (Sericulture)—भारत-वर्ष में 50 हजार से भी अधिक कृषक परिवार रेशम के कीड़े पालने का व्यवसाय करते हैं। मैसूर, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार तथा मद्रास में यह व्यवसाय बहुत प्रचलित है। रेशम के कीड़ों से प्राप्त पदार्थ से री सिल्क तथा आर्ट सिल्क (Raw silk & Art Silk) बनाई जाती है जो बहुत उत्तम होती है। भारत में रेशम के कीड़े चार प्रकार के होते हैं—रेशम, टसर, अंडी मोर मूंगा। इनका पालन मुख्यतः गहतूत के पेड़ों पर किया जाता है।

12. जटा (Coir) उद्योग—मारियल की जरा के रेशों से अनेक प्रकार की सुन्दर वस्तुएँ तथा पदार्थ, बैग, दरियाँ आदि बनाई जाती हैं। यह मोटर की राइदाँ, सोफासेट गद्दे आदि बनाने के काम भी आती है। भारतवर्ष का यह व्यवसाय मुख्य रूप से केरल में होता है जहाँ मारियल की सबसे अधिक उपज होती है। मैसूर, मद्रास, बं० बंगाल



व उद्दीप्ता में भी जटा उद्योग प्रचलित है। इससे बनी वस्तुएं विदेशों में भेजकर अधिकाधिक विदेशी मुद्राएं प्राप्त की जा सकती हैं।

13. अन्य व्यवसाय—कृषि सहायक धन्यों में बैलगाड़ी किराये पर चलाने का काम, सब्जी व फल उगाने का व्यवसाय आदि सम्मिलित किये जा सकते हैं। ये व्यवसाय कृषक की आय में वृद्धि करते हैं।

जैसा ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है कि भारत की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में इनका अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। किन्तु इनको अविश्वरक्षने के लिए यह आवश्यक है कि कृषक को कतिपय नवीन तकनीकियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सहायता एवं तकनीकी मार्ग दर्शन इन व्यवसायों की उत्पत्ति में सहायक होगा।

### सारांश

कृषि के अतिरिक्त किये जाने वाले व्यवसाय से ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को समृद्धि प्राप्त होती है। यह तीन बातों पर निर्भर करती है—  
(1) सामाजिक व धार्मिक दृष्टिकोण, (2) आवश्यक करने वालों की उपलब्धि, (3) विपणन की सुविधा।

सहायक उद्योगों का महत्व—

1. अर्थ-बेकारी की समाप्ति, (2) कृषकों को अतिरिक्त आय, (3) स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति, (4) बायें प्रणाली की सरलता, (5) धार्मिक समानता, (6) कृषि के पूरक तथा (7) अन्य काम।

कुछ सहायक उद्योग—

1. दूध तथा घी का उद्योग, (2) ऊन उद्योग, (3) चमड़े व खान का उद्योग, (4) लोदी उद्योग, (5) हाथ से बानस माछ करने का उद्योग, (6) मृद एवं लकड़ी का उद्योग, (7) ताड़ गुड़ उद्योग, (8) मधु बनाने वाला उद्योग, (9) पानी केल उद्योग,

(10) रस्सा व टोकरियाँ बनाने का उद्योग, (11) रेशमी कीड़े पालने का व्यवसाय, (12) जूटा उद्योग, (13) अन्य व्यवसाय ।

### प्रश्न

1. ग्रामीण क्षेत्रों में सहायक उद्योगों का क्या महत्व है ? स्पष्ट कीजिए ।
2. प्रमुख सहायक उद्योगों का वर्णन कीजिये ।
3. टिप्पणियाँ लिखिए—
  - (अ) दूध तथा घी का व्यवसाय,
  - (आ) ऊन व्यवसाय,
  - (इ) चमड़ा उद्योग तथा
  - (ई) खादो उद्योग ।

—

## अध्याय 12

# भारतवर्ष में भूमि सुधार

## LAND REFORMS IN INDIA

“भूमि सुधार का सामाजिक परिवर्तन तथा आर्थिक विद्यमान से गहरा सम्बन्ध है।”

—डेनियल पार्नेर

आर्थिक विकास में कृषि की भूधारण व्यवस्था (System of Land Tenure) तथा भूमि सुधारों (Land Reforms) का बहुत प्रभाव पड़ता है। भूमि पर किसान के उचित अधिकार से बढ़कर कृषि विकास की ओर कोई प्रेरणा नहीं हो सकती। श्री आर्थर यंग ने ठीक ही कहा है “अधिकार का जादू रेत को भी सोने में परिवर्तित कर सकता है।”\*

भूमि सुधारों का अर्थ एवं महत्व (Meaning and Importance of Land Reforms)

भूमि सुधार का अर्थ उन परिवर्तनों से है जो कृषि उत्पादन में वृद्धि कर सामाजिक न्याय की प्रेरणा देता है। ये परिवर्तन भूधारण की प्रथा, कृषि जोत का प्रकार, वास्तविकी सुधार, लगान, उत्पादन वृद्धि के प्रयत्नों आदि से सम्बन्ध रखने वाले होते हैं।

आर्थिक विकास के लिए भूमि सुधारों का बहुत महत्व है। भूमि सुधारों से कृषि में विकास होता है भूमि सुधार का तीन दृष्टियों से

\*“The magic of property can turn sand into gold.” — Arthur young.

महत्व है—(1) कृषक की आय बढ़ाने के लिए, (2) कृषि के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए, तथा (3) सामाजिक न्याय दिलाने के लिए ।

डॉ. बाबलकर ने भूमि सुधारों का महत्व केवल उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से ही अधिक माना है । डॉ० आर. के. मुकुर्जी ने इनका महत्व कृषक के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए माना है । डॉ० दातावाला के अनुसार भूमि सुधार 'सामाजिक न्याय' की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है । प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में भूमि सुधारों की आवश्यकता सामाजिक न्याय तथा आर्थिक प्रगति के लिए अनुभव की है ।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भूमि सुधारों की आवश्यकता आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय प्राप्त करने की दृष्टि से होती है । भूमि सुधारों से ही कृषि विकास की प्रेरणा, अधिक खाद्यान्नों व कच्चे माल की प्राप्ति, ऊँचा जीवन स्तर, अधिक आय, बचत व पुंजी निर्माण का स्तर एवं समानता का वातावरण तैयार होता है ।

स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व भूमि व्यवस्था—

भारत में प्राचीन काल की भूमि व्यवस्था का विवरण मनुस्मृति में मिलता है । उस समय भूमि की उगाई में से राज्य सामान्यतः  $\frac{1}{6}$  भाग और विपत्तिकाल में  $\frac{1}{3}$  भाग लेता था । मुगलकाल में भूमि व्यवस्था में शेरशाह तथा टोडरमल ने सुधार किये । तदीपरान्त लार्ड कार्नवालिस ने स्थायी बन्दोबस्त ( Permanent Settlement ) की प्रथा चालू की ।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व भू-धारण की तीन प्रथाएँ प्रचलित थीं—

1. रयतवाड़ी ( Ryotwari ) प्रथा—यह प्रथा स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले बम्बई, (अब महाराष्ट्र), दक्षिणी मद्रास, अधिकांश ब्रह्म व बिहार के कुछ भागों में प्रचलित थी । इस प्रथा में किसान मालगुजारी ( land revenue ) सीधी सरकार को देता था । यह प्रथा सन् 1792 में कैप्टेन रॉड व डॉमिंग मुनरो द्वारा चालू की गई थी ।

2. महलवाड़ी (Mahalwari) प्रथा—इस प्रथा का जन्म सन् 1833 में रेग्यूलेटिंग ऐक्ट के अन्तर्गत मायरा व अवध में हुआ। इस प्रथा में सरकार द्वारा भूमि उस ग्राम के कुछ व्यक्तियों को समुदाय के रूप में दी जाती थी जो भूमि को किसानों में विभक्त कर देता था। समुदाय का मुखिया सरकार को लगान देता था। यह प्रथा पंजाब, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती थी।

3. जमींदारी (Zamindari) प्रथा—इस प्रथा में एक व्यक्ति (जमींदार) कई गाँवों या एक गाँव अथवा उसके किसी हिस्से का स्वामी माना जाता था। जमींदार सरकार को मालगुजारी चुकाने के लिए उत्तरदायी होता था। जमींदार कृषकों को भूमि लगान पर देता था। इस लगान में से कुछ अपने पास रख कर शेष सरकार को दे देता था। इस प्रकार जमींदार किसान और सरकार के बीच मध्यस्थ (middleman) का काम करता था। सरकार को इस प्रथा से बहुत लाभ था कि उसे किसान से लगान वसूल करने का कठिनाई वाला काम नहीं करना पड़ता था। किन्तु इस पद्धति में धीरे-धीरे अनेक बुराईयों का समावेश हो गया। इस प्रथा के अन्तर्गत कृषकों का शोषण, उत्पादन में प्रेरणाओं का अभाव, जोतों का घनामकारी होना, राजनीतिक दोष आदि अनेक बुराईयाँ उत्पन्न हो गईं।

इन्हीं अनेक दोषों के कारण स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहिले जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करने का निर्णय लिया गया।

**भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम—**

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सरकार ने कृषकों की स्थिति में सुधार लाने की दृष्टि से भूमि सुधार के अनेक कार्यक्रम बनाये।

1. जमींदारी प्रथा एवं मध्यस्थ वर्ग की समाप्ति—स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाये गये। जमींदारी उन्मूलन का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। इससे लगभग 2 करोड़ रुपये वाले कारागार सीधे सरकार के नियन्त्रण में आ गए।

सहकारी कृषि एवं चकबन्दी कार्यक्रमों में इस सुधार से सहायता मिली। जमींदारों को मुद्यावजा एवं पुनर्वासि के लिए अनुदान के रूप में लगभग 320 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। अनुमान है कि लगभग 250 करोड़ रुपये और दिया जाएगा।\*

2 काश्तकारी सुधार (Tenancy Reforms)—एक अर्द्ध-विकसित देश में जहाँ भूमि पर जनसंख्या का भार बहुत अधिक हो तथा जमींदारों द्वारा शोषण होता हो वहाँ काश्तकारी सुधार सामाजिक न्याय की दृष्टि से वांछनीय है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद विविध राज्यों में काश्तकारी कानून बनाये गये।

सगान नियमन (Regulation of rent) के अन्तर्गत काश्तकारों से लिये जाने वाले अधिकतम लगान की सीमा तय कर दी गई। प्रथम योजना में गुजरात, महाराष्ट्र व राजस्थान में कुल उपज का  $\frac{1}{6}$ , दिल्ली में  $\frac{1}{5}$  तथा उड़ीसा में  $\frac{1}{3}$  भाग सगान के रूप में लिये जाने की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई।

लगभग प्रत्येक राज्य में काश्तकारों की सू-धारण की सुरक्षा के सम्बन्ध में कानून बनाये गये जिससे किसान को मनमाने तरीके से बेदखल नहीं किया जा सकता।

काश्तकारी पुनर्ग्रहण (Resumption of tenancies) एवं काश्तकारों को स्वामित्व (ownership) के अधिकार दिलाने के सम्बन्ध में भी अनेक कानून बनाये गये। तृतीय योजना में काश्तकारों को भू-स्वामित्व दिलाने का अधिक कार्य किया गया।

3. सीमा निर्धारण (Celling of Land Holdings)—समाजवादी समाज की रचना की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति के अधिकार में रहे जा सकने वाली भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करना आवश्यक है। इससे आर्थिक व सामाजिक असमानता कम होगी। इसी दृष्टि से अनेक राज्यों में सीमा निर्धारण कानून बनाये गये। ये

कानून दो प्रकार के हैं (1) भविष्य के जोतों पर सीमा निर्धारण तथा (2) वर्तमान जोतों पर सीमा निर्धारण। भूतपूर्व पंजाब राज्य को छोड़कर प्रायः सभी राज्यों में ये कानून बन चुके हैं। सीमा निर्धारण कानूनों को लागू करने में सरकार को जो अतिरिक्त भूमि मिलेगी उसका उपयोग भूमिहीन श्रमिकों के लिए किया जाएगा। भिन्न-भिन्न राज्यों में यह सीमा भिन्न भिन्न है।\* सीमा निर्धारण करते समय भूमि की किरम आदि का ध्यान रखा गया है।

● विभिन्न राज्यों की वर्तमान एवं भविष्य की जोतों का सीमा निर्धारण निम्नांकित प्रकार से किया गया है—(Source : India 1969 p. 253)

राज्य	भविष्य (ए० डी में)	वर्तमान
आंध्र प्रदेश	18 से 26	27 से 324
बिहार	20 से 60	20 से 60
जम्मू-कश्मीर	22 3/4	22 3/4
मध्य प्रदेश	25 से 75	25 से 75
महाराष्ट्र	18 से 126	18 से 126
उड़ीसा	20 से 80	20 से 80
राजस्थान	25 से 336	25 से 336
प० बंगाल	25	25
मणिपुर	25	25
असम	50	50
गुजरात	19 से 132	19 से 132
केरल	15 से 36	15 से 36
मद्रास	24 से 120	24 से 120
मैसूर	18 से 141	27 से 216
पंजाब	20 से 75	20 से 75
सत्तर प्रदेश	12 1/2	40 से 80
...	24 से 60	21 से 60
...	25 से 75	25 से 75

4. **चकबन्दी**—दूरस्थ छोटे-छोटे खेतों की समस्या के हल का लयम वृद्धन चकबन्दी (consolidation) है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में चकबन्दी कार्यों में काफी प्रगति हुई। हरियाणा एवं पंजाब में चक-बंदी का कार्य लगभग पूरा हो गया है। सन् 1968-69 के अंत तक 2,957 करोड़ हेक्टर भूमि पर चकबन्दी की गई।

5. **सहकारी कृषि**—प्रथम दो पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारी कृषि को गुरुत्व आधार पर बढ़ा करने का निश्चय किया गया। तृतीय योजना के पाँचवें योजनाओं के अन्तर्गत 2,749 सहकारी कृषि समितियाँ तथा साइलेंट योजनाओं के बाहर 2,752 सहकारी कृषि समितियाँ बनाई गईं। मार्च सन् 1968 के अन्त में इन सहकारी समितियों की संख्या 8,582 थी। चतुर्थ योजना में इस विचारधारा को अधिक व्यापक बनाने पर ध्यान दिये जायेंगे। सहकारी कार्यक्रमों को नियोजन एवं प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी कृषि वसुधैव कुटुम्बक की नींव रखी जा रही है।

6. **भूदान (Bhoodan)**—स्वच्छता से भूमि की मूल्य का यह मान्यता सन् 1951 में आचार्य विनोबा भावे ने प्रस्तावित किया। आन्दोलन के शुरुआती चरण में आचार्य ने कहा कि "एक व्यक्ति एवं समाज के निवासियों पर आधारित समाज में भूमि पर सभी को अधिकार होना चाहिए। इसीलिए हम भूमि की विद्या नहीं मानते बल्कि भूमि की दान करते हैं। जिस पर निषेधों का सही अधिकार होता है। इसका मूल उद्देश्य यह है कि सही विभागों का प्रतिपादन किया जाये जिससे बिना किसी बलपूर्वक के सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों को दीव दिया जा सके।" व्यवहार में भूदान वह आन्दोलन है जो स्वच्छता के दिने दने भूमि के दान पर आधारित है। आनंदलाल दत्त



ग्राम्योपजन के अनेक रूप हैं, यथा-ग्राम्यशिक्षण, बुद्धिदान, जीवन दान, साधन दान, दूध दान व घास दान । मार्च 1967 तक 42.7 लाख एकड़ भूमि भूदान में प्राप्त की गई जिसमें से 12 लाख एकड़ भूमि निर्धन भूमिहीनों में बांट दी गई थी । अगस्त सन् 1967 तक 39,672 गाँव 'ग्रामदान' ग्राम्योपजन में सम्मिलित हो गये हैं ।\*

7. ग्राम्य सुधार—उत्प्रेरक कार्यक्रमों के अभाव में भूमि के संयोजन व कृषि के साधन एवं पद्धति को उत्पन्न करने के अनेक प्रयत्न किये गये हैं । भूमि के उपविभाजन एवं अग्रगम्यता को रोकने के लिए हस्तांतरण, उत्तराधिकार एवं लीज (Leases) के सम्बन्ध में अंकुश लगाने के कानून भी समयसमय पर लागू किये जा चुके हैं ।

भूमि सुधार कार्यक्रमों का मूल्यांकन (Evaluation)—

भारत में भूमि सुधार के अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम तैयार किये गये किन्तु अनेक कारणों से इनका प्रभाव उतना नहीं पड़ा जितनी आशा की गई थी ।

कृषि उत्पादन वृद्धि की दृष्टि से जमींदारी उन्मूलन, कार्यकारी सुधार, शक बन्दी, सरकारी कृषि एवं साधन व पद्धति में किये गये प्रयत्न उत्तेजनीय हैं । इन कार्यक्रमों से कृषिजन्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि हुई है ।

सामाजिक न्याय की दृष्टि से भूमि सुधारों से बहुत अपेक्षाएं थी किन्तु उनकी आंशिक पूर्ति ही सम्भव हुई है । जमींदारी प्रथा के उन्मूलन एवं भू-धारण की सुरक्षा से जहाँ कृषक को निश्चितता प्रदान करने के प्रयत्न किये गये वहाँ सीमा निर्धारण, भूदान एवं अन्य सौजन्यात्मक उपायों से निर्धन भूमिहीन श्रमिकों को अपने आर्थिक विकास के अवसर प्रदान किये गये । भूमि सुधारों से सामाजिक न्याय व समानता की प्रेरणा मिलती है ।

हमारे यहाँ अनेक कारणों से भूमि सुधारों के वांछित परिणाम नहीं मिले । इस सम्बन्ध में योजना आयोग ने अनुभव किया है और कहा

है कि "वह बात बहुत ही कम समझी गई कि भूमि सुधार एक सफेद बिजाम कार्यक्रम है। यह मनी-पाति अनुभव नहीं किया जाता है कि भू-स्वामित्व में सुधार करना तथा जोत की अधिकतम सीमा सीमा लागू करना सहकारिता पर आधारित ग्राम्य धर्म व्यवस्था के निर्माण की आवश्यक चीजें हैं। यही नहीं भूमि सुधारों के प्रशासनिक ढंग की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। मिल-मिलाकर कानून की उपेक्षा करने या अमल न करने की चेष्टाएं बे-रोक-टोक चल रही हैं। कानून की कारगर ओर पर लागू करने के लिए ग्राम समाज का समर्थन तथा अनुमति भी हासिल नहीं की जा सकी है।"

भारत में भूमि सुधारों की वांछित तकल्लता न मिल सकने के कारणों में भूमि सुधार कानूनों की दुर्बलताएं, कार्यान्वयन में शिथिलता, कारतबारी सूचनाओं (Tenancy Records) का अभाव आदि उल्लेखनीय हैं।

इस प्रकार भारत में भूमि सुधारों की दिशा सही होती हुए भी प्रशासनिक एवं अन्य कारणों से वे अपना अधिक प्रभाव नहीं दिखा सके हैं। स्थिति में सुधार लाने के लिए भूमि सुधारों पर कोई फोर्से फाउन्डे-शन के दम की रिपोर्टें तथा भूमि सुधारों पर नागपुर-प्रस्ताव (1959) में वर्णित उपाय उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये सुझाव हैं—कृषि व्यवस्था में लॉन्ग, रोजगार के वैकल्पिक साधन, आर्थिक प्रेरणार्थ, ग्राम संगठनों का सहयोग, मात्री व्यवस्था का स्वरूप, सहकारी कृषि, कीमतों का निर्धारण आदि।

भूमि सुधारों के सम्बन्ध में अधिक विस्तार नहीं किया जाना चाहिये। यही कृषि विकास एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्र में आशा की किरण है।

**राजस्थान में भूमि सुधार (Land Reforms in Rajasthan)**

ग्रन्थ राज्यों की भाँति भूमि सुधार के सम्बन्ध में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् अनेक प्रयत्न किए गए। (1) जागीरदारी समाप्त करने के

‘नए सन् 1952 में ‘भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम’ पारित हुआ। इस कानून के अन्तर्गत 17,000 गांवों में बसने वाले काश्तकारों को लाभ मिला और जमींदारी उन्मूलन के कारण 60 प्रतिशत भूमि पर सरकार का सीधा अधिकार स्थापित हो गया। सरकार ने जागीरदारों को लगभग 36 करोड़ रुपये मुआवजे के रूप में दिये। अब तक लगभग सभी जागीरें समाप्त कर दी गई हैं।

2. जमींदारी व बिस्वेदारी उन्मूलन के लिए सन् 1958 में अधिनियम पारित किया गया। वह अधिनियम सन् 1959 में लागू किया गया जिसके अनुसार राज्य के 8 जिलों में व्याप्त दस प्रकार का उन्मूलन हो गया।

3. सन् 1955 में राजस्थान काश्तकारी कानून (The Rajasthan Tenancy Act) पारित हुआ। इस कानून के पारित होने से पूर्व अलग-अलग देशी रियासतों के अलग-अलग कानून थे। काश्तकारी कानूनों में मुख्य उल्लेखनीय हैं—काश्तकारी रक्षा अध्यादेश, 1949 (बेदसमी रोकने हेतु), राजस्थान उपज लगान नियमन अधिनियम, 1952 (मध्यस्थों द्वारा 1/6 उपज से अधिक लगान नहीं लिया जा सकता), काश्तकारी कानून, भू-राजस्व कानून 1955 आदि। इन कानूनों के पारित होने से राजस्थान में काश्तकारों को भू-धारण की सुरक्षा, उचित लगान, बेगार से मुक्ति आदि लाभ प्राप्त हुए हैं।

4. ओलों का सीमा निर्धारण (ceiling on land holdings) — करने के कानून बना दिये गये हैं। सीमा निर्धारण सामाजिक न्याय की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान में वर्तमान तथा माकी ओलों पर 25 से 336 एकड़ की सीमा निर्धारित कर दी है।

5. भूमि सुधार—भूमि सुधारों में अन्य उल्लेखनीय बातों में भूदान गहवागी कृषि एवं चरबन्दी हैं। राजस्थान में भूदान से प्राप्त 417-450 एकड़ भूमि में से 92,623 एकड़ भूमि का वितरण कर दिया गया है। चरबन्दी कानून के अन्तर्गत राज्य में 585 गांवों में चरबन्दी

की जा चुकी है। इनके अतिरिक्त राजस्थान में भू-अभिलेख (Land Records) भी नियमित रूप से रखे जा रहे हैं।

इस प्रकार पिछले 20 वर्षों में राजस्थान में भूमि सुधार के सम्बन्ध में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं।

### सारांश

भूमि सुधारों का अर्थ और महत्व—भूमि सुधार का अर्थ उन परिवर्तनों से है जो कृषि उत्पादन में वृद्धि कर सामाजिक न्याय की प्रेरणा देता है। भूमि सुधार का तीन दृष्टियों से महत्व—(1) कृषक की आय बढ़ाने के लिये (2) कृषि उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए तथा (3) सामाजिक न्याय दिलाने के लिए।

स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व भूमि व्यवस्था—स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व भू-धारण की तीन प्रथाएँ प्रचलित थीं—(1) रैयतवाड़ी (2) महलवाड़ी (3) जमींदारी—जमींदार किसान और सरकार के बीच मध्यस्थ का काम करता था। इससे छः प्रकार की बुराईयाँ होती थी—(1) कृषकों का शोषण (2) कृषि उत्पादन में कमी (3) कृषक की ऋण अवस्था (4) जोत का अलमकारी होना (5) देश हितों के प्रतिकूल (6) अनाधिक पद्धति।

भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम—स्वतन्त्र भारत में भूमि सुधार के अनेक कार्यक्रम बनाये गये। जिनमें प्रमुख इस प्रकार से हैं—(1) जमींदारी प्रथा एवं मध्यस्थ वर्ग की समाप्ति (2) काश्तकारी सुधार (3) सीमा निर्धारण (4) खवबन्दी (5) सहकारी कृषि (6) भूदान (7) अन्य सुधार।

भूमि सुधार कार्यक्रमों का मूल्यांकन—अत्यन्त महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों के बावजूद अनेक कारणों से उनका प्रभाव उतना नहीं पड़ा जितना कि पड़ना चाहिये था।

राजस्थान में भूमि सुधार—राजस्थान में इस प्रकार भूमि सुधार प्रयत्न किये गए—(1) जागीरदारी समाप्त करने के लिए 1952 का

अधिनियम, (2) जमींदारी व बिस्वेशरी उन्मूलन के लिए 1958 का अधिनियम, (3) 1955 का राजस्थान काश्तकारी कानून, (4) थोती का सीमा निर्धारण, (5) अन्य सुधार ।

इस प्रकार राजस्थान में भूमि सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम चलाये गए ।

### प्रश्न

1. "भूमि सुधार का सामाजिक परिवर्तन तथा आर्थिक विकास से गहरा सम्बन्ध है"—वेनियल थार्नर—आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं ?
2. भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं, किसी भी देश की अर्थ-व्यवस्था में इसका क्या महत्व है ?
3. स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत में हुए भूमि सुधार का वर्णन कीजिये ।
4. सक्षित टिप्पणी लिखिये—
  - ( i ) रैपतवाड़ी
  - ( ii ) महुसवाड़ी
  - ( iii ) जमींदारी
  - ( iv ) चकबन्दी
  - ( v ) सहकारी कृषि
  - ( vi ) भूदान ।

## अध्याय 13

### कृषि श्रमिक

---

#### AGRICULTURAL LABOUR

---

“पञ्चवर्षीय योजनाओं का एक मूल उद्देश्य यह भी है कि ग्रामीण जनता के सभी वर्गों को रोजगार और अच्छे जीवन के सभी अवसर प्रदान किए जायें और खास कर खेतिहर श्रमिकों और पछड़ों हुई जातियों को शेष व्यक्तियों के स्तर तक आने के अवसर प्रदान किए जायें।”

—भारतीय योजना आयोग

किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि वहाँ के स्वास्थ्य एवं चरित्रवान निवासियों पर निर्भर करती है। इस सम्बन्ध में यहाँ भारत की स्थिति का अध्ययन कर लेना उचित होगा। 32,68,090 वर्ग किलोमीटर\* क्षेत्रफल वाला भारत देश जिसमें लगभग 51½ करोड़ जनसंख्या रहनी है अपनी अनेक विशेषतायें रखता है। यह जनसंख्या सम्पूर्ण विश्व की जनसंख्या की 16 प्रतिशत है। हमारे देश में लगभग 68-9 प्रतिशत जनसंख्या कृषि एवं कृषि सम्बन्धी अन्य व्यवसायों पर आधारित है।

कृषि व्यवसाय पर आधारित जनसंख्या में अधिकांश कृषक प्रत्यक्ष कृषि श्रमिक ही हैं। कृषि श्रमिकों का मात्र एक अल्प वर्ग बन गया है।

19 वीं शताब्दी के पूर्व इनका स्पष्ट वर्ग अलग से नहीं था। 19वीं सदी के अन्त में इनकी संख्या अधिक नहीं थी। किन्तु 20 वीं शताब्दी

में उनकी संख्या में वृद्धि हुई। इसी समय इनकी अनेक समस्याओं ने  
 उग्र रूप धारण कर लिया। बीबा जीवन स्तर, निर्धनता, बेकारी,



## कृषि श्रमिक

मजदूर-बेकारी आदि आज भी इन श्रमिकों की मूल समस्याएं हैं।  
 सरकार ने भी इन समस्याओं के निराकरण के प्रयत्न प्रारम्भ  
 दिये हैं।

अर्थ—

सन् 1951 की जनसंख्या में कृषि श्रमिक उन्हें माना गया जो क्षेत्रों पर मजदूरी लेकर काम करे। लेकिन इस परिभाषा में उन लोगों को सम्मिलित नहीं किया गया जिनके पास थोड़ी बहुत भूमि भी है चाहे वे क्षेत्रों में मजदूरी ही करते हों। इस प्रकार 1951 तक कृषि श्रमिकों में केवल 'भूमि हीन' (Land less) श्रमिकों को ही सम्मिलित किया गया।

सन् 1950-51 में गठित प्रथम खेतिहर श्रम जांच समिति (First Agricultural Labour Enquiry) ने कृषि श्रमिक उन्हें माना है जो वर्ष में अपने काम के कुल दिनों में आधा से अधिक दिन सन्धियों में श्रमिक के रूप में कार्य करें।

सन् 1956-57 की खेतिहर श्रम जांच समिति (द्वितीय) ने कृषि के अतिरिक्त पशुपालन बागवानी एवं दुग्ध व्यवसाय में लग्न श्रमिकों को भी कृषि श्रमिक माना है बशर्तें कृषि कार्यों में मजदूरी श्राव्य का प्रमुख साधन हो।

कृषि श्रमिक जांचों (Agricultural Labour Enquiries) के परिचाय —

कृषि श्रम की प्रथम जांच सन् 1950-51 में की गई। इस जांच में 800 गाँवों के 11,000 कृषि श्रमिक परिवारों का अध्ययन किया गया। इस जांच के प्रतिवेदन (Reports) सन् 1954-55 में प्रकाशित हुए।

द्वितीय जांच सन् 1956-57 में सम्पन्न हुई जिसका प्रतिवेदन सन् 1960 में प्रकाशित हुआ। इस जांच में 3,600 गाँवों के 28,560 परिवारों के आँकड़े एकत्रित किये गए।



एक अन्य बात—ग्रामीण श्रम जाँच (Rural Labour Enquiry)—सन् 1963 में की गई जिसकी रिपोर्ट अभी प्रकाशित नहीं हुई है।

प्रथम एवं द्वितीय जाँच के तुलनात्मक परिणाम नीचे दिये जा रहे हैं।

1. सन् 1956-57 में कृषि श्रमिक परिवारों की संख्या 1.63 करोड़ आंकी गई जबकि सन् 1950-51 में यह संख्या 1.79 थी। इस कमी का कारण समभवतः इन दोनों जाँचों में 'कृषिश्रमिक' की परिभाषा का अन्तर है।

2. भूमिहीन कृषि श्रमिकों का प्रतिशत सन् 1956-57 में 57 था जबकि सन् 1950-51 में यह प्रतिशत 50 था।

3. सन् 1950-51 में स्थायी श्रमिकों (Attached Labour) तथा अस्थायी श्रमिकों (Casual Labour) का अनुपात 10 : 90 था सन् 1956-57 में स्थायी श्रमिकों का प्रतिशत 27 था।

4. कृषि श्रमिक परिवार के सदस्यों की औसत संख्या सन् 1950-51 (4.30 सदस्य) की तुलना में सन् 1956-57 में यह (4.40 सदस्य) गई।

5. सन् 1950-51 में 3.5 करोड़ कृषि श्रमिक (जिनमें से 1.9 करोड़ पुरुष, 1.4 करोड़ स्त्रियाँ, 20 लाख बच्चे) थे जबकि सन् 1956-57 में कृषि श्रमिकों की संख्या 3.3 करोड़ थी (जिसमें 1.8 करोड़ पुरुष-स्त्रियाँ तथा 30 लाख बच्चे शामिल हैं)।

6. कृषि श्रमिकों के (अस्थायी) रोजगार की तुलनात्मक स्थिति निम्नांकित तालिका से स्पष्ट हो जाती है—

श्रमिक (अस्थायी)	मजदूरी पर जाने के दिन		स्वयं के काम में लगने के दिन		बकारी के दिन	
	1950-51	1956-57	1950-51	1956-57	1950-51	1956-57
पुरुष	200	197	75	40	90	128
स्त्रियाँ	134	141	×	×	×	×
बच्चे	165	204	×	×	×	×

7. सन् 1950-51 में कृषि एवं गैर कृषि मजदूरी से कृषि श्रमिकों की आय का 76 प्रतिशत भाग हुआ वहीं सन् 1950-51 में यह प्रतिशत 81 था। सन् 1950-51 की तुलना में द्वितीय आँक में मजदूरी की दर में कमी का सामना मिला। सन् 1950-51 में वहाँ प्रति श्रमिक परिवार की औसत वार्षिक आय 447 थी वहीं सन् 1956-57 में यह घटकर 437 हो गई।

8. कृषि श्रमिक परिवारों का औसत वार्षिक उपभोग जहाँ सन् 1950-51 में 461 रुपये के मूल्य का होता था वहीं सन् 1956-57 में बढ़कर 617 हो गया। इस प्रकार जहाँ पहले 14 रुपये का घाटा था वहाँ दूसरी आँक में यह घाटा 180 रुपये प्रति परिवार हो गया। इस बड़ी हुई घाटे की रकम को प्राप्त करने से ऋण दस्तता में वृद्धि हुई। पहले जहाँ सन् 1950-51 में प्रति परिवार 47 रुपये का ऋणभार था वह बढ़कर सन् 1956-57 में 88 रुपये हो गया।

उक्त दोनों आँक प्रतिवेदनो के परिणामों का अध्ययन कर लेने के पश्चात् यह कहा जा सकता है कि सन् 1950-51 की तुलना में कृषक मजदूर परिवारों की सकल आय में कमी हुई है। भोजन, आवास एवं मजदूरी की दरों में गिरावट आई है। ऋण भार एवं निर्धनता की वृद्धि हुई है। ये सब परिणाम इनकी समस्या की गम्भीरता को प्रमाणित करते हैं।

× आँकड़े अपूर्ण हैं।

कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि—

विद्यमान 70-80 वर्षों में कृषि श्रमिकों की संख्या एवं समस्याओं में वृद्धि हुई है। इनके वृद्धि के कारणों की जानकारी नीचे दी जा रही है—

कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि

के कारण

1. जनसंख्या में वृद्धि
2. भूमि पर जन भार में वृद्धि-उपविभाजन
3. कुटीर उद्योगों का पतन
4. सामाजिक कारण
5. शिक्षा का अभाव
6. अन्य कारण

1. भारतवर्ष में प्रतिवर्ष लगभग 125 लाख से जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की यही दर रही तो लगभग 45 वर्ष बाद भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होगा। \* इस तेज गति से बढ़ने वाली जनसंख्या ने कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि कर दी है।

2. भूमि पर जन भार में वृद्धि एवं उपविभाजन की समस्या ने भी कृषि श्रमिकों के इस वर्ग में संख्या की वृद्धि की है। ग्रामीण जीवन में अल्प व्यवसायों का अभाव होने से गांव की सम्पूर्ण जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर रहना चाहती है किन्तु भूमि के अभाव में अधिकांश व्यक्तियों को कृषि श्रमिक बन जाना पड़ता है।

3. कुटीर उद्योगों का पतन—कुटीर उद्योगों के पतन के कारण इन व्यवसायों में लगे कारीगर भी कृषि श्रमिक बन गये। सपु उद्योगों के अभाव में इन कारीगरों को कृषि के प्रतिरिक्त किसी भी व्यवसाय में रोजगार नहीं दिया जा सकता। इसलिये कृषि श्रमिकों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

4. सामाजिक कारण—वर्तमान ग्रामीण समाज में फैली हुई रुढ़ियों के कारण सामान्यतः भूमिहीन श्रमिक गांवों को छोड़कर सामग्र

श्रवणार्थों में रोजगार प्राप्त करने में हिचकिचाता है। परिणामस्वरूप गाँव में ही कृषि श्रमिक के रूप में अपने जीवन यापन का कार्य करता है।

5. शिक्षा का अभाव—हमारे समाज एवम् देश का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञानता है। गाँवों में शिक्षा के कारण अज्ञानता हटिवादिता आदि के दलदल में फँसा व्यक्ति अपने को नहीं छुड़ा सकता और बाध्य होकर कृषि श्रमिक बन जाता है।

6. अन्य कारण—छोटे-छोटे खेतों के मालिक किसान पूँजी के अभाव में अपनी कृषि विकास योजनाओं को क्रियान्वित नहीं कर पाते। माँगवादी दृष्टिकोण एवम् अल्प शक्तता ऐसे अन्य कारण हैं जिनसे भारतीय किसान केवल कृषि श्रमिक बन कर अपना जीवन यापन करता है।

उपरोक्त कारणों ने भारतीय कृषि श्रमिकों की समस्या में वृद्धि कर अनेक समस्याएँ उत्पन्न कर दी हैं। डॉ० राधाकमल मुकुर्जी ने तेजी से बढ़ने वाले कृषि श्रमिकों की संख्या के कारणों को इस प्रकार स्पष्ट किया है—“ग्रामीण धर्म-व्यवस्था में सम्मिलित अधिकारों का नष्ट होना, सामूहिक उपक्रम का विघटन, जोतों का उपविभाजन, कुटीर कर्षकों का पतन, लगान लेने वालों की संख्या में वृद्धि, भूमि को गिरवी रखने तथा स्थानांतरित करने पर प्रतिबन्ध न होना। इन बातों ने छोटे किसानों की स्थिति को दुर्बल बनाकर कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि कर दी है।”

✓  
 कृषि श्रमिकों की समस्याएँ—

जैसा ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है भारत में कृषि श्रमिकों की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। आज जिन समस्याओं का सामना हमें करना पड़ रहा है वे हैं—बेकारी एवम् अर्द्ध-बेकारी, नीची मजदूरी, नीचा जीवन स्तर, अल्प शक्तता, अज्ञानता, बेगार, कृषक दासता, काम के निर्दिष्ट घंटे एवम् प्रकृति, सगठन का अभाव, आवास समस्या, आदि।

सुझाव—कृषि श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए यह आवश्यक है कि शीघ्र ही राज्य एवं समाज सेवा संस्थाएँ आवश्यक प्रयत्न करें। कृषि श्रमिकों की समस्याओं को सुलझाने की दिशा में निर्माकित उपाय कारगर सिद्ध हो सकते हैं—

1. औद्योगिक विकास—देश में परम्परागत उद्योगों के पुनर्र्थान के अतिरिक्त मूल एवं भारी उद्योगों का विस्तार दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के अनिश्चित जन शक्ति (Man power) का प्रयोग किया जा सकेगा।

2. वैज्ञानिक एवं गहरी कृषि को अपना कर भूमि की उत्पादन शक्ति में वृद्धि की जानी चाहिये ताकि भूमि हीन श्रमिकों को भी उसके लाभ का समुचित भाग मिल सके।

### श्रमिकों की स्थिति सुधारने के उपाय

1. औद्योगिक विकास
2. वैज्ञानिक एवं गहरी कृषि
3. मूलतम मजदूरी का निर्धारण
4. श्रमिकों के संगठन
5. अधिक रोजगार
6. कार्य-व्यवस्था में सुधार
7. शिक्षा व प्रशिक्षण
8. सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था
9. धुरान
10. सामुदायिक विकास का विस्तार

3. मूलतम मजदूरी के निर्धारण संबंधी कानूनों का सख्ती से पालन कराया जाना चाहिये ताकि रखायी एवं उत्पायी कृषि श्रमिकों को उचित मजदूरी मिल सके।

4. श्रमिकों के संगठन को प्रोत्साहन दिया जाए ताकि वे संगठन बनने लक्षणों के लिए उचित मजदूरी पर कार्य की व्यवस्था कर अधिक लाभ से मुक्ति दिलायें।

5. अधिक रोजगार-ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण कार्य, विचारों के लिए बाध एवं बंधनों का निर्माण एवं अन्य कार्यों में

रोजगार के नये अवसर प्रदान किये जाने चाहिये ताकि इन श्रमिकों की मदद-रोजगार एवम् बेरोजगारी पर काबू पाया जा सके ।

6. कार्य बरामों पर सुधार—इन श्रमिकों के कार्य करने की दशाओं एवं कार्य करने की अवधि का उचित निर्धारण किया जाना चाहिये । महिला एवं बाल कृषि श्रमिकों को भारी कामों से मुक्ति दिलाने का यत्न किया जाना चाहिये ।

7. शिक्षा व प्रशिक्षण—शिक्षा का महत्व तो सर्व विदित है ही साथ में इन श्रमिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि वे अपने कार्य में अधिक दक्षता प्राप्त कर सकें ।

8. सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था बेकारी के दिनों में भरण-पोषण के लिए भत्ते की व्यवस्था कर दी जानी चाहिये । कार्य करते समय होने वाली दुर्घटनाओं की स्थिति में क्षतिपूर्ति की व्यवस्था भी की जानी चाहिये ।

10. भूदान—देश में खून रहित सामाजिक क्रान्ति (Bloodless Social Revolution) का सूत्रपात सन् 1951 में श्री विनोबा भावे ने किया । ग्वाय और समानता के सिद्धान्त पर आधारित इस आंदोलन में भूमिपतियों से निर्धन एवं भूमि रहित श्रमिकों के लिए भूमि प्राप्त की जाती है । ऐसी प्राप्त भूमि को भूमिहीन या स्वल्पभूमि वाले किसानों में बाँट दिया जाता है । इस कार्यक्रम से इन भूमि रहित कृषि श्रमिकों की स्थिति में बहुत सुधार आया है । भूदान कार्यक्रम को अधिक व्यापक एवं गतिशील बनाया जाना चाहिये ।

11. सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का विस्तार—ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों के कल्याण एवं समृद्धि के लिए सामुदायिक विकास कार्यों को अधिक व्यापक बनाना जाना चाहिये ।

पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत कृषि श्रमिक—

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ऐसे क्षेत्रों में जहाँ कृषि श्रमिकों को सुरक्षा अधिक दी सामुदायिक विकास योजनाओं द्वारा स्थिति सुधारने के प्रयत्न किये गये । दूसरे पंचवर्षीय, श्रमिक सहकारिताओं एवं

पुनर्वास योजनाओं के अतिरिक्त श्रमिकों के लिए सहकारी फार्म स्थापित करने के प्रयत्न किये गये । परन्तु कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई ।

द्वितीय योजना में कृषि श्रमिकों की कठिनाइयाँ दूर करने हेतु चार सूची कार्यक्रम हाथ में लिया गया । पहला प्रयत्न कृषि उत्पादन में वृद्धि कर वेतन दरों में बढ़ोतरी से संबंधित था । दूसरे, ग्रामीण एवं छोटे उद्योगों के विकास एवं विस्तार से अतिरिक्त रोजगार प्राप्त किये जायें । भूमि के पुनः वितरण, गिदा विस्तार एवं अन्य कार्यक्रमों से कृषि श्रमिक के षड, क्षमता, प्रेरणा और योग्यताओं में वृद्धि करने का तीव्र कार्यक्रम अपनाया गया । चौथा प्रयत्न खेतिहर मजदूरों की रहने की स्थिति में सुधार करने से सम्बन्धित है । दूसरी योजना काल में भूमि रहित श्रमिकों के पुनर्वास पर 5 करोड़ रुपये खर्च किये गये ।

तृतीय योजना में ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों पर विज्ञान राशि विनियोग करने की व्यवस्था की गई थी । कृषि श्रमिकों के पुनर्वास पर केन्द्रीय सरकार द्वारा 8 करोड़ रुपये एवं राज्य सरकारों द्वारा 4 करोड़ रुपये खर्च होने की व्यवस्था थी । केन्द्रीय कृषि श्रम सत्ताहकार समिति की सत्ताह पर 50 लाख एकड़ भूमि पर 7 लाख परिवारों को बसाने की योजना बनाई गई । मार्च 1967 के अन्त तक दान में प्राप्त 42.7 एकड़ भूमि में से 12 लाख एकड़ भूमि का वितरण कर दिया गया है ।\*

सन् 1951 की जनगणना में कृषि श्रमिक उन्हें माना गया वो सेवों पर मजदूरी लेकर काम करें ।

कृषि श्रमिक जाँचों के परिणाम—कृषि श्रम की प्रथम जाँच सन् 1950-51 में व द्वितीय जाँच सन् 1956-57 में व एक अन्य जाँच सन् 1963 में सम्पन्न हुई ।

कृषि श्रमिकों की सख्या में वृद्धि के कारण—

(i) जनसंख्या में वृद्धि (ii) भूमि पर जम भार में वृद्धि—उप

विमाजन (iii) कुटीर उद्योगों का पतन (iv) सामाजिक कारण (v) शिक्षा का अभाव (vi) अन्य कारण ।

**कृषि श्रमिकों की समस्याएँ—**

बेकारी एवं अर्द्ध-बेकारी, नीची मजदूरी, निम्न जीवन स्तर, अल्प प्रसूता, अशिक्षा, बेगार, कृषक दासता, काम के अनियमित घण्टे, संगठन का अभाव, आवास समस्या ।

**कृषि श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिये—**

कृषि श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए निम्नलिखित उपाय जरूरी हैं—

(i) औद्योगिक विकास (ii) वैज्ञानिक एवं गहरी कृषि (iii) न्यून-तम मजदूरी का निर्धारण (iv) श्रमिकों के संगठन (v) पब्लिक रोजगार (vi) कार्य दशाओं में सुधार (vii) शिक्षा व प्रशिक्षण (viii) सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था (ix) भूदान (x) सामुदायिक विकास का विस्तार ।

**पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि श्रमिक—**

प्रथम पंचवर्षीय योजना में—कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं,

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में—कृषि श्रमिकों की कठिनाइयाँ दूर करने के लिये चार सूची कार्यक्रम हाथ में लिया गया ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में—विभिन्न कार्यक्रमों पर गौर किया गया ।

### प्रश्न

1. 'कृषि श्रमिक' से क्या समझते हैं । वर्तमान में कृषि श्रमिकों की समस्या क्यों बढ़ रही है ?
2. कृषि श्रमिक जाँच आयोगों द्वारा विभिन्न समस्याओं पर जो जाँच की गई है उसकी आलोचना कीजिये ।
3. भारत में कृषि श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के लिए सुझाव दीजिये ।



## अध्याय 14

### भारतीय औद्योगिक विकास का सामान्य सर्वेक्षण

#### GENERAL SURVEY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT OF INDIA

“ऊन, सूत या रेशम ने निर्मित वस्तुएं जो अनेक महिलाओं के वस्त्रों से लगाकर उनके फर्नीचर एवं घरों की सजावट से सम्बन्ध रखती थीं वे भारतीय उद्योगों द्वारा ही निर्मित थीं।”

बीकनी रिप्पू

“उद्योगों के बिना कोई भी देश अपनी स्वतन्त्रता को सुरक्षित नहीं रख सकता।”  
—श्री जवाहरलाल नेहरू

किसी भी देश के आर्थिक विकास में उद्योगों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान होता है। भारत एक अत्यन्त सुमन्य एवं प्राचीन देश है, जिसके प्राकृतिक साधन अतुल्य एवं विशाल हैं। जब विश्व के उन देशों में, जो आज सबसे अधिक विकसित माने जाते हैं, जंगली जाड़ियाँ निवास करती थीं भारतवासी उद्योग एवं कला-कौशल में बहुत आगे बढ़े हुये थे।

भारत का औद्योगिक अतीत—भारत का औद्योगिक अतीत हमारे लिए गौरव की वस्तु है। यहाँ के उद्योग घन्य बहुत विकसित अवस्था में थे। हम अपने यहाँ से कई देशों को माल भेजते थे जिसका मुआना स्वर्ण में मिलता था हमीलिए भारत को ‘सोने की चिड़िया’ कहा जाता था। किन्तु अनेक कारणों से हमारे उद्योग पथों का पतन हो गया। ब्रिटिश सरकार की स्वतन्त्र व्यापार नीति (Free trade Policy) के परिणामस्वरूप हमारे यहाँ विदेशों से अनेक वस्तुएं आने लगीं। इस लिए हमारे वस्तुओं की मांग में कमी हो गई और विदेशों से सस्ते मूल्य में प्रवेशित विभिन्न वस्तुओं का आयात बढ़ गया। राजा महाराजाओं

का संरक्षण न रहने के कारण भी उद्योगों का पतन हुआ। हमारे विश्व प्रसिद्ध उद्योग धीरे-धीरे नष्ट होते गए और हमारा देश कृषि प्रधान देश बन गया। उद्योग धंधों के अभाव में हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

अब यह बात सर्वमान्य है कि घटते-विकसित देशों की उन्नति के लिए औद्योगिक विकास ही एक महत्वपूर्ण साधन है। भारत में भी उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में कुछ उद्योग प्रारम्भ किये गये, किन्तु औद्योगिक विकास का असली प्रारम्भ प्रथम महायुद्ध काल में हुआ।

प्रथम महायुद्ध (1914-19) में युद्ध की विभीषिका के कारण जनसाधारण दैनिक उपयोग की वस्तुओं के लिए कठिनाई महसूस करने लगा। भारत में यह अनुभव किया जाने लगा कि विदेशी उद्योगों पर निर्भरता बुरी है। सन् 1916 में नियुक्त औद्योगिक आयोग (Industrial Commission) ने भी भारत में औद्योगिक विकास का सुझाव दिया। सन् 1917 में भारत सरकार ने म्युनिशन बोर्ड (Munition Board) की नियुक्ति की जिसने भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहित करने के प्रयत्न किये। युद्धकाल में भारतीय कपड़ा, दूट, चमड़ा, लोहा व इस्पात, तेल, सेजोब, सीमेंट, रंग, बार्निश आदि के कारखाने बने।

युद्ध समाप्त होने के पश्चात् कीमतों के कम होने से उद्योगों एवं कृषि का ह्रास हुआ। विश्वव्यापी मंदी (Depression) के कारण भारतीय उद्योगों को आपात आदि देशों के बने मास से स्पर्द्धा करना पड़ी। सन् 1930 में सूती वस्त्रोद्योग तथा सन् 1924 में लोहा तथा इस्पात उद्योगों को संरक्षण (Protection) प्रदान किया गया।

सन् 1930 से 1939 तक की अवधि में भारतीय उद्योगों में नये जीवन का संचार हुआ। कपड़ा, सीमेंट, लोहा-इस्पात एवं दूट के उत्पादन में व्यापक वृद्धि हुई। संरक्षण नीति, नए कारखानों का निर्माण, विदेशी आरोपन आदि कारणों से भारतीय उद्योगों का विकास हुआ।

**द्वितीय महायुद्ध—(1939-45)** के प्रारम्भ हो जाने से भारतीय वस्तुओं की माँग बढ़ी। युद्ध सम्बन्धी सामग्री का निर्माण बहुतायत से किया जाने लगा। सरकार ने उद्योगों की सहायता के लिए औद्योगिक अनुसंधान बोर्ड की स्थापना की। मार्र्जेंट कमेटी की सिफारिश पर औद्योगिक प्रशिक्षण (Industrial Training) की व्यवस्था भी की गई। इस प्रकार द्वितीय महायुद्ध काल में पुराने उद्योग चले, नए प्रारम्भ हुए, नई प्रशिक्षण कला का विकास हुआ, मशीन के कल-पुर्वों के कारखाने मजदूरों से जम गये। \* सन् 1940 में एक बोर्ड ऑफ साइंटिफिक एंड इन्डस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना हुई। कुल मिलाकर द्वितीय महायुद्ध के काल में भी भारतीय उद्योगों का विकास हुआ।

**युद्धोत्तर काल में औद्योगिक विकास**

**(Post-war Industrial Development)—**

युद्धकाल में कारखानों में समता से अधिक कार्य होने से अनेक व्यवसायों में लगी मशीनें खीखी-खीखी अवस्था में पहुँच गई। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आने के साथ-साथ मुद्रा-स्फीति (Inflation) के प्रभाव स्पष्ट मजूर होने लगे। इसी समय देश का विभाजन (Partition) हुआ जिसने भारतीय औद्योगिक ढाँचे पर गहरा प्रभाव डाला। दिसम्बर सन् 1947 में त्रिपक्षीय सम्मेलन (Tri partite conference) बुलाया गया (उद्योगपति, मजदूर व सरकार) जिसमें औद्योगिक समस्याओं पर विचार किया गया।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद एक सुनिश्चित योजना के आधार पर औद्योगिक विकास करने हेतु 6 अप्रैल सन् 1948 को भारत सरकार की औद्योगिक नीति (Industrial Policy) की घोषणा की गई। इस नीति ने औद्योगिक विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy) का आधार स्पष्ट कर दिया।

**प्रथम पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक उत्पादन में 38 प्रतिशत की**

वृद्धि हुई। इस अवधि में धातुयान, डी. डी. टी., पेमिसिलीन, रेल के डिब्बों आदि का निर्माण प्रारम्भ किया। सार्वजनिक क्षेत्र (Public sector) में वितरजन का कारखाना, सिन्दरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री, इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज आदि की प्रगति संतोषजनक रही।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मूल एवं भारी (Basic and heavy) उद्योगों के विस्तार पर बल दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र में इस्पात के तीन कारखाने, भारी बिजली के सामान, भारी मशीन आदि के निर्माण कार्य सम्पन्न हुए। सीमेंट, कागज, रासायनिक उद्योग, टेलीफोन एवम् अन्य उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। योजना के अन्त में सन् 1950-51 की तुलना में 94 प्रतिशत उत्पादन अधिक होता था। इस योजना में निर्धारित औद्योगिक उत्पादन के सम्पूर्ण लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके। इसका मुख्य कारण विदेशी विनिमय (Foreign Exchange) का संकट था।

तृतीय योजना में औद्योगिक विकास के कार्यक्रमों का उद्देश्य आगामी 15 वर्षों में तीव्र औद्योगीकरण की नींव डालना था। इस योजना में आधारभूत पूंजी एवं उत्पादक उद्योगों की प्राथमिकता दी गई। इस योजना में तकनीकी प्रशिक्षण पर भी बल दिया गया। इस योजना में उद्योग एवं सनिज विकास के लिए 2,993 करोड़ (सार्वजनिक क्षेत्र में 1,808 तथा निजी क्षेत्र में 1,185 करोड़) रुपये की व्यवस्था की गई। इस राजि में से 1,338 करोड़ रुपये के मूल्य की विदेशी विनिमय की व्यवस्था की गई। तृतीय योजना की अवधि में अनेक उद्योगों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक एवं सनिज विकास योजनाओं पर लगभग 3090 करोड़ रुपये विनियोग करने की व्यवस्था है।\* इस योजना में इस्पात, मशीन उत्पादन, सर्वरक, मशीनी जोहार, रासायनिक पदार्थ आदि के उत्पादन विस्तार के लक्ष्य रक्खे गये।

औद्योगीकरण की आवश्यकता (Need for Industrialisation) कृषि प्रधान अर्द्ध-विकसित देशों की आर्थिक समृद्धि के लिए व उद्योगों का विकास अत्यन्त आवश्यक है। अब यह सभी प्रकार मान जा चुका है कि उद्योगों के बिना देश के आर्थिक विकास की बात सोचनी ही व्यर्थ है। आज विश्व के सभी विकसित देश (Developed countries) औद्योगीकरण के ही बल पर विश्व में अपना ठेका स्थान बना पाए हैं। भारतवर्ष जैसे अर्द्ध-विकसित और नियंत्रण राष्ट्र के लिए भी बड़े उद्योगों द्वारा ही आर्थिक समृद्धि प्राप्त की जा सकती है।

भारत में कृषि पर जनसंख्या का जो अत्यधिक भार है उसे हल करने, प्रति व्यक्ति आय एवं राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने, बेरोजगारी एवं अर्द्ध-बेकारी को समाप्त करने, कृषि विकास के लिए आवश्यक सीमार, कीटाणुनाशक दवाइयाँ एवं रासायनिक उर्वरक जुटाने, पूँजी निर्माण और विनिमय को प्रोत्साहन देने, लोगों के उपभोग एवं जीवन-स्तर को बढ़ाने, देश की सुरक्षा के प्रयत्नों को मजबूत बनाने, देश को आत्म-निर्भर बनाने, विदेशों पर निर्भरता समाप्त करने, भुगतान संतुलन को अनुकूल बनाने एवं देश का सर्वांगीण विकास करने हेतु यह आवश्यक है कि हम बड़े उद्योगों का विकास करें।

**उद्योगों के भेद (Kinds of Industry) —**

उद्योगों को मुख्य रूप से तीन भागों में बाँटा जाता है— (अ) कुटीर उद्योग (Cottage Industry), (ब) लघु उद्योग (Small Scale Industry) तथा (स) बृहत् स्तरीय उद्योग (Large Scale Industry)।

---

● कुटीर एवं लघु उद्योगों के विस्तृत सर्वे एवं प्रकार के माध्यम में सबसे बड़ा की पुस्तक में विस्तार से पढ़ें।

(अ) कुटीर उद्योग—कुटीर उद्योग वे हैं जो गाँवों में स्थित हैं, जो कृषि के सहायक धन्ये हैं तथा जिनमें अधिकतर कार्य हाथ से ही परिवार के अन्य सदस्यों की सहायता से किया जाता है।

(ब) लघु स्तरीय उद्योग—सामान्यतः लघु उद्योग वे उद्योग हैं जिनकी पूँजी 5 लाख रुपये से कम है और जहाँ वर्षों की सहायता से 10 से 50 तक व्यक्ति\* कार्य करते हैं। भारतवर्ष में अब ये उद्योग काफी विकसित हो रहे हैं।



कुटीर उद्योग

(स) गृह स्तर के उद्योग—ये वे उद्योग हैं जिनमें बहुत-सी ( 5 लाख रुपये से अधिक ) पूँजी के साथ अत्यधिक संख्या में व्यक्ति द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। भारतवर्ष में सूती वस्त्रोद्योग, लोह एवं इस्पात उद्योग तथा चीनी उद्योग कई वर्षों से बड़े पैमाने पर चलाये जा रहे हैं। देश की अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ एवं समृद्ध करने की दृष्टि से ये उद्योग महत्वपूर्ण हैं।

जहाँ एक ओर उद्योग कुटीर रोजगार प्रदान करने, कम पूँजी में काम चलाने, औद्योगिक विकेंद्रीकरण, कलात्मक वस्तुओं के निर्माण भूमि पर जनसंख्या के भार में कमी करने, उत्तम कोटि की वस्तुओं के निर्माण करने एवं सरल कार्य प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण हैं, वहाँ दूसरी ओर गृह उद्योग अर्थ-व्यवस्था को गतिमान करने, देश में उत्पादन

बढ़ाने, उत्पादन की लागत नम करने, निर्यात की आवश्यकताओं को पूरा करने, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने, दीर्घकाल में बेरोजगारी व धर्म-रोजगारी को समाप्त करने, कृषि विकास के लिए आवश्यक उपकरण एवं दवाइयाँ जुटाने की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण हैं। बड़े उद्योगों की स्थापना के बिना वर्तमान आर्थिक स्पर्धा के युग में किसी भी देश का आगे बढ़ना सम्भव नहीं है। स्वर्गीय नेहरू के अनुसार "देश में भारी उद्योगों के विकास का महत्व है। मैं तो कहूँगा कि भारी उद्योगों के बिना कोई भी देश अपनी स्वतन्त्रता को सुरक्षित नहीं रख सकता। भारी उद्योग ही बुनियादी चीज है, बाकी सब उद्योग तो उनके बच्चे हैं।" इस प्रकार किसी भी देश की अर्थ व्यवस्था में तीनों ही प्रकार के उद्योगों का स्थान महत्वपूर्ण होता है किन्तु आज के इस वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के युग में वृहत् उद्योगों का ही महत्व अधिक है।

**भारत में औद्योगिक पिछड़ापन ( Industrial Backwardness in India )—**

औद्योगिक विकास का महत्व सर्व विदित होते हुए भी भारतवर्ष अभी औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। यद्यपि हमारे देश में प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता देखते हुए औद्योगिक विकास की सम्भावनाएं बहुत हैं फिर भी हम इस दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। हम यहाँ उन समस्याओं का चर्चेख करेंगे जो औद्योगिक पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी हैं—

1. वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव ( Lack of Scientific outlook)—भारतवासी प्राचीनकाल से ही वाणिज्यवादी रहे हैं। वे अब भी नये उद्योगों में विनियोग करने की अपेक्षा वाणिज्य (Commerce) को अधिक सामदारी समझते हैं। इसके अतिरिक्त कृषि की प्रधानता, ग्रामों की व्यापकता आदि कारणों से भी उद्योगों के पक्ष में उचित मातावरण का निर्माण नहीं हो पाया।

2. पूँजी की समस्या (Problem of Capital)—हमारे देश में राष्ट्रीय आय कम होने से पूँजी निर्माण की क्षमता कम है। बिना अधिक पूँजी के बड़े उद्योगों की स्थापना सम्भव नहीं है। यही कारण है भारत में तीव्र औद्योगीकरण का अभाव है।

3. मशीनों के मशीनीकरण एवं प्रविधि सम्बन्धी समस्याएँ (Problems of techniques and modernisation of machines)—हमारे देश में मशीनों की हालत अत्यन्त असन्तोषप्रद है। चिस्मो-पिटी इन मशीनों द्वारा उत्पादन किया जाता है जिससे उत्पादन की लागत (Cost of productions) बढ़ जाती है।

(Techniques) तथा मशीनों की पुनर्स्थापना (Replacement) सम्भव नहीं है। इसलिए भारतीय उद्योगों का विकास रुका हुआ है।

4. कच्चे माल की समस्या (Problem of Raw material)—यद्यपि अधिकांश उद्योगों के लिए कच्चा माल हमारे देश में ही उपलब्ध हो जाता है फिर भी उत्तम शिष्ट का कच्चा माल हमें विदेशों से मंगाना पड़ता है। हमारी ओर कच्चे माल की मुख्य सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण भी उद्योगों को राति उठानी पड़ती है।

### औद्योगिक समस्याएँ

1. वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव
2. पूँजी की समस्या
3. मशीनों के मशीनीकरण एवं प्रविधि सम्बन्धी समस्या
4. कच्चे माल की समस्या
5. विदेशी पूँजी की समस्या
6. श्रमिकों की समस्या
7. सरकारी नीति
8. प्रबन्ध अधिकर्ता प्रणाली के दोष
9. असन्तुलन की समस्या
10. औद्योगिक अक्षमता
11. शक्ति के साधनों की समस्या
12. प्रबन्ध की समस्या



5. विदेशी पूंजी की समस्या (Problem of foreign capital)—उद्योगों के धमिनकीकरण तथा विदेशों से सात्र सामान मंगाने के निम्ने पर्याप्त मात्रा में विदेशी पूंजी की आवश्यकता होती है। भारत में पिछले 10-12 वर्षों से विदेशी पूंजी का सट आया हुआ है। हम पर पहले ही विदेशी ऋण भार अधिक है। इसलिए और अधिक पूंजी हमें विदेशों से नहीं प्राप्त हो पा रही है।

6. कुशल धमिकों की समस्या (Problem of skilled Labour)—औद्योगिक विकास के लिए जहाँ एक ओर अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है वहाँ कुशल धमिकों की महत्ता भी कम नहीं है। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ अब भी अनेक व्यवसायों में प्रशिक्षित धमिकों एवं कर्मचारियों का अभाव है।

7. सरकारी नीति (Government Policy)—औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल औद्योगिक नीति, कर नीति, धम नीति एवं सटकर नीति का होना आवश्यक है। भारत सरकार की औद्योगिक नीति अब भी पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। राष्ट्रीयकरण का मय भारतीय उद्योगपतियों द्वारा विकास योजनाओं के निर्माण में बाधा है। प्रगतिशील धम एवं कर नीतियों से पूंजीपतियों द्वारा किए जाने वाले पूंजी के विनियोग में कटौती हुई।

8. प्रबन्ध अधिकर्ता प्रणाली के दोष (Evils of managing Agency System)—प्रबन्ध अधिकर्ताओं द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास में दिया गया योग मुनाया नहीं जा सकता किन्तु वर्तमान औद्योगिक ढाँचे में प्रबन्ध अधिकर्ता प्रणाली के दोष सुविदित हैं। इनकी दोषपूर्ण कार्यप्रणाली औद्योगिक पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी है।

9. असन्तुलनों की समस्या (Problem of Imbalances)—भारतीय उद्योगों में अनेक प्रकार के असन्तुलनों की समस्या उत्पन्न हो गई है। क्षेत्रीय (Regional), निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में असन्तुलन (Sectoral imbalance) उत्पादक व उपभोग उद्योगों में असन्तुलन (Imbalance in Producers & Consumers Industries), आदि समस्याएँ भी तीव्र औद्योगीकरण के मार्ग में बाधाएँ हैं।

10. औद्योगिक अशान्ति (Industrial unrest)—बड़े उद्योगों की स्थापना के साथ साथ औद्योगिक अशान्ति में वृद्धि हुई है। मजदूरों और मालिकों में मधुर सम्बन्ध न होने के कारण उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

11. शक्ति के साधनों की समस्या (Problem of Power)—विश्व के अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारतीय उद्योगों की उत्पादन लागत कम करना आवश्यक है। बिना पर्याप्त मात्रा में सस्ते शक्ति के साधनों के भारतीय उद्योगों का विकास कठिन है। यद्यपि भारत में शक्ति के साधनों की सम्भावनाएं (Potentialities) बहुत हैं फिर भी उनके अनेक उचित विद्योहन (utilization) के अभाव में उद्योगों के लिए कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

12. प्रबन्ध की समस्या (Problem of Organisation)—प्रबन्ध अधिकारियों की दोषपूर्ण कार्यप्रणाली के साथ-साथ योग्य व प्रशिक्षित प्रबन्धों का भी अभाव है। प्रबन्धक की योग्यता का उद्योगों के विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector) में प्रबन्धित उद्योगों में भी कुशलता की कमी (Inefficiency) दृष्टिगोचर होती है।

भारत में तीव्र औद्योगीकरण (Rapid Industrialisation) के लिए सुझाव—

हमारे देश में औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक सनित्र पदार्थ, कृषि अन्य कच्चा माल, शक्ति के साधनों की क्षमता, विस्तृत बाजार एवं जनशक्ति पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। तीव्र औद्योगीकरण के लिए निम्नांकित उपाय काम में लाये जाने चाहिए—

1. प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग—सनित्र पदार्थों का उपयोग औद्योगिक विकास के लिए किया जाना चाहिए। विस्तृत जनशक्ति एवं वन सम्पदा का भी अधिकतम उपयोग कर औद्योगीकरण को बढ़ावा देना चाहिए।

2. पूंजी का मुद्रबन्ध—वर्तमान बचतों को विनिमय के लिए व्यर्धन देने के माध्यम से पूंजी निर्माण की क्षमता को बढ़ाया जाना चाहिए। प्रसन्नता की बात है कि पञ्चवर्षीय योजनाओं में पूंजी निर्माण की दर बढ़ाकर उद्योगों के लिए अधिकाधिक पूंजी जुटाने की व्यवस्था की जा रही है।

3. विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन मूल और भारी उद्योगों के लिए विदेशों से साज सामान मँगाने के लिए अधिक से अधिक विदेशी पूंजी को आकर्षित किया जाना चाहिए। सीमित विदेशी पूंजी का अधिकाधिक लाभदायक उपयोग करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

4. अभिनवीकरण (Modernisation) के कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि उत्पादन की लागत में प्रभावपूर्ण कमी की जा सके। पिछले कुछ वर्षों में देश में अनेक वित्त निगम इस कार्य के लिए कारखानों को साधन प्रदान कर रहे हैं।

5. सरकारी उद्योगों में दक्षता लाने के लिए प्रबन्ध को अधिक प्रभावी (Effective) बनाया जाना चाहिये।

6. औद्योगिक प्रशिक्षण—की समुचित व्यवस्था के लिए देश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ, मजदूर शिक्षण केन्द्र, आदि संघटनों का संचालन किया जाना चाहिए। भारत सरकार इस ओर बहुत प्रयत्नशील है।

7. उचित औद्योगिक धम एवं कर नीति—सरकार की नीतियों में निम्नी प्रकार की अनिविचलता को स्थान नहीं होना चाहिए। सन् 1956 की औद्योगिक नीति ने अनेक अनिविचलताओं को समाप्त कर भारतीय उद्योगपतियों में फिर से विश्वास को प्रतिष्ठित किया है।

8. श्रम प्रयत्न—औद्योगिक विकास के लिए श्रम प्रयत्नों के प्रति-रिण्ड औद्योगिक जाति स्थापित करने के लिए श्रम कल्याण (Labour Welfare) कार्यक्रमों का संचालन दिया जाना चाहिए। सांस्कृतिक

व निम्नी क्षेत्रों के मध्य उचित समन्वय एवम् सहयोग स्थापित किया जाना चाहिए। यातायात के साधनों के विकास के प्रतिरिक्त क्षेत्रीय एवम् उद्योगों के मध्य विषमताओं को समाप्त किया जाना चाहिए। कुटीर एवम् लघु उद्योगों का क्षेत्र सुस्पष्ट निर्धारित कर दिया जाना चाहिए।

प्रसन्नता की बात है कि आर्थिक नियोजन के पिछले 17 वर्षों में औद्योगिक विकास के सराहनीय प्रयत्न किये गये हैं। कुछ विद्वानों का विचार है कि भारत विकासशील (Developing) देशों में सबसे अधिक विकसित (Developed) है।\* विकास की गति तीव्र करने के लिए हमें उद्योगों का और विस्तार करने की आवश्यकता है।

भारत सरकार की औद्योगिक नीति (Industrial Policy of Government of India)

यहाँ भारतीय उद्योगों के विकास के सदर्भ में भारत सरकार की औद्योगिक नीति का उल्लेख करना उचित ही होगा।

स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय उद्योगों के विकास के लिये सरकार की कोई उल्लेखनीय औद्योगिक नीति नहीं रही। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद ही हमारी राष्ट्रीय सरकार ने उद्योगों के विकास की नीति की घोषणा की। इस नीति में समय-समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन किये गये।

सन् 1948 की औद्योगिक नीति (Industrial Policy of 1948) —

सन् 1948 में भारत सरकार द्वारा अपनी औद्योगिक नीति (Industrial Policy) की घोषणा की गई। इस नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:—

1. वृहत् उद्योग—इन्हें चार भागों में बांटा गया—(अ) राज्य

---

\*Indian Economy since Independence, H. Venkatasubbiah, p. viii

अधिकृत क्षेत्र में तीन महत्वपूर्ण उद्योग रहे गए जिन पर सरकार का एकाधिकार होगा ।

(ब) राज्य नियंत्रित (Controlled) क्षेत्र—इसमें छः आधारभूत उद्योग रहे गए जिनके राष्ट्रीयकरण के प्रश्न के बारे में सरकार 10 वर्ष बाद फिर से विचार करेगी ।

(ग) 'सी' श्रेणी में वे 20 उद्योग रहे गये जो उद्योगपतियों द्वारा चलाये जाएंगे और जिन पर सरकार का सामान्य नियन्त्रण एवम् नियमन रहेगा ।

(द) शेष सभी उद्योग निजी क्षेत्र (Private) में रहेंगे ।

2. सघुष कुटीर उद्योग—इस नीति के अन्तर्गत कुटीर व लघु उद्योगों को विकसित करने एवम् समन्वय के लिए विभिन्न संस्थाओं की स्थापना की घोषणा की गई ।

औद्योगिक समन्वय—मजदूरों एवम् मालिकों में अच्छे संबंध स्थापित करने की आवश्यकता पर भी इस नीति में जोर दिया गया ।

4. विदेशी पूँजी—इस नीति में विदेशी पूँजी की सुरक्षा एवम् विनियोग की सुविधाओं का आश्वासन दिया गया ।

संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि इस नीति मिश्रित अर्थ व्यवस्था (Mixed Economy) के विचार को स्पष्ट किया । किन्तु इस नीति की घोषणा से औद्योगिक क्षेत्र में अनिश्चितता एवम् भय का वातावरण उत्पन्न हो गया । इसीलिए सन् 1956 में नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा की गई ।

सन् 1956 की नवीन औद्योगिक नीति (New Industrial policy 1956)—

प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा से उत्पन्न भय एवम् अनिश्चितता के वातावरण को दूर करने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम

उठाये। इनमें औद्योगिक (विकास एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1951 केन्द्रीय (औद्योगिक) सहायकार समिति, 1952 का गठन तथा औद्योगिक (विकास एवं नियन्त्रण) अधिनियम संशोधन 1953 तथा 1955 की व्यवस्थाएं उल्लेखनीय हैं। इतना सब होने के बावजूद भी भारतीय गणराज्य के संविधान एवं द्वितीय योजना की आवश्यकताओं के अनुरूप नई औद्योगिक नीति की घोषणा करना वांछनीय हो गया। तदनुसार 30 अप्रैल सन् 1956 को तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। इस नीति की मुख्य विशेषताएं ये हैं—

1. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों का महत्त्व—नवीन नीति में राज्य के नीति में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (Directive principles) के अनुसार समाज की रचना करने के उद्देश्य से इस नीति में भारी उद्योगों व मशीन उद्योगों का विकास करने के लिए, जहाँ आवश्यक हो, सरकारी क्षेत्र का विस्तार किया जाने का लक्ष्य रखा गया।

2. उद्योगों का वर्गीकरण (Classification of Industries)—  
(अ) चारुत्स्तरीय उद्योगों को चार के स्थान पर नवीन नीति में तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया। प्रथम अनुसूची (Schedule 'A') में उन 17 उद्योगों को सम्मिलित किया गया जिनके विकास का सम्पूर्ण दायित्व सरकार पर होगा। द्वितीय अनुसूची में वे बारह उद्योग सम्मिलित किये गये जिनके भावी विकास का उत्तरदायित्व सरकार पर होगा।

(ब) सड़क तथा कुटीर उद्योग—नई नीति में इन उद्योगों को पूर्वी, शक्ति के साधन एवम् तकनीकी सहायता देकर स्वावलम्बी बनाने की व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया।

3. सन्तुलित विकास—सभी क्षेत्रों में यातायात, जल एवम् शक्ति के साधनों की सुविधाएं प्रदान कर क्षेत्रीय आर्थिक असमानताओं को दूर करने के प्रयत्न किये जायेंगे।

4. कर्मचारियों का प्रशिक्षण—नवीन नीति में औद्योगिक एवम् व्यावसायिक प्रशिक्षण सेवाओं के विस्तार की अनिवार्यता को महसूस किया गया।

5. औद्योगिक शान्ति—(Industrial rest) के लिए मजदूरों को भी विकास कार्य में साझेदार मानने का सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया ।

6. विदेशी पूँजी—सन् 1948 की ही नीति के सम्बन्धित अंत को दोहरा दिया गया ।

यद्यपि नवीन औद्योगिक नीति के विषय में भी अनेक तर्क दिये जाते हैं फिर भी इस नीति की घोषणा के बाद भारतीय उद्योग एक सुदृढ़ आधार पर विकसित हो रहे हैं । भारत की औद्योगिक नीति में श्रमिकों के प्रशिक्षण (Training), मही आँकड़ों के संकलन (Collection of data) एवम् प्रबंध में श्रमिकों को हिस्सा देने की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

### मार्गान्त

हिमी भी देश के धार्मिक विकास के उद्योगों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान होता है ।

भारत का औद्योगिक स्थिति—अतीत में यहाँ के उद्योग अत्यन्त कम विकसित अवस्था में थे । प्रथम महायुद्ध के कारण जन साधारण ईनिक उद्योगों की उन्नति के लिए कठिनाई महसूस करने लगे । मुद्रास्फाट उद्योगों का ह्रास हुआ । सन् 1930 से 1939 तक में उद्योग में नये जीवन का संचार हुआ । द्वितीय महायुद्ध काल में पुराने उद्योग पनपे, नये उद्योग प्रारम्भ हुये ।

संघर्षपूर्ण योजनाओं में औद्योगिक विकास—

प्रथम पञ्चवर्षीय योजना में—औद्योगिक उत्पादन में 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना में—मूल व प्राथमिक उद्योगों के विस्तार पर बल दिया ।

मृदाय पंचवर्षीय योजना में—आधारभूत पूँजी एवं उत्पादक उद्योगों को प्राथमिकता दी गई ।

औद्योगीकरण की आवश्यकता—बड़े उद्योगों के बिना आदिक विकास की बात सोचना ही व्यर्थ है ।

उद्योगों के स्तर—( 1 ) कुटीर उद्योग ( 2 ) मध्य स्तरीय उद्योग ( 3 ) बृहत् स्तर के उद्योग ।

भारत में औद्योगिक विद्यमान—हमारे उद्योग पिछड़े हुए हैं क्योंकि—

( 1 ) वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव ( 2 ) पूँजी की समस्या ( 3 ) मशीनों के नवीनीकरण एवं प्रबन्ध सम्बन्धी समस्या ( 4 ) कच्चे माल की समस्या ( 5 ) विदेशी पूँजी की समस्या ( 6 ) श्रमिकों की समस्या ( 7 ) सरकारी नीति ( 8 ) प्रबन्ध अधिकर्ता प्रणाली के दोष ( 9 ) असन्तुलन की समस्या ( 10 ) औद्योगिक अज्ञान ( 11 ) शक्ति के साधनों की समस्या ( 12 ) प्रबन्ध की समस्या ।

भारत में तीव्र औद्योगीकरण के लिए सुझाव—

( 1 ) प्राकृतिक साधनों का समुचित प्रयोग ( 2 ) पूँजी का सुप्रबन्ध ( 3 ) विदेशी पूँजी को प्रोत्साहन ( 4 ) श्रमनवीकरण ( 5 ) उचित प्रबन्ध ( 6 ) औद्योगिक प्रतिष्ठान ( 7 ) उचित औद्योगिक धर्म एवं नैतिकता ( 8 ) अन्य प्रयत्न ।

भारत सरकार की औद्योगिक नीतियाँ—

स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व कोई उल्लेखनीय नीति नहीं थी—

सन् 1948 की नीति—बृहत् उद्योगों को चार भागों में बाँटा गया । मध्य उद्योगों के लिए विभिन्न समस्याओं को सोलने की योजना की गई । संक्षेप में इनमें विभिन्न धर्म व्यवस्था के विचार को स्पष्ट किया । 1956 की नवीन औद्योगिक नीति—

विशेषताएँ—( 1 ) राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों का ग्रहण ( 2 ) उद्योगों का वर्गीकरण—बृहत् उद्योगों को तीन भागों में बाँटा ( 3 ) सन्तुलन विधान ( 4 ) समन्वयियों का प्रतिष्ठान ( 5 ) औद्योगिक नीति ( 6 ) विदेशी पूँजी ।



## प्रश्न

1. "किसी भी देश के आर्थिक विकास में उद्योगों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान होता है"—क्या आप इस कथन से सहमत हैं ?  
हाँ तो क्यों ?
  2. भारत में पंचवर्षीय योजना काल में हुये औद्योगिक विकास पर निबन्ध लिखिये ।
  3. उद्योग किनने प्रकार के होते हैं ? तृस्तरीय उद्योग से आप क्या समझते हैं ? ऐसे कुछ प्रमुख उद्योगों का वर्णन कीजिये ।
  4. भारत के उद्योगों में पिछड़ापन क्यों है ? इन्हें दूर करके उद्योग और औद्योगिकीकरण हेतु भारत को क्या करना चाहिये ? सुझाव दीजिये ।
  5. संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये—
    - ( i ) 1948 की औद्योगिक नीति
    - ( ii ) 1956 की औद्योगिक नीति
    - ( iii ) औद्योगिक समस्याएँ ।
-

## आधुनिक भारतीय उद्योग

### MODERN INDIAN INDUSTRIES

"ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने पूर्वी द्वीप समूह में जमी हुई अपनी वच रहित का ही अनुसरण किया। इसने देश के उद्योगी तथा व्यापार को चौपट कर दिया तथा भारतीय पदार्थों को यूरोप के बाजार से बाहर निकाल कर भारतीय चर्खे, हाथ करचे तथा उसके पहियों को चकनाचूर कर दिया।"

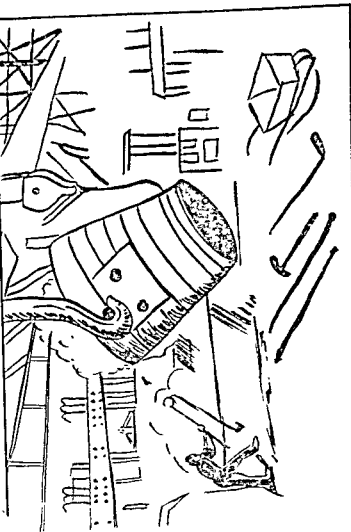
— काले माधव

वर्तमान बृहत् भारतीय उद्योगों में सूती वस्त्र, लोहा व इस्पात, चीनी, डूट, सीमेंट, रासायनिक पदार्थ, उर्वरक आदि का नाम उल्लेखनीय है। यहां हम कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों की प्रगति, वर्तमान स्थिति एवं समस्याओं का अध्ययन करेंगे।

#### लोहा व इस्पात उद्योग (Iron and Steel Industry)

लोहा व इस्पात उद्योग किसी भी देश के तीव्र औद्योगीकरण के लिए आवश्यक है। इसे औद्योगिक व्यवस्था में रीढ़ की हड्डी (Back Bone) कहा जाता है। देश की सुरक्षा, कृषि, उद्योग व माता-पिता के विकास में इस उद्योग का बहुत योगदान होता है।

इतिहास—भारतवर्ष में यह व्यवसाय अत्यन्त प्राचीनकाल से ही किया जाता है। कहा जाता है कि ईसा से 5,000 वर्ष पूर्व भी भारत वासी इस उद्योग का संचालन बहुत कुशलता पूर्वक किया करते थे। दिल्ली की कुतुबमीनार के पास बनी लोहे की कीली 1,500 वर्ष पूर्व सगाई गई थी। समोका की साट भी हमारे लोह और इस्पात उद्योग के प्राचीन मील की प्रतीक है। परन्तु लोह तथा इस्पात का बड़े पैमाने पर कार्य सन् 1907 में हुआ जबकि टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी



के बिहार में कारखाना खोला । सन् 1908 में बंगाल में मासनसोल के निकट 'इन्डियन आयरन तथा स्टील कंपनी' और सन् 1923 में मद्रासती (मैसूर) में मैसूर आयरन वर्क्स की स्थापना की गई । सन् 1924 में इन उद्योगों को सुरक्षण (Protection) प्राप्त हो गया जो सन् 1924 तक चलता रहा । इसी बीच सन् 1937 में 'बंगाल स्टील कॉर्पोरेशन' की स्थापना हुई । सन् 1952 में 'बंगाल स्टील कॉर्पोरेशन' और 'इन्डियन आयरन तथा स्टील कंपनी' का विलीनीकरण हो गया ।

**वर्तमान स्थिति**—स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सांख्यिक क्षेत्र में लोहा तथा इस्पात उद्योग का तेजी से विकास किया जा रहा है । द्वितीय योजना काल में सरकारी कंपनी 'हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड' के प्रयत्न से तीन कारखाने बनाए गये—

1. करकेला स्टील प्लांट (Rourkela Steel Plant)—उड़ीसा में पश्चिमी जर्मनी की मुक्तिवात फर्म 'क्रूप' के सहयोग से बनाया गया । यह कारखाना अब 12 लाख टन इस्पात उत्पादन की क्षमता रखता है । 1968-69 में इसने 12.43 लाख टन कच्चा लोहा तथा 11.61 लाख टन इस्पात पिंड का उत्पादन किया । सन् 1962 में इस्पात कारखाने के निकट रासायनिक खाद का एक कारखाना भी खोला गया । करकेला स्टील प्लांट की इस्पात पिंड क्षमता सन् 1968 में बढ़ाकर 18 लाख टन कर दी गयी ।

2. बिलाई (Bhilai) स्टील प्लांट—मोडियत कृष के सहयोग से मध्य प्रदेश में बनाये गये इस कारखाने में सन् 1968-69 में 19.35 लाख टन कच्चा लोहा तथा 17.35 लाख टन इस्पात पिंड का उत्पादन किया ।

3. दुर्गापुर स्टील प्लांट (Durgapur Steel Plant)—यह इस्पात का कारखाना पश्चिमी बंगाल के दुर्गापुर नामक स्थान पर सन् 1962 में खोला गया । 1968-69 में इस कारखाने ने 9.58 लाख टन लोहा तथा 7.5 लाख टन इस्पात पिंड तैयार किया ।

गृहीत योजना काम में इन कारखानों की उत्पादन क्षमता में बहुत विस्तार दिया गया। 1965 में मोविपत रुम के साथ सम्झौता किया गया जिसके अन्तर्गत बोकारो (बिहार) में एक नया स्टील प्लांट बनाया जा रहा है। इस कारखाने का प्रथम चरण मार्च 1971 में बन कर तैयार होगा। रुम की सरकार ने 20 करोड़ रुपये का ऋण विदेशों से राज सामान मंगाने के लिए स्वीकार किया है।

## भारत लोहा और स्पात उद्योग केन्द्र

कुल्लू • आसुननेरु  
जमशेदपुर • दुर्गापुर  
मिलाई • सरकेला

भद्राचली

● लगभग 166.6 करोड़ रुपये।

अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत में लोहा तथा इस्पात के छोटे-बड़े 167 कारखाने हैं जिनमें लगभग 131 करोड़ रुपये की घालू पूंजी लगी हुई है। इन कारखानों में लगभग 93 हजार व्यक्ति काम करते हैं। सन् 1967 में 70.10 लाख टन कच्चा लोहा तथा 41.35 लाख टन इस्पात तैयार किया गया। सन् 1967-68 में भारत ने 54.83 करोड़ रुपये के मूल्य का लोहा तथा इस्पात निर्यात (Export) किया।\*

हमारे लोहा और इस्पात व्यवसाय की सार्वजनिक क्षेत्र में काफी उन्नति हुई है। उद्योग में उन्नत उत्पादन विधियों का प्रयोग भी प्रारम्भ कर दिया गया है। सन् 1949 में लास्ट्रिया में प्रतिपादित एल० डी० प्रक्रिया (L.D Process) का प्रयोग हमारे यहाँ भी प्रारम्भ कर दिया गया है, जो उत्पादन लागत में कमी करती है। वर्तमान वर्षों में इस उद्योग द्वारा विभिन्न वस्तुओं का निर्माण बड़ा है। पिछले कुछ वर्षों में रेल की भारी पटरियाँ, टिन, प्लेटें, तार, चद्दर, पहिये, एक्सल आदि अनेक वस्तुओं का भारी संख्या में निर्माण हुआ। इतना होते हुए भी वह उद्योग हमारी सभी धरेख आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता।

उद्योग की समस्याएँ, उपचार एवं प्रगति—देश में इस उद्योग से सम्बन्धित सारी प्राकृतिक सुविधाएँ उपलब्ध होते हुए भी इस उद्योग के सामने निम्न समस्याएँ हैं—

(1) कोयले की कमी—अच्छी किस्म के कोयले की कमी के कारण घटिया किस्म का कोयला प्रयोग में लाया जाता है, जिससे उत्पादन लागत बढ़ जाती है। अतः घटिया कोयले को उन्नत करने अथवा संपन्न भंडार वाले लिग्नाइट के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिये। इस सम्बन्ध में कोयला साफ करने के लिए कारखाने खोले जा रहे हैं।

कच्चे माल की कठिनाई—उद्योगों के लिए अच्छी कोटि का कच्चा माल, जैसे उत्तम चूने का पत्थर आदि कारखानों के निकटवर्ती भागों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने से उन्हें दूर के क्षेत्रों से मयाना

पड़ता है, जिससे उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है। अतः यातायात का विकास आवश्यक है। सरकार पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत यातायात के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रही है।

### समस्याएँ

1. कोयले की कमी
2. कच्चे माल की कमी
3. पूँजी का अभाव
4. कुशल धमिर्कों तथा विशेषज्ञों की कमी
5. आधुनिक यंत्रों की कमी
6. श्रम सम्बन्धी कठिनाइयाँ
7. मूल्य सम्बन्धी कठिनाइयाँ
8. यातायात के साधनों का अभाव

### (3) पूँजी का अभाव—

इस्पात उद्योग के विस्तार एवं अमिनवीकरण के लिए बहुत पूँजी की आवश्यकता है। भारत में पूँजी निर्माण की शक्ती कम होने से हमें अधिकतर विदेशी सहायता पर ही निर्भर रहना पड़ता है और पूँजी के अभाव में पुरानी मशीनों से ही काम लेना पड़ता है। देश में पूँजी संचय को प्रोत्साहन देना चाहिये। सरकारी तथा विदेशी सहायता बहुत आवश्यक है।

(4) कुशल धमिर्कों तथा विशेषज्ञों की कमी—इस उद्योग को अधिक कुशल और सामर्थ्यवान बनाने के लिए (expert) एवं कुशल धमिर्कों की आवश्यकता है। विदेशों से अनेक विशेषज्ञों को बुलाना पड़ता है, जिससे विदेशी मुद्रा की समस्या उत्पन्न होती है। अतः हमारे विदेशों को बाहर प्रशिक्षण के लिए अधिक संख्या में भेजना चाहिये और देश में धमिर्कों के लिए तीव्र गति से प्रशिक्षण केन्द्र खोलने चाहिये। अब तकनीकी प्रशिक्षण (technical training) के विचार्य हेतु प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(5) आधुनिक यंत्रों की कमी—पूँजी तथा विशेषज्ञों की कमी के कारण अनेक छोटा और दम्पान कारखानों में आधुनिक तकनीकी कार्य एवं प्रयोग में ग्री मादे जाने विशेष उत्पादन शक्ती कम रही है।

अतः उत्पादन की नवीन विधियों व आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करना आवश्यक है ।

(6) धम सम्बन्धी कठिनाइयाँ—औद्योगिक अशान्ति के कारण उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है । सरकार को धम कल्याण के सर्वेस में नियम पारित कर धम और पूंजी में सौहार्दपूर्ण वानावरण कायम करना चाहिये । इस सम्बन्ध में सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है ।

(7) मूल्य सम्बन्धी कठिनाई—भारतीय इस्पात का 'निर्धारित मूल्य' समय-समय पर बदलता रहता है, जिसमें इस्पात की कीमतें अनिश्चित रहती हैं ।

(8) यातायात के साधनों का अभाव—कच्चा माल, कोयला आदि आवश्यक सामान कारखानों तक पहुँचाने व निमित्त माल को विभिन्न क्षेत्रों में ले जाने के लिए सुगम और सस्ते साधन उपलब्ध न होने से कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । सरकार यातायात के विकास पर बहुत ध्यान दे रही है ।

अन्त में कहा जा सकता है कि भारतीय लोहा एवं इस्पात उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है क्योंकि हमारे यहाँ उद्योग के लिए आवश्यक सामग्री, जैसे कच्चा लोहा, मैंगनीज, डोलोमाइट (Dolomite) आदि बहुतायत में पाई जाती है ।

### सूती वस्त्र उद्योग

#### COTTON TEXTILE INDUSTRY

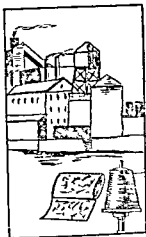
“सूती उद्योग भारत के प्राचीन युग का गौरव, वर्तमान एक भविष्य का सपना, किन्तु सदा की आशा है ।” — बुकनेन

यह उद्योग देश का सबसे बड़ा उद्योग है । सूत और वस्त्र उत्पादन की मात्रा देखते हुए भारत संसार में तीसरे स्थान पर और सूत उपभोग की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता है ।

इतिहास—भारत का वस्त्रोद्योग प्राचीन काल में बहुत उन्नत था । भारत कई देशों को अपने यहाँ के बने हुए वस्त्र भेजता था । यह व्यवसाय



उस समय बूटीय उद्योगों के रूप में चलाया जाता था। भारत में सर्व-प्रथम संगठित रूप में सूती वस्त्र के कारखाने की स्थापना सन् 1818 में



## सूती वस्त्र उद्योग

आयात में कमी हुई और देश में बने कपड़े की माँग में वृद्धि हुई।

प्रथम महायुद्ध काल—प्रथम महायुद्ध काल में अन्य उद्योगों में साथ साथ सूती वस्त्र का भी बहुत विकास हुआ। युद्धकाल में इस उद्योग की सफलता के पीछे सैनिक कपड़े की बढ़ी हुई माँग और विदेशों से आयात न होने के कारण देशी कपड़ों की माँग में वृद्धि हुई थी। युद्धकाल की यह समृद्धि अधिक दिनों तक न चल सकी। मंदी और आपात की बढ़ती हुई स्पर्धा के कारण भारतीय सूती कपड़े के व्यवसाय को बहुत प्रभाव लगा। इस काल में उद्योगपतियों एवं श्रमिकों के अनेक झगड़े हुए। सरकार ने उद्योग की सहायता करने के लिए सन् 1924 में वस्त्रों पर से उत्पादन शुल्क (Excise duty) हटा दिया कुछ समय बाद सरधान की माँग भी की गई। सन् 1927 में संरक्षण (protection) नीति

बलवत्ता में हुई। किन्तु इस उद्योग की वास्तविक नींव सन् 1854 में पड़ी, जब कि बम्बई में सूती वस्त्र का कारखाना स्थापित किया गया। इसके बाद बम्बई महमदाबाद, नागपुर तथा शोनापुर में कई कपड़े बनाने के कारखाने खोले गए। प्रारम्भिक काल में इस उद्योग की प्रगति बहुत धीमी रही। सन् 1881 से प्रथम महायुद्ध के काल तक भारतीय सूती वस्त्र उद्योग तेजी से बढ़ा। स्वर्गीय राष्ट्र-पिता महात्मा गांधी के 'स्वदेशी आंदोलन' से उद्योग पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। विदेशी कपड़े के

अपनाई गई, जिसमें विदेशी वस्त्र के आयात पर कर लगाया गया ।

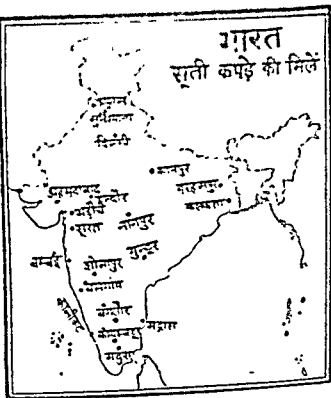
**द्वितीय महायुद्ध काल—**द्वितीय महायुद्ध काल में भारतीय वस्त्रोद्योग को विकसित करने का मुनहरा अवसर मिला, जबकि इंग्लैंड और जापान भारत को वस्त्र भेजने वाले दोनों ही देश, युद्ध के मकर में पड़े हुए थे अतः इस काल में बपड़े के उत्पादन और मुख्य दोनों में ही वृद्धि हुई । सन् 1943 में वस्त्रों का मुख्य खरब गीमा तक पहुँच गया । सरकार ने मूल्य-वृद्धि रोकने के कई प्रयत्न किए । मुख्य निर्यात के अतिरिक्त वितरण पर भी नियंत्रण कर दिया गया । सन् 1947 में देश के विभाजन के परिणामस्वरूप कपास उत्पादन करने वाले कई क्षेत्र पाकिस्तान में चले गये इसलिये कच्चे माल की कमी अनुभव हुई । सन् 1947 में उद्योग की स्थिति कुछ सुधार आने से सरधान नीति को समाप्त कर दिया गया ।

**पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत प्रगति—**प्रथम पंचवर्षीय योजना में सूत और वस्त्र उत्पादन के निर्धारित लक्ष्यों से अधिक सफलता मिली । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वस्त्र निर्मात और प्रति व्यक्ति वस्त्र उपभोग के महत्वपूर्ण लक्ष्य रखे गए । इस योजना में 91-44 करोड़ मीटर वारिक वस्त्र निर्मात का लक्ष्य रखा गया था । योजना के अंत तक सूती वस्त्र के वारिक उत्पादन का लक्ष्य 775 करोड़ मीटर पर निर्धारित किया गया था जो पूरा हो गया है ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सूती वस्त्र उत्पादन का वारिक लक्ष्य 865 करोड़ मीटर रखा गया था । वर्तमान कारखानों की उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के अतिरिक्त 25 हजार स्वयंसेवक करके लक्ष्य का लक्ष्य रखा गया है ।

चौथी योजना में 40 लाख लघु, 25 हजार करके लक्ष्य का निश्चित किया गया है । देश में बपड़े की महानो के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाएगा । बपड़े के उत्पादन तथा निर्यात को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा । योजना की धराधि में अग्निबीजरण के लिए 132-5

बसोदू तथा विकास व्यवस्थाओं के लिए 1339 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का लक्ष्य है ।



वर्तमान स्थिति—देश के संगठित व्यवसायों में इसका स्थान सर्व प्रथम है । इस समय देश में 647 कारखाने हैं इनमें (358 केवल

सूत कातने वाले हैं) जिनमें 174.5 लाख तकुए (Spindles) तथा 289 लाख करघे (Looms) लगे हुए हैं। प्रतिवर्ष 25 से 40 नए कारखानों की स्थापना होती है। इस क्षेत्र में सहकारी कारखाने भी स्थापित हो रहे हैं।

सन् 1968 में कारखानों द्वारा 436.61 करोड़ मीटर कपड़ा तथा 96.09 किलोग्राम सूत (Yarn) का उत्पादन हुआ।

उद्योग की समस्याएँ उपचार एवं प्रगति—

यद्यपि भारतीय सूती वस्त्र उद्योग का अविष्य उज्ज्वल है तथापि इसके सामने वर्तमान समय में कुछ गम्भीर समस्याएँ हैं। इन समस्याओं को दूर किये जाने पर ही सूती वस्त्र उद्योग के विकास की आशा की जा सकती है। ये समस्याएँ निम्नलिखित हैं—

1. कच्चे माल की समस्या—कपास की कमी उद्योग की सबसे गम्भीर समस्या है। भारत कपास में घातम निर्मात्र नहीं है। देश के

विमादन ने इस समस्या को और गम्भीर बना दिया। लम्बे रेशे वाली उत्तम कपास हमें विदेशों से मगानी पड़ती है।

भारत सरकार कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। पंचवर्षीय

योजनाओं के अन्तर्गत कपास उत्पादन के लिये विशेष लक्ष्य रखे गए हैं। सन् 1967-68 में 55.62 लाख गॉस कपास का उत्पादन हुआ।

2. आधुनिकीकरण (Modernisation) की समस्या—आधुनिक सूती वस्त्र के कारखानों में लगी हुई मशीनें पिसी हुई हैं। उत्पादन बढ़ाने तथा उत्पादन लागत कम करने के लिए आधुनिकीकरण आवश्यक है। योजना आयोग ने उद्योग में आधुनिकीकरण को कृष्ण

#### वस्त्रोद्योग की समस्याएँ

1. कच्चे माल की समस्या
2. आधुनिकीकरण की समस्या
3. विवेकीकरण की समस्या
4. निर्यात बढ़ाने की समस्या
5. उत्पादन समन्वय की समस्या

लागत का अनुमान 360 करोड़ रुपये लगाया है, जो देश के सामर्थ्य से बाहर है। भारत सरकार ने 'राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम' की स्थापना की है जो आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत खरीदने के लिए ऋण देता है।

3. विवेकीकरण (Rationalization) की समस्या—भारतीय सूती वस्त्रोद्योग का विकास विवेकपूर्ण वैज्ञानिक आधार पर नहीं हुआ है। इससे वस्त्र की उत्पादन लागत बढ़ती है। लगभग 125 कपड़े की छोटी अनाधिक मिलों को पुनः संगठित करके उनमें विवेकीकरण अर्थात् संगठन और मशीनों से सम्बन्धित सुधार करने चाहिये। बेरोजगारी की समस्या को ध्यान में रखते हुए विवेकीकरण धीरे-धीरे करना होगा।

4. निर्यात बढ़ाने की समस्या—सूती वस्त्रों की निर्यात वृद्धि की समस्या गम्भीर रूप धारण कर रही है। जापान और पाकिस्तान से प्रतिस्पर्धा निरन्तर बढ़ रही है। कई कपास उत्पादन करने वाले देश भी अपने देशों में सूती वस्त्र के निजी कारखाने खोलना चाहते हैं जिससे हमारे कपड़े की विदेशों में माँग और कम हो जाएगी। अतः उत्पादन लागत कम करके नये-नये डिजाइन निकालकर विज्ञापन द्वारा निर्यात बढ़ाना चाहिये।

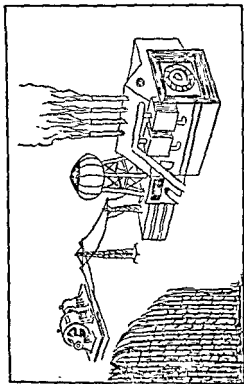
5. उत्पादन समन्वय की समस्या—सूती वस्त्र का उत्पादन कारखानों, हाथ करघों तथा शक्ति करघों द्वारा किया जाता है। इनमें समन्वय का अभाव है। अतः इन तीनों की स्पर्धा के स्थान पर समन्वय (Co-ordination) इस प्रकार किया जाय कि किसी भी स्तर के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव न पड़े।

संक्षेप में, सूती वस्त्र उद्योग को पनपाने के लिए उत्पादन लागत को कम करना अति आवश्यक है। ऐसा तभी सम्भव हो सकता है जबकि आधुनिकीकरण एवं विवेकीकरण कार्यक्रमों को तेजी से अपनाया जाय।

### चीनी उद्योग (SUGAR INDUSTRY)

चीनी उद्योग भारतीय मण्डित उद्योगों के क्षेत्र में दूसरा स्थान

रखता है। हमारा देश शाकाहारी प्रधान (Vegetarian) होने के कारण हमारे भोजन में चीनी का बहुत महत्व है। साथ ही चीनी विदेशी मुद्रा कमाने का भी महत्वपूर्ण साधन है।



शेक-कर उद्योग

इतिहास—ऐसा समझा जाता है कि भारतवर्ष का चीनी व्यवसाय बहुत पुराना है। किन्तु पहले कुछ और साइतारे उद्योग ही थे और

आधुनिक यंत्रों वाले कारखानों का मूत्रपात सन् 1930 के बाद ही अधिक ठीक से हुआ। इस समय भारत सरकार ने उद्योग के विकास के लिए संरक्षण (Protection) प्रदान किया। संरक्षण के परिणामस्वरूप बाहर से आने वाली चीनी की मात्रा में कमी हुई। संरक्षण के कारण ही अन्य उद्योगों की घरेलू चीनी उद्योग का सबसे अधिक विकास हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि 'भारतीय चीनी उद्योग संरक्षण का बालक है।' (Indian Sugar Industry is the child of protection)

द्वितीय महायुद्ध काल में चीनी उद्योग को पुनः संरक्षण प्रदान किया गया। इस समय चीनी की कीमत बहुत बढ़ गई। अतएव सरकार ने चीनी के मूल्य और वितरण पर नियंत्रण करना स्वीकार किया। यह उद्योग सन् 1950 तक सरकारी संरक्षण प्राप्त करता रहा। सन् 1931 से 1950 तक लगभग सारी अवधि में चीनी उद्योग को संरक्षण मिलता रहा। वही सन् 1931 में चीनी मिलों की संख्या 32 और उत्पादन 5 लाख टन था, वहां 1951 में यह संख्या बढ़ कर लगभग 141 और 14.2 लाख मी. टन हो गई।

**पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत प्रगति—**

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चीनी उत्पादन का लक्ष्य 15.2 लाख मी. टन प्रतिवर्ष रखा गया, किन्तु मींग बढ़ जाने के कारण इसमें संशोधन करके 19.2 लाख मी. टन कर दिया गया। नए कारखाने खोले गये और चीनी उद्योग के विकास एवं नियंत्रण के लिए 'चीनी विकास परिषद्' की स्थापना की गई। योजना के अन्त में चीनी का उत्पादन 18.9 लाख मी. टन प्रतिवर्ष हो गया। इस अवधि में लगभग 15 करोड़ रुपये की पूंजी का और विनियोग (investment) इस व्यवसाय में किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में चीनी की क्षमता बढ़ा कर 25.4 लाख मी. टन कर देने का लक्ष्य था। उत्पादन बढ़ाने के लिए सहकारी चीनी मिलों (Co-operative Sugar Mills) की स्थापना के लक्ष्य रखे गये। इस अवधि में चीनी मिलों में आधुनिक

कीकरण एवं विवेकीकरण को प्राथमिकता (Priority) दी गई। योजना के अन्तिम वर्ष में चीनी का उत्पादन 26.4 लाख मी. टन हुआ। इस अवधि में चीनी उद्योग विकास पर 10 करोड़ रुपये खर्च किया गया। इस अवधि में उत्पत्ति बढ़ जाने से चीनी का निर्यात भी किया गया।

तृतीय पंचवर्षीय योजना—के अन्त में चीनी के उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य 35.6 लाख मी. टन पर निर्धारित किया गया था। योजना समीप ने यह तय किया है कि चीनी के निर्यात को बढ़ाया जाय।

वर्तमान स्थिति—सन् 1967-68 में भारतवर्ष में चीनी मिलों की संख्या 200 थी। अनुमान है कि इस उद्योग में 15 लाख श्रमिक काम कर रहे हैं। इस उद्योग से सरकार को 65 करोड़ रुपये की वार्षिक आय होती है और इसमें 100 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी लगी हुई है। सन् 1967-68 में शक्कर का उत्पादन 22.48 लाख टन हुआ।\* इसी वर्ष में देश से शक्कर का निर्यात सन् 1966-67 की अपेक्षा 1.70 लाख टन कम किया गया। यह उद्योग लगभग 2 करोड़ कृषकों से गन्ना खरीद कर राष्ट्रीय स्तर में 5% योगदान देता है। सन् 1963 में चीनी उत्पादन और बन्ने के मूल्य की कठिनाइयों के कारण चीनी का राशन कर दिया गया था। अब आंशिक नियंत्रण की नीति अपनाई गई है। इस उद्योग का लगभग एक चौथाई भाग सहकारी क्षेत्र (Co-operative Sector) में है। यह उद्योग मुख्यतः उत्तर प्रदेश और बिहार में केन्द्रित है।

उद्योग की समस्याएँ एवं उपचार

चीनी उद्योग की कुछ गंभीर समस्याएँ हैं, जिन पर विचार करना आवश्यक है।

---

\*India 1969, p. 324



### चीनी उद्योग की समस्याएँ

1. गन्ने की कमी
2. गन्ने की कीमत सम्बन्धी कठिनाइयाँ
3. गन्ने की घटिया किस्म
4. गन्ना पेरने का अल्प समय
5. गन्ने का दोषपूर्ण विवरण
6. कृषि पक्ष और निर्माण पक्ष में अन्तर
7. अतिरिक्त उत्पादन इकाइयाँ
8. प्राधुनिकीकरण की समस्या
9. ईंधन की समस्या
10. उद्योग का स्थानीकरण
11. उपोत्पत्ति के उपयोग का अभाव
12. चीनी का संकट

1. गन्ने की कमी—अन्य देशों की तुलना में यहाँ गन्ने का उत्पादन बहुत कम है। भारत में गन्ने की प्रति हेक्टर लगभग 35-4 मी. टन है। यह चीन से कच्चा चीनी तुलना में एक तिहाई, जावा की तुलना में चौथाई तथा हवाई (Hawaii) की तुलना में पाँचवा भाग है। गन्ने की कमी का सीधा प्रभाव चीनी उद्योग पर पड़ता है।

अतः गन्ने के उत्पादन को बढ़ाने के प्रयत्न किये जाने चाहिए। इसके लिए सिंचाई की सुविधाएँ, उत्तम बीज, साद, औजार, कीटाणु नाशक औषधियाँ, भूमि क्षय की

रोक आदि सुविधाएँ आवश्यक हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में गन्ना उत्पादन वृद्धि पर ध्यान दिया जा रहा है। चौथी पंचवर्षीय योजना में भी कृषि विकास पर बहुत बल दिया जाएगा।

2. गन्ने की कीमत सम्बन्धी कठिनाइयाँ—हमारे यहाँ जावा और अन्य चीनी उत्पादक देशों की तुलना में गन्ने की कीमत अधिक है। परिणामस्वरूप उत्पादन लागत बढ़ जाती है। क्योंकि गन्ने की कीमत में कमी होना खेती के विकास पर निर्भर करता है, इसलिये इस दिशा में सहकारी प्रयत्न करने चाहिए।

3. गन्ने की घटिया किस्म—गन्ने की कीमत तो अधिक है ही साथ ही साथ गन्ने से प्राप्त होने वाली चीनी का प्रतिशत भी बहुत कम



110 दिन का गन्ना पेरने का कार्य होता है, जबकि अन्य देशों में 240-250 दिनों तक गन्ना पेरने का कार्य होता है। इससे भारतीय चीनी उत्पादन लागत बढ़ जाती है। अतः अनुसंधान करके गन्ना पेरने की अवधि में वृद्धि की जानी चाहिए। इसके लिए आगे-पीछे फसल उगाने पर खोज की जानी चाहिए।

5. गन्ने का बोधपूर्ण वितरण—कई कारखाने ऐसे क्षेत्रों में स्थित हैं जहाँ गन्ना बहुत कम पैदा होता है। फलस्वरूप उन कारखानों को दूर-दूर से गन्ना मंगाना पड़ता है, जिससे दुलाई खर्च बढ़ जाता है अतः उन्नत यातायात के साधनों के प्रतिरिक्त देश के सभी भागों में गन्ना उत्पादन के विशेष कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए।

6. कृषि पक्ष और निर्माण पक्ष में अन्तर—हमारे यहाँ गन्ना उत्पादन एवं चीनी निर्माण कार्य अलग-अलग पक्षों द्वारा किया जाता है। चूँकि इन दोनों में समन्वय की कमी है, इसलिए कारखाने गन्ने की मात्रा एवं उत्तमता को नियमित नहीं कर सकते। अतः विश्व के अन्य चीनी उत्पादक देशों की भाँति दोनों पक्षों में उचित तालमेल बिटाना चाहिए, सहकारी चीनी मिलों द्वारा यह कार्य अधिक सरलता से हो जायगा।

7. अनाधिक उत्पादक इकाइयाँ (Uneconomic Units)—कई चीनी कारखाने ऐसे हैं जिनकी उत्पादन क्षमता बहुत कम है और ये चीनी उत्पादन लागत को बढ़ा देने हैं। एकीकरण, समिन्दीकरण तथा विवेकीकरण पद्धतियों द्वारा इस सैब दोष को दूर करना चाहिए।

8. आधुनिकीकरण की समस्या—भारत में अधिकांश मिलें अनाधिक इकाइयों के रूप में हैं। पुरानी उत्पादन पद्धतियों और घिसी हुई मशीनों के प्रयोग से उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है। फलस्वरूप निर्यातों को भारतीय चीनी बहिरी पड़ती है जिससे निर्यात में क़मी आती है। अतः हममें आधुनिकीकरण आवश्यक है। “राष्ट्रीय उद्योग विकास विधायक” इस ओर प्रयत्नशील है।

9. ईंधन (Fuel) की समस्या—चीनी मिलों में बहुधा गन्ने का छिलका (bagasse) जलाया जाता है। किन्तु यह अपर्याप्त मात्रा में है। अतः विद्युत के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। योजनाओं के अन्तर्गत जल विद्युत शक्ति के विकास पर बल दिया जा रहा है।

10. उद्योग का स्थानीयकरण—समूचे उद्योग के लगभग 75 प्रतिशत कारखाने उत्तर प्रदेश तथा बिहार में स्थित हैं तथा उनमें चीनी की खपत बहुत कम है; जबकि बम्बई व मद्रास में चीनी की माँग अधिक है, लेकिन वहाँ चीनी उत्पादन के कारखाने नगण्य हैं। कारखानों के एक ही स्थान पर केन्द्रीयकरण होने से यातायात व्यय बड़ जाता है। अतः देश के सभी भागों में चीनी के कारखानों का विस्तार करना चाहिए। सहकारी क्षेत्र में इस उद्योग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

11. उपोत्पत्ति के उपयोग का अभाव—चीनी कारखानों की उपोत्पत्ति (by products) का समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप उत्पादन लागत बढ़ी हुई है। गन्ने का छिलका (bagasse) कागज तथा गन्ता बनाने के काम में लिया जा सकता है। इसके अलावा भारी मात्रा में जमा होने वाला शीरा (Molasses) को अलकोहल (alcohol), उर्वरक (fertilizers), कोरों के भोजन व अन्य उपयोग में लाया जा सकता है।

12. चीनी का संकट—पिछले कुछ वर्षों से घरेलू उपयोग के लिए चीनी का संकट चल रहा है। मूल्य भी बढ़ गए हैं। सरकार ने स्थिति सुधारने के लिए चीनी का मूल्य नियन्त्रण तथा राशन कर दिया है।

अन्त में हम कह सकते हैं कि चीनी उद्योग को उन्नत दिशाओं में विकसित करने पर ही निर्भर बढ़ावा जा सकेगा। हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति चीनी का उपयोग 3.2 कि. ग्राम प्रति वर्ष है जबकि अन्य देशों में इससे कई गुनी खपत है।

#### 4. जूट उद्योग (Jute Industry)—

इस उद्योग की उपयोगिता राष्ट्र के जीवन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे लिये विदेशी विनिमय भी प्राप्त करवाता है। भारत को प्रारम्भ से ही इस उद्योग में एकाधिकार (monopoly) प्राप्त रहा है। वस्तुओं को पैक करने, नौकाओं व जलयोतों पर पाल का काम करने, मोटे-मोटे रस्मों के द्वारा वस्तुओं को बाँधने में जूट का प्रमुख स्थान है।

प्रारम्भिक काल—जूट के अधिकारिण करवाने हुगली के तट पर कलकत्ता के चारों ओर केन्द्रित है। यद्यपि जूट की खेती प्राचीनकाल से होती आ रही है, किन्तु इसका निर्यात व्यापारिक पैमाने पर 16 वीं शताब्दी में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना के साथ प्रारम्भ होता है। सन् 1854 में जब रूसी पाट का निर्यात बन्द हो गया तो एक अंग्रेज उद्योगपति आर्कलैण्ड ने सेरामपुर के पास रिशरा नामक जगह पर जो बंगाल में है, पहली जूट की मिल की नींव डाली। इससे अन्य लोगों को भी प्रोत्साहन मिला और फिर बोनियों कम्पनी की स्थापना सन् 1859 में हो सकी। पहले 30 वर्षों में विकास की गति मन्द रही। सन् 1868 से सन् 1873 तक मिलों ने खूब लाभ कमाये, इसलिये और भी मिलें खुलने लगीं और 30 मिलों में मजदूरों की संख्या 20,000 तक पहुँच गयी। इनमें से 16 मिलें बम्बई के पास केन्द्रित थीं। निर्यात बढ़े और सन् 1885 में जूट के बीरों की जगह जूट के कपड़ों का उत्पादन बढ़ा। सन् 1900 के बीच एक अकाल पड़ा, जिससे उद्योग को घबका लगा लेकिन 20 वीं शताब्दी के प्रारंभ में कृषि की उन्नति के साथ-साथ इस उद्योग ने भी उन्नति की। सन् 1906 में फिर उद्योग में शिथिलता आई क्योंकि जर्मनी और अमेरिका में जूट और पाट के कई स्थानापन्न (Substitutes) ढूँढे जाने लगे।

प्रथम महायुद्ध व उद्योग—युद्ध काल में जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया और रूसी सन का निर्यात बन्द हो गया। अतः भारत के इस उद्योग को लाभ पहुँचा व प्रोत्साहन मिला। सन् 1918 तक जूट की खपत 55 लाख गॉठ प्रतिवर्ष हो गयी, जब कि यह माँग युद्ध के पहले

44 साल गोट थी। इस अवधि में उद्योगपतियों ने 55% से 60% तक लाभ कमाया।

युद्ध के बाद मांग गिरने से निर्यात कम हुए। मजदूरों ने मजदूरी की वृद्धि की मांग की और अवसाद (Depression) का समय आया। सन् 1929 की महान आर्थिक मंदी का सबूत भी आया लेकिन संगठन बढ़ा होने के कारण उद्योग इस संकट को झेल सका।

द्वितीय महायुद्ध काल में उद्योग—युद्ध से उद्योग को एक बार फिर प्रोत्साहन मिला। कूट की मांग बढ़ने से मासिक उत्पादन सन् 1939 में 90,700 टन से बढ़कर सन् 1940 में 1,25,700 टन हो गया। यह उद्योग का नया रिकार्ड था। युद्ध के प्रथम वर्ष में मिलों की संख्या 107 तक पहुँच गयी जिसमें 98 बंगाल, 3 उत्तर प्रदेश, 3 बिहार, 2 मद्रास और एक अन्य प्रदेश में स्थित थी।

विभाजन में उद्योग—सन् 1947 में देश के विभाजन ने इस उद्योग पर सबसे अधिक बारी प्रभाव डाला। पाकिस्तान को 63.4% बच्चे कूट उत्पादन का भाग मिला और भारत में 113 मिलें रह गयीं। बाद में बिहार, उड़ीसा में उत्तर प्रदेश की मिट्टी पर परीक्षण हुए और वहाँ उत्पादन एवं प्रसार हुआ। इस समय देश में 88 कूट मिलें हैं।

कूट उद्योगों की वर्तमान स्थिति—प्रथम योजना में उद्योग ने आशातीत सफलता प्राप्त की और कूट के सामान का उत्पादन 11.1 लाख टन था। सन् 1955-56 में कूट के सामान का निर्यात 8,75,000 टन था। सन् 1951-52 में कोरिया के युद्ध ने निर्यात की प्रोत्साहन दिया। सन् 1960 में 84,000 टन बच्चे कूट का निर्यात किया गया। द्वितीय योजना में बच्चे कूट का उत्पादन रुद्ध 40 लाख टॉन्स रखा गया था। तृतीय योजना में 72 लाख तथा चौथी योजना में 110 लाख टॉन्स रखा गया है। अभी एग्जिट से 21 मिलों के सहरी सेती बार्देबम प्रारम्भ हो चुका है। सन् 1966-67 में 283.53 करोड़

रूपरे के मूल्य की जूट वस्तुओं का निर्यात हुआ १० सन् 1968 में जूट निर्यात माल का उत्पादन 10.85 लाख टन हुआ ।†

उद्योग की समस्याएँ तथा सुझाव (Problems and Suggestions)

1. कच्चे माल का अभाव (Shortage of raw material)—कच्चे माल का अभाव देश-विभाजन के साथ ही प्रारम्भ हुआ । इस अभाव को दूर करने के लिये नये क्षेत्र उत्पादन के लिए खूँटे गये । किन्तु उल्लंघान एवं मिट्टी की विविधता के कारण आयातनक संकलता न मिली । जूट का उत्पादन बढ़ा तो अवश्य किन्तु जिस निम्न कोटि की हो रही । यतः उच्च कोटि का जूट अब भी आयात करना पड़ता है । जूट आयोग (Jute commission) ने उत्पादकों को उचित मूल्य देने की सिफारिश की ताकि लोगों को प्रोत्साहन मिल सके । पटसन समिति के अध्यक्ष भी एन सी. श्रीवास्तव ने कहा कि जूट के सामान की वर्तमान खपत को देखते हुए यह आशा की जाती है कि सन् 1970-71 तक 10 लाख 41 हजार टन और सामान की खपत होने लगेगी ।

2. निर्यात सम्बन्धी समस्या (Problem of export)—जूट उद्योग की दूसरी समस्या निर्यात के साथ जुड़ी हुई है क्योंकि भारत अपने कुल जूट के निर्यात का 8.9% अकेले पश्चिमी यूरोप को निर्यात करता है । यतः खपत बढ़ाने के लिए इन देशों को सहायता से एक लम्बी अवधि का निर्यात कार्यक्रम तैयार करना चाहिये । साथ ही साथ जापान, थाईलैण्ड, बर्मा, फ्रांस, हॉलैण्ड और बेल्जियम में जूट मिलों की स्थापना और उत्पादन विद्या जा रहा है । विदेशों में जूट के स्थापना प्रचल गये हैं । स्वयं पाकिस्तान एक लम्बे प्रतिद्वन्द्वी के रूप में हमारी टक्कर में लड़ा है । इन सब परिस्थितियों में आवश्यकता इस बात की है कि निर्यात बढ़ाया जाए और उच्च कोटि का माल तैयार हो । इसके ठीके पटसन समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि अपनी जूट की ऐसी स्थापना की जाये जिसके अनुसार किसी सामान या संयंत्र को पटसन का अधिकृत स्टॉक रखने का काम सौदा सार ।

\* India 1969, p. 370

† India 1969, p. 323

3. **अभिनवीकरण की समस्या (Problem of modernisation)**—अभिनवीकरण की समस्या जो भारत के सभी उद्योगों के साथ दिखलाई पड़ती है, बड़ी गम्भीर है। नई मशीनों द्वारा बनाया हुआ माल सस्ता और अच्छा होने के कारण ग्राहकों को जल्दी आकर्षित कर लेता है। अतः इस उद्योग में अभिनवीकरण आवश्यक है। इसके लिए राष्ट्रीय भौद्योगिक विकास निगम विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

### सीमेन्ट उद्योग (Cement Industry)

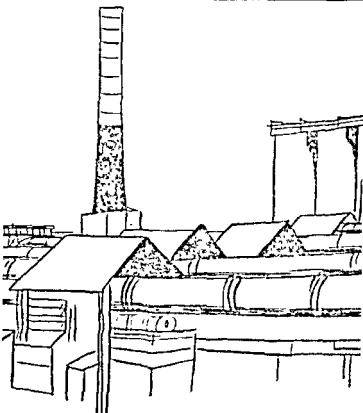
मानव की तीन प्रमुख आवश्यकताएँ हैं—भोजन, वस्त्र तथा मकान। भवन निर्माण कार्य के लिए सीमेन्ट की आवश्यकता होती है। बाँध, सड़कें एवं अन्य निर्माण कार्यों में भी सीमेंट का महत्व सुविदित है।

**इतिहास**—सीमेन्ट उद्योग बहुत प्राचीन व्यवसाय नहीं है। सर्व प्रथम सीमेन्ट बनाने का कार्य सन् 1904 में मद्रास में हुआ किन्तु इसका वास्तविक प्रारम्भ सन् 1912-13 में हुआ जब विशाल पैमाने पर तीन कम्पनियों का निर्माण हुआ। प्रथम महायुद्ध से इस उद्योग को काफी प्रोत्साहन मिला। सन् 1923 तक भारत में 10 सीमेन्ट कम्पनियाँ खुल गईं। इसी समय सीमेन्ट उद्योगपतियों ने अपने हितों की रक्षा के लिए “इण्डियन सीमेन्ट मैन्यूफैक्चरर्स एसोशिएशन” की स्थापना की। सन् 1936 में व्यवसायिक स्पर्धा के निवारणार्थ एसोसिएटेड सीमेन्ट कम्पनीज (A.C.C.) लि० का गठन हुआ। द्वितीय महायुद्ध काल में इस व्यवसाय की उन्नति हुई।

विभाजन (1947) के समय भारत में 18 कारखाने रह गये। प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) के अन्त में सीमेन्ट का उत्पादन 47 लाख टन हुआ।

**द्वितीय योजना**—के अन्त में सीमेन्ट का उत्पादन 79 लाख टन तथा तृतीय योजना के अन्त में 110 लाख टन हो गया। सन् 1965 में





सीमेंट उद्योग

सार्वजनिक क्षेत्र में सीमेंट उद्योग के लिए अनुसंधान, प्राविधिक सलाह तथा उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए 'सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया' का गठन किया गया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सीमेंट की उत्पादन क्षमता लगभग 230 लाख टन हो जाने का अनुमान है। सन् 1962 में मिलावट रोकने के लिए अध्यादेश जारी किया गया। सन् 1966 के प्रारम्भ में मूल्य एवं वितरण पर से सरकारी नियन्त्रण हटा लिया गया। पुनः नियन्त्रण लगाया गया परन्तु सन् 1970 में नियन्त्रण हटा लेने का निश्चय किया गया है।

वर्तमान स्थिति—इन समय सीमेंट उद्योग में लगभग 55 हजार श्रमिक काम करते हैं। उद्योग में लगभग 115 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है। भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक प्रयोग केवल 18 ग्राम\* है जिसकी आवश्यकता में काफी बढ़ जाने की सम्भावना है। सन् 1968-69 में सीमेंट का वार्षिक उत्पादन 122 लाख टन† था।

भारतीय सीमेंट उद्योग को भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कुछ मुख्य समस्याएं हैं—मूल्य सम्बन्धी, पूंजी की कमी, प्रतिस्थापित क्षमता (Installed Capacity) का अपूर्ण उपयोग, कच्चे माल व दानावात की कठिनाइयाँ।

इन समस्याओं के निराकरण के लिए मूल्य नियंत्रण, आवधिक सहयोग मशीनों के आयात की व्यवस्था, विरम नियन्त्रण, कोयले की नियमित पूर्ति तथा सरकार की लाइसेन्सिंग पद्धति को व्यावहारिक बनाया जाना चाहिये।

**रेशमी बस्तीउद्योग (Silk Industry)**—वर्ष 19 बी मरी

\* कुछ अन्य देशों में यह औसत है—ब्रिटेन 206 कि. ग्राम, जापान में 226 कि. ग्राम, जर्मनी में 259 कि. ग्राम, अमेरिका में 272 कि. ग्राम तथा स्विट्जरलैण्ड में 386 कि. ग्राम।

† India 1969, p. 324



अब तक हम चमड़ा और लालें निर्यात करते थे किन्तु अब देश में ही चमड़े का सामान बनाने का धन्दा विकसित हो जाने के कारण यह निर्यात धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तथा मद्रास में यह व्यवसाय अधिक उन्नत है। यह व्यवसाय निजी क्षेत्र के ही नियन्त्रण में है।

11. कागज उद्योग (Paper Industry)—देश में पहला कारखाना 1870 में खोला गया। यह व्यवसाय सार्वजनिक क्षेत्र में भी किया जाता है। मध्य प्रदेश का भेननल गूड्रि प्रिंट एण्ड पेपर मिल, नेपालगर सार्वजनिक क्षेत्र का कारखाना है। सन् 1968 में कागज तथा बोर्ड का उत्पादन लगभग 6.35 लाख टन हुआ।\*

12. वनस्पति तेल उद्योग (vegetable oil Industry)—वनस्पति तेलों का वार्षिक उत्पादन लगभग 29 लाख टन माना जाता है। देश में लगभग 55 कारखाने, महाराष्ट्र, गुजरात, पं० बंगाल, मिसूर आदि राज्यों में स्थित हैं। यह व्यवसाय भी निजी क्षेत्र के अधिकार में ही है।

13. कोयला उद्योग (Coal Industry)—सन् 1814 में बंगाल के रानीगंज क्षेत्र में कोयले की खान खोदी गई। यह व्यवसाय सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों में ही किया जाता है। सन् 1967-68 में कोयले का उत्पादन 685.2 लाख टन हुआ। इस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र का अधिकार बढ़ता जा रहा है।\*\*

14. पोत निर्माण (Ship Building) सार्वजनिक क्षेत्र में विशालापरट्टनम् जहाजी बड़े निर्माण के कारखाने के धनिरित्त कोचीन में भी एक कारखाना खोला जा रहा है। अब हमारे देश में धाधुनिक सिस्टम के उत्तम चार जहाज प्रति वर्ष बनाये जा सकते हैं। तटीय एवं आन्तरिक जल यातायात के लिए आवश्यक सामग्री का उत्पादन निजी क्षेत्र में ही होता है।

---

\*India 1969, p. 325

\*\*India 1969, p. 340

15. रेल के डिब्बे का निर्माण (Railway Coach Industry)—सार्वजनिक क्षेत्र में पेराम्बूर (मद्रास) की इन्टरनल कोच फैक्ट्री तथा हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड के अतिरिक्त निजी क्षेत्र में भी जजिफ नामक कम्पनी रेल डिब्बों का निर्माण करती है।

16. रेल इंजिन बनाने का उद्योग (Locomotives)—सार्वजनिक क्षेत्र में चितरंजन लोकोमोटिव रेल इंजिन बनाने का कार्य 1950 से कर रहा है। इस कारखाने ने मार्च मन् 1969 तक 2,254 रेल के इंजिनों का निर्माण किया था। निजी क्षेत्र में टाटा इंजिननिर्माण एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी (TELCO) भी मोटर गेज के इंजिनों का निर्माण कर रहा है। अब सार्वजनिक क्षेत्र में एक डीजल इंजिनों का निर्माण करने वाले कारखाने का निर्माण वाराणसी में कर दिया गया है।

17. वायुयान (Air Craft) उद्योग—वायुयान का निर्माण का कार्य एक मात्र सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकार में है। 'हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड' की विभिन्न इकाइयाँ मिरा, गुजर मोनिक जेट, सडाकु-HF-27, भारकेउस-703 एवरो-747, 'कृष्ण' एवं 'पुष्पक' आदि वायुयान बना रही हैं। इसके विभिन्न कारखाने नासिक, हैदराबाद, बंगलूर, कानपुर आदि में स्थित हैं।

18. ऑटोमोबाइल, मोटर साइकिलें तथा स्कूटर बनाने का उद्योग कुछ वर्षों पहले तक हमारे देश में ये सभी वस्तुएँ विदेशों से आती थीं। अब हमारे देश में ही विभिन्न प्रकार की मोटरें, कारें, जीपें, ट्रक आदि बनाई जाने लगी हैं। इनको बनाने वाले कारखाने निजी क्षेत्र में ही हैं। इस उद्योग में विदेशी सहयोग भी प्राप्त किया गया है। हमारे देश में लगभग 57 हजार मोटरों तथा 25 हजार मोटर साइकिलों तथा स्कूटरों का उत्पादन प्रति वर्ष होता है।

19. भारी औद्योगिक एवं कृषि मशीनों का निर्माण—इस क्षेत्र में मुख्य कार्य सार्वजनिक क्षेत्र कर रहा है। रांची का हैवी मशीनरी प्लांट, दुर्गापुर का भारीय मशीनरी प्लांट, रांची की ही हैवी मशीन टूल्स प्रिविक्ट तथा काठगढ़ी जोब्स लॉड, बलनौर का हिन्दुस्तान मशीन

1. लीटो व रूपायन उद्योग—इंडियन—बंगाल सिपि—  
 प्रोबना काल में बीन फाँटनाई बगल गये—(1) फाँटनाई इंडियन  
 (2) प्रोबना इंडियन (3) इंडियन इंडियन  
 उद्योग की समस्याएँ, उद्योग की समस्याएँ—  
 समस्याएँ—(1) फाँटनाई (2) फाँटनाई (3) फाँटनाई

## भारत

को लिये जाया जाता है ।  
 भारत में लीटो व रूपायन उद्योग—इंडियन—बंगाल सिपि—  
 प्रोबना काल में बीन फाँटनाई बगल गये—(1) फाँटनाई इंडियन  
 (2) प्रोबना इंडियन (3) इंडियन इंडियन  
 उद्योग की समस्याएँ, उद्योग की समस्याएँ—  
 समस्याएँ—(1) फाँटनाई (2) फाँटनाई (3) फाँटनाई

सर्वप्रथम प्रश्न—क्या वे भी मर जायेंगे, जिनके, जिनके

विषय की प्रतीति है।

सर्वप्रथम प्रश्न—क्या वे भी मर जायेंगे, जिनके, जिनके

प्रश्न है।

उत्तर की प्रतीति, उत्तर की प्रतीति—

सर्वप्रथम—(1) कौन सा है (2) प्रतीति का प्रतीति

प्रतीति (3) प्रतीति का प्रतीति (4) प्रतीति का प्रतीति

(5) उत्तर की प्रतीति।

3. प्रतीति प्रतीति—क्या वे भी मर जायेंगे।

प्रतीति प्रतीति—क्या वे भी मर जायेंगे, जिनके, जिनके

10 प्रतीति का प्रतीति प्रतीति प्रतीति प्रतीति प्रतीति प्रतीति

प्रतीति प्रतीति—क्या वे भी मर जायेंगे, जिनके, जिनके

प्रतीति प्रतीति—क्या वे भी मर जायेंगे, जिनके, जिनके

प्रतीति प्रतीति—क्या वे भी मर जायेंगे, जिनके, जिनके

प्रतीति प्रतीति—क्या वे भी मर जायेंगे, जिनके, जिनके





1. The following people are the most likely to be the best fit for the job:

एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था का विश्लेषण (Trade and Commerce) हेतु अर्थव्यवस्था की स्थिति के साथ-साथ निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए।

WLB 1216

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1

[illegible]

1949 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

~~These studies show that the risk of infection is~~

## INDIAN FOREIGN TRADE

111110 11221 11331 11441

2. **वस्तुनं प्रमाणं (Manufactured Goods)** अ

1 121 4 155 3 183

1. **Surplus (Excess of exports)**—\$4,193 million (1961-62)

(Also Features)

by 1939 was 6061 and 1939 was 6061

110

[illegible]

(1) 1939  
 (2) 1939  
 (3) 1939  
 (4) 1939  
 (5) 1939  
 (6) 1939  
 (7) 1939  
 (8) 1939  
 (9) 1939  
 (10) 1939

1. 1939 (a) 1939 (b) 1939 (c) 1939 (d) 1939 (e) 1939 (f) 1939 (g) 1939 (h) 1939 (i) 1939 (j) 1939  
 2. 1939 (a) 1939 (b) 1939 (c) 1939 (d) 1939 (e) 1939 (f) 1939 (g) 1939 (h) 1939 (i) 1939 (j) 1939  
 3. 1939 (a) 1939 (b) 1939 (c) 1939 (d) 1939 (e) 1939 (f) 1939 (g) 1939 (h) 1939 (i) 1939 (j) 1939  
 4. 1939 (a) 1939 (b) 1939 (c) 1939 (d) 1939 (e) 1939 (f) 1939 (g) 1939 (h) 1939 (i) 1939 (j) 1939  
 5. 1939 (a) 1939 (b) 1939 (c) 1939 (d) 1939 (e) 1939 (f) 1939 (g) 1939 (h) 1939 (i) 1939 (j) 1939  
 6. 1939 (a) 1939 (b) 1939 (c) 1939 (d) 1939 (e) 1939 (f) 1939 (g) 1939 (h) 1939 (i) 1939 (j) 1939  
 7. 1939 (a) 1939 (b) 1939 (c) 1939 (d) 1939 (e) 1939 (f) 1939 (g) 1939 (h) 1939 (i) 1939 (j) 1939  
 8. 1939 (a) 1939 (b) 1939 (c) 1939 (d) 1939 (e) 1939 (f) 1939 (g) 1939 (h) 1939 (i) 1939 (j) 1939  
 9. 1939 (a) 1939 (b) 1939 (c) 1939 (d) 1939 (e) 1939 (f) 1939 (g) 1939 (h) 1939 (i) 1939 (j) 1939  
 10. 1939 (a) 1939 (b) 1939 (c) 1939 (d) 1939 (e) 1939 (f) 1939 (g) 1939 (h) 1939 (i) 1939 (j) 1939





5. यह धीरे धीरे का निर्यात मात्रा—यह 1947 के निर्यात-वर्ष के बाद 70 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत हो गई है। निर्यात के बाद के बाद 70 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत हो गई है। निर्यात के बाद के बाद 70 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत हो गई है।

4. निर्यात में निर्यात (Manufactured and Goods) की मात्रा—यह धीरे धीरे बढ़ रही है। निर्यात के बाद के बाद 70 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत हो गई है। निर्यात के बाद के बाद 70 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत हो गई है।

3. रुपये की मूल्यमूल्य (Devaluation of the Rupee)—यह धीरे धीरे बढ़ रही है। निर्यात के बाद के बाद 70 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत हो गई है। निर्यात के बाद के बाद 70 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत हो गई है।

2. निर्यात का मूल्यमूल्य (Balance of Trade)—यह धीरे धीरे बढ़ रही है। निर्यात के बाद के बाद 70 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत हो गई है। निर्यात के बाद के बाद 70 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत हो गई है।

निर्यात के निर्यात (Internal trade) में बढ़ रही है। निर्यात के बाद के बाद 70 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत हो गई है। निर्यात के बाद के बाद 70 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत हो गई है।



**1 JULY 1970 DE LER P 11E 6Z TEL#**

'(12) [REDACTED] [REDACTED] ON THE DATE OF 12 FEBRUARY  
AT THE TIME OF 12 FEBRUARY AT THE PLACE OF—[REDACTED]

- 12 DE 13

[illegible]

DATE: 10-10-68 BY: [illegible] 10-10-68

THE HON. MR. JUSTICE 'ERIN O'BRIEN' BILLY 'ERIN' O'BRIEN

1. What is the purpose of the study?

**1. PURPOSE**

[illegible]

6. 1941-1942 年 11 月 1 日 至 1942 年 11 月 30 日

1. हमारे देश में एक ही धर्म है, एक ही भाषा है, एक ही जाति है।

5. Wash, dry, and weigh the residue.

1. 3. 2018 10:15:00 2. 3. 2018 10:15:00 3. 3. 2018 10:15:00 4. 3. 2018 10:15:00 5. 3. 2018 10:15:00

4. *Arachis* (oil seeds)—oil, meal, cake, hull, straw

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29. 31. 33. 35. 37. 39. 41. 43. 45. 47. 49. 51. 53. 55. 57. 59. 61. 63. 65. 67. 69. 71. 73. 75. 77. 79. 81. 83. 85. 87. 89. 91. 93. 95. 97. 99. 101. 103. 105. 107. 109. 111. 113. 115. 117. 119. 121. 123. 125. 127. 129. 131. 133. 135. 137. 139. 141. 143. 145. 147. 149. 151. 153. 155. 157. 159. 161. 163. 165. 167. 169. 171. 173. 175. 177. 179. 181. 183. 185. 187. 189. 191. 193. 195. 197. 199. 201. 203. 205. 207. 209. 211. 213. 215. 217. 219. 221. 223. 225. 227. 229. 231. 233. 235. 237. 239. 241. 243. 245. 247. 249. 251. 253. 255. 257. 259. 261. 263. 265. 267. 269. 271. 273. 275. 277. 279. 281. 283. 285. 287. 289. 291. 293. 295. 297. 299. 301. 303. 305. 307. 309. 311. 313. 315. 317. 319. 321. 323. 325. 327. 329. 331. 333. 335. 337. 339. 341. 343. 345. 347. 349. 351. 353. 355. 357. 359. 361. 363. 365. 367. 369. 371. 373. 375. 377. 379. 381. 383. 385. 387. 389. 391. 393. 395. 397. 399. 401. 403. 405. 407. 409. 411. 413. 415. 417. 419. 421. 423. 425. 427. 429. 431. 433. 435. 437. 439. 441. 443. 445. 447. 449. 451. 453. 455. 457. 459. 461. 463. 465. 467. 469. 471. 473. 475. 477. 479. 481. 483. 485. 487. 489. 491. 493. 495. 497. 499. 501. 503. 505. 507. 509. 511. 513. 515. 517. 519. 521. 523. 525. 527. 529. 531. 533. 535. 537. 539. 541. 543. 545. 547. 549. 551. 553. 555. 557. 559. 561. 563. 565. 567. 569. 571. 573. 575. 577. 579. 581. 583. 585. 587. 589. 591. 593. 595. 597. 599. 601. 603. 605. 607. 609. 611. 613. 615. 617. 619. 621. 623. 625. 627. 629. 631. 633. 635. 637. 639. 641. 643. 645. 647. 649. 651. 653. 655. 657. 659. 661. 663. 665. 667. 669. 671. 673. 675. 677. 679. 681. 683. 685. 687. 689. 691. 693. 695. 697. 699. 701. 703. 705. 707. 709. 711. 713. 715. 717. 719. 721. 723. 725. 727. 729. 731. 733. 735. 737. 739. 741. 743. 745. 747. 749. 751. 753. 755. 757. 759. 761. 763. 765. 767. 769. 771. 773. 775. 777. 779. 781. 783. 785. 787. 789. 791. 793. 795. 797. 799. 801. 803. 805. 807. 809. 811. 813. 815. 817. 819. 821. 823. 825. 827. 829. 831. 833. 835. 837. 839. 841. 843. 845. 847. 849. 851. 853. 855. 857. 859. 861. 863. 865. 867. 869. 871. 873. 875. 877. 879. 881. 883. 885. 887. 889. 891. 893. 895. 897. 899. 901. 903. 905. 907. 909. 911. 913. 915. 917. 919. 921. 923. 925. 927. 929. 931. 933. 935. 937. 939. 941. 943. 945. 947. 949. 951. 953. 955. 957. 959. 961. 963. 965. 967. 969. 971. 973. 975. 977. 979. 981. 983. 985. 987. 989. 991. 993. 995. 997. 999. 1001. 1003. 1005. 1007. 1009. 1011. 1013. 1015. 1017. 1019. 1021. 1023. 1025. 1027. 1029. 1031. 1033. 1035. 1037. 1039. 1041. 1043. 1045. 1047. 1049. 1051. 1053. 1055. 1057. 1059. 1061. 1063. 1065. 1067. 1069. 1071. 1073. 1075. 1077. 1079. 1081. 1083. 1085. 1087. 1089. 1091. 1093. 1095. 1097. 1099. 1101. 1103. 1105. 1107. 1109. 1111. 1113. 1115. 1117. 1119. 1121. 1123. 1125. 1127. 1129. 1131. 1133. 1135. 1137. 1139. 1141. 1143. 1145. 1147. 1149. 1151. 1153. 1155. 1157. 1159. 1161. 1163. 1165. 1167. 1169. 1171. 1173. 1175. 1177. 1179. 1181. 1183. 1185. 1187. 1189. 1191. 1193. 1195. 1197. 1199. 1201. 1203. 1205. 1207. 1209. 1211. 1213. 1215. 1217. 1219. 1221. 1223. 1225. 1227. 1229. 1231. 1233. 1235. 1237. 1239. 1241. 1243. 1245. 1247. 1249. 1251. 1253. 1255. 1257. 1259. 1261. 1263. 1265. 1267. 1269. 1271. 1273. 1275. 1277. 1279. 1281. 1283. 1285. 1287. 1289. 1291. 1293. 1295. 1297. 1299. 1301. 1303. 1305. 1307. 1309. 1311. 1313. 1315. 1317. 1319. 1321. 1323. 1325. 1327. 1329. 1331. 1333. 1335. 1337. 1339. 1341. 1343. 1345. 1347. 1349. 1351. 1353. 1355. 1357. 1359. 1361. 1363. 1365. 1367. 1369. 1371. 1373. 1375. 1377. 1379. 1381. 1383. 1385. 1387. 1389. 1391. 1393. 1395. 1397. 1399. 1401. 1403. 1405. 1407. 1409. 1411. 1413. 1415. 1417. 1419. 1421. 1423. 1425. 1427. 1429. 1431. 1433. 1435. 1437. 1439. 1441. 1443. 1445. 1447. 1449. 1451. 1453. 1455. 1457. 1459. 1461. 1463. 1465. 1467. 1469. 1471. 1473. 1475. 1477. 1479. 1481. 1483. 1485. 1487. 1489. 1491. 1493. 1495. 1497. 1499. 1501. 1503. 1505. 1507. 1509. 1511. 1513. 1515. 1517. 1519. 1521. 1523. 1525. 1527. 1529. 1531. 1533. 1535. 1537. 1539. 1541. 1543. 1545. 1547. 1549.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1 2 1215 14 1221 25 1115 211215 09 14

THEY ARE NOT THE SAME AS THE OTHERS IN THE FIELD

2. **बाप-उत तिन, भाई-भाई, बहिन, भो. वि. भाई**

— 222 —

[illegible]

பாடல் 1 : பரமபுரம் 22 ஆம் அடியில் உள்ளது, கருவியை

1. 1992 年 1 月 1 日以前

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 2826 2827 2828 2829 2830 2831 2832

— ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

— (Items of Exports) —

Figure 3. (continued)

250



[illegible]

1. 4. 1944

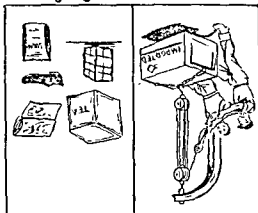
4. **रासायनिक दवा (Chemicals)** तथा **वायुमय-वायुमय** (Air, water, gas, etc.) के अभाव में

4 2 1512

[illegible]

पुनर्पु

PLATE



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

2. कपास—कपास का पत्ता लंबा और चौड़ा होता है। इसका रंग सफेद होता है। इसका उपयोग कपड़ों में होता है।

[illegible][illegible]

1. ଉପସ୍ଥାପନା

10. **सामान्य**—इस म धारा का अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के अश्लील या अप्रामाणिक चित्रों, फिल्मों, या अन्य सामग्री को सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित करता है, तो उसे सजा दी जा सकती है।

6. ፩. ጥቅም ስራ ለማድረግ ለሚገባው ሰው ማድረግ ይቻላል፡፡

8 कपास और कपास की गुत्ता (Pulp) - सं. १०. अतिरक्त  
कपास, फिदा, अर्धरी, गद्द फिदाए व फिदाए आदि रंगों से कपा  
सों के कपास की गुत्ताएँ बनाई जाती हैं ।

[illegible]

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84



1) K. B. M. J. L. P. d. (M. G. H. S.) d. 1961 k. B. I. N. S. I. N. S.  
d. 1961 k. B. I. N. S. I. N. S. d. 1961 k. B. I. N. S. I. N. S.

1 1213 1415 1516

2013 年 12 月 10 日 星期三

**100-1619-1000**

1) ከገንዘብ ፉጋኝነት (ፋይናንስ) ጋር ማሳሰቢያ ማድረግ  
 2) ከገንዘብ ፉጋኝነት ጋር ማሳሰቢያ ማድረግ (ፋይናንስ)

1. The FBI is a federal agency.

— LINE 11E AT END

1950 年 5 月 15 日 星期日

1. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[illegible]

1214

\_\_\_\_\_

1. What is the purpose of the document?  
 2. What are the main points of the document?  
 3. What are the key findings of the document?  
 4. What are the recommendations of the document?  
 5. What are the conclusions of the document?

1. අනුමතය ලබා දීමට ප්‍රධාන මිනිසුන් තෝරා ගන්නා අතර

2. निर्यात नीति (Export Policy) : निर्यात नीति से संबंधित











259

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

State Trading)

[illegible]

(\*) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z) (aa) (ab) (ac) (ad) (ae) (af) (ag) (ah) (ai) (aj) (ak) (al) (am) (an) (ao) (ap) (aq) (ar) (as) (at) (au) (av) (aw) (ax) (ay) (az) (ba) (bb) (bc) (bd) (be) (bf) (bg) (bh) (bi) (bj) (bk) (bl) (bm) (bn) (bo) (bp) (bq) (br) (bs) (bt) (bu) (bv) (bw) (bx) (by) (bz) (ca) (cb) (cc) (cd) (ce) (cf) (cg) (ch) (ci) (cj) (ck) (cl) (cm) (cn) (co) (cp) (cq) (cr) (cs) (ct) (cu) (cv) (cw) (cx) (cy) (cz) (da) (db) (dc) (dd) (de) (df) (dg) (dh) (di) (dj) (dk) (dl) (dm) (dn) (do) (dp) (dq) (dr) (ds) (dt) (du) (dv) (dw) (dx) (dy) (dz) (ea) (eb) (ec) (ed) (ee) (ef) (eg) (eh) (ei) (ej) (ek) (el) (em) (en) (eo) (ep) (eq) (er) (es) (et) (eu) (ev) (ew) (ex) (ey) (ez) (fa) (fb) (fc) (fd) (fe) (ff) (fg) (fh) (fi) (fj) (fk) (fl) (fm) (fn) (fo) (fp) (fq) (fr) (fs) (ft) (fu) (fv) (fw) (fx) (fy) (fz) (ga) (gb) (gc) (gd) (ge) (gf) (gg) (gh) (gi) (gj) (gk) (gl) (gm) (gn) (go) (gp) (gq) (gr) (gs) (gt) (gu) (gv) (gw) (gx) (gy) (gz) (ha) (hb) (hc) (hd) (he) (hf) (hg) (hh) (hi) (hj) (hk) (hl) (hm) (hn) (ho) (hp) (hq) (hr) (hs) (ht) (hu) (hv) (hw) (hx) (hy) (hz) (ia) (ib) (ic) (id) (ie) (if) (ig) (ih) (ii) (ij) (ik) (il) (im) (in) (io) (ip) (iq) (ir) (is) (it) (iu) (iv) (iw) (ix) (iy) (iz) (ja) (jb) (jc) (jd) (je) (jf) (jg) (jh) (ji) (jj) (jk) (jl) (jm) (jn) (jo) (jp) (jq) (jr) (js) (jt) (ju) (jv) (jw) (jx) (jy) (jz) (ka) (kb) (kc) (kd) (ke) (kf) (kg) (kh) (ki) (kj) (kk) (kl) (km) (kn) (ko) (kp) (kq) (kr) (ks) (kt) (ku) (kv) (kw) (kx) (ky) (kz) (la) (lb) (lc) (ld) (le) (lf) (lg) (lh) (li) (lj) (lk) (ll) (lm) (ln) (lo) (lp) (lq) (lr) (ls) (lt) (lu) (lv) (lw) (lx) (ly) (lz) (ma) (mb) (mc) (md) (me) (mf) (mg) (mh) (mi) (mj) (mk) (ml) (mm) (mn) (mo) (mp) (mq) (mr) (ms) (mt) (mu) (mv) (mw) (mx) (my) (mz) (na) (nb) (nc) (nd) (ne) (nf) (ng) (nh) (ni) (nj) (nk) (nl) (nm) (nn) (no) (np) (nq) (nr) (ns) (nt) (nu) (nv) (nw) (nx) (ny) (nz) (oa) (ob) (oc) (od) (oe) (of) (og) (oh) (oi) (oj) (ok) (ol) (om) (on) (oo) (op) (oq) (or) (os) (ot) (ou) (ov) (ow) (ox) (oy) (oz) (pa) (pb) (pc) (pd) (pe) (pf) (pg) (ph) (pi) (pj) (pk) (pl) (pm) (pn) (po) (pp) (pq) (pr) (ps) (pt) (pu) (pv) (pw) (px) (py) (pz) (qa) (qb) (qc) (qd) (qe) (qf) (qg) (qh) (qi) (qj) (qk) (ql) (qm) (qn) (qo) (qp) (qq) (qr) (qs) (qt) (qu) (qv) (qw) (qx) (qy) (qz) (ra) (rb) (rc) (rd) (re) (rf) (rg) (rh) (ri) (rj) (rk) (rl) (rm) (rn) (ro) (rp) (rq) (rr) (rs) (rt) (ru) (rv) (rw) (rx) (ry) (rz) (sa) (sb) (sc) (sd) (se) (sf) (sg) (sh) (si) (sj) (sk) (sl) (sm) (sn) (so) (sp) (sq) (sr) (ss) (st) (su) (sv) (sw) (sx) (sy) (sz) (ta) (tb) (tc) (td) (te) (tf) (tg) (th) (ti) (tj) (tk) (tl) (tm) (tn) (to) (tp) (tq) (tr) (ts) (tt) (tu) (tv) (tw) (tx) (ty) (tz) (ua) (ub) (uc) (ud) (ue) (uf) (ug) (uh) (ui) (uj) (uk) (ul) (um) (un) (uo) (up) (uq) (ur) (us) (ut) (uu) (uv) (uw) (ux) (uy) (uz) (va) (vb) (vc) (vd) (ve) (vf) (vg) (vh) (vi) (vj) (vk) (vl) (vm) (vn) (vo) (vp) (vq) (vr) (vs) (vt) (vu) (vv) (vw) (vx) (vy) (vz) (wa) (wb) (wc) (wd) (we) (wf) (wg) (wh) (wi) (wj) (wk) (wl) (wm) (wn) (wo) (wp) (wq) (wr) (ws) (wt) (wu) (wv) (ww) (wx) (wy) (wz) (xa) (xb) (xc) (xd) (xe) (xf) (xg) (xh) (xi) (xj) (xk) (xl) (xm) (xn) (xo) (xp) (xq) (xr) (xs) (xt) (xu) (xv) (xw) (xx) (xy) (xz) (ya) (yb) (yc) (yd) (ye) (yf) (yg) (yh) (yi) (yj) (yk) (yl) (ym) (yn) (yo) (yp) (yq) (yr) (ys) (yt) (yu) (yv) (yw) (yx) (yy) (yz) (za) (zb) (zc) (zd) (ze) (zf) (zg) (zh) (zi) (zj) (zk) (zl) (zm) (zn) (zo) (zp) (zq) (zr) (zs) (zt) (zu) (zv) (zw) (zx) (zy) (zz)

9561

(२) अथवा अथवा अथवा अथवा (Minerals and Metals Trading Corporation), 1962 अथवा

(a) उत्तर प्रदेश मूल्य वितरण (Metal Scrap Trade Corporation), 1964

- Corporation), 1964

उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में विद्यमान विभिन्न प्रकार के पशुओं के पालन के विषय में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए :-

1. ከጋራ ይገኛል

1-224 8 1234567890

2023 81  
 2023 81  
 2023 81  
 2023 81



11

10

page



5 (E)

13

1

(b)

**E 19**

**FILE**

(€)

(E)

(b)

(B)

1118

111

**byline**



2. भारत के मुख्य भाषाओं व लिपियों का विवरण दीजिये और बताइये कि किस भाषा से लिपि बनाने के लिए सबसे अधिक लोग पसंद करते हैं ?  
(रा. बी. ई. 1961)
3. भारत की भाषाओं में क्या विशेषता है ?  
(रा. बी. ई. 1966)
4. भारत लिपिबोधन विधियाँ —  
(1) भारत के भाषाओं के मुख्य वर्ण  
(रा. बी. ई. 1967-1968)  
(2) भारत की लिपिबोधन विधियाँ की जाँच  
(3) लिपिबोधन विधियाँ
5. भारत के भाषाओं की मुख्य भाषा बताइये । भारत सरकार ने लिपि की लिपिबोधन के लिए क्या कदम उठाए हैं ?  
(रा. बी. ई. 1969)

# भारत में बेरोजगारी की समस्या

## PROBLEM OF UNEMPLOYMENT IN INDIA

"बेरोजगारी का सबसे बड़ा दृष्टिकोण नीतिगत और नीतिक है। यह समस्याएँ भी अर्थी है नहीं बल्कि वेदा और मय की भी समस्या है।"

प्रायः की बड़ी बड़े अर्थशास्त्रज्ञों ने अनेक सामाजिक एवं आर्थिक

समस्याओं की व्याख्या की है। बड़ी बड़े अर्थशास्त्रज्ञों की विचारधारा में

मिश्र, अर्थ एवं समाज की मूल समस्याएँ पूर्ण रीत्या (full

employment) की व्याख्या में ही समाहित हैं। किन्तु प्रायः

ये अर्थशास्त्रज्ञों की समस्या में बड़ा फरक है अर्थशास्त्र के अन्तर्गत

है। बेरोजगारी की समस्या अर्थशास्त्रज्ञों के लिए एक रीति के अन्तर्गत

समाहित है। यह समस्या यदि और अधिक दृष्टिकोणों से देखी जाय, तो

समाजिक, अर्थ एवं समाजिक सभी दृष्टिकोणों में समाहित है। आर्थिक दृष्टिकोण

की है अर्थशास्त्र के अन्तर्गत (developing) देशों

में यह समस्या अर्थशास्त्र के अन्तर्गत है।

बेरोजगारी का अर्थ—

सामान्यतः किसी भी देश में काम करने योग्य एवं उद्योगशील

की आर्थिक कार्य में सम्मिलित हो बेरोजगारी कहलाता है। इसके अन्तर्गत

ही सम्मिलित है—अर्थशास्त्रज्ञों के अनुसार (Frictional Unemploy-

ment), अर्थशास्त्र में बेरोजगारी (Disguised Unemployment),

वैवस्था (Voluntary) बेरोजगारी, अनैच्छिक (Involuntary)

बेरोजगारी, सीजनल बेरोजगारी (Seasonal Unemployment) अर्थात्

बेरोजगारी, आदि। इस प्रकार हमें यह स्पष्ट होना चाहिये कि



वर्ष 1961 की जनगणना के अनुसार भारत की कार्यशील जनसंख्या (working population) 42.98 करोड़ थी।

| वर्ष | जनसंख्या (1000 में) |
|------|---------------------|
| 1961 | 42980               |
| 1951 | 35970               |
| 1941 | 31860               |
| 1931 | 28190               |
| 1921 | 25170               |
| 1911 | 22550               |
| 1901 | 20140               |
| 1891 | 18470               |
| 1881 | 16890               |
| 1871 | 15420               |
| 1861 | 14020               |
| 1851 | 12690               |
| 1841 | 11420               |
| 1831 | 10210               |
| 1821 | 9060                |
| 1811 | 7970                |
| 1801 | 6940                |
| 1791 | 5970                |
| 1781 | 5060                |
| 1771 | 4210                |
| 1761 | 3420                |
| 1751 | 2690                |
| 1741 | 2020                |
| 1731 | 1410                |
| 1721 | 860                 |
| 1711 | 370                 |
| 1701 | 100                 |

यदि हम 1961 की जनगणना के अनुसार भारत की कार्यशील जनसंख्या (working population) 42.98 करोड़ थी।

यदि हम 1961 की जनगणना के अनुसार भारत की कार्यशील जनसंख्या (working population) 42.98 करोड़ थी।

यदि हम 1961 की जनगणना के अनुसार भारत की कार्यशील जनसंख्या (working population) 42.98 करोड़ थी।

यदि हम 1961 की जनगणना के अनुसार भारत की कार्यशील जनसंख्या (working population) 42.98 करोड़ थी।

यदि हम 1961 की जनगणना के अनुसार भारत की कार्यशील जनसंख्या (working population) 42.98 करोड़ थी।

की अर्थात् कम कर्म करने वाले लोगों की अनुसूची 18.84 करोड़ थी। वहीं आर्य के अनुसार कम कर सकते वाली अनुसूची 36 प्रतिशत है वहीं कायदे अनुसूची अनुसूची 43 प्रतिशत है। ऐसी स्थिति में लगभग 13 प्रतिशत लोग भी काम कर सकते थे कार्य नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बेरोजगार थे। इस प्रकार भारतवर्ष अपनी जन शक्ति का पूर्ण उपयोग कर सकते थे असमर्थ नहीं है।

ऐसा देखें यदि वे रोजगार प्राप्त करने में सक्षम करने का कार्य मुख्य रूप से रोजगार विनिमयन—(Employment Exchanges) अपना काम निरन्तर चलाते रहें किन्तु आज है। इस कार्यकारी की स्थापना सन् 1945 में की गई। वे अक्सर पूछ सकते हैं कि वे अपनी बेरोजगारी के कारण अनुसूची में अपना प्रवेश (Registration) करवा दें। किन्तु निम्नलिखित शर्तिका से इस कार्यकारी के पास यह अधिकार नहीं है।

अनुसूचित के अनुसार चलाए जा रहे हैं आगे —

| अनुसूचित  |          | की संख्या का प्रतिशत |  |
|---|----------|----------------------|--|
| (13 फरवरी 1966 की)                              |          |                      |  |
| 1. व्यावसायिक, तकनीकी व सरकारी                  | 1,53,058 | 5.8                  |  |
| 2. व्यावसायिक, व्यावसायिक व सरकारी              | 4,364    | 0.2                  |  |
| 3. निम्न, निम्न व निम्न                         | 94,316   | 3.6                  |  |
| 4. निम्न, निम्न व सरकारी                        | 9,702    | 0.4                  |  |
| 5. सरकारी व सरकारी                              | 2,481    | 0.1                  |  |
| 6. निम्न व निम्न                                | 62,159   | 2.4                  |  |
| 7. सरकारी व सरकारी                              | 1,95,323 | 7.4                  |  |
| 8. सरकारी (रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार व रजिस्ट्रार) | 99,536   | 3.8                  |  |
| 9. सरकारी रजिस्ट्रार व रजिस्ट्रार व रजिस्ट्रार  | 1,03,371 | 3.9                  |  |







[illegible]

“我 的 生 活 是 这 样”

मिश्र व बेरोजगारी की समस्या—(Extent of unemployment in India)—मिश्र व बेरोजगारी की समस्या भारत में एक गंभीर समस्या है। यह समस्या केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी व्यापक रूप से पाई जाती है।

**1. Find the value of x**

[illegible]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 104

6. सम-प्रमाण — यदि दो वस्तुओं की द्रव्यमानें सम हों, तो वे सम-प्रमाण (Cyclical) होती हैं। यदि दो वस्तुओं की द्रव्यमानें सम हों, तो वे सम-प्रमाण (Cyclical) होती हैं। यदि दो वस्तुओं की द्रव्यमानें सम हों, तो वे सम-प्रमाण (Cyclical) होती हैं।

1 2345 6789 1011 1213

[illegible]



में वह रही है। लगभग 2.5 प्रतिशत की दर से प्रतिवृत्त करने में एक वर्ष लगाने के बाद प्रतिवृत्त (लगभग 125 लाख) वर्ष बढ़ा है। इससे आम लोक (Labour force) में वृद्धि होगी है और वृद्धि होगी।

3. वृद्धि होगी का उद्देश्य—आर्थिक विकास में वृद्धि होगी। वृद्धि पर आर्थिक विकास बढ़ेगा और वृद्धि में वृद्धि होगी। वृद्धि पर वृद्धि होगी और वृद्धि में वृद्धि होगी। वृद्धि पर वृद्धि होगी और वृद्धि में वृद्धि होगी।

4. वृद्धि होगी का उद्देश्य—वृद्धि होगी की दर बढ़ेगी होगी। वृद्धि पर वृद्धि होगी और वृद्धि में वृद्धि होगी। वृद्धि पर वृद्धि होगी और वृद्धि में वृद्धि होगी। वृद्धि पर वृद्धि होगी और वृद्धि में वृद्धि होगी।

5. वृद्धि होगी का उद्देश्य—वृद्धि होगी में वृद्धि होगी। वृद्धि पर वृद्धि होगी और वृद्धि में वृद्धि होगी। वृद्धि पर वृद्धि होगी और वृद्धि में वृद्धि होगी। वृद्धि पर वृद्धि होगी और वृद्धि में वृद्धि होगी।

6. वृद्धि होगी का उद्देश्य—वृद्धि होगी की दर बढ़ेगी होगी। वृद्धि पर वृद्धि होगी और वृद्धि में वृद्धि होगी। वृद्धि पर वृद्धि होगी और वृद्धि में वृद्धि होगी। वृद्धि पर वृद्धि होगी और वृद्धि में वृद्धि होगी।

7. वृद्धि होगी का उद्देश्य—वृद्धि होगी की दर बढ़ेगी होगी। वृद्धि पर वृद्धि होगी और वृद्धि में वृद्धि होगी। वृद्धि पर वृद्धि होगी और वृद्धि में वृद्धि होगी। वृद्धि पर वृद्धि होगी और वृद्धि में वृद्धि होगी।

1. Երբ որ Երևանի քաղաքի քաղաքապետը  
 2. Երբ որ Երևանի քաղաքի քաղաքապետը  
 3. Երբ որ Երևանի քաղաքի քաղաքապետը  
 4. Երբ որ Երևանի քաղաքի քաղաքապետը  
 5. Երբ որ Երևանի քաղաքի քաղաքապետը  
 6. Երբ որ Երևանի քաղաքի քաղաքապետը  
 7. Երբ որ Երևանի քաղաքի քաղաքապետը  
 8. Երբ որ Երևանի քաղաքի քաղաքապետը  
 9. Երբ որ Երևանի քաղաքի քաղաքապետը  
 10. Երբ որ Երևանի քաղաքի քաղաքապետը

1953-54

— Երեսն և երեսույն լրիվագիտ և լրիվագիտ ուսանող

[illegible]

\_\_\_\_\_



1. जनसंख्या नियंत्रण (Population Control) के लिए परिवार नियोजन (Family Planning), देर से विवाह (Late marriages) आदि विचार किए जाने चाहिए।

विवाह देर-देर-देर करने पर काम होगा।

## 2. गरीबों में कुटीर उद्योग

गरीबों के लिए उद्योगों का विकास करना चाहिए। गरीबों को उद्योगों में काम करने में मदद देनी चाहिए। गरीबों को उद्योगों में काम करने में मदद देनी चाहिए।

3. शिक्षा की महत्ता के बिना  
गरीबों में उद्योगों का विकास  
संभव नहीं है। गरीबों को शिक्षा  
देनी चाहिए। गरीबों को शिक्षा  
देनी चाहिए।

1. जनसंख्या नियंत्रण
2. कुटीर उद्योगों का विकास
3. शिक्षा की महत्ता
4. गरीबों में उद्योगों का विकास
5. जनसंख्या नियंत्रण
6. कुटीर उद्योगों का विकास
7. परिवार नियोजन
8. देर से विवाह
9. परिवार नियोजन
10. जनसंख्या नियंत्रण

समाप्त—

4. जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन, देर से विवाह, लैट मर्राज (Late marriages) आदि विचार किए जाने चाहिए।

5. जनसंख्या नियंत्रण—देर से विवाह, लैट मर्राज (Late marriages) आदि विचार किए जाने चाहिए।





यदि वे अतिशय की समझा वही समझ है यदि वे अतिशय समझ की समझ है ।

अतिशय की समझ—यदि वे अतिशय समझ की समझ है ।

यदि वे अतिशय की समझ है ।

(1) अतिशय की समझ है ।

(2) अतिशय की समझ है ।

(3) अतिशय की समझ है ।

(4) अतिशय की समझ है ।

(5) अतिशय की समझ है ।

(6) अतिशय की समझ है ।

(7) अतिशय की समझ है ।

(8) अतिशय की समझ है ।

(9) अतिशय की समझ है ।

—

- ( ॥ ) श्रीगुरुदेवकी ।  
( १ ) अक्षर श्रीगुरुदेव ।

4. श्रीगुरुदेवकी । श्रीगुरुदेव —

की श्रीगुरुदेवकी ।

3. श्रीगुरुदेवकी । श्रीगुरुदेवकी । श्रीगुरुदेवकी ।

करके श्रीगुरुदेवकी ।

2. श्रीगुरुदेवकी । श्रीगुरुदेवकी । श्रीगुरुदेवकी ।

श्रीगुरुदेवकी ।

1. श्रीगुरुदेवकी । श्रीगुरुदेवकी । श्रीगुरुदेवकी ।

श्रीगुरुदेवकी ।

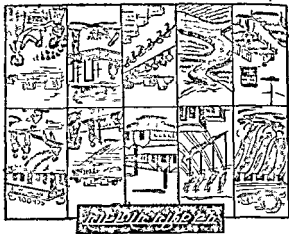
( 10 ) श्रीगुरुदेवकी ।

श्रीगुरुदेवकी । ( 8 ) श्रीगुरुदेवकी । ( 9 ) श्रीगुरुदेवकी ।

श्रीगुरुदेवकी । ( 6 ) श्रीगुरुदेवकी । ( 7 ) श्रीगुरुदेवकी ।

'निर्वाह' का अर्थ है 'जीवन'। यह एक सामान्य शब्द है जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत बार-बार प्रयोग होता है।  
 'निर्वाह' शब्द का अर्थ है 'जीवन'। यह एक सामान्य शब्द है जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत बार-बार प्रयोग होता है।  
 'निर्वाह' शब्द का अर्थ है 'जीवन'। यह एक सामान्य शब्द है जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत बार-बार प्रयोग होता है।

'निर्वाह' शब्द का अर्थ है 'जीवन'। यह एक सामान्य शब्द है जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत बार-बार प्रयोग होता है।



ECONOMIC PLANNING IN INDIA-1

भारत में आर्थिक नियोजन-1

[illegible][illegible][illegible][illegible]

ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷା (Definition)

[illegible]



[illegible]

(Need of Economic Planning)

DATE: 11/11/11 TIME: 11:11 AM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

END OF LETTER TO THE DIRECTOR IN WASH (01)

12 JUL 1963

FILE THE COPY IN FILE THE COPY IN FILE THE COPY IN FILE THE COPY IN

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

[illegible]

U.S. DEPARTMENT OF THE INTERIOR (Publicity) - 25

12/15/1991

DATE: 11/11/2019 TIME: 10:00 AM

7. **भारत (Public) या (Private) क्षेत्र—**

12316

1019 60074 48 42714 9515 2/10 10444410 10 PLEN

“THESE ARE THE ‘NEW’ RELIGIONS—THEY ARE THE ‘NEW’ RELIGIONS.”

1. SECRET (continued)

Dr. Ravi K. Singh (Technical Co-ordinator)

5. Other \_\_\_\_\_

12 JUN 1962

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY  
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION  
455 FIFTH AVENUE  
NEW YORK, N. Y. 10018

(resources), and what are the

1. 四國一戰時局表 明治四十四年 東京海軍省

1 2 3 4 5

DATE: 2/10 hrs to hrs min to min sec of month year of century

(continued on reverse side)

[illegible]

1. पूँजीवाद के दोष (Evils of Capitalism) — पूँजीवादी पूँजीवादी अधःपतन (Capitalist Economy) में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं का स्वतन्त्र-व्यवहार था। परन्तु पूँजीवादी अधःपतन में श्रमिकों का शोषण होता था। पूँजीवाद के दोष (Evils of Capitalism) — पूँजीवादी अधःपतन (Capitalist Economy) में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं का स्वतन्त्र-व्यवहार था। परन्तु पूँजीवादी अधःपतन में श्रमिकों का शोषण होता था।

[illegible]

3. विकास क्षेत्र (Economic Depression)—यह 1929 में





4. **ସମାପ୍ତି (Establishment of Equality)** — ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା (Equality) ସ୍ଥାପନ କରିବା।
5. **ସମାପ୍ତି (Establishment of Equality)** — ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା (Equality) ସ୍ଥାପନ କରିବା।
6. **ସମାପ୍ତି (Establishment of Equality)** — ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା (Equality) ସ୍ଥାପନ କରିବା।

वर्ध-वृद्धावस्था) का प्रमुख कारण रक्त के रक्त प्रवाह का अभाव है।

प्रतिपक्ष प्रमाणों के अभाव में यह कहा जा सकता है कि रक्त प्रवाह का अभाव रक्त के रक्त प्रवाह का अभाव है।

प्रतिपक्ष प्रमाणों के अभाव में यह कहा जा सकता है कि रक्त प्रवाह का अभाव रक्त के रक्त प्रवाह का अभाव है।

प्रतिपक्ष प्रमाणों के अभाव में यह कहा जा सकता है कि रक्त प्रवाह का अभाव रक्त के रक्त प्रवाह का अभाव है।

प्रतिपक्ष प्रमाणों के अभाव में यह कहा जा सकता है कि रक्त प्रवाह का अभाव रक्त के रक्त प्रवाह का अभाव है।

प्रतिपक्ष प्रमाणों के अभाव में यह कहा जा सकता है कि रक्त प्रवाह का अभाव रक्त के रक्त प्रवाह का अभाव है।



RECEIVED: 11/10/1964  
RECEIVED: 11/10/1964

[illegible][illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

[illegible]

5. संस्कृत में समाजशास्त्र (Sociology)

169 4112

1. THE STATE OF TEXAS, County of EL PASO, do hereby certify that

3. अन्यथा (अप्राप्त)

1. Black Hills (200

2. የጥያቄው ዋና ዋና ክፍሎች

14 (Per capita income) 4445 41 445 1

1. በጊዜ ላይ ማመልከት፡ ማመልከት ማለት ማሳደግ፣ ማሳደግ ማለት ማሳደግ ነው።

— 4 —



THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THESE THINGS, HOWEVER, DO NOT MEAN THAT THE

2. התאמת המערכת -

1992 1993

1. The first step is to identify the problem.

— ३ (100) —

महोदय प्रमाणित है कि आपका पत्र प्राप्त हुआ है।

(संपूर्ण पृ. ३०/पृ. ३०)

संस्कृत में अर्थशास्त्र (Objects of Economics)

1. **साम्यवादी (Democratic Planning)**—इस प्रकार की योजना में समाज के सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। यह योजना साम्यवाद के सिद्धांतों पर आधारित होती है। इसमें समाज के सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। यह योजना साम्यवाद के सिद्धांतों पर आधारित होती है।

2. **राज्यवादी (Planned Economy)**—इस प्रकार की योजना में समाज के सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। यह योजना साम्यवाद के सिद्धांतों पर आधारित होती है। इसमें समाज के सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। यह योजना साम्यवाद के सिद्धांतों पर आधारित होती है।

3. **अर्थव्यवस्था (Economic System)**—इस प्रकार की योजना में समाज के सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। यह योजना साम्यवाद के सिद्धांतों पर आधारित होती है। इसमें समाज के सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। यह योजना साम्यवाद के सिद्धांतों पर आधारित होती है।

4. **साम्यवाद (Socialism)**—इस प्रकार की योजना में समाज के सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। यह योजना साम्यवाद के सिद्धांतों पर आधारित होती है। इसमें समाज के सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। यह योजना साम्यवाद के सिद्धांतों पर आधारित होती है।

5. **साम्यवाद (Socialism)**—इस प्रकार की योजना में समाज के सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। यह योजना साम्यवाद के सिद्धांतों पर आधारित होती है। इसमें समाज के सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। यह योजना साम्यवाद के सिद्धांतों पर आधारित होती है।



[illegible]

121412

(Private Sector) የገንዘብ ምርትና አገልግሎት

ԵՊ ԼԵՂ ԲԵՂԷ Զ ԲՆԻՆ ԼԵՂԵ ՆԻ ԸՔ ԵՂԼԵՂԷ ԼԵՂԷ ԼԵ  
 ԼԵՂԷ ԼԵՂԼԵՂԷ ԼԵՂ ԼԵՂԷ ԵՂ Զ ԶԵԼ ԶԵ Բ ԼԵՂԷ ԳՂԼԵՂԷ  
 Լ ԼԵՂԷ ԼԵՂԷ ԼԵ ԼԵՂԷ

ቀንደርቱን ስርዓቱ ተይ ያ ያደርገው ስራ (፪)

16P 1129 1135

1968 3 21.63 34.116 14 11.12 1.214 1.214 1.214 (A)

1129

உயிர்வாழ்வு இது உயிர் வாழ்வதற்கு தேவையான அனைத்து வகை பொருள்களையும் உள்ளடக்கியதாகும்.

[illegible]

LEADS ARE BEING MADE TO IDENTIFY THE PERSONS (2)

!1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 194

! 1129 1125 1115 1111

1b2 2b3/4b5 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z) (aa) (ab) (ac) (ad) (ae) (af) (ag) (ah) (ai) (aj) (ak) (al) (am) (an) (ao) (ap) (aq) (ar) (as) (at) (au) (av) (aw) (ax) (ay) (az) (ba) (bb) (bc) (bd) (be) (bf) (bg) (bh) (bi) (bj) (bk) (bl) (bm) (bn) (bo) (bp) (bq) (br) (bs) (bt) (bu) (bv) (bw) (bx) (by) (bz) (ca) (cb) (cc) (cd) (ce) (cf) (cg) (ch) (ci) (cj) (ck) (cl) (cm) (cn) (co) (cp) (cq) (cr) (cs) (ct) (cu) (cv) (cw) (cx) (cy) (cz) (da) (db) (dc) (dd) (de) (df) (dg) (dh) (di) (dj) (dk) (dl) (dm) (dn) (do) (dp) (dq) (dr) (ds) (dt) (du) (dv) (dw) (dx) (dy) (dz) (ea) (eb) (ec) (ed) (ee) (ef) (eg) (eh) (ei) (ej) (ek) (el) (em) (en) (eo) (ep) (eq) (er) (es) (et) (eu) (ev) (ew) (ex) (ey) (ez) (fa) (fb) (fc) (fd) (fe) (ff) (fg) (fh) (fi) (fj) (fk) (fl) (fm) (fn) (fo) (fp) (fq) (fr) (fs) (ft) (fu) (fv) (fw) (fx) (fy) (fz) (ga) (gb) (gc) (gd) (ge) (gf) (gg) (gh) (gi) (gj) (gk) (gl) (gm) (gn) (go) (gp) (gq) (gr) (gs) (gt) (gu) (gv) (gw) (gx) (gy) (gz) (ha) (hb) (hc) (hd) (he) (hf) (hg) (hh) (hi) (hj) (hk) (hl) (hm) (hn) (ho) (hp) (hq) (hr) (hs) (ht) (hu) (hv) (hw) (hx) (hy) (hz) (ia) (ib) (ic) (id) (ie) (if) (ig) (ih) (ii) (ij) (ik) (il) (im) (in) (io) (ip) (iq) (ir) (is) (it) (iu) (iv) (iw) (ix) (iy) (iz) (ja) (jb) (jc) (jd) (je) (jf) (jg) (jh) (ji) (jj) (jk) (jl) (jm) (jn) (jo) (jp) (jq) (jr) (js) (jt) (ju) (jv) (jw) (jx) (jy) (jz) (ka) (kb) (kc) (kd) (ke) (kf) (kg) (kh) (ki) (kj) (kk) (kl) (km) (kn) (ko) (kp) (kq) (kr) (ks) (kt) (ku) (kv) (kw) (kx) (ky) (kz) (la) (lb) (lc) (ld) (le) (lf) (lg) (lh) (li) (lj) (lk) (ll) (lm) (ln) (lo) (lp) (lq) (lr) (ls) (lt) (lu) (lv) (lw) (lx) (ly) (lz) (ma) (mb) (mc) (md) (me) (mf) (mg) (mh) (mi) (mj) (mk) (ml) (mm) (mn) (mo) (mp) (mq) (mr) (ms) (mt) (mu) (mv) (mw) (mx) (my) (mz) (na) (nb) (nc) (nd) (ne) (nf) (ng) (nh) (ni) (nj) (nk) (nl) (nm) (nn) (no) (np) (nq) (nr) (ns) (nt) (nu) (nv) (nw) (nx) (ny) (nz) (oa) (ob) (oc) (od) (oe) (of) (og) (oh) (oi) (oj) (ok) (ol) (om) (on) (oo) (op) (oq) (or) (os) (ot) (ou) (ov) (ow) (ox) (oy) (oz) (pa) (pb) (pc) (pd) (pe) (pf) (pg) (ph) (pi) (pj) (pk) (pl) (pm) (pn) (po) (pp) (pq) (pr) (ps) (pt) (pu) (pv) (pw) (px) (py) (pz) (qa) (qb) (qc) (qd) (qe) (qf) (qg) (qh) (qi) (qj) (qk) (ql) (qm) (qn) (qo) (qp) (qq) (qr) (qs) (qt) (qu) (qv) (qw) (qx) (qy) (qz) (ra) (rb) (rc) (rd) (re) (rf) (rg) (rh) (ri) (rj) (rk) (rl) (rm) (rn) (ro) (rp) (rq) (rr) (rs) (rt) (ru) (rv) (rw) (rx) (ry) (rz) (sa) (sb) (sc) (sd) (se) (sf) (sg) (sh) (si) (sj) (sk) (sl) (sm) (sn) (so) (sp) (sq) (sr) (ss) (st) (su) (sv) (sw) (sx) (sy) (sz) (ta) (tb) (tc) (td) (te) (tf) (tg) (th) (ti) (tj) (tk) (tl) (tm) (tn) (to) (tp) (tq) (tr) (ts) (tt) (tu) (tv) (tw) (tx) (ty) (tz) (ua) (ub) (uc) (ud) (ue) (uf) (ug) (uh) (ui) (uj) (uk) (ul) (um) (un) (uo) (up) (uq) (ur) (us) (ut) (uu) (uv) (uw) (ux) (uy) (uz) (va) (vb) (vc) (vd) (ve) (vf) (vg) (vh) (vi) (vj) (vk) (vl) (vm) (vn) (vo) (vp) (vq) (vr) (vs) (vt) (vu) (vv) (vw) (vx) (vy) (vz) (wa) (wb) (wc) (wd) (we) (wf) (wg) (wh) (wi) (wj) (wk) (wl) (wm) (wn) (wo) (wp) (wq) (wr) (ws) (wt) (wu) (wv) (ww) (wx) (wy) (wz) (xa) (xb) (xc) (xd) (xe) (xf) (xg) (xh) (xi) (xj) (xk) (xl) (xm) (xn) (xo) (xp) (xq) (xr) (xs) (xt) (xu) (xv) (xw) (xx) (xy) (xz) (ya) (yb) (yc) (yd) (ye) (yf) (yg) (yh) (yi) (yj) (yk) (yl) (ym) (yn) (yo) (yp) (yq) (yr) (ys) (yt) (yu) (yv) (yw) (yx) (yy) (yz) (za) (zb) (zc) (zd) (ze) (zf) (zg) (zh) (zi) (zj) (zk) (zl) (zm) (zn) (zo) (zp) (zq) (zr) (zs) (zt) (zu) (zv) (zw) (zx) (zy) (zz)

[illegible]





11/11/11 11/11/11 11/11 11

(Perspective Plunging) 41

15 16 17 18 19 20

\* 1871 1872 1873 1874 1875

[illegible]

12] 19 E2]E2R (3) (C2E

1911

— (Phonics) Reading

1997년 12월 15일

11-11-11 11:11 (11-11-11)

Heute ging ich mit meiner Mutter

411/15-197 H 11112 1(1)

10/15/14 10:11:14 AM 10/15/14

1 2 3 4

— 114 —

સાધક (સાધક) નામ  
સર્વ વિદ્યા કુંજ વિદ્યા મંડળ

ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ।

**LIFE & DEATH OF DIPLOMATS**

ALL INFORMATION CONTAINED  
HEREIN IS UNCLASSIFIED

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847

(Planning from above

THE POLICE ARE IN THE

【摘要】 目的 探讨不同剂量依那普利对原发性高血压患者血清尿酸浓度的影响。方法 选取原发性高血压患者 100 例, 随机分为 3 组, 分别给予依那普利 10 mg、20 mg、40 mg 治疗, 观察 4 周后血清尿酸浓度的变化。结果 依那普利 10 mg、20 mg、40 mg 组治疗后血清尿酸浓度均显著降低, 且 40 mg 组降低幅度最大。结论 依那普利能有效降低原发性高血压患者血清尿酸浓度, 且剂量越大, 降低幅度越大。

## Summary

上上上上 全全全全

THE FIRST

1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1



5. ସୂଚକାଙ୍କିତ ନିମ୍ନ

**9. Appendix**

THE STATE OF

11111

## REFERENCES

262

ଏ ଶିଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କୁ—ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏ କଳାରେ ଅଭ୍ୟାସ

ହାତରେ ଥିବା ଲୋକ (୦୧) କରାଯିବ  
 ଲୋକ ଲୋକ (୦୨) କରାଯିବ ଲୋକ ଲୋକ (୦୩) ଏ ଲୋକ (୦୪)  
 ଲୋକ (୦୫) ଲୋକ (୦୬) ଲୋକ (୦୭) ଲୋକ (୦୮) ଲୋକ (୦୯)  
 ଲୋକ (୧୦) ଲୋକ (୧୧) ଲୋକ (୧୨) ଲୋକ (୧୩) ଲୋକ (୧୪)  
 ଲୋକ (୧୫) ଲୋକ (୧୬) ଲୋକ (୧୭) ଲୋକ (୧୮) ଲୋକ (୧୯)  
 ଲୋକ (୨୦) ଲୋକ (୨୧) ଲୋକ (୨୨) ଲୋକ (୨୩) ଲୋକ (୨୪)

ହାତରେ ଥିବା ଲୋକ (୧) ଲୋକ (୨) ଲୋକ (୩) ଲୋକ (୪)  
 ଲୋକ (୫) ଲୋକ (୬) ଲୋକ (୭) ଲୋକ (୮) ଲୋକ (୯)  
 ଲୋକ (୧୦) ଲୋକ (୧୧) ଲୋକ (୧୨) ଲୋକ (୧୩) ଲୋକ (୧୪)  
 ଲୋକ (୧୫) ଲୋକ (୧୬) ଲୋକ (୧୭) ଲୋକ (୧୮) ଲୋକ (୧୯)  
 ଲୋକ (୨୦) ଲୋକ (୨୧) ଲୋକ (୨୨) ଲୋକ (୨୩) ଲୋକ (୨୪)

ଏ ଲୋକ ଲୋକ (୧) ଲୋକ (୨) ଲୋକ (୩) ଲୋକ (୪)  
 ଲୋକ (୫) ଲୋକ (୬) ଲୋକ (୭) ଲୋକ (୮) ଲୋକ (୯)  
 ଲୋକ (୧୦) ଲୋକ (୧୧) ଲୋକ (୧୨) ଲୋକ (୧୩) ଲୋକ (୧୪)  
 ଲୋକ (୧୫) ଲୋକ (୧୬) ଲୋକ (୧୭) ଲୋକ (୧୮) ଲୋକ (୧୯)  
 ଲୋକ (୨୦) ଲୋକ (୨୧) ଲୋକ (୨୨) ଲୋକ (୨୩) ଲୋକ (୨୪)

## ପ୍ରତିଷ୍ଠା

ଏ ଲୋକ ଲୋକ (୧) ଲୋକ (୨) ଲୋକ (୩) ଲୋକ (୪)  
 ଲୋକ (୫) ଲୋକ (୬) ଲୋକ (୭) ଲୋକ (୮) ଲୋକ (୯)  
 ଲୋକ (୧୦) ଲୋକ (୧୧) ଲୋକ (୧୨) ଲୋକ (୧୩) ଲୋକ (୧୪)  
 ଲୋକ (୧୫) ଲୋକ (୧୬) ଲୋକ (୧୭) ଲୋକ (୧୮) ଲୋକ (୧୯)  
 ଲୋକ (୨୦) ଲୋକ (୨୧) ଲୋକ (୨୨) ଲୋକ (୨୩) ଲୋକ (୨୪)

ଏ ଲୋକ ଲୋକ (୧) ଲୋକ (୨) ଲୋକ (୩) ଲୋକ (୪)  
 ଲୋକ (୫) ଲୋକ (୬) ଲୋକ (୭) ଲୋକ (୮) ଲୋକ (୯)  
 ଲୋକ (୧୦) ଲୋକ (୧୧) ଲୋକ (୧୨) ଲୋକ (୧୩) ଲୋକ (୧୪)  
 ଲୋକ (୧୫) ଲୋକ (୧୬) ଲୋକ (୧୭) ଲୋକ (୧୮) ଲୋକ (୧୯)  
 ଲୋକ (୨୦) ଲୋକ (୨୧) ଲୋକ (୨୨) ଲୋକ (୨୩) ଲୋକ (୨୪)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

7. भौतिक (Physical) तथा वित्तीय (Financial) योजना—  
 भौतिक योजना वह योजना है जिसमें वित्त के संचालन के लिए आवश्यक भौतिक संसाधनों की आवश्यकता का अनुमान लगाया जाता है। वित्त योजना वित्त के संचालन के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों का अनुमान लगाती है।

1. The following is a list of the names of the persons who have been named in the above-mentioned affidavits as having been in the possession of the same at the time of the same being seized:

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| 8. अत एव ननु न प्रतीयते  | प्रतीयते |
| 7. प्रतीयते अतः प्रतीयते | प्रतीयते |
| 6. प्रतीयते              | प्रतीयते |

अब हमें भलीभाँति समझ  
 (Perspective Planning) का  
 महत्व होना चाहिए।

१. कविर्वाचकः कविः  
 २. कविः कविः  
 ३. कविः कविः  
 ४. कविः कविः  
 ५. कविः कविः  
 ६. कविः कविः  
 ७. कविः कविः  
 ८. कविः कविः







(ପ୍ରା. କୌଟି, ପ୍ର. ପୃ. 1969)

- (A) ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ
- (B) ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ
- (C) ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ
- (D) ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ
- (E) ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ

4. ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ —

1. ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ  
 2. ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ  
 3. ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ

1. ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ  
 2. ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ  
 3. ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ

ଶାସ୍ତ୍ରୀ

1. 1951-52

2. 1952-53

3. 1953-54

4. 1954-55

5. 1955-56

6. 1956-57  
7. 1957-58  
8. 1958-59  
9. 1959-60  
10. 1960-61  
11. 1961-62  
12. 1962-63  
13. 1963-64  
14. 1964-65  
15. 1965-66  
16. 1966-67  
17. 1967-68  
18. 1968-69  
19. 1969-70  
20. 1970-71  
21. 1971-72  
22. 1972-73  
23. 1973-74  
24. 1974-75  
25. 1975-76  
26. 1976-77  
27. 1977-78  
28. 1978-79  
29. 1979-80  
30. 1980-81  
31. 1981-82  
32. 1982-83  
33. 1983-84  
34. 1984-85  
35. 1985-86  
36. 1986-87  
37. 1987-88  
38. 1988-89  
39. 1989-90  
40. 1990-91  
41. 1991-92  
42. 1992-93  
43. 1993-94  
44. 1994-95  
45. 1995-96  
46. 1996-97  
47. 1997-98  
48. 1998-99  
49. 1999-00  
50. 2000-01  
51. 2001-02  
52. 2002-03  
53. 2003-04  
54. 2004-05  
55. 2005-06  
56. 2006-07  
57. 2007-08  
58. 2008-09  
59. 2009-10  
60. 2010-11  
61. 2011-12  
62. 2012-13  
63. 2013-14  
64. 2014-15  
65. 2015-16  
66. 2016-17  
67. 2017-18  
68. 2018-19  
69. 2019-20  
70. 2020-21  
71. 2021-22  
72. 2022-23  
73. 2023-24  
74. 2024-25  
75. 2025-26  
76. 2026-27  
77. 2027-28  
78. 2028-29  
79. 2029-30  
80. 2030-31  
81. 2031-32  
82. 2032-33  
83. 2033-34  
84. 2034-35  
85. 2035-36  
86. 2036-37  
87. 2037-38  
88. 2038-39  
89. 2039-40  
90. 2040-41  
91. 2041-42  
92. 2042-43  
93. 2043-44  
94. 2044-45  
95. 2045-46  
96. 2046-47  
97. 2047-48  
98. 2048-49  
99. 2049-50  
100. 2050-51

—

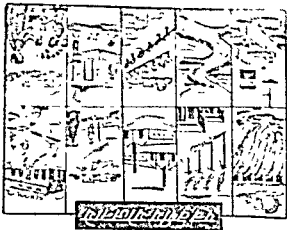
“The Commission has been set up to study the economic situation of the country and to make recommendations for the improvement of the economic condition of the country.”

## ECONOMIC PLANNING IN INDIA-II

1. Introduction

2. Objectives





मध्य प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि (Public Sector) में 2,069 करोड़ रुपये की राशि की जा रही है। इस राशि में 1,960 करोड़ रुपये की राशि की जा रही है।

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

[illegible]

1991

2. **ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଦିବସ** : ଏହି ଦିବସ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଦେଶର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି । ଏହା ପୃଥିବୀର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱାଗତ୍ୟାକାଂକ୍ଷିତ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ ।

DATE: 12/13/13 BY: [redacted]

[illegible]

1960

420

188

91

304

205

752

(1960)

1960-61

1961-62

1962-63

1963-64

1964-65

1965-66

(Source)

1960-61

1961-62

1962-63

1963-64

1964-65

1960

1960

1960

23

459

1960-61

27

523

1961-62

4

74

1962-63

2

43

1963-64

13

260

1964-65

16

310

1965-66

15

291

1966-67

1960

1960

1960

(1960)

1960-61

1961-62



1. यह योजना रोजगार (Employment) की रीति से बहुत बड़ी होगी। योजना के भीतर वह भी (वैयक्तिक) से बहुत बड़ा धारण कर होगा।
2. इस योजना में विदेश-व्यय विधिवत रीति से बहुत कम होगा। इससे स्पष्ट होगा कि योजना की कारगरिबता करने में पूरी रीति रहेगी।
3. इस योजना में उद्योग-धर्म के विकास पर कम ध्यान दिया जाएगा। धन ही को प्रोत्साहित से ही धर्म-धर्म और सहकारिता आदि कारगर में कारगर बनी रहेगी।
4. इस योजना की काफी संख्या के बाद भी अन्त में प्राप्ति-जन प्रयोग (Plan consciousness) की संसार नहीं हो पाया और यह बहुत सरकारी कारगर बन कर रहेगा।
- इसमें यह भी कि प्रमुख कारगर प्रोत्साहित है कि इस योजना बहुत बड़ा संभव है। इस संभव से और और ही प्रोत्साहित योजना बहुत बड़ा संभव है।

## द्वितीय पंचवर्षीय योजना

### SECOND FIVE YEAR PLAN

(सर्वा—) अन्त, 1956 से मार्च 1961)

इस पंचवर्षीय योजना के मुख्य-मुख्य सामान्य बिंदु पर विशेष ध्यान देना होगा। यह योजना इस योजना की योजना में 45 प्रतिशत की योजना है। यह योजना के मुख्य-मुख्य बिंदु पर विशेष ध्यान देना होगा।

1. योजनागत में निम्नलिखित 25% प्रतिशत की योजना होगी।
2. यह योजना की योजना पर बहुत बड़ा ध्यान देना होगा।

इस योजना की योजना पर बहुत बड़ा ध्यान देना होगा। यह योजना की योजना पर बहुत बड़ा ध्यान देना होगा।



| କ୍ର.ସଂ. | ନାମ                   | ପଦବୀ          | ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସ |
|---------|-----------------------|---------------|---------------|
| ୧୦୦     | ଶ୍ରୀମତୀ ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ | ପ୍ରଧାନ ଶିଳ୍ପୀ | ୧୯୫୫          |
| ୧୦୧     | ଶ୍ରୀମତୀ ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ | ପ୍ରଧାନ ଶିଳ୍ପୀ | ୧୯୫୫          |
| ୧୦୨     | ଶ୍ରୀମତୀ ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ | ପ୍ରଧାନ ଶିଳ୍ପୀ | ୧୯୫୫          |
| ୧୦୩     | ଶ୍ରୀମତୀ ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ | ପ୍ରଧାନ ଶିଳ୍ପୀ | ୧୯୫୫          |
| ୧୦୪     | ଶ୍ରୀମତୀ ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ | ପ୍ରଧାନ ଶିଳ୍ପୀ | ୧୯୫୫          |
| ୧୦୫     | ଶ୍ରୀମତୀ ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ | ପ୍ରଧାନ ଶିଳ୍ପୀ | ୧୯୫୫          |
| ୧୦୬     | ଶ୍ରୀମତୀ ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ | ପ୍ରଧାନ ଶିଳ୍ପୀ | ୧୯୫୫          |
| ୧୦୭     | ଶ୍ରୀମତୀ ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ | ପ୍ରଧାନ ଶିଳ୍ପୀ | ୧୯୫୫          |
| ୧୦୮     | ଶ୍ରୀମତୀ ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ | ପ୍ରଧାନ ଶିଳ୍ପୀ | ୧୯୫୫          |
| ୧୦୯     | ଶ୍ରୀମତୀ ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ | ପ୍ରଧାନ ଶିଳ୍ପୀ | ୧୯୫୫          |
| ୧୧୦     | ଶ୍ରୀମତୀ ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ | ପ୍ରଧାନ ଶିଳ୍ପୀ | ୧୯୫୫          |

|       |          |    |
|-------|----------|----|
| PRDJR | 4 22 214 | 24 |
|-------|----------|----|

| ક્રમ નંબર                  | 4600       | 100     |
|----------------------------|------------|---------|
| 1. અંતિમ નવ મે સંવત્સર પાસ | 1,052.50 = | 23-1=22 |
| 2. રેલ્વે ના સંવત્સર       | 150        | 3       |
| 3. સેવા                    | 780        | 17      |
| 4. સેવા સમય ના સંવત્સર     | 570        | 12      |
| 5. અન્ય સંવત્સર            | 60         | 2       |
| 6. અન્ય ના સંવત્સર         | 948        | 20      |
| 7. સંવત્સર ના સંવત્સર      | 1090       | 24      |

— 1954 11-12 26 1012454

3. **व्यवसायिक (व्यापार) -** व्यापार का अर्थ है वस्तुओं का खरीदना और बेचना। व्यापारिक व्यवसाय में व्यक्ति या कंपनी दूसरों से वस्तुओं को खरीदती है और उन्हें और अधिक मूल्य पर बेचती है। व्यापारिक व्यवसाय के दो प्रकार हैं - **निर्यात** और **आयात**। निर्यात व्यवसाय में व्यक्ति या कंपनी अपने देश के वस्तुओं को विदेशों में बेचती है, जबकि आयात व्यवसाय में व्यक्ति या कंपनी विदेशों के वस्तुओं को अपने देश में खरीदती है। व्यापारिक व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। व्यापारिक व्यवसाय के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं - **कपड़ा**, **खाने की वस्तुएँ**, **घर के सामान**, **कारें**, **इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएँ** आदि। व्यापारिक व्यवसाय में व्यक्ति या कंपनी को अपने वस्तुओं की कीमतों को निर्धारित करना पड़ता है, जोकि बाजार की मांग और आपूर्ति के अनुसार होना चाहिए। व्यापारिक व्यवसाय में व्यक्ति या कंपनी को अपने वस्तुओं की गुणवत्ता को बनाए रखना पड़ता है, जोकि ग्राहकों की संतुष्टि के लिए आवश्यक है। व्यापारिक व्यवसाय में व्यक्ति या कंपनी को अपने वस्तुओं की बिक्री को बढ़ावा देना पड़ता है, जोकि विज्ञापन, प्रदर्शन, ब्रोकरों के माध्यम से हो सकता है। व्यापारिक व्यवसाय में व्यक्ति या कंपनी को अपने वस्तुओं की बिक्री के लिए उचित ऋण लेना पड़ता है, जोकि बैंक, वित्तीय संस्थानों से हो सकता है। व्यापारिक व्यवसाय में व्यक्ति या कंपनी को अपने वस्तुओं की बिक्री के लिए उचित कर चुकाना पड़ता है, जोकि सरकार को देना होता है। व्यापारिक व्यवसाय में व्यक्ति या कंपनी को अपने वस्तुओं की बिक्री के लिए उचित सुरक्षा लेना पड़ता है, जोकि पुलिस, सशस्त्र बल से हो सकता है। व्यापारिक व्यवसाय में व्यक्ति या कंपनी को अपने वस्तुओं की बिक्री के लिए उचित निगरानी रखनी पड़ती है, जोकि सरकार को देनी होती है। व्यापारिक व्यवसाय में व्यक्ति या कंपनी को अपने वस्तुओं की बिक्री के लिए उचित दस्तावेज बनाना पड़ता है, जोकि ग्राहकों को देना होता है। व्यापारिक व्यवसाय में व्यक्ति या कंपनी को अपने वस्तुओं की बिक्री के लिए उचित भुगतान लेना पड़ता है, जोकि ग्राहकों से हो सकता है। व्यापारिक व्यवसाय में व्यक्ति या कंपनी को अपने वस्तुओं की बिक्री के लिए उचित भुगतान देना पड़ता है, जोकि बैंक, वित्तीय संस्थानों से हो सकता है। व्यापारिक व्यवसाय में व्यक्ति या कंपनी को अपने वस्तुओं की बिक्री के लिए उचित भुगतान लेना पड़ता है, जोकि ग्राहकों से हो सकता है। व्यापारिक व्यवसाय में व्यक्ति या कंपनी को अपने वस्तुओं की बिक्री के लिए उचित भुगतान देना पड़ता है, जोकि बैंक, वित्तीय संस्थानों से हो सकता है।

1. Write the following

[illegible][illegible][illegible]





कृषि विकास की योजना थी। द्वितीय योजना ने सीधे अधिक बल दिया और तृतीय योजना ने कृषि एवं उद्योग सम्मिलित विकास पर बल दिया।

1. तृतीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य (Objects)

तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करते समय उद्देश्यों की ध्यान में रखा गया था—

1. तृतीय योजना काल में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत से आय में वृद्धि प्राप्त करना, जिससे विनियोग की स्थिति में वृद्धि प्राप्त करना जिससे उद्योगों तथा निर्यात की मात्रा में वृद्धि प्राप्त करना जिससे उद्योगों तथा निर्यात की मात्रा में वृद्धि प्राप्त किया जा सके।

2. आगामी दस वर्षों में देश के औद्योगीकरण की दृष्टि से देश में ही पूरा की जा सके इसके लिए मूल उद्योगों तथा निर्यात उद्योग, ईंधन तथा शक्ति के साधनों का विकास करना जिससे उद्योगों तथा निर्यात की मात्रा में वृद्धि प्राप्त किया जा सके।

| 100      | 7,500      | 5th 100  |
|----------|------------|----------|
| 10       | 2,200      | 10th 100 |
| 7        | 550        | 10th 100 |
| 3        | 275        | 10th 100 |
| 12       | 865        | 10th 100 |
| 11       | 800        | 10th 100 |
| 6        | 450        | 10th 100 |
| 1        | 100        | 10th 100 |
| 7        | 550        | 10th 100 |
| 23       | 1,710      | 10th 100 |
| 10th 100 | (10th 100) | 10th 100 |

[illegible]

● 11月11日 星期四

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

[illegible]

(112 112 001' 112

11,600 2124 2444 (1111) 2444 7500 + 1111

(CLASS 2125 0017 1001 1001)

6.309+ (10,400) 000'01

कुल विनियोग 10,400 करोड़ रुपये (सार्वजनिक क्षेत्र 6,309 + निजी क्षेत्र 4,100 करोड़ रुपये)

कुल व्यय 11,600 करोड़ रुपये (सार्वजनिक क्षेत्र 7,500 + निजी क्षेत्र 4,100 करोड़ रुपये)

उपरोक्त तालिका को देखने से पता लगता है कि द्वितीय योजना की तुलना में कृषि तथा सामुदायिक विकास तथा शक्ति पर व्यय का अनुपात बढ़ा है। निषाद, लघु उद्योग तथा संगठित नदीय व सतह पर व्यय का अनुपात कम हुआ है। पर यह बात उल्लेखनीय है कि प्रत्येक मद पर लक्ष्य की जाने वाली राशि में काफी कृति हुई।  
वित्तोप साधन\*

तृतीय योजना के प्रास्तावित कार्यक्रमों पर व्यय की जाने वाली राशि का प्रकल्प निम्नांकित धोरणों से विवेक जाने की व्यवस्था थी—

| साधन                              | राशि(करोड़ रु.) | प्रतिशत    |
|-----------------------------------|-----------------|------------|
| अतिरिक्त कर                       | 1,710           | 23         |
| राजस्व के धातु गाने से बचत        | 550             | 7          |
| रेल्वी द्वारा संग्रह              | 100             | 1          |
| सार्वजनिक उद्योगों से प्राप्त लाभ | 450             | 6          |
| सार्वजनिक ऋण                      | 800             | 11         |
| अल्प बचत एवं अन्य ऋण              | 865             | 12         |
| अल्प पुर्णगत ऋण                   | 275             | 3          |
| बाह्य की दत्त व्यवस्था            | 550             | 7          |
| विदेशी कर्जा                      | 2,360           | 30         |
| <b>कुल योग</b>                    | <b>7,500</b>    | <b>100</b> |

\* Third Five Year Plan-Fiscal Draft.

\* Third Five Year Plan-Final Draft.

| वर्ष  | रुपि (करोड़ में) | प्रतिशत |
|-------|------------------|---------|
| 23    | 1,710            | 23      |
| 7     | 550              | 7       |
| 1     | 100              | 1       |
| 6     | 450              | 6       |
| 11    | 800              | 11      |
| 12    | 865              | 12      |
| 3     | 275              | 3       |
| 7     | 550              | 7       |
| 30    | 2,200            | 30      |
| 7,500 |                  | 100     |

गिरा की मात्रा निर्धारित की गई है।

गिरा की मात्रा निर्धारित की गई है।

गिरा की मात्रा निर्धारित की गई है।

गिरा की मात्रा निर्धारित की गई है।

गिरा की मात्रा निर्धारित की गई है।

गिरा की मात्रा निर्धारित की गई है।

गिरा की मात्रा निर्धारित की गई है।

गिरा की मात्रा निर्धारित की गई है।

गिरा की मात्रा निर्धारित की गई है।

गिरा की मात्रा निर्धारित की गई है।

गिरा की मात्रा निर्धारित की गई है।

गिरा की मात्रा निर्धारित की गई है।

कुल विनियोग 10,400 करोड़ रुपये (सार्वजनिक क्षेत्र 6,309 + निजी क्षेत्र 4,100 करोड़ रुपये)

कुल व्यय 11,600 करोड़ रुपये (सार्वजनिक क्षेत्र 7,500 + निजी क्षेत्र 4,100 करोड़ रुपये)

उपरोक्त साक्षिदा को देखने से पता लगता है कि द्वितीय योजना की तुलना में कृषि तथा सामुदायिक विकास तथा शक्ति पर व्यय का अनुपात बढ़ा है। सिंचाई, लघु उद्योग तथा संगठित उद्योग व शक्ति पर व्यय का अनुपात कम हुआ है। पर यह बात उल्लेखनीय है कि प्रत्येक मद पर खर्च की जाने वाली राशि में काफी वृद्धि हुई।  
द्वितीय साधन\*

तृतीय योजना के प्रास्तावित कार्यक्रमों पर व्यय की जाने वाली राशि का प्रबन्ध निम्नांकित स्रोतों से किये जाने की व्यवस्था थी—

| साधन                              | राशि(करोड़ रु.) | प्रतिशत |
|-----------------------------------|-----------------|---------|
| अनिरिक्त कर                       | 1,710           | 23      |
| राजस्व के धातु माते से बचत        | 550             | 7       |
| रेलों द्वारा अगदान                | 100             | 1       |
| सार्वजनिक उद्योगों से प्राप्त भाग | 450             | 6       |
| सार्वजनिक अधुण                    | 800             | 11      |
| अल्प बचत एवं अन्य अधुण            | 865             | 12      |
| अल्प पुजीगत धारा                  | 275             | 3       |
| बाटे की एवं व्यवस्था              | 550             | 7       |
| विदेशी सहायता                     | 2,200           | 30      |
| कुल योग                           | 7,500           | 100     |

• Third Five Year Plan-Final Draft.

सार्वजनिक क्षेत्र पर होने वाले खर्च में से 6,000 करोड़ रुपये राष्ट्रीय सरकार द्वारा और शेष राशि राज्य सरकारों की जानी थी।

#### 4. तृतीय योजना के विभिन्न कार्यक्रम

यहाँ हम विकास व उत्पादन के विभिन्न कार्यक्रमों पर विचार करेंगे—

1. कृषि—कृषि, सिंचाई और सामुदायिक विकास पर 950 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई, जबकि द्वितीय योजना में केवल 950 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। योजना के अन्तर्गत उत्पादन 30 प्रतिशत से बढ़ाने का लक्ष्य था। उत्पादन की प्राप्ति हेतु सिंचाई का विकास किया जाना था। तृतीय योजना के प्रारम्भ में 282 लाख हेक्टर (700 करोड़ एकड़) पर सिंचाई की व्यवस्था की गई थी, जो कि 1950-51 में 362 लाख हेक्टर (900 लाख एकड़) हो गई थी। 88.5 लाख हेक्टर (220 लाख एकड़) भूमि को सिंचित करने के लिए 1950-51 में 1,000 करोड़ रुपये का अनुमानित खर्च था।

कुल विनियोग 10,400 करोड़ रुपये (सार्वजनिक क्षेत्र 6,309 + निजी क्षेत्र 4,100 करोड़ रुपये)

कुल व्यय 11,600 करोड़ रुपये (सार्वजनिक क्षेत्र 7,500 + निजी क्षेत्र 4,100 करोड़ रुपये)

उपरोक्त तालिका को देखने से पता लगता है कि द्वितीय योजना की तुलना में कृषि तथा सामुदायिक विकास तथा शक्ति पर व्यय का अनुपात बढ़ा है। सिंचाई, लघु उद्योग तथा संगठित उद्योग व शक्ति पर व्यय का अनुपात कम हुआ है। पर यह बात उल्लेखनीय है कि प्रत्येक मद पर खर्च की जाने वाली राशि में काफी वृद्धि हुई।  
वित्तीय साधन\*

तृतीय योजना के प्रास्तवित कार्यक्रमों पर व्यय की जाने वाली राशि का प्रबन्ध निम्नांकित स्रोतों से रिये जाने की व्यवस्था थी—

| साधन                             | राशि(करोड़ रु) | प्रतिशत    |
|----------------------------------|----------------|------------|
| अनिरिक्त कर                      | 1,710          | 23         |
| राजस्व के धानू स्रोतों से बचत    | 550            | 7          |
| रेलों द्वारा भण्डान              | 100            | 1          |
| सार्वजनिक उद्योगों से प्राप्त धन | 450            | 6          |
| सार्वजनिक ऋण                     | 800            | 11         |
| अल्प बचत एवं अन्य ऋण             | 865            | 12         |
| अन्य पुंजीगत धन                  | 275            | 3          |
| घाटे की मदें व्यवस्था            | 550            | 7          |
| विदेशी सहायता                    | 2,200          | 30         |
| <b>कुल योग</b>                   | <b>7,500</b>   | <b>100</b> |

• Third Five Year Plan-Final Draft.

सार्वजनिक क्षेत्र पर होने वाले खर्च में से 6,038 करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार द्वारा और शेष राशि राज्य सरकारों की जानी थी।

#### 4. तृतीय योजना के विभिन्न कार्यक्रम

यहाँ हम विकास व उत्पादन के विभिन्न कार्यक्रमों पर करेंगे—

1. कृषि—कृषि, सिंचाई और सामुदायिक विकास के 1,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई, जबकि द्वितीय योजना पर केवल 950 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। योजना कायम का उत्पादन 30 प्रतिशत से बढ़ाने का लक्ष्य था। उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई का विकास किया जाना था जो योजना के प्रारम्भ में 282 लाख हेक्टर (700 लाख एकड़) से बढ़कर 362 लाख हेक्टर (900 लाख एकड़) हो जाने की योजना थी। 88.5 लाख हेक्टर (220 लाख एकड़) सूखे (Dry Farming) से निपटने के लिए योजना के अन्तर्गत



करना था जो अर्ध-व्यवस्था को स्वावलम्बन की ओर ले जाते हों, जैसे—लोहे और इस्पात, मशीन औजार तथा उत्पादक उद्योग। उपभोग वस्तुओं के उत्पादन का विकास निजी क्षेत्र द्वारा सम्पन्न होने का लक्ष्य था। इन सब के परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन 70 प्रतिशत तक बढ़ने की सम्भावना थी। सार्वजनिक क्षेत्र में एक इस्पात का कारखाना ओकरो स्टील प्लांट, रुस की साहपता से खोले जाने की व्यवस्था थी। योजना काल में धातु-उद्योग, औद्योगिक मशीनरी अल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील, ताँबा, जस्ता, सीमेंट, दवाइयाँ, रंगों का समान, कपड़ा, कागज, चीनी, तेल, घड़ियाँ, साइकिलें, रेडियो, कपड़ा, सिलाई मशीनों आदि के उत्पादन के अधिक सदन निर्धारित किये गये।

3. पातोष एवं सधु उद्योग—योजना के अन्तर्गत 264 करोड़ रुपये खर्च करने की व्यवस्था की गई। इन उद्योगों को विवसित करने से रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होने का अनुमान था। सधु उद्योगों को ऋण देने के अतिरिक्त सरकारी गारंटी देने की व्यवस्था भी की गई। हाथ करघा, शक्ति करघा, रेशम व खादी के बपड़े में उत्पादन वृद्धि के लक्ष्य रखे गये। इन उद्योगों में विद्युत तथा छोटे पवन प्रयोग में लाने से उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयत्न किये गये।

4. यातायात—देश में औद्योगिक विकास के लिए यातायात की महत्ता भली-भाँति समझ ली गई है। इसीलिए प्रत्येक योजना में इसे सर्वाधिक महत्व दिया गया है। तीसरी योजना में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। यातायात का विकास करने हेतु 1,486 करोड़ रुपये खर्च किये जाने की व्यवस्था थी। योजना काल में 1,930 कि. मी. (1,200 मील) नई रेलवे लाइन बिछाने, 40,300 कि. मी. (23,000 मील) सतह वाली (surfaced) सड़कें बनाने, जहाजी-मार समुद्र तथा बन्दरगाहों की समता में वृद्धि किये जाने का लक्ष्य था। पोस्ट आफिस तथा तारघरों की संख्या में वृद्धि की गई।

5. सामाजिक सेवाएँ—तृतीय योजना में सामाजिक सेवाओं के

विस्तार के लिए, 13,00 करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था की गई। वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण पर अधिक बल दिया गया, 11 से 16 वर्ष के बच्चों को नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था योजना की विशेषता है। स्कूल जाने वाले छात्रों की संख्या इस अवधि में 204 लाख (अर्थात् 435 लाख से बढ़कर 639 लाख) बढ़ जाने का अनुमान है।

स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार नियोजन (Family planning) कार्यक्रमों का विस्तार किया गया। ग्रामीण जल प्रदाय तथा निर्माण योजनाओं के अतिरिक्त आवास (Housing) सुविधाओं का विस्तार भी किया गया। समाज कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत बाल-कल्याण, महिला कल्याण, समाज सुरक्षा, विस्थापितों को बसाने, आदि कार्यक्रम भी रहे गये।

6. राष्ट्रीय आय (National Income)—यह माशा की गई कि योजना में लक्षित सभी कार्यक्रम पूरे हो जाने पर राष्ट्रीय आय में लगभग 30 प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। सन् 1960-61 में जो राष्ट्रीय आय 14,500 करोड़ रु० थी वह सन् 1965-66 में बढ़कर 19,000 करोड़ रु० हो जाने की आशा थी। प्रति व्यक्ति आय 300 रुपये से बढ़कर 385 रुपये हो जाने की संभावना थी।

7. रोजगार (Employment)—अनुमान है कि तृतीय योजना काल में 145 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। इस अवधि में जनसंख्या की वृद्धि लगभग 170 लाख होने का अनुमान था। इसलिए अब रोजगार के अधिक अवसर ढूँढ़ने चाहिये। इस संबंध में स्थानीय संगठनों द्वारा जन सहयोग के माध्यम पर कार्यक्रम बनाए जाने चाहिये।

द्वितीय योजना का मूल्यांकन—

द्वितीय योजना काल में हमें माशातीत सफलता नहीं मिली। मौसम की प्रतिकूलता, शक्ति के साधनों-विशेषतः कोयले और जलविद्युत की

कमी, कौमी धाकमण, पाकिस्तान से दुश् आदि कारणों से हम योजना के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सके। यहाँ हम योजना से सम्बन्धित विभिन्न अवलम्बियों पर विचार करेंगे—

1. योजना व्यय (Plan Expenditure)—हम योजना में वहाँ मार्गदर्शक क्षेत्र में 7,500 करोड़ रुपये खर्च करने की व्यवस्था की गयी। वास्तविक व्यय लगभग 8,623 करोड़ अर्थात् प्रस्तावित व्यय से 1,123 करोड़ रुपये अधिक खर्च हुआ। इस व्यय की वृद्धि का मुख्य कारण मुद्रा प्रसार (Inflation) है।

2. योजना के निर्देशित वित्तपोषण—हम योजना में प्रस्तावित मापों के हवाले पर कहीं अधिक व्यवस्था की गयी। योजना काल में 2,200 करोड़ रुपये के हवाले पर विदेशी सहायता के रूप में 2,435 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई। बाटे की अर्थ व्यवस्था का अनुमान वहाँ 310 करोड़ रुपये का लगाया गया था वहाँ इस रूप में 1,151 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। योजना काल में अतिरिक्त बाटे से 2,333 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई। 800 करोड़ रुपये के हवाले पर मार्गदर्शक क्षेत्रों से 914 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई। प्रस्तावित मापों से बाटे की योजना में कमी बाटे का अर्थ व्यवस्था, रोजा से अर्थ व्यवस्था मार्गदर्शक क्षेत्रों से से से।

3. राष्ट्रीय आय—वित्तपोषण योजना में राष्ट्रीय आय में प्रस्तावित 5 प्रतिशत वृद्धि वर्ष वृद्धि के हवाले पर केवल 2.5 प्रतिशत में ही वृद्धि हुई। वर्ष 1960-61 के कुल आय का बाटका के माप में (1961-66) राष्ट्रीय आय 15,930 करोड़ रुपये की तथा वृद्धि प्रतिशत माप (1957-61 के कुल आय पर) 32.5 प्रतिशत की। राष्ट्रीय आय के क्षेत्र में उच्च विकास का कारण वृद्धि का उद्योगों के उत्पादन में कमी

4. रोजगार—योजना के प्रारम्भ में बेरोजगारों की संख्या 70 लाख थी। योजना की अवधि में 145 लाख लोगों को रोजगार दिया गया किन्तु इसी दौरान 170 लाख नए व्यक्ति श्रमशक्ति में सम्मिलित हो गए। इस प्रकार तृतीय योजना के अन्त में लगभग 95 लाख व्यक्ति बेरोजगार थे।

5. कृषि—योजना के अधिकांश वर्षों में प्रकृति की प्रतिकूलता के कारण कृषि उत्पादन के सम्पूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति करना सम्भव नहीं हुआ। योजना के अन्तिम वर्ष में खाद्यान्नों का उत्पादन 72.29 मिलियन टन हुआ। इस योजना में कृषि, सामुदायिक विकास एवं सहकारिता के विकास पर 1,104 करोड़ रुपये खर्च किए गये।

6. उद्योग—योजना की अवधि में मूल औद्योगिक क्षेत्र का उत्पादन 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भी अधिक बढ़ा। आर्थिक एवं सुरक्षा संकटों के कारण औद्योगिक विकास के सम्पूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति सम्भव नहीं हुई। जिन परियोजनाओं का कार्य व्यर्थ रहा या वे अब शीघ्र ही पूरी हो जाएंगी। योजना काल में सगठित उद्योगों, तनिज विकास कार्यक्रमों, कुटीर एवं लघु उद्योगों पर 1,959 करोड़ रुपये खर्च हुआ जो प्रस्तावित व्यय से लगभग 175 करोड़ रुपये अधिक है।

7. सिंचाई एवं शक्ति—योजनाकाल की बढ़ी एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं से सिंचित क्षेत्र 5.5 मिलियन एकड़ से बढ़कर 13.1 मिलियन एकड़ हो गया। लगभग 28,100 गांवों की ओर बिजली दी गई। योजना काल में जल विद्युत निर्माण की क्षमता 4.6 मिलियन किलोवाट से बढ़ गई। सिंचाई एवं शक्ति के विकास पर 1,920 करोड़ रुपये खर्च हुए।

8. मातामृत एवं समाज सेवाएँ—तीसरी योजना में इन पर 3,645 करोड़ रुपये खर्च हुआ जो प्रस्तावित व्यय से 859 करोड़ रुपये अधिक है। स्कूलों की संख्या 4 लाख से बढ़कर 5 लाख हो गई। परिवार नियोजन केन्द्र 1,649 से बढ़कर 11,474 हो गये।

मजददर मदकों की सम्बाई 255 हजार रिमो मोटर से बडर 284 हजार रिमोमोटर हो गई ।

इन तथ्यों की देखने मे पता चलता है कि तृतीय योजना में निर्धारित सभी लक्ष्यों की प्राप्ति सम्भव नहीं हो सकी । इसके अतिरिक्त इस योजना की मुख्य असफलता मुद्रा प्रसार अथवा मूल्य वृद्धि है । बेरोजगारी की समस्या का विकराल रूप, राष्ट्रीय आय में पर्याप्त वृद्धि न होना, कर भार में वृद्धि आदि कुछ अन्य बातें हैं जो योजना की कमियों में गिनी जाती हैं ।

यद्यपि तृतीय योजना के परिणाम अधिक आशाप्रद नहीं रहे फिर भी देश चतुर्थ योजना में अधिक तेजी से विकास के लिए कटि-बद्ध है । आर्थिक विकास के लिए थोड़ा कष्ट तो उठाना ही पड़ता है । फिर आर्थिक विकास तो राजनीतिक स्वतन्त्रता को बनाये रखने के लिए आवश्यक है, इसके लिए हमें त्याग और कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए ।

### भारत की वार्षिक योजनाएँ (Annual Plans in India)

योजना लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है । योजनाओं का वास्तविक महत्व उसी अवस्था में पूर्णरूप से कार्यशील होता है जबकि दीर्घकालीन दृष्टिकोण के सन्दर्भ में क्रमशः अल्पकालीन योजनाएँ बनती रहें । कभी-कभी बदलती हुई राष्ट्रीय एवम् अन्तराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण योजना को बनाए रखना कठिन हो जाता है तब कुछ समय के लिए दीर्घकालीन दृष्टिकोण के स्थान पर अल्पकालीन दृष्टिकोण से ही कार्य करना होता है । भारत में भी चतुर्थ योजना के स्थान पर वार्षिक संगठनात्मक योजनाएँ बनाने का यही उद्देश्य है ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल सन् 1961 से 31 मार्च सन् 1966) को अनेक विषम परिस्थितियों के मध्य गुजरना पड़ा । दो-दो युद्ध और सूखों (Draughts) को पार करने में इस योजना की शक्ति सक्षमों की प्राप्ति की अपेक्षा इससे निपटने में अधिक लगी ।

कृषीय योजना की असफलता ने हमारी सहायता करने वाले देशों के इष्टिकोण में परिवर्तन किया। आज कोई भी अर्द्ध विकसित राष्ट्र बिना अन्तराष्ट्रीय सहयोग व सहायता के विकास नहीं कर सकता। भारत भी इन बदली हुई परिस्थितियों में अपनी चतुर्थ योजना को प्रभावशाली ढंग से लागू करने में कठिनाई महसूस कर रहा था। इसीलिए परिस्थितियों के अनुकूल बनाने तक वाषििक संगठनात्मक योजनाएँ बनाई गईं। यहाँ हम दो वाषििक संगठनात्मक योजनाओं का अध्ययन करेंगे।

### वाषििक योजना सन् 1966-67

वाषििक योजना (सन् 1966-67) के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 2,221 करोड़ रुपए व्यय करने का लक्ष्य रखा गया। इस वाषििक योजना के महत्वपूर्ण लक्ष्य (Targets) इस प्रकार हैं —

**विद्युत**—सन् 1966-67 के मध्य यह लक्ष्य रखा गया था कि इस वर्ष में विद्युत उत्पादन क्षमता में 2 मिलियन किलोवाट की वृद्धि होगी किन्तु वास्तविक वृद्धि 1.2 मिलियन किलोवाट से ही हुई।

**कृषि**—सन् 1949-50 को आधार वर्ष मान कर जो कृषि उपज निर्देशांक इस वाषििकी योजना में बनाया गया वह 135.7 के बराबर रहा, उपज में 4 अंकों की वृद्धि हुई।

**औद्योगिक**—देश में औद्योगिक उत्पादन में विगत कुछ वर्षों से गिरावट आ रही थी। जहाँ सन् 1963-64 में औद्योगिक उत्पादन 8.5 प्रतिशत की दर से बढ़ा वहीं औद्योगिक उत्पादन में सन् 1964-65 में 7 प्रतिशत व सन् 1965-66 में 3.9 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई। इसी के अनुरूप सन् 1966-67 में (इस वाषििक योजना में) औद्योगिक उत्पादन वृद्धि की दर तीन प्रतिशत रही। इस गिरावट का मुख्य कारण कृषि उपज में गिरावट था।

**यातायात**—भारत में रेलों की भारवहन क्षमता का अनुमान तीसरी योजना के अन्त में 230 मिलियन टन लगाया गया था।

सन् 1966-67 के लिए जहाँ भारघहन क्षमता 216 मिलियन टन बढ़ने का अनुमान था वहीं वास्तविक वृद्धि 203 मिलियन टन से हुई

राष्ट्रीय भाव—सन् 1966-67 में राष्ट्रीय भाव का अनुमान (वर्तमान मूल्य स्तर पर) 22,900 करोड़ रुपए लगाया गया था सन् 1965-66 में यह राशि 20,250 करोड़ रुपए थी । सन् 1966-67 में अत्यधिक मूल्य वृद्धि के कारण ही थोक मूल्य निर्देशांक (Wholesale Price Index) 165.1 से बढ़कर 191 हो गया ।

वार्षिक योजना सन् 1967-68 Annual Plan (1967-68)—

प्रस्तावित चतुर्थ योजना के द्वितीय वर्ष (सन् 1967-68) की वार्षिक योजना के लिए कुल 2,246 करोड़ रुपए की राशि व्यय के लिए निर्धारित की गई । सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय की जाने वाली राशि का आवंटन इस प्रकार किया गया—

| भेद                               | व्यय (करोड़ रु० में) |
|-----------------------------------|----------------------|
| कृषि                              | 296.65               |
| सिंचाई                            | 46.77                |
| सामुदायिक विकास व सहकारिता        | 79.85                |
| शक्ति                             | 384.78               |
| संगठित उद्योग                     | 520.19               |
| लघु व ग्रामीण उद्योग              | 43.55                |
| यातायात व संचार                   | 418.75               |
| निर्माणा                          | 111.66               |
| स्वास्थ्य व परिवार नियोजन         | 75.84                |
| जलपूर्ति                          | 39.96                |
| (अन्य अनुसंधान व लोक कल्याण सहित) | 228.00               |
| योग                               | 2,246.00             |

उपरोक्त तालिका में वर्णित मदों में विशेष ध्यान देने की बात यह है कि इस वार्षिक योजना में मध्यम व बृहत् सिंचाई शक्ति, उद्योग व वातावरण पर जो व्यय की राशियाँ रखी गई हैं वे क्रमशः निर्धारित योजना के अनुरूप ही हैं।

इन वार्षिक योजना के वित्तीय प्रबन्ध की स्थिति निम्नवित्त तालिका से स्पष्ट हो जावेगी।

| मद                                   | करोड़ रुपये |
|--------------------------------------|-------------|
| बापू राज्य खाते से अक्षत             | 212         |
| रेलों द्वारा अंशदान                  | -29         |
| सार्वजनिक उद्योगों से प्रतिरिक्त भाग | 239         |
| अतिरिक्त कर                          | 360         |
| वन अक्ष                              | 204         |
| दल्य अक्ष                            | 136         |
| स्वर्ण बाण्ड                         | -3          |
| वार्षिक उपाय                         | 22          |
| अवोदीय अक्ष                          | 86          |
| विविध पुंजी प्राप्ति                 | -50         |
| घाटे की व्यवस्था (केंद्र में)        | -1          |
| घाटे की व्यवस्था (राज्यों में)       | 15          |
| काल्य अक्ष (P. L. 480 महिन)          | 1001        |
| कुल योग                              | 2,192       |

इन प्रकार से कुल अनुमानित वार्षिकी एवं व्यय के 54 करोड़ रुपए का अन्तर रहा (2,246-2,192=54)।

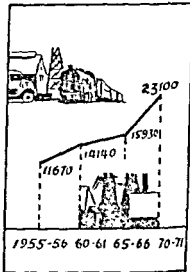


## तीन पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत भारत की आर्थिक प्रगति की समीक्षा

### (A REVIEW OF THE ECONOMIC PROGRESS INDIA UNDER THE THREE FIVE YEAR PLANS)

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् आर्थिक विभाग के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गईं। देश में जिमायन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न आवश्यकताओं के पुनर्वास (Rehabilitation) से लेकर खान और पारिस्थिकी के समस्त संघर्ष तक अनेक समस्याओं का हमने सामना किया। देश की आर्थिक प्रगति का रूप (Chariot) निरन्तर आगे बढ़ता जा रहा।

यहाँ हम प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय योजनाओं में विभिन्न क्षेत्रों में हुई आर्थिक प्रगति का अध्ययन करेंगे—



राष्ट्रीय आय में वृद्धि

#### 1. राष्ट्रीय आय

(National Income)

सन् 1950-51 से

1964-65 तक राष्ट्रीय आय

में 69 प्रतिशत से वृद्धि हुई।

इस सम्पूर्ण अवधि में औसत

वृद्धि लगभग 3.8 प्रतिशत

प्रतिवर्ष से हुई। प्रथम

योजना के आरम्भ में जब

राष्ट्रीय आय 9,850 करोड़

रुपये थी तब सन् 1964-65

में बढ़कर 16,630 करोड़

रुपये (सन् 1960-61 के मूल्य स्तर) हो गई।

प्रति व्यक्ति आय में, केवल

1.8 प्रतिशत प्रतिवर्ष से

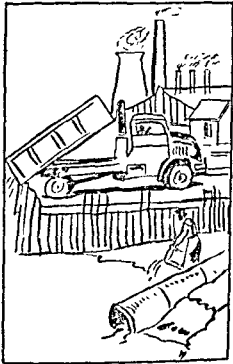
वृद्धि हुई क्योंकि इस अवधि में लगभग 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से जनसंख्या में वृद्धि हुई। सन् 1965-66 में प्रति व्यक्ति आय 325 रुपये थी।

2. कृषि—योजना के प्रथम चौदह वर्षों में कृषि उत्पादन में लगभग 65 प्रतिशत वृद्धि हुई। ज्वारान्नो, तिलहनो, गन्ने, कपास, जूट आदि के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। सन् 1950-51 में जहाँ प्रति व्यक्ति सादाभातों का उत्पादन 12.8 औंस होता था वह सन् 1964-65 में बढ़कर 15.4 औंस हो गया। योजनाकाल में प्रति व्यक्ति उपलब्ध केलोरी 1,759 से बढ़कर 2,145 हो गई। कपड़े का उत्पादन 11 मीटर प्रति व्यक्ति से बढ़कर 15 मीटर प्रति व्यक्ति हो गया। प्रथम तीन योजनाओं में छोटी, मध्यम एवं बड़ी सिंचाई योजनाओं से 4.54 करोड़ एकड़ भूमि पर प्रतिरिक्त सिंचाई होने लगी।

3. उद्योग शक्ति व यातायात—इन योजनाओं में उद्योग, शक्ति एवं यातायात के क्षेत्रों में काफी प्रगति हुई। उद्योगों के उत्पादन में लगभग 152 प्रतिशत वृद्धि हुई। उद्योगों में विनियोग की राशि में भारी वृद्धि हुई सन् 1950-51 में जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में 55 करोड़ तथा निजी क्षेत्र में 233 करोड़ की पूँजी लगी हुई थी वहाँ पृथीय योजना के अन्त में यह राशि क्रमशः—520 करोड़ तथा 1,050 करोड़ रुपये हो गई।

विद्युत-शक्ति में चार गुनी वृद्धि हुई। सन् 1950-51 में जहाँ विद्युत निर्माण की प्रतिस्थापित क्षमता 23 लाख किलोवाट थी वह सन् 1965-66 में बढ़कर 102 लाख किलोवाट हो गई। बिजली वाले गाँवों की संख्या 3,700 से बढ़कर 52,300 हो गई।

सतहदार सड़कों की लम्बाई 1,56,000 कि॰ मी॰ से बढ़ कर 2,84,000 कि॰ मी॰ हो गई। रेलों की मारवहन क्षमता दुगुनी से भी अधिक हो गई।



उद्योग



## यातायात उद्योग

4. समाज सेवाएं (Social Service)—पिछले पन्ध्र वर्षों में यात्रा सेवाओं के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत प्रगति हुई है। स्कूलों की संख्या 2-31 लाख से बढ़कर 5-05 लाख हो गई है। शिक्षण, चिकित्सा, सामाजिक स्वास्थ्य, एक परिवार नियोजन पिछले वर्षों का विकास, औद्योगिक धर्मियों के लिए भवनों की आवश्यकता आदि सुविधाओं का कई गुना विस्तार हुआ है। मलेरिया रोग का सम्पूर्ण निराकरण हो गया है। जीवन आयु 32 से बढ़कर 50 वर्ष हो गई है।



उपरोक्त उपलब्धियों से हमारे आर्थिक विकास के प्रयत्नों का जानकारी मिलती है ।

कमियाँ—

हमारे देश में तीन पंचवर्षीय योजनाओं की कतिपय उपलब्धियों (achievements) की जानकारी उपरोक्त तथ्यों से मिलती है । किन्तु आज भी जनसाधारण योजनाओं के प्रति सार्वजनिक उत्साह का प्रतीक नहीं करता । योजनाओं में अनेक कमियाँ रही हैं जिनका विस्तृत वर्णन (कारणों सहित) प्रत्येक योजना के साथ विद्यते पृष्ठों में दिया गया है । यदि विभिन्न योजनाओं की कमियों को गणनित दिया जाए तो निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं—

1. मुख्य शहर में वृद्धि हो रही है ।
2. जनता घर घर मार में वृद्धि हो रही है ।
3. बेरोजगारी में वृद्धि होनी आ रही है ।
4. योजनाओं की निर्धारित प्राथमिकताएँ (Priorities) देश की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं ।
5. सरकार की नीति, योजना निर्माण, योजना का चिन्तामयन एवं चर्चे-वर्तों में समायोजन नहीं है ।
6. समाजवादी समाज की संरचना लागू नहीं है ।
7. कृषि, उद्योग, राष्ट्रीय स्तर आदि के मन्त्रों की प्रतीति में नहीं है ।
8. निजी क्षेत्र की सहायता नहीं ।
9. विकास व्यय (Development Expenditure) का अनुमान नहीं लगाया गया । प्रत्येक योजना के निर्धारित धर्मों में कम तथा दूसरी व तीसरी योजनाओं में अधिक व्यय हुआ है ।

1. वित्तीय साधनों (Financial Resources) सम्बन्धी कठिनाइयाँ रही हैं ।
2. विदेशी विनिमय का संकट बना रहा है ।
3. आवश्यक तकनीकी (Technical) ज्ञान एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव रहा है ।
4. सार्वजनिक क्षेत्र में कुशलता का अभाव रहा है ।
5. उचित प्रशासनिक व्यवस्था की कमी रही है ।
6. जनसहयोग (Public-co-operation) की कमी योजनाओं का सबसे बड़ी असफलता रही है ।
7. योजनाओं से प्राप्त सफलताओं एवं विफलताओं का मूल्यांकन करने के लिए उचित व्यवस्था का अभाव रहा है ।
8. देश में हृदय बिश्वास की भावना एवं गति से सम्बन्ध की कमी नीति नियोजन की असफलता के लिए उत्तरदायी है ।

भारत में आर्थिक नियोजन की सफलता के मार्ग में उपस्थित बाधाओं की सरकार की नीति में परिवर्तन लाकर दूर किया जा सकता है ।

योजनाओं की सफलता के लिए सुझाव (Suggestions)—

योजना की सिद्धि पर देश की समृद्धि निर्भर करती है । इसलिये इसे दूर सम्भव प्रयत्न करने चाहिये । निम्नांकित सुझाव इस दिशा में हितपूर्वक योगदान दे सकते हैं—

(अ) वित्तीय साधनों संबंधी—भारत जैसे अर्द्ध-विकसित राष्ट्र में निर्यात, बचत की कमी एवं कम विनियोग का कुपक व्याप्त है । इसी कारण है हमारी योजनाओं के लिए उचित साधनों का अभाव होता है ।

1. आन्तरिक साधन (Internal Resources)—उत्पादन वृद्धि एवं कल्याणकारी कार्यों के लिए बढ़ते हुए विनियोग की आवश्यकता होती है । आन्तरिक वित्तीय साधन मुख्यतः घरेलू बचत (Domestic Savings) तथा वित्तीय नीति (Fiscal Policy) पर निर्भर करते हैं ।

सुझाव—

(घ) वित्तीय साधनों का विस्तार—

1. आंतरिक साधन विशेषतः बचत
2. बाह्य साधन

(च) प्रशासन सम्बन्धी—

1. नीति व उद्देश्यों में समानता
2. कुशल प्रशासन व्यवस्था तथा उचित क्रियान्वयन
3. ईमानदार कर्मचारी
4. भ्रष्टाचन

(स) जनसहयोग—

1. योजना भावना का प्रसार
2. मूल आवश्यकताओं की वृत्ति
3. कार्य परियोजनाएं

(द) अन्य—

1. मूल्य नीति, तकनीकी साधन व महयोग आदि।

हमारे यहाँ सन् 1950-51 में घरेलू बचत का प्रतिशत कुल राष्ट्रीय आय का 5½ प्रतिशत था। यह प्रतिशत सन् 1965-66 में बढ़कर 10½ प्रतिशत हो गया। किन्तु इस अवधि में विनियोग किये जाने वाली राशि तीन गुनी हो गई। इस प्रकार विनियोग की तुलना में बचत की वृद्धि का अनुपात कम रहा।

देश में 'बचत' का बहुत बड़ा महत्व है। एक छोटे जहाँ इससे देश के आर्थिक विकास के लिए सपना मिलता है वही दूसरी ओर यह जनता की क्रयशक्ति (Purchasing Power) में कमी लाकर मुद्रा प्रसार या मूल्य वृद्धि को रोकती है।

आंतरिक साधनों के रूप में सार्वजनिक उद्योगों से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस लिए हमें अधिक से अधिक आंतरिक बचतों को प्राप्ति एवं महरी दोनों ही क्षेत्रों में बढ़ाना चाहिये।

नया सार्वजनिक उद्योगों में कुशलता को बढ़ाकर योजनाओं के लिए प्रतिष्ठित साधन प्राप्त करने चाहिये।

2. बाह्य साधन (External Resources)—किसी भी देश के आर्थिक विकास में विदेशी सहायता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। भारत ने भी विदेशों से अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए बहुत सहायता प्राप्त की है। किन्तु आर्थिक राष्ट्रवाद (Economic nationalism) के जन्म तथा गृह बन्दियों के कारण बहुत लम्बे समय तक भारतवर्ष बिना कर्त के विदेशी सहायता प्राप्त कर सकेगा। इसमें सन्देह है। इसलिए हमें विदेशी मुद्रा कमाने के लिए निर्यात प्रोत्साहन (Export promotion) की ओर ध्यान देना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाये हैं किन्तु उनसे अधिक लाभ नहीं मिला है। इसलिए सरकार इस सम्बन्ध में फिर से प्रयत्न करे और हमारी योजनाओं की आवश्यकताओं तथा ऋण चुकाने के लिए जरूरी विदेशी मुद्रा जुटावे। इस सम्बन्ध में आयात नियन्त्रण नीति एवं विदेशी साधनों का मितव्यवतापूर्ण उपयोग भी लाभदायक सिद्ध हो सकता है।

(ब) योजना के क्रियान्वयन एवं प्रशासन से सम्बन्धित—पिछले वर्षों में इस क्षेत्र में जो कमियाँ अनुभव की गई हैं उनके निराकरण हेतु निम्नांकित उपाय किये जाने चाहिए।

1. नीति व उद्देश्यों में समानता—सरकारी नीति व योजना के उद्देश्यों में समानता लाने की दिशा में आवश्यक प्रयत्न किये जाने चाहिए। उदाहरणार्थ समाजवादी समाज की स्थापना का आदर्श प्राप्त करने के लिए योजनाओं में आर्थिक व सामाजिक विषमताओं को दूर करने के लिए योजनाओं में आर्थिक व सामाजिक विषमताओं को दूर करने के निश्चित उद्देश्यों का उल्लेख किया जाना चाहिए।

2. योजना के क्रियान्वयन की उचित व्यवस्था के बिना कोई भी योजना चाहे कितनी ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, सफल नहीं हो सकती। प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के अनुसार योजना आयोग का पुनर्गठन तो हो चुका है किन्तु केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के स्तर पर योजना को कार्यान्वित करने के लिए उचित व्यवस्था का अभाव है। प्रत्येक राज्य में समन्वय समितियों (Co-ordination



Committees) की स्थापना भी की जानी चाहिए । जिला व ब्लॉक ( District and Block ) स्तर पर भी व्यवस्था में प्रभावशाली परिवर्तन लाने की आवश्यकता है ।

3. ईमानदार कर्मचारियों—हमारी योजनाएँ बहुत अच्छे एवं ऊँचे आदर्शों को लेकर बनायी जाती हैं किन्तु कर्मचारियों के आवरण एवं कार्यप्रणाली से उनका पूरा लाभ नहीं मिल पाता । सन्चरित व कार्यप्रिय कर्मचारियों के बिना योजनाएँ मूलतः कागजी योजनाएँ बनकर रह जाती हैं । राष्ट्रीय चारित्रिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि भ्रष्ट एवं बेईमान कर्मचारियों को दंडित किया जाए । योजनाओं को क्रियान्वित करने में जो बाधाएँ उत्पन्न करें उनको उचित मार्ग बताने हेतु आवश्यक माचार संहिता (Code of conduct) का निर्माण किया जावे । कर्मचारियों का उचित व्यवहार ही जन साधारण को योजना के प्रति आकर्षित कर सकेगा ।

4. मूल्यांकन की उचित पद्धति के बिना योजनाओं की उपलब्धियों एवं असफलताओं की सही जानकारी हासिल नहीं की जा सकती । हमारे योजना आयोग ने पिछले वर्षों में कुछ अध्ययन दलों (Study groups) की स्थापना की है जो विभिन्न क्षेत्रों की उपलब्धियों आदि की जानकारी प्राप्त करते हैं ।

(स) जनसहयोग (Public Co-operation)—हमारी योजनाओं का मुख्य आधार जन सहयोग है । किन्तु अभी तक जन साधारण इनके प्रति उदासीन है । अधिकाधिक जनसहयोग प्राप्त करने के लिए निम्नांकित उपाय काम में लाये जाने चाहिए—

1. योजना भावना (Plan consciousness) का प्रसार मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में किया जाना चाहिए । ग्रामीण जनता को सरल दृश्य एवं श्रव्य (Audio-visual) साधनों का प्रयोग कर योजनाओं के सम्बन्ध में अधिकाधिक जानकारी दी जानी चाहिए । इस क्षेत्र के

महाविद्यालयों के योजना मंच (Planning Forms) अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं ।

2. ग्रामीण जीवन की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयत्न किये जाने चाहिए । ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की सुविधाएँ, आवास सुविधाएँ एवं सिंचाई एवं कृषि विकास की सुविधाएँ जुटा कर निवासियों को योजनाओं के प्रति अधिक चेतम्य बना कर जन सहयोग के लिए प्रेरित किया जा सकता है ।

3. कार्य परियोजनाओं (Work projects) —के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय समूहों की सहायता की जानी चाहिए जिससे सरकार और जनता के बीच सहयोग का विस्तार हो सके । यद्यपि पिछली तीन योजनाओं में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के द्वारा इन परियोजनाओं में जनसहयोग प्राप्त करने की चेष्टा की गई किन्तु अभी भी इस क्षेत्र में बहुत कुछ किया जाना बाकी है । विस्तृत जन सहयोग के बिना योजनाएँ जनसाधारण को प्रभावित नहीं कर पाएँगी ।

(६) अन्य सुझाव—योजनाओं की कार्यविधि, वित्तीय साधनों एवं जनसहयोग के क्षेत्र में प्रयत्न करने के साथ साथ प्रभावशाली मूल्य नीति, आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए उचित कर प्रणाली, कुशल श्रमिकों की व्यवस्था, विदेशों से तकनीकी सहयोग, भौतिक साधनों का उचित उपयोग आदि कुछ उपाय हैं जिनसे योजनाओं के वांछित परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं ।

श्री अशोक मेहता के अनुसार “योजना के प्रमुख उद्देश्यों तक पहुँचने के लिए संगठित तथा निश्चित प्रयत्न अनिवार्य हैं । इसके लिए व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण, सही मूल्यांकन, विभिन्न संस्थाओं एवं व्यक्तियों में दायित्व की भावना तथा अग्रिमशीलता आवश्यक है ।”

### सारांश

भारत में आर्थिक नियोजन—स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद ही भारत में संगठित प्रयत्न प्रारम्भ किये गये । 1950 में पठित भारतीय

योजना आयोग ने भारत की योजनाओं के निर्माण व मूल्यांकन में महत्वपूर्ण योग दिया।

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) — योजना का मुख्य उद्देश्य विमात्रन तथा दुर्घटन अग्रगण्यता को दूर करना था। योजना पर 1960 करोड़ रुपये खर्च हुये यह योजना कृषि विकास को मुख्य योजना थी।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61) — उद्देश्य — 1. राष्ट्रीय आय में वृद्धि, 2. औद्योगीकरण, 3. रोजगार के अवसरों में वृद्धि तथा 4. आर्थिक विषमताओं में कमी।

योजना पर 4,600 करोड़ रुपये खर्च किये गये। यह योजना औद्योगिक विकास के लिये महत्वपूर्ण थी।

तृतीय पंचवर्षीय योजना — (1961-66)। उद्देश्य — 1. राष्ट्रीय आय में वृद्धि, 2. साक्षात् में आत्म निर्भरता व कृषि उत्पादन में वृद्धि, 3. मूल उद्योगों का विकास, 4. रोजगार के अवसरों में वृद्धि तथा 5. आर्थिक विषमताओं को दूर करना।

योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में अनुमानित 7500 करोड़ रुपये की लगभग 8628 करोड़ रुपये खर्च हुये। योजना में कृषि, उद्योग एवं यातायात के विकास पर अधिक बल दिया गया है।

भारत की वार्षिक योजनाएँ—

तृतीय पंचवर्षीय योजना के मध्य विभिन्न विधम परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप अनुर्य योजना के स्थान पर भारत में वार्षिक योजनाएँ बनाई गईं।

वार्षिक योजना 1966-67—इस अवधि में 2221 करोड़ रु० व्यय करने का लक्ष्य था। विद्युत, कृषि उद्योग, यातायात, राष्ट्रीय आय आदि में भी विभिन्न लक्ष्य रसे गये।

वार्षिक योजना — 1967-68—इसमें 2248 करोड़ रुपये व्यय करने का अनुमान था। जिसमें सबसे ज्यादा राशि संगठित उद्योगों पर

ध्यय करने का अनुमान था । इससे अनुमानित प्राप्तिमें व ध्यय से 54 करोड़ रु० का अन्तर रहा था ।

तीन पंचवर्षीय योजनाओं में भारत की आर्थिक प्रगति—मान्य में तीन योजनाओं के मध्य आभासीत सफलता प्राप्त हुई है । विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त सफलता—

1. राष्ट्रीय आय—सन् 1950-51 से 1964-65 तक राष्ट्रीय आय 69 प्रतिशत ज्यादा हुई ।

2. कृषि—कृषि उत्पादन में 65 प्रतिशत वृद्धि हुई । सभी प्रकार की सिंचाई योजनाओं से 4-54 करोड़ एकड़ भूमि पर अतिरिक्त सिंचाई होने लगी ।

उद्योग शक्ति व मातायात—उद्योगों का उत्पादन 152 प्रतिशत ज्यादा हुआ । विद्युत शक्ति में चार गुना वृद्धि हुई । रेलों की मार बाह्यन समता दुगुनी हो गई ।

3. समाज सेवाएँ—मनुष्य की औसत उम्र 32 वर्ष से बढ़कर 50 वर्ष हो गई । मलेरिया का निराकरण हो गया ।

कमियाँ—(1) ग्राम्य शहर में वृद्धि, (2) घर घर में वृद्धि, (3) बेरोजगारी में वृद्धि, (4) प्राथमिकताओं का देश की आवश्यकताओं के अनुकूल न होना, (5) सरकार की अस्पष्ट नीति, (6) समाजवादी समाज की संरचना का न होना, (7) सड़कों की प्रगति का न होना, (8) निजी क्षेत्र की उद्वेग की गई, (9) विकास ध्यय का दलदल अनु-मान लगाया गया, (10) वित्तीय साधनों का उपलब्ध न होना, (11) विदेशी विनिमय का संकट, (12) प्रतिष्ठित कर्मचारियों का अभाव, (13) अकुशलता, (14) अनुचित अन्तर्गतिक व्यवस्था, (15) जनता के सहयोग का अभाव, (16) मूल्यांकन का अभाव, (17) हड़ विधान का अभाव ।

योजनाओं की सफलता के लिए सुझाव—

(अ) वित्तीय साधनों का विस्तार—







